मैकब्राइड कमीशन रिपोर्ट 'मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड' का हिन्दी अनुवाद और उसका विश्लेषण (पृष्ठ 01-64)

(Hindi Translation and Analysis of Macbride Commission Report 'Many Voices One World')
(Page 01-64)

Dissertation submitted to Jawaharlal Nehru University
in partial fulfillment of the requirements for
the award of the degree of

MASTER OF PHILOSOPHY

शोध निर्देशक

डॉ. राम चंद्र

शोधार्थी

प्रियंका श्रीवास्तव

भारतीय भाषा केंद्र

भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

नई दिल्ली- 110067

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
Jawaharlal Nehru University
भारतीय भाषा केन्द्र
Centre for Indian Languages
भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान
School of Language, Literature and Culture Studies
नई दिल्ली- 110067, भारत New Delhi – 110067, (India)

Date: 25. July 2014

DECLARATION

I hereby declare that the research work done in this M. Phil. Dissertation entitle **"Macbride Commission Report 'Many Voices One World' Ka Hindi Anuvaad Aur Uska Vishleshan (Pristh 01–64)", (Hindi Translation and Analysis of Macbride Commission Report 'Many Voices One World' (Page 01-64))** by me is the original research work and it has not been previously submitted for any other degree in this or any other University/ Institution.

PRIYANKA SRIVASTAVA

(Research Scholar)

Dr. RAM CHANDRA

SUPERVISOR

CIL/SLL&CS/JNU

CHAIRPERSON

CIL/SLL&CS/JNU

विषय-सूची

भूमिका i-iii

अध्याय एक: मैकब्राइड कमीशन और मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड का परिचय 1-32

क मैकब्राइड कमीशन का परिचय 1-5

ख मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड का परिचय 6-32

अध्याय दो: मैकब्राइड कमीशन रिपोर्ट "मेनी वॉयसेसे वन वर्ल्ड" का अनुवाद 33-190

आमुख 33-38

भूमिका 39-46

भाग एक: अध्याय-1 47-72

अध्याय-2 73-116

अध्याय-3 117-135

भाग दो: अध्याय-1 136-190

अध्याय तीन: अनूदित रचना में अनुवाद संबंधी समस्याओं का विश्लेषण 191-209

उपसंहार 210-214

संदर्भ-ग्रंथ 215-216

भूमिका

वैश्विक स्तर पर समाज बहुभाषी है। बहुभाषी समाज में एक-दूसरे से संचार करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आज विभिन्न समाजों एवं समुदायों में अनुवाद केवल संचार के लिए नहीं बल्कि ज्ञान-विज्ञान, कला -संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक आदि से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। मौखिक और लिखित दोनों स्तर पर अनुवाद हो रहें हैं। भारत में अनुवाद परम्परा बहुत प्राचीन है। लेकिन तकनीकी, जनसंचार और सूचना साहित्य के अनुवाद की कमी यहाँ अब भी बनी हुई है। तकनीकी, जनसंचार, सूचना, वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ज्यादा न होने के कारण भारत जैसे बहुभाषी देश में ज्ञान का व्यापक प्रसार नहीं हो पा रहा है और एक बड़ा हिस्सा जानकारियों के अभाव में जी रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई सूचना आ रही है जिसे तुरंत ही अपनी भाषा में अनुवाद कर के अपने लोगों को सूचनाओं से समृद्धि किया जा रहा है।

अनुवाद भी संचार की प्रक्रिया का हिस्सा है और संचार के बिना कोई भी देश अपने अस्तित्व को नहीं बचाए रख सकता है। लेकिन अगर संचार प्रणाली का प्रयोग एक देश, समुदाय और समाज द्वारा अपनी संस्कृति, भाषा, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को किसी दूसरे देश, समुदाय और समाज पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जाने लगे तो यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। आज प्रत्येक देश को यह जानकारी रखना आवश्यक हो गया है कि कहीं संचार माध्यम का प्रयोग उसके देश के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। अनुवाद भी इस निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1980 में बने मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट वैश्विक संचार

की समस्याओं पर थी। जब विकसित देश संचार माध्यम का प्रयोग कर अपनी संस्कृति, राजनीति और आर्थिक नीतियों एवं प्राथमिकताओं को विकासशील देशों पर थोपना चाहते थे जिनका विरोध विकासशील देश आरम्भ से करते आ रहे थे। इस विरोध के कारण के यूनेस्को ने मैकब्राइड कमीशन की स्थापना की और समस्याओं का व्यापक स्तर अध्ययन हुआ। यह रिपोर्ट अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में लिखी गई जिनका अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में किया गया और पूरी रिपोर्ट को पूर्णरूप से अंग्रेज़ी भाषा में ही रखी गया। भारत ने भी इस रिपोर्ट को बनने योगदान दिया लेकिन आज 34 सालों के बाद भी यह रिपोर्ट हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद न हो सकी । इससे भारतीयों को संचार की समस्याओं के बारे में जानकारी न हो सकी। जनसंचार के क्षेत्र में प्रतिदिन नई -नई जानकारियां संप्रेषित की जा रही हैं, जिनका अनुवाद लोगों को उनकी भाषा में होना जरूरी है । लेकिन भारत में हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषा में ऐसी उपयोगी सामग्री के अनुवाद तेजी से नहीं हो रहे हैं।

लघु शोध प्रबन्ध लिखना मेरे एम. फिल के कोर्स का हिस्सा है। लेकिन लघु शोध प्रबन्ध लिखने के लिए किस विषय का चयन किया जाए यह अत्यधिक चुनौती पूर्ण कार्य है। विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ने और समझने के बाद किस प्रकार कार्य किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरा ध्यान मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट पर गया। 2005 में मैकब्राइड रिपोर्ट को जारी हुए 25 साल हो गए थे। इस रिपोर्ट को 2004 में पुनः प्रकाशित किया गया था। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर संचार की समस्याओं पर बृहद अध्ययन करके लिखा गया था। "मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड" के बनने के इतने सालों के बाद भी विडम्बना यह है कि भारतीय भाषा में इसका अनुवाद अभी तक संभव नहीं हो सका है। भारतीय

जनसंचार व्यवस्था अभी अपने शैशवकाल में है, इसलिए इस रिपोर्ट के द्वारा भारतीय जनसंचार व्यवस्था की कमियों एवं सामग्रियों को समझा जा सकता है। आज वैश्विक स्तर पर जब संचार माध्यमों द्वारा आर्थिक शोषण, सार्वजनिक निषेध, आर्थिक नियंत्रण, राजनीतिक निगरानी तथा विचारों का वर्चस्ववादी सत्ता द्वारा दमन जैसी गतिविधियाँ लगातार जारी है, तो इस स्थिति में इस रिपोर्ट का अध्ययन भारतीय जन द्वारा अपनी भाषा में किया जाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्हीं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मैंने इस रिपोर्ट का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने का निश्चय किया है । अभी तक इसका अनुवाद हिन्दी में न उपलब्ध होना अपने आप में चकित करने वाला विषय है। प्रस्तुत अनुवाद-कार्य द्वारा इसी कमी की भरपाई की दिशा में एक विनम्र प्रयास है। इस अनुवाद कार्य से जनसंचार के क्षेत्र में भारतीय समाज किस तरह अंधेरे में है, समझ पाएगा और जनसंचार के इस बारिक खेल को जिसमें मानसिक गुलाम बनाने का खेल तेजी से खेला जा रहा है उससे बचने की कोशिश करेगा।

प्रस्तुत लघु शोध में "मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड" का संक्षेप में परिचय, अनुवाद तथा अनुवाद का विश्लेषण किया गया है। प्रथम अध्याय में पाठक को विषय के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से खण्ड क में 'मैकब्राइड कमीशन का परिचय' तथा खण्ड ख में "मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड" के रिपोर्ट को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय के "खण्ड क" में मैकब्राइड कमीशन कब बना, किस लिये बना, कौन-कौन इसमें शामिल थे, किस संस्था द्वारा यह शोध कार्य किया गया का वर्णन है। "खण्ड ख" में "मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड" रिपोर्ट का संक्षेप में परिचय दिया गया है कि यह रिपोर्ट क्या है, किस विषय से सम्बन्धित है। अध्याय दो में मैकब्राइड कमीशन का अनुवाद पृष्ठ 1 से पृष्ठ 64 तक किया गया है। अध्याय तीन में अनुवाद के बारे में तथा अनूदित पाठ में

अनुवाद सम्बन्धित समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। एम. फिल. पाठ्यक्रम के समय सीमा तथा अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए केवल 64 पृष्ठों तक अनुवाद किया है। लेकिन जल्द ही मैं पूरी रिपोर्ट का अनुवाद करूंगी । आशा है प्रस्तुत लघु शोध हम सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और यह चिंतन का एक आधार प्रदान कर सकेगा।

अध्याय एक

एक मैकब्राइड कमीशन और मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड का परिचय

खण्ड-क

मैकब्राइड कमीशन का परिचय

1970 में संचार के मुद्दों से सम्बन्धित अंतरराष्ट्रीय बहसों को संचार के वैश्विक सवालों का सामना करना पड़ा। तीसरी दुनिया के देश औद्योगिक देशों के प्रभाव से खुद को मुक्त रखना चाहते थे। इस कारण प्रभावित या संक्रमित सूचनाओं का विरोध कर रहे थे। यह वह दौर था जब औद्योगिक देश मुक्त सूचना प्रवाह की बातें करते नहीं थक रहे थे। जबकि तीसरी दुनिया के देशों को प्रेषित सूचनाएं प्रायः अवांछनीय ढंग से संपादित-संशोधित रहती थी। पत्रकारिक स्वतंत्रता के समर्थकों को राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर काबिज घुसपैठियों के रूप में चिन्हित किया जाने का चलन जोर पकड़ रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचार की इन्हीं समस्याओं और औद्योगिक तथा तीसरे देशों के बीच संचार माध्यमों को लेकर हो रहे विरोध का अध्ययन करने के लिए 1977 में मैकब्राइड कमीशन की स्थापना यूनेस्कों द्वारा की गई। 1976 में यूनेस्को के महानिदेशक एमडो-मबो को नैरोबी में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन के 19वें सत्र में निर्देश दिया गया कि वह एक ऐसे आयोग का गठन करें जो समकालीन समाज में संचार की सभी समस्याओं का अध्ययन करे और बताए की तकनीकी विकास तथा संचार में नए बदलाव आने के कारण किस प्रकार ये अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित कर रहे हैं। इस कमीशन ने जनसंचार का ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अध्ययन वैश्विक स्तर पर किया। इस आयोग का प्रमुख लक्ष्य था कि समाचार और जनसंचार का प्रवाह उतना ही न्याय संगत हो जितना का मौलिक अधिकार। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी शोध किया कि समकालीन समाज में जनसंचार का प्रयोग करना सभी का मौलिक अधिकार

है या उसमें किसी का प्रभाव ज्यादा है। मैकब्राइब कमीशन की रिपोर्ट ही मुख्य कारण था जिसके कारण अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लगभग 17 और 23 साल छोड़ दी थी। मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक बड़े मीडिया वैश्विक बहस की शुरूआत हो गई थी। 1970-75 में गरीब देशों पर साम्राज्यवादी विचारों को थोपने के विरोधों के कारण इस आयोग का गठन किया गया था जिसके विरोध में पश्चिम के देशों द्वारा 1976-77 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कमेटी का गठन किया था।

इस कमीशन की रिपोर्ट 'मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड' के नाम से आयी। कमीशन की अध्यक्षता आइरिस पत्रकार, वकील और राजनीतिज्ञ, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के अध्यक्ष, एमेनेस्टी इंटरनेशनल के स्थापित सदस्यों में शामिल, नांबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि, नोबेल और लेनिन पुस्कार विजेता सीन मैकब्राइड ने की थी जिसके कारण इसे मैकब्राइड कमीशन भी कहा जाता है। इसमें सीन मैकब्राइड के अलावा विश्व के सभी कोनों से 15 सदस्यों को शामिल किया गया था जो अपने विषय के अलावा संचार के विषय के भी विद्वान थे। इनके नाम इस प्रकार थे- एली एबल (अमेरिका)पत्रकार और प्रसारणकर्ता, ह्यूबर्ट ब्यूव-मेरी (फ्रांस)पत्रकार, ले मोन्डे समाचार पत्र के संस्थापक, सेन्टर दे फारमेशन इत दे परफेक्सनोमेन्ट देस जर्नालिस्टिज पेरिस के अध्यक्ष, एल्बे मा एकोंजो (ज़ैरे) पत्रकार, राष्ट्रीय प्रेस के निर्देशक, ज़ैरे प्रेस ऐजेन्सी के महानिदेशक, गेब्रियल गार्सिया मार्कोएज (कोलंबिया)पत्रकार और लेखक,एल्बेम सर्जी लेसेव (यूएसएसआर) तास न्यूज एजेन्सी के महानिदेशक, मोक्तर ल्युबिस (इंडोनेशिया) पत्रकार, प्रेस फाउंडेशन ऑफ़ एशिया के अध्यक्ष , मुस्तफा मासमौउदी (ट्यूनीशिया) यूनेस्को में ट्यूनीशिया के प्रतिनिधि, राज्य के सूचना विभाग के औपचारिक सचिव, मिशियो नगाई (जापान) पत्रकार और समाजशास्त्री, शिक्षा मंत्री, असाही सिम्बुन अखबार के स्तम्भकार, फ्रेड आईसेक एक्पोरूआरो ओमू (नाइजीरिया)

बेनिन विश्वविद्यालय में शोध के प्राध्यापक, पूर्व में राज्य के सूचना,समाज विकास और खेल के कमीशनर, बॉग्डेन ओसोल्निक (युगोस्लाविया) पत्रकार, राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीय सभा के सदस्य, जमाल अल ओतिफी (मिस्र) सूचना और संस्कृति मंत्रालय के पूर्व मंत्री, प्राध्यापक काहिरा विश्वविद्यालय, पत्रकार, वकील और कानूनी सलाहकार, जोहानेस पीटर प्रोंक (नीदरलैंड) अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, जुआन सोमाविया (चिली) कार्यकारी निदेशक लैटिनोअमेरिकानो दे इस्तूडिओस ट्रान्सनासिओनलेस (मैक्सिको सिटी), बूबली जार्ज वर्गीज़(भारत) पत्रकार और गांधी पीस फाउंडेशन के फेलो और बैटी जिमरमैन (कनाडा) रेडियो कनाडा इंटरनेशनल के निदेशक और प्रसारणकर्ता।

मैकब्राइड कमीशन मीडिया और सूचनाओं से सम्बन्धित आधुनिक समाज की समस्याओं के अध्ययन के लिए बनाया गया था। सूचना प्रौद्योगिक विकास तथा इसका प्रयोग विश्व शान्ति को भंग करने में न किया जाए, इस आधार-बिन्दु को ध्येय मानकर अपनी जांच-पड़ताल शुरू की तथा तत्सम्बन्धी सुझाव पेश किए। इस रिपोर्ट में जनसंचार के अलावा मीडिया के व्यवसायीकरण, एकरूपता तथा उसकी स्वतंत्रता पर भी विचार किए गए थे और इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था।

इस रिपोर्ट को मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में इस रिपोर्ट की निंदा करते हुए 1984 और 1985 में यूनेस्कों से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी और बाद में 1997 और 2003 में पुनः शामिल हो गए। संचार मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसका दुरुपयोग या किसी एक पक्ष द्वारा अपने हित में नहीं किया जा सकता, को भी इस आयोग ने मुद्दा बनाया था।

विश्व में मानव विकास की समस्याओं तथा शांति बनाए रखने में संचार व्यवस्था किस प्रकार काम करेगा इन पहलुओं पर भी गंभीरतापूर्वक विचार

किया गया था। समाचार मूल्यों की अवधारणा का परिवर्तित होना, समाचार पत्रों की कार्य-प्रणाली में फेरबदल, पत्रकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष, जन माध्यमों की अन्य जवाब देही से सम्बन्धित निष्पक्ष एवं तर्क संगत बहस, वैश्विक स्तर के समसामयिक विषयों को सुलझाने में मीडिया की भूमिका आदि मुद्दे इस कमीशन के विशद मूल्यांकन एवं विश्लेषण का अंग-उपांग थे। इस रिर्पोट में पहली और तीसरी दुनिया के मध्य संचार की वजह से बढ रही नकारात्मकता को दूर करने का हर संभव प्रयास किया था। इस कमीशन में बेहतर समाज के निमार्ण में संचार की अप्रितम भूमिका के बारे में विशद विवेचना-विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है जो सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह को जरूरी एवं महत्वपूर्ण मानते हैं।

आयोग को इस सौंपें हुए कार्य के लिए पूरी बौद्धिक स्वतंत्रता दी गई थी और आयोग ने रिपोर्ट के विषय वस्तु को लिखने में पूर्ण स्वतंत्रता और बिना पक्षपात के कार्य किया। दिसम्बर 1977 से नवम्बर 1979 तक आयोग के आठ सत्र 42 दिन चले। इसमें पेरिस में 4 सत्र और अन्य सत्र क्रमशः स्वीडेन में अप्रैल 1978, जनवरी 1979 यूगोस्लाविया, भारत में मार्च 1979 तथा मैक्सिको में जून 1979 तक चले। स्टाकहोम के सत्र में स्वीडिस सरकार के साथ मिलकर समाचार की संरचना, संग्रह तथा प्रसार के ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। पेरिस के बाहर भी अन्य सत्रों के गोल मेज सम्मेलन में इसी के समान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका प्रमुख विषय संचार का समाज, विकास, तकनीकी और संस्कृति के सम्बन्ध पर था। आयोग के द्वारा रिपोर्ट पर काम करते हुए इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का विभिन्न प्रकार के सेमिनार सभा, सम्मेलन में जाना होता जिस का आयोजन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और पेशेवर संघों तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय और राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाता था। कमीशन के कार्य में अतिरिक्त

स्वायत्त निवेश संसार भर के विशेषज्ञों द्वारा संचार के विशिष्ट पहलुओं पर किया गया और दर्जनों अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय तथा राष्ट्रीय संस्थाओं, शोध केन्द्रों, पत्रकारिता के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पेशेवर संघों और ऐसे अन्य संस्थाओं द्वारा साधारणतौर पर बहुत से बहस, शोध खाज, प्रासंगिक प्रलेखन और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां दी गई। आयोग को सौ से अधिक व्यक्तिगत, संस्थानिक तथा सरकारी टिप्पणियां इसके अंतरिम रिपोर्ट पर मिले जिसे प्रकाशित किया गया। सात हजार से ज्यादा पतों पर रिपोर्ट प्रसारित की गयी और 1978 में यूनेस्को के आम सभा के 20वें सत्र में कमीशन ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। विभिन्न देशों के विद्वानों ने अपनी विशेषज्ञता के साथ काम करते हुए अपनी सहमती देते हुए इस कार्य को कामयाब बनाया। इसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। फरवरी 1980 के बेलग्रेड में येनेस्को के 21वें सम्मेलन में विवादास्पद बहस के बावजूद एमडो-मैटर मबो ने इस आयोग को मंजूरी दे दी। इस आयोग की रिपोर्ट "मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड" के नाम से आयी जिसे बाद किताब की शक्ल दे दी गई।

खण्ड-ख

मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड: एक परिचय

संचार आधारित सूचना सामग्रियों के मुक्त/निर्बाध प्रवाह सम्बन्धी समस्याओं को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट जो कि "मेनी वायसेस वन वर्ल्ड" शीर्षक से प्रस्तुत की गई थी सामान्यतया "मैकब्राइड रिपोर्ट" के नाम से जानी जाती है। ध्यातव्य है कि मैकब्राइड रिपोर्ट बड़े स्तर पर संचार संदर्भित वैश्विक समस्याओं पर आधारित है। 2004 में सूचना-समाज के मूल्यांकन पर बहस करते हुए इसके महत्व को स्वीकार करते हुए रोमैन एंड लिटिलफिल्ड ने इसे पुनः प्रकाशित किया। रिपोर्ट के साथ विवादों के होने तथा ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा कमीशन को बीच में छोड़ देने के कारण यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से प्रकाशित न हो सकी थी। यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने 1980 में आयोग के इन विचारों को किताब के शक्ल में प्रकाशित करने का निर्णय लिया था जो कि संचार का वैश्विक स्तर पर अध्ययन करके लिखी गई थी। इसमें संचार के इतिहास के विश्लेषण एवं मूल्यांकन का बेहतरीन कार्य किया गया है। वर्तमान समय में जब विकलिक्स तथा एडवर्ड स्नोडेन दुनिया को आगाह करते हैं कि किस प्रकार संचार माध्यमों का प्रयोग मनुष्यों के खिलाफ हो रहा है तथा सूचना तकनीकी मनुष्य समाज के लिए खतरा बनती जा रही है तब यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती है।

कालाब्रिज ने 2004 में पुनः प्रकाशित मैकब्राइड की रिपोर्ट में अपनी प्रस्तावना में लिखा है-"अगर जनसंचार के क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवर्तन के स्तर पर वैश्विक न्याय मिले तथा वैश्विक संचार

का प्रयोग ज्ञान, समझ और पारस्परिक समझ के अर्थ में किया जाए तो एक अच्छे संसार की संभावना बन सकती है।" इस रिपोर्ट में मीडिया और संचार की नीति समाज, संस्कृति और आर्थिक विकास के विषय में किस तरह से जुड़ी होंगी इस पर जोर दिया गया है। इसमें मीडिया शिक्षा को बढ़ावा देने तथा संचार की सुविधाओं को स्थानीय लोगों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है।

मैकब्राइड रिपोर्ट को लिखने वाले स्वीकारते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में समानता को प्राप्त करने के लिए मीडिया संगठनों की बनावट और संरचना के अनुरूप संचार बाजारों को बड़े बदलाव की जरूरत है। उनका कहना था कि मीडिया, संचार नियमन एवं बाजार संरचना, टेलीकंम्युनिकेशन बाजार को उदार बनाना चाहिए एवं नीतियों का लक्ष्य प्रसारण और अखबारों के एकाधिकार और प्रमुखता को कम करना चाहिए। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद केवल वैश्विक संचार ही नहीं बदला बल्कि वैश्विक राजनीति भी बदल गई। आयोग ने संचार की समस्याओं को कम करने के लिए "न्यू वर्ल्ड इनफारमेशन एंड कम्यूनिकेशान आर्डर" की स्थापना का सुझाव दिया। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट की आलोचना बाजार विरोधी कह कर की। मैकब्राइड की रिपोर्ट पत्रकारों के लिए आचार संहिता को बनाने की बात कहने के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विषयवस्तु की विभिन्नता को बचाने की आवश्यकता पर जोर देती है। गर्बनर(1993) और पोदोवानी एवं नोरदेन सट्रेन्ज़(2005) ने मैकब्राइड रिपोर्ट के बारे में कहा कि इस रिपोर्ट ने एक वैश्विक मीडिया के बहस को उठाया है। इस रिपोर्ट को विश्लेषणात्मक बहस के उद्देश्य के साथ बनाया गया और यह रिपोर्ट साम्राज्यवाद के खिलाफ शोध था। रिपोर्ट की शुरुआत संचार के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय अधिकारों के वर्णन के साथ होती

है। इसमें सरकार नियंत्रण, सेंसरशिप, सूचना का एकतरफा प्रवाह, सांस्कृतिक प्रभुत्व और जन-मीडिया के व्यवसायीकरण से सम्बन्धित सांस्कृतिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने रिपोर्ट बनाई। संचार के इतिहास के लिए इस रिपोर्ट को बनाने वालों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस रिपोर्ट में पश्चिम की मीडिया द्वारा जनसंचार माध्यमों के केन्द्रीकरण और मीडिया पर किस तरह पश्चिम मीडिया का वर्चस्व है इस बात को भी ध्यान में रखकर शोध-कार्य किया गया था।

मैकब्राइड रिपोर्ट 5 भागों में लिखा गया है। प्रत्येक भाग में अलग-अलग अध्यायों के अंदर संचार से जुड़े बिन्दुओं का विश्लेषण किया गया । इसमें यह भी बताया गया है कि आयोग का गठन संचार की समस्याओं के लिए किस तरह हुआ है और किन-किन विद्वानों ने सहयोग किया। इस आयोग की रिपोर्ट को बनाने में किस तरह की गतिविधियां की गई इसका विस्तार से वर्णन है।

इस रिपोर्ट का पहला भाग संचार और समाज के सम्बन्धों पर है। संचार और समाज के सम्बन्धों का वर्णन ऐतिहासिक, समसामयिक तथा अंतरराष्ट्रीय आयामों के अंतर्गत की गई है । ऐतिहासिक आयाम के अध्याय में बताया गया है कि संचार जीवन की गतिविधियों का हिस्सा सदैव से रहा है। चाहे सामाजिक गतिविधियां हो या सभ्यता की अभिव्यक्ति हो, संचार के द्वारा ही होता है। संचार ने ही अतीत से वर्तमान तक के विचारों के पूल बनाने में हमारी मदद की है। बिना संचार के मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। चाहे मनुष्य ने सृजनात्मक कार्य किया हो या विनाश का संचार ही माध्यम रहा है। मनुष्य संचार के द्वारा ही एक बेहतर जीवन के प्रयास में यहाँ तक पहुँच पाया है। जैसे-जैसे दुनिया उन्नतशील होती गई संचार का

कार्य अधिक जटिल होता गया। इतिहास में मनुष्य ने अपने चारों तरफ से आने वाले सूचनाओं को प्राप्त करने और उन्हें आत्मसात करने की योग्यता को लगातार विकसित करता रहा है। सबसे पहले उसने अपने भावभंगिमा से संदेशों का आदान-प्रदान किया फिर अग्नि संकेत, चित्र ग्राफ़िक, चित्रलिपि संगीत, नृत्य,आदि से संदेश संचारित किए। दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क की कमी के चलते विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास हुआ। भाषाओं की वजह से विभिन्न आर्थिक-नैतिक और सांस्कृतिक परम्पराओं वाले समाजों में विशिष्ट शब्दावलियों और भाषाई संरचनाओं का उदय हुआ। संचार का विकास तेजी से हो तो रहा था लेकिन जिस समुदाय या क्षेत्र का वर्चस्व ज्यादा होता उसकी भाषा का वर्चस्व भी उतना ही होता। इसलिए साम्राज्यवाद के युग के दौरान उपनिवेशिक शक्तियों की भाषा ही उनके उपनिवेशों में प्रशासन, कानूनों, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा बन गई। एशिया और अफ्रिका के कुछ स्वतंत्र हो चुके राष्ट्रों में एक हद तक अंग्रेजी और फ्रेंच की आज भी यही स्थिति है।

मनुष्य का लिखना उसके संचार के विकास की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लिखने की कला ने उसके मौखिक शब्दों को स्थायित्व दिया। पहले लकड़ी, मिट्टी की पट्टी, पत्थर की नक्काशी से लिखने की शैली की शुरूआत हुई जो आगे चलकर ताम्रपत्रों, चमड़े पर लिखे जाने लगे। किताबों का इतिहास 13वीं शताब्दी से मिलता है। किताबों ने कई महान सभ्यताओं के विचार और ज्ञान को प्रसारित किया। आधुनिक युग की शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की तारीख से मानी जाती है। मुद्रण का आविष्कार चीन में नवीं शताब्दी और यूरोप में 15वीं शताब्दी में हुआ। चीन, भारत, मिस्र, रोमन जैसी सभ्यताओं में विचारों और ज्ञान का अमूल्य भंडार पुस्तकें थी। क़ागज़

के आविष्कार के साथ ही किताबों के उत्पाद में महत्वपूर्ण प्रगति की। क़ागज़ से पहले भोजपत्रों और तामपत्रों पर लिखा जाता था। ईसा की पहली शताब्दी से कागज का इस्तेमाल हुआ। अरब में 18वीं तथा यूरोप में 14वीं शताब्दी में क़ागज़ के इस्तेमाल की शुरूआत हुई। 17वीं शताब्दी में किताबों के बाद समसामयिक पर्चों और बाद में समाचार पत्रों का आगाज हुआ। शुरुआती दौर में समाचार पत्रों की स्थापना व्यापार, सामग्री, जहाजों के आवागमन और अन्य दूसरी सूचनाओं के लिए की गयी थी। ब्रिटेन, अमेरिका को प्रेस की आज़ादी की जीत 18वीं शताब्दी के अंत में सैद्धांतिक रूप से मिली। प्रेस की बढ़ती लोकप्रियता तथा समाज के बदलाव में हस्तक्षेप के साथ जनसंचार के उपकरणों में भी विकास हुआ। पहले फ़ोनोग्राफ़, टेलीग्राफ़ी, टेलीफोन, वायरलेस, रेडियो का विकास हुआ। 1894 में पहली फिल्म प्रदर्शित की गई। 1904 में फ़ोटोटेलीग्राम के जरिये पहली फ़ोटो प्रेषित की गई। 1920 में रेडियो नेटवर्क स्थापित हुआ। 1954 तक रंगीन टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोप ने 1857 में पानी के नीचे बिछाए केबिल तार से अंतर-महाद्वीपीय संचार शुरू किया। उपग्रह और अंतरिक्ष में मानव रहित यानों को भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया। रेलवे के द्वारा समाचार प्रसारित किया जाने लगा। विज्ञापनों से मिले धन से समाचार संस्थाओं को वित्तीय सहयोग मिला और टेलीग्राफ़ के जरिए ताजा खबरों का प्रसारण किया जाने लगा और प्रेस अपने को चौथा स्तम्भ कहने लगा था।

'समकालीन आयाम' के अध्याय में बतलाया गया है कि संचार के माध्यम से केवल समाचारों और संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाता बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के रूप में विचारों, तथ्यों तथा आकड़ों को भी साझा किया जाता है। संचार के कार्य के अंतर्गत सूचना देना,

समाजीकरण, मनोरंजन तथा शिक्षित करना आता है। संचार एक सामाजिक आवश्यकता भी है। अतीत में संचार व्यवस्था को अकसर समाज के भीतर एक अलग घटना के रूप में देखा जाता था, जो अनिवार्य रूप से तकनीकी से संबंधित था और समाज के अन्य पहलुओं से कमोबेश कटा हुआ था। राजनीतिक व्यवस्था में इसका स्थान, सामाजिक संरचना के साथ इसका जुड़ाव और सांस्कृतिक जीवन पर उसकी निर्भरता पर शायद ही कभी पर्याप्त विचार किया गया हो। संचार के साधनों के बुरे कामों या विकृतियों के संदर्भ वास्तव में समकालीन समाजों के अंतर्निहित विरोधाभासों से संबंधित हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के कई प्रभाव हैं-वास्तविक या आभासी, गहरे या उथले, स्थाई या अल्पकालिक; जिसके लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिनमें से संचार केवल एक है। समग्र रूप से संचार को इसके राजनीतिक आयामों, इसकी समस्याओं के संदर्भ को जाने बिना समझा नहीं जा सकता है और राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखे बिना उनका समाधान भी नहीं किया जा सकता है। अगर राजनीति शब्द का इस्तेमाल 'उच्च' भाव के रूप में किया जाए तो उसके संचार के साथ बेहद मजबूत संबंध हैं। संचार और राजनीति के संबंधों के दो रूप हैं-सत्ता और संचार का संबंध और दूसरा स्वतंत्रता और संचार का संबंध। संचार पर मौजूदा वैश्विक बहस अपरिहार्य रूप से राजनीतिक है, क्योंकि चिताएं, उद्देश्य और दलीलों की मुख्यतः राजनीतिक विशेषताएं हैं। अपनी संरचना और अपनी विषय-वस्तु, दोनों ही लिहाज से संचार कई तरह से अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है और उस पर निर्भर है। आर्थिक जीवन के लिए सूचना का सतत प्रवाह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते महत्व वाले घटक के रूप में संचार देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक बढ़ते हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और उत्पादकता तथा रोजगार पर उसका सीधा प्रभाव है। खासतौर से, दूरसंचार में

प्रगति से सूचनाओं का तत्काल संप्रेषण शुरू हुआ है, और ऐसे में कुछ स्थानों में कुशल श्रमिकों के बिना काम चल रहा है, जबकि अन्य स्थानों पर इसकी प्रकृति बदली है। ये संचार ही है जो अब औद्योगिक समाजों में विकास की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को थामे हुए है और उसे विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में देखा जा सकता है। ज्यादातर देशों में संचार के तीव्र विकास, जनसंचार के विभिन्न रूपों के विस्तार और खासतौर से श्रव्य-दृश्य संचार, के साथ ही सूचना विज्ञान के प्रसार ने नए क्षितिज खोले हैं और शिक्षा तथा संचार के बीच संपर्क को कई गुना किया है। संचार की शैक्षणिक क्षमताओं में स्पष्ट बढ़ोतरी हुई हैं। संचार की भूमिका को संस्कृति का एक प्रमुख वाहक के रूप में देखा जा सकता है।

'अंतरराष्ट्रीय आयाम' अध्याय में ज़्यादातर सवालों के अंतरराष्ट्रीय आयामों के विमर्श हैं, बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की प्रमुख घटना लगभग अस्सी देशों का स्वतंत्रता प्राप्त करना था, जिसके कारण करीब दो अरब लोग उपनिवेशवादी वर्चस्व से आज़ाद हुए। इसके बावजूद वर्तमान विश्व की दशाएं-राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैन्य के साथ ही सामाजिक तथा सांस्कृतिक- कुछ देशों की स्थिति और प्रभाव के बढ़ने और बड़ी संख्या में देशों की निर्भरता की ओर रुझान व्यक्त कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक आजादी सीमित है, और यहां तक कि आर्थिक निर्भरता द्वारा खोखली कर दी गई है, और खासतौर से विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों की प्रकृति तथा श्रम के अंतरराष्ट्रीय विभाजन के चलते ऐसा हुआ है। ये भी लगातार साफ होता जा रहा है कि बौद्धिक तथा सांस्कृतिक निर्भरता के प्रभाव भी उतने ही गंभीर है जितने की राजनीतिक अधीनता या आर्थिक निर्भरता के। संचार के साधनों द्वारा इसे संरक्षण दिए बिना कोई

भी वास्तविक, प्रभावशाली आजादी नहीं हो सकती है। ये दलील दी जाती है कि जिस देश का मास मीडिया विदेशी वर्चस्व के तहत है, वे राष्ट्र होने का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय संचार की विशेषताओं में असमानता, विषमता और असंतुलन के कई अंतर्निहित कारण भी हैं, खासतौर से औद्योगीकृत और विकासशील देशों के बीच। यथा-हथियारों की दौड़, अकाल, गरीबी, निरक्षरता, नस्लवाद, बेरोजगारी, आर्थिक अन्याय, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण का विनाश, महिलाओं के प्रति भेदभाव मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा हैं ये समस्याएं जिनका समाधान देशों के बीच सलाह और सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। मास मीडिया को इन समस्याओं और दूसरी समस्याओं के प्रति अंतरराष्ट्रीय जनमत को सचेत करने में, उनके समाधान के लिए इच्छाशक्ति तैयार करने और अगर जरूरी हुआ तो समुचित समाधान के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आम लोगों को सुसज्जित करना में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। संचार में जगजाहिर असंतुलन इस राय का समर्थन करता है कि "मुक्त प्रवाह" कुछ और नहीं बल्कि "एक तरफा" प्रवाह है, और ये जिस सिद्धान्त पर आधारित था उसे फिर से दोहराना चाहिए ताकि "मुक्त और संतुलित प्रवाह" की गारंटी दी जा सके। औद्योगिकृत और विकासशील देशों के बीच समाचारों और सूचनाओं के प्रवाह में असंतुलन समकालीन विश्व में बुनियादी राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बहस की तरह अंतरराष्ट्रीय बैठकों का प्रमुख मुद्दा था। मुक्त प्रवाह और एकतरफा प्रवाह, संतुलन और असंतुलन की अवधारणा बहस का मुद्दा और वास्तव में अंतरराष्ट्रीय विवाद बन गई हैं। ऐसे में, 1970 के करीब पहली बार वह अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई, जिस पर की संचार का अंतरराष्ट्रीय बहस केंद्रित था। इस प्रकार संचार और सूचना के क्षेत्र में "पुरानी व्यवस्था" से अलग एक "नई व्यवस्था"

की मांग साकार हुई। नई व्यवस्था आज इस धारणा की अनिवार्य उपज है कि सूचना और संचार सभी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अनिवार्य कारक हैं और खासतौर से अधिकारों की समानता, देशों तथा लोगों की आजादी और निर्बाध विकास के सिद्धान्त पर आधारित नई व्यवस्था की स्थापना के लिए। इस तरह संचार का रूपांतरण नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बुनियादी अवधारणा से संबंधित है। कुछ मामलों में, विकास और संचार समान सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं या उन पर आधारित होते हैं। इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस तरह के दावे और प्रतिदावे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूनेस्को द्वारा अपनाए गए कई निर्णयों और संकल्पों की बुनियाद तैयार करते हैं। खासतौर से वह निर्णय जिसने अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई।

भाग दो में आज के संचार के बारे में बताया गया है। संचार का अर्थ, बुनियादी ढ़ांचे, बदलते स्वरूप में एकीकरण, एकाग्रता, प्रतिभागियों द्वारा अंतःक्रिया और विषमता का वर्णन इस भाग में किया गया है। संचार के अर्थ अध्याय के अंतगर्त वर्णन है कि विविध प्रकार के संचार का अर्थ मानव के संदेश संप्रेषण की क्षमता से है जो भाव-भंगिमाओं, चित्रों, संकेतों, मुद्राओं, संख्याओं, शारीरिक भाषा और भाषा, लेखन, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों द्वारा संप्रेषित की जाने से है। लेकिन जब भाषा का विकास हुआ तो उसने मनुष्य की संचार की योग्यता को बढ़ा दिया। जिससे जटिल सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों तक आसानी से संचारित होती थी। संचार के लिए संकेतों और शब्दों का उतना ही महत्व है जितना की भाषा का। संसार भर में लगभग 3500 से ज्यादा भाषाओं को चिह्नित किया गया था और जिनमें लगभग 500 भाषाएं लिखित भाषा न होकर केवल बोल-चाल की भाषा थीं।

मानव लाखों साल पूर्व के समाज में शुरुआत में अपने शारीरिक भाव-भंगिमाओं के द्वारा अपने व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता था। फिर मौखिक भाषा का विकास किया। उसके बाद मनुष्य पढ़ने और लिखने लगा। समकालीन विकास में समुदायों ने अपने अंतर वैयक्तिक संचार का विकास करते हुए पोस्ट, टेलीफोन, स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों, कम्प्यूटर और इंटरनेट जैसी महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यमों का विकास कर अपनी अभिव्यक्ति को गति प्रदान की। संचार विस्तार के बुनियादी ढ़ांचे वाले अध्याय विभिन्न प्रकार के संदेशों के संग्रहण, संचरण और प्रसार के आधारभूत सुविधाओं के संरचना और विविधता से संबन्धित हैं। पुस्तकालयों, दस्तावेज लिखने वाले केन्दों का उपयोग सूचनाओं और दस्तावेज को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे डाटा संग्रहण का कार्य उद्योग का रूप ले लिया। समाचार संग्रहण, संपादन और प्रसारण में भी तकनीकी विकास हुआ। 20 वर्षों में न केवल जन मीडिया बल्कि सभी संस्थाएं चाहे वह शैक्षिक, व्यापारिक, तकनीकी या सूचना से सम्बन्धी हो डाटा बैंक से जुड़ गए। डाटा संग्रहण ने संचार का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। विकसित देशों में टेलीफोन का प्रयोग होने लगा। टेलीफोन द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क हो रहा था। जिला और सामुदायिक स्तर के फोन का इस्तेमाल विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाने लगा। लेकिन फिर भी बहुत से देश टेलीफोन सेवा पर व्यय करने असमर्थ थे। टेलीफोन सेटेलाइट नेटवर्क से आमने-सामने का संचार सफल बन गया। इलेक्ट्रानिक संचार के विकास ने ट्रांन्समीशन चैनलों को बढ़ा दिया। बहुत से देशों में उच्च फ्रिक्वेन्सी प्रसारण का विकास हुआ। 1960 में केवल 16 देशों में 30 किलोवाट तक प्रसारण करने की क्षमता थी। सिनेमा ऐसी तकनीकी थी जो मनोरंजन के साथ-साथ सूचना और विभिन्न प्रकार के संदेशों का प्रसारण करती थी। इन

सभी परिष्कृत विकास ने संचार के सभी क्षेत्रों और प्रभाव में वृद्धि करने के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। लेकिन संचार के ये सभी बदलाव तकनीकी थे। ये तकनीकी बदलाव राजनीतिक और आर्थिक भी थे।

'बदलते स्वरूप में एकीकरण' अध्याय में वर्णन किया गया है कि अपने विकास के आरम्भिक पड़ावों पर विभिन्न संचार माध्यम एक-दूसरे से परिचालन में अधिक या कम रूप से पृथक थे। प्रत्येक माध्यम के पास अपने विशेष दर्शक के लिए सूचना, मनोरंजन और संस्कृति के जरूरतों का पूरा करने के लिए तरीके थे। तकनीकी विकास करके संचार माध्यम तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन बुनियादी सवाल आधुनिक परम्परा और परम्परागत मीडिया के बीच सम्बन्धों को लेकर था। संचार शक्ति का प्रयोग जब सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रिया कलापों में प्रयोग किया जाता है तो यह बात ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संचार माध्यमों का एक-दूसरे से किस प्रकार सम्बन्ध होना चाहिए। पारम्परिक संचार माध्यमों का प्रयोग करके भी आधुनिक मीडिया उत्पादों को बढ़ाना चाहिए। संचार पूरे सामाजिक प्रणाली का हिस्सा होता है। वह समाज को बाटने के लिए संचारित नहीं हो सकता। इसलिए वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास एवं नए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संचार के एकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। केन्द्रीकरण के अध्याय के अंतर्गत संचार के विकास में संचार के बहुत से बदलावों द्वारा प्रभावित होने पर विचार किया गया है। प्रभावित करने वाले कारक थे- अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यम, संचार के क्षेत्र का विस्तार, मीडिया की विविधता तथा इसके अर्थों की विभिन्नता। संचार का वैश्विक परिदृश्य विशेषरूप से स्वामित्व, वित्त प्रबन्ध और प्रबन्ध के तरीके से एकाधिकार के धारण को दिखा रहा था। इसलिए आयोग द्वारा मीडिया

स्वतंत्रता को सुधारने तथा सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान केन्द्रीत करने का प्रस्ताव दिया गया। प्रतिभागियों द्वारा अंतःक्रिया के अध्याय में बताया गया है कि संचार प्रक्रिया में व्यक्तिगत समूह, निजी तथा सार्वजनिक प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय निगम और संस्था शामिल थे। उनकी भूमिका की जांच करना आवश्यक था। संचार की बहुत सी समस्याओं पर मिलकर काम करना चाहिए था। विषमता वाले अध्याय में वर्णन है कि वैश्विक स्तर पर संचार की सुविधाओं का विकास लगातार हो रहा था लेकिन संचार की विभिन्नता और विषमता उनके बुनियादी चरित्र में थी। संचार की ये विषमता भाषा विज्ञान, नस्ली बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच गरीब और अमीर जनसंख्या के बीच तथा देशों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच मिलती थी। इस समस्या को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निगमों में बदलाव करके लाया जा सकता था। विकासशील देशों को भी कोशिश करनी चाहिए कि संचार का ये जो अंतराल है उसे मात्रात्मक रूप से न माप कर के संचार के क्षमताओं और नीतियों में आत्मनिर्भर होकर काम करें।

भाग तीन सार्वजनिक सरोकार के समस्याएं और मुद्दों से सम्बन्धित है। लगभग सभी देशों के संचार में सुधार और विस्तारण हो रहा था फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना के प्रसारण और इसके विषयवस्तु में संतुलन और विविधता की कमी बनी हुई थी जो कि संचार के समस्याओं पर हो रहे बहस के केन्द्र में था। इस भाग में संचार प्रभाव में दोष, संचार की अंतर्वस्तु में प्रधानता, संचार का लोकतांत्रिकरण, संसार की कल्पना, जनता और जनमत के अंतर्गत संचार की समस्या पर विमर्श किया गया है। संचार प्रभाव में दोष के अध्याय में बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनमत के बुनियादी सिद्धान्त , सूचना की स्वतंत्रता, सूचना के संतुलित प्रभाव

और मीडिया के स्वतंत्र पहुंच द्वारा समाज का स्वाभाविक विकास होता है। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार सभी के पास अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संचार का स्वतंत्र प्रभाव और सूचना की आजादी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य मुद्दा बना है। संचार की स्वतंत्रता सूचना का संग्रहण, संपादन और सभी मीडिया, सामाजिक समूहों, व्यक्तिगत संस्थाओं को स्वतंत्रता पूर्वक प्रसारण करना है। लेकिन स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये बाधाएं सेंसरशिप, पत्रकारों और किताबों को प्रतिबन्धित करने, राजनीतिक गतिविधियों द्वारा एकाधिकार स्थापित करने और कानून के दमनकारी होने से है। यू.एस. तथा स्वीडेन देश की सुरक्षा और बचाव के नाम पर सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को रोक रहे थे। बहुत से देशों में राष्ट्रीय आपातकाल ने नाम पर स्वतंत्र प्रवाह को सेंसरशिप के नियमों के तहत रोका गया था जिससे शक्तिशाली देश विकासशील देशों पर विषम प्रभाव डालने लगे। संचार के समानांतर प्रवाह की मांग होने लगी। संचार का समानांतर प्रवाह एक आदर्श स्थिति है क्योंकि प्रगतिशील समाज में समानांतर प्रवाह बड़ी संख्या में सूचना के उत्पाद को समानता के साथ प्रसारित करता है। इसलिए संचार की समानांतर अवधारणा जनता के लिए संचार की पहुंच और भागीदारी को प्रोत्साहित करने लगी। जनसंचार का प्रेस, पीरियोडिकल्स, किताब, फिल्म, पत्र, रिकार्डिंग, रेडियो, टीवी, डाटा आपूर्ति, टेलीकम्यूनिकेशन आदि के रूप में इतना विस्तार हुआ कि औद्यौगिक क्षेत्रों को लाभ कमाने का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इस प्रकार जनसंचार के सामाजिक सेवा का जो पहलू है समाप्त हो गया है। संचार की अंतर्वस्तु में प्रधानता अध्याय में कैसे सूचना, समाचार और संचार एक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाते हैं और कैसे किसी व्यक्ति के नज़रिये और विचारों को प्रभावित करते हैं इससे सम्बन्धित है। इसमें बताया गया है कि संचार के

विषयवस्तु की विकृति पर ध्यान देना होगा। समाचार मूल्य क्या होंगे और किस प्रकार इसकी सत्यता और विकृति को परखा जाये संचार के नीति-निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। किन उद्देश्यों को लेकर समाचार और इसके मूल्यों को विकृत किया जा रहा है उसका विश्लेषण करना चाहिए। बहुत से देशों में संचारक सूचना स्रोतों की कमी या स्वतंत्रता से सूचना संग्रहीत करने में असमर्थ हैं। ये अवरोध सरकारी नियंत्रण, नौकरशाही या सरकारी सेंसरशिप के अन्य रूपों से हो रहा है। संचार के लिए विकास जरूरी है लेकिन यह संस्कृति के गुणों और मूल्यों के लिए खतरा बनता जा रहा है। मीडिया लोगों को उनके अपनी संस्कृति से अलगाव पैदा कर रही है। सूचना की अस्पष्टता या विकृति समुदायों को उनकी संस्कृति से अलग कर अजनबी बना दे रही है। संचार ने भाषाओं के अस्तित्व के साथ छेड़-छाड़ कर दूसरी भाषा के संचार की विषयवस्तु को प्रभावित कर रहा है। इसलिए अपनी समुदाय-संस्कृति को बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए विभिन्न देशों के सरकारों ने राष्ट्रीय नीति की स्थापना की ताकि उनके देशों की संस्कृति बच सके। आयोग ने कहा कि सरकार और समुदाय को लेखकों और कलाकारों को संस्कृति की रचनात्मकता तथा सम्प्रेषणीयता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही सांस्कृतिक पहचान का सबसे सच्चा सुरक्षा कवच है। विकसित और विकासशील देशों को साथ मिलकर संचार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि सभी समस्याएं संचार के प्रवाह में सूचना, संदेश और सांस्कृतिक उत्पादों के आदान-प्रदान से सम्बन्धित हैं। संचार के लोकतांत्रिकरण अध्याय में संचार के लोकतांत्रिक क्रियान्वयन में क्या-क्या बाधाएं हैं उनके बारे में वर्णन है। इन बाधाओं को खत्म कैसे किया जा सकता है इसका भी वर्णन किया गया है। संचार समाज को प्रभावित करता है। संसार के सभी राष्ट्र राजनीतिक प्रणाली के विविधता

के अंतर्गत रहते हैं जिनमें से कुछ पूर्णरूप से अलोकतांत्रिक हैं। धन के असमान वितरण तथा अफ़सरशाही वर्ग के कारण भी लोकतांत्रिकरण में बाधा पहुंचती है। विभिन्न प्रकार के सूचना, अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करके संचार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समस्या पैदा किया जा रहा है। अन्य प्रकार का अवरोधक प्रेषक और प्रापक के बीच में संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को समझने में ज्ञान की कमी के कारण हो रही है। संचार की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को तोड़ने के शुरूआत के क्रम में जनसंचार माध्यमों का विकेन्द्रीकरण स्थानीय, क्षेत्रीय तथा सामुदायिक स्तर पर किया जाना चाहिये। संचार का लोकतांत्रिकरण केवल पेशेवरों की इच्छाशक्ति या किसी समूह द्वारा वैकल्पिक माध्यम की स्थापना द्वारा नहीं हो सकता। संचार का अधिकार सभी का मौलिक अधिकार है जो संसार को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की ओर ले जा सकता है। दो तरफा संचार, स्वतंत्र सूचना के आदान-प्रदान तथा विभिन्न सूचना स्रोतों के विस्तार के बिना संचार का अधिकार सफल नहीं हो सकता है। संसार की कल्पना अध्याय में मानव जाति द्वारा विभिन्न समस्याओं को संचार द्वारा हल करने की कोशिश पर विमर्श किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक देश युद्ध के खतरों के प्रति सजग हैं और संसार को भी युद्ध से खतरा हैं। मीडिया का प्राथमिक कार्य है जनता को महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना। युद्ध का ख़तरा असहिष्णुता, अंध देशभक्ति द्वारा अकाल, बाढ़, महामारी तथा अन्य त्रासदियों की रिपोर्ट जिनसे विकासशील देश प्रभावित होते हैं और सरकार और निजी संस्थाएं सहायता पहुँचाती हैं इस पर मीडिया को इससे आगे जाकर इनके कारणों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करना चाहिए। यह उत्तर-दक्षिण के बीच असमानता के भेद की मात्र बात नहीं है। संचार विषमता जो उत्तर-दक्षिण के बीच है, प्रदर्शित करना चाहिए। ये विषमता पूरे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में

है। संचार को इसमें परिवर्तन के लिए खड़े रहना चाहिए। उत्तर-दक्षिण के समान आद्यौगिक देशों के बीच में भी कुछ झगड़े थे उदाहरण स्वरूप 1970 का शीत युद्ध जो कि यू.एस.ए. और यू.एस.एस.आर. के बीच हुआ था। अब पूरब की मीडिया पश्चिम के बारे में और पश्चिम की पूरब के बारे में समाचार देने लगी है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या सूचना के विनियम के गुणात्मक और परिणात्मक असंतुलन की है। आयोग ने मीडिया का प्राथमिक कार्य शिक्षित करना और मानवाधिकार की जानकारी देना बताई है। संचार व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और स्वतंत्र विकास को अपनाए। स्त्री को समानता का अधिकार देना और सभी क्षेत्रों के सामाजिक जीवन में स्त्री प्रतिभागी हो, एक देश के सम्पूर्ण विकास, संसार के कल्याण और शांति के लिए जरूरी है। औरतों को भी शिक्षा, सामाजिक भागीदारी और संचार में समान रूप से भाग लेने के मौके की मांग होनी चाहिए है। संचार की जिम्मेदारी है कि वह स्त्रियों को समान अवसर दें। अध्याय पांच जनता और जनमत से सम्बन्धित है। इसमें जनता की अवधारणा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जनमत तथा जनता और जनमत के अवधारणा के परे भी विमर्श से सम्बन्धित है। विभिन्न प्रकार के विचार और सामाजिक विभिन्नता वाले इस संसार में जनता की बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाओं में से केवल एक यही सामान्य बिन्दु मिलता है कि जनता व्यक्तियों के अव्यवस्थित समूह को कहते हैं। संचार के कार्य में मीडिया का प्रभाव और जनता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी भी प्रकार से राष्ट्रों के अंदर और राष्ट्रों के बीच संचार के विकास में जनता की भूमिका को महत्वहीन नहीं समझा जा सकता। जनमत सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के आधार पर बनता है। जनता की राय निकटतम रूप से आदमी के सामाजिक प्रकृति से जुड़ा होता है। 19वी

TH22988

शताब्दी में लोग जनमत के बारे में कम जागरूक थे। लेकिन धीरे-धीरे जनता की राय बढ़ने लगी। जनता ने जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उदाहरण के लिए उपनिवेशों का विरोध, फाँसीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोध में जनमत ही था। स्पेन, ग्रीस और पुर्तगाल के लोकतांत्रिकरण में जनमत की भूमिका थी। जनसंचार का जनता के विचार से गहरा सम्बन्ध है। संचार की प्रक्रिया और विषयवस्तु जनता और जनमत में यथार्थ विश्लेषण के विभिन्न प्रचलन के बुनियाद पर आधारित है। लेकिन मीडिया के द्वारा प्रस्तुत जनमत सूचना के स्रोत की जगह राजनीतिक स्वार्थ को सीधा करने वाला साधन बन गया है। जब सरकार, आर्थिक तथा अन्य स्थापित प्राधिकरण जनता के सरोकार से जुड़ी सूचना को प्रतिबन्धित या विकृत करता है तो पत्रकारिता एक जवाबी शक्ति बन सकती है। दुनिया भर के जनता की राय का निर्माण एक ही तरह की समस्या के ऊपर होता है जैसे विकास की समस्या, भूख और कुपोषण, सामाजिक असमानता, ऊर्जा संकट, युवाओं की समस्या आदि। दुनिया भर की जनता के राय द्वारा ही शांति व्यवस्था बनाए रखने या परमाणु युद्ध की समस्या से निपटने का काम किया जाता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मीडिया की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की राय को सही ढंग से प्रस्तुत करे। यह हमेशा से होता आया है कि मीडिया विचार बनाता है तथा जनता आँख मूंद कर विचारों को ले लेती है। जबकि लोकतांत्रिक समाज का उद्देश्य होना चाहिए नागरिकों का जनता के कार्यों के लिए जो निर्णय की प्रक्रिया अपनायी जाती है उसमें मीडिया किसी तरह का भ्रम न फैलाए क्योंकि जनमत केवल मत नहीं होता बल्कि जनता के कार्यों और सामाजिक क्रियाओं के अनुभव की जानकारी द्वारा एक जागरूकता होती है।

चौथे भाग में संचार के संस्थागत और पेशेवर ढांचे के अंतर्गत संचार नीतियों, संसाधन स्रोतों, शोध योगदान, पेशेवर संचारक, पत्रकारों का अधिकार और उत्तरदायित्व और पेशेवर आचरण के मापदंडों के अध्याय के अंतर्गत विवेचना की गई है। संस्थागत ढ़ांचा संचार नीतियों, सूचना और संचार के विकास के योजना को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की व्यवस्था करता है। संचार नीति के अध्याय में संचार नीतियों को लेकर लम्बे समय से हुए बहस का वर्णन है। आयोग ने बताया है कि एक से अधिक देशों ने राष्ट्रीय नीतियां बनाई हैं या कहीं से लिया है तो उन्हें एक ही उद्देश्य के लिए संचार की नीतियों को बनाना चाहिए। संचार नीति वैश्विक स्तर पर सबके विकास की होनी चाहिए। संस्था के आधारभूत संरचना में संचार परिवर्तन न केवल क्षैतिज बल्कि समतल संचार के स्तर पर होना चाहिए। लेकिन विकसित देश संचार नीति और आधारभूत संरचना का प्रयोग अपने हित के लिए कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना की स्वतंत्रता सभी का संविधान में प्रयोग हो क्योंकि संचार की स्वतंत्रता रैली, आंदोलन, प्रदर्शन के साथ-साथ पत्राचार और पर्यटन आदि को भी स्वतंत्रता देती है। संचार के संस्थागत ढांचे में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। संचार की आधारभूत संरचना में मीडिया और तकनीकी का प्रभुत्व होता है जो कि संचार संगठनों को बनाता है। संसाधन स्रोत के अध्याय में वर्णन है कि मीडिया के संसाधन स्रोतों को परिभाषित करना कठिन है जो संचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। संचार नीति और योजना को प्रभावित करने वाले समस्याओं में से एक है आधारभूत संरचनाएं। कुछ देशों विशेषकर विकासशील देशों में मास मीडिया के विषय से सम्बन्धित पर्याप्त आकड़ों की कमी है। इन कमियों के कारण नीति बनाना अत्यधिक कठिन और महंगा कार्य है। वैश्विक संचार आवश्यकताओं

को सूची बद्ध करके और प्राथमिकताओं की पहचान करके राष्ट्रीय संचार नीति बनानी चाहिए। कुछ विकासशील देशों में भी इस तरह के काम हुए हैं। सभी देशों को अपने संचार की आधारभूत संचरना पर ध्यान देना चाहिए जिससे कोई देश उनकी अनदेखी न कर सके। सभी देशों के लिए आविष्कार, उत्पाद तथा नई प्रौद्योगिकी को संचार के लिए प्रयोग करना आवश्यक है। विकासशील देशों को अनुपयुक्त संचार मॉडल की आलोचना करनी चाहिए और तकनीकी का प्रयोग अपने राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। सभी देशों को संचार के विकास के लिए पर्याप्त कोष देना चाहिए। कोई भी देश संचार के विकास के कोष का अकेला मालिक नहीं हो सकता। संचार परियोजना के प्रकृति और क्षेत्र को देखते हुए खर्च का एक दम सही डाटा नहीं दिया जा सकता है लेकिन कुछ उदाहरण हैं जैसे- नोरडिक-यूनेस्को प्रोजेक्ट अफ्रीका में स्थानीय प्रसारण विकास के लिए था जिसका खर्च 17 लाख, 37 हजार, 9 सौ डालर था। अंतरराष्ट्रीय योगदान और विदेशी सहयोग सभी के संचार विकास के लिए प्रभावशाली होने चाहिए। शोध के योगदान के अध्याय में बारे में वर्णन किया गया है कि संचार शोध शुरुआत में जनसंचार द्वारा आर्थिक फायदा प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गए थे। एक बड़ी संख्या में संचार के सैद्धान्तिक और व्यवहारिक प्रारूप का शोध विज्ञापनों, चुनावी अभियान, मतदान, जनमत, जनसंपर्क के क्रियाकलापों और अखबार के प्रसार को बढ़ा कर आर्थिक फायदे की कोशिश के लिए किया जा रहा था। 1960 में पहली बार मीडिया प्रभाव के वास्तविकता का अध्ययन किया गया और नई संचार प्रणाली की प्राथमिक बनावट को ऐसा बनाया गया जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया और पहले ही दशक में महसूस किया गया कि विकसित देशों के संचार मॉडल जो शोध के लिए हैं उन्हें सुधारा जाए क्योंकि वह विकासशील देशों की सच्चाई नहीं बताते। धीरे -धीरे

संचार समस्याओं के लिए शोध का तरीका बदल गया। हर देश अपनी संचार समस्याओं के लिए शोध करने लगे। इन शोधों में प्रमुख कमी थी कि बड़े पैमाने पर संचार शोध केवल अद्यौगिक देशों की छोटी संख्या पर शुरू किया गया था। असंतुलन न केवल देशों बल्कि क्षेत्रों के बीच था जिसे शोध द्वारा छिपाया गया था। आयोग ने बताया है कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि सभी जगहों में एक ही समय में शोध द्वारा समस्याओं को निपटाया जा नहीं सकता। वर्तमान और भविष्य के शोध को हमारे समय की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और हल करना चाहिए। संचार शोध का लक्ष्य संचार को सामाजिक प्रक्रिया मान कर करना चाहिए जिसमें मीडिया संस्थाओं का अध्ययन पृथक करके नहीं बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बन्ध कैसे है, यह देखकर। पेशेवर संचारक अध्याय में वर्णन है कि संचार को परिभाषित करना कठिन है। इसको परिभाषित करने में कुछ न कुछ छूट जाता है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचार पेशेवरों को परिभाषित करने की समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती। अन्य क्षेत्रों की तरह संचार में व्यावसायिकता का विकास हुआ है। संचार में व्यावसायिकता; समाचार के उत्पाद और प्रसार के लिए सभी समाजों द्वारा संवेदनशील होने, राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सूचना के होने, तकनीकी का तेजी से विकास होने और विशेषज्ञता की मांग की वृद्धि होने पर हुआ है। लेकिन लोगों और राष्ट्रों के बीच संचार के प्रसार में व्यावसायिकता को संचार के लोकतांत्रिक तरीकों या उपभोक्ताओं के भाग लेने को रोकना नहीं चाहिए। किसी भी प्रणाली की योग्यता व्यापकरूप से जो उसको चला रहा है उसकी क्षमताओं से संचालित होती है। विस्तृत परिदृश्य में संचार के प्रशिक्षण के विभिन्न विशेषज्ञों के प्रकार को शामिल करने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों की कमी है

जिससे की संचार की नीति और योजना बनाने वालों को मापन संसाधन प्रशिक्षण के बारे में ध्यान देना चाहिए। संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिदृश्य और संचार विकास को ध्यान में रखकर देना चाहिए। पत्रकारों के अधिकार और उत्तरदायित्वों अध्याय में बताया गया है कि संचार के क्षेत्र में बहुत से लोग कार्य करते हैं। लेकिन पत्रकार उसमें महत्वपूर्ण बिन्दु होता है इसलिए पत्रकार को विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उनके लिए पत्रकारिता बस एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य ही नहीं है बल्कि विचारों और मतों को बनाने की शक्ति भी उनके पास ही होती है। पत्रकारों के लिए पत्रकारिता व्यवसाय और मिशन दोनों है। पत्रकारों के ऊपर समाज में सही सूचना पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। पत्रकार को बिना किसी प्रभाव के जानकारी प्रसारित करना चाहिए क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनता को सच बताने की शक्ति होती है। पत्रकारों के कार्य और उनकी सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता रहती है। पत्रकार घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी होता है इसलिए उसे लक्षित किया जाता है। बहुत से संघर्षों में उसे शारीरिक कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ती है इसलिए पत्रकारों को विशेष सुविधा, सुरक्षा तथा काम की गारंटी देनी चाहिए। बहुत से देशों में पत्रकारिता व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं का विशेष संवैधानिक नियम बनाए गए हैं तथा पत्रकार के व्यवसाय का क्या-क्या अधिकार है उस पर भी विचार किया गया है। पत्रकारों के अधिकार के अंतर्गत उन्हें सूचना को स्वतंत्र हो कर प्रसारित करने की आज़ादी होनी चाहिए। पेशेवर मापदण्ड अध्याय वर्णन करता है कि पेशेवर मापदण्ड की शुरूआत 1920 से अब तक बनी हुई है। पेशेवर नैतिक मापदण्ड के कानून 60 देशों में थे। कुछ देशों में प्रेस, प्रसारण और सिनेमा के भिन्न-भिन्न नियम उन्हें संचालित करते हैं। संचार के व्यावसायिक नैतिक मापदण्ड में मूलभूत बदलाव द्वितीय विश्वयुद्ध

के समय हुआ। विभिन्न सरकारी और असरकारी संस्थाओं के विभिन्न प्रयासों के बाद संचार के स्थानीय या राष्ट्रीय नैतिकता के नियम बने। 1926 में वाशिंगटन के अमेरिकन प्रेस कांन्फ्रेंस में पुराने पत्रकारों के आचार संहिता से कानून लिए गए। यूनाइटेड नेशन्स में 1950 और 1952 में सूचना की स्वतंत्रता और सूचना सूची के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की संहिता तैयार किया। विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संस्थान पेशेवर नैतिक कानून में लगे हैं। 50 प्रेस समिति, मीडिया समिति और अन्य संस्थाएं हैं जो कि पूरे संसार में काम करती हैं, उनमें से अधिकतर प्रेस से सम्बन्धित हैं और बहुत ही कम प्रसारण से। पहला प्रेस कांउसिल 1916 में स्वीडेन में स्थापित था। प्रेस और मीडिया की स्थापना विभिन्न तरीके से हुई। समिति को बनाने का निर्णय पेशेवर लोगों ने और मीडिया ने स्वयं लिया। बहुत से देशों में कानून द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देने का और सुधार करने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अधिकतर देशों में उत्तर देने का अधिकर सिर्फ प्रेस के लिए है। इस अस्थिर संसार में जहां गलत समाचार अशांत सामाजिक संघर्षों को पैदा कर रहा है या बढ़ा रहा है, अन्य देशों के विश्वास को बरबाद कर रहा है तब संचार के प्रयोग के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए व्यावसायिक आचरण के लिए कानून की आवश्यकता है।

मैकब्राइड रिपोर्ट के भाग पांच में भविष्य के संचार को कैसा होना चाहिए इस पर आयोग की सलाह है। आयोग ने इस रिपोर्ट के अंत में अपना निष्कर्ष तथा सिफारिशें या सलाह संचार के क्षेत्र के लिए बताए हैं। इस रिपोर्ट में जो सर्वेक्षण किये गए हैं उससे संचार के स्रोतों और संभावनाओं को प्रभावशाली ढंग से विस्तार मिला है। संचार, शक्ति का साधन, एक क्रांतिकारी हथियार और एक व्यावसायिक उत्पादन या शिक्षा का माध्यम हो सकता है।

इसलिए आयोग ने बहुत से सुझाव संचार द्वारा भविष्य के विकास के लिए दिये हैं। आयोग ने संचार की इन समस्याओं के निवारण को विभिन्न देशों के विभिन्न परम्पराओं, सामाजिक जीवन की पद्धति, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन, जरूरतों और संभावनाओं के साथ सामान रूप में प्रदर्शित किया है। संचार के क्षेत्रों में विस्तृत रूपरेखा, सामान्य लक्ष्य और मूल्य की स्थापना संचार के परस्पर निर्भरता में स्थापित की जा सकती है, इस निष्कर्ष को रिपोर्ट में दिया है। मानव जाति को हथियारों की दौड़ और अस्वीकार वैश्विक असमानता की स्थिति से उत्पन्न तनाव से भविष्य और उत्तरजीविता के लिए खतरा है। समकालीन परिस्थितियां अत्यधिक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था तथा मौलिक अधिकारों के प्राप्ति की मांग करती हैं। इन लक्ष्यों को समझा और उदारता के द्वारा पूरा किया जा सकता है एवं स्वतंत्र, खुले एवं संतुलित संचार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। संचार की समीक्षा में स्पष्ट दिखाई देती है कि सबसे अधिक महत्व संचार, इसकी संरचना एवं सूचना प्रभाव में असंतुलन और असमानता को दिया जाना चाहिए। विकासशील देशों को संचार के क्षेत्रों में अपनी निर्भरता कम करने और एक नये एवं न्याय संगत व्यवस्था की मांग करनी चाहिए। संचार का लोकतांत्रिकरण, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए जिससे कि संचार समाज में लोकतांत्रिकरण की भूमिका निभा सके। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय संचार नीति को जोड़ना चाहिए। सभी देशों को अपने संचार पद्धति का देश की परिस्थिति, जरूरत और परम्परा के अनुसार विकास करना चाहिए ताकि उनकी अखंडता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मजबूत बने। वैश्विक स्तर पर नये सूचना और संचार व्यवस्था के ढ़ांचे का विकास करना जरूरी है। संचार और सूचना प्रणाली के असंतुलन के कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक और तकनीकी असमानता बढ़ती है। इस शोध में बहुत सी सिफारिशें की गयी हैं। संचार समूह और व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकार होना चाहिए। विकसित और विकासशील देशों के बीच संचार के अंतराल को खत्म करना चाहिए। संचार के अंतर्वैयक्तिक और पारम्परिक स्वरूप मनुष्य और उनके समाजों को उनके अधिकार, विभिन्नता में एकता को बनाए रखने और विश्व अन्योन्याश्रिता में राष्ट्रीय विकास के विस्तृत परिदृश्य में व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। संचार नीतियों को संचार के उपयुक्त चयन करने के लिए एक मार्गदर्शक की पेशकश करनी चाहिए। विकासशील देशों को प्रिन्ट मीडिया, प्रसारण और टेलीकम्यूनिकेशन के साथ प्रशिक्षण और उत्पादन सुविधाओं से सम्बन्धित अपने संचार प्रणाली के अनिवार्य तत्वों को स्थापित और विकसित करना चाहिए। मजबूत समाचार एजेन्सियां प्रत्येक देश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचारों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय मुद्रित माध्यम को किताबों, समाचार पत्रों और पिरियोडिकल के लिए प्रसारण नेटवर्क की स्थापना द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। रेडियो के विकास को टेलीविजन माध्यम के विकास से ज्यादा महत्व देना चाहिए क्योंकि यह अशिक्षित क्षेत्रों में मजबूत पकड़ और पहुंच रखता है। समुचित शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाएं मीडिया और प्रोडक्शन संस्थाओं के लिए कर्मचारी वर्ग की आपूर्ति जैसे प्रबन्धक, तकनीशियन और रखरखाव के कर्मचारियों को समुचित शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाओं को देने की आवश्यकता है।

इस तरह समुदायों को मनोरंजन और शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराना चाहिए। संचार के शैक्षिक और सूचनात्मक प्रयोग को मनोरंजन के समान ही महत्व देना चाहिए। सभी विकास की परियोजनाओं में पर्याप्त धन मिलना

चाहिए। समाचार का संतुलित तथा स्वतंत्र प्रसारण होना चाहिए। संचार नीतियों को बढ़ावा देने के लिए गैर तकनीकी भाषा तथा विकास के मुद्दों और लक्ष्यों के लोकप्रिय समझ को बनाने के लिए बोधगम्य प्रतीकों, छवियों और रूपों का प्रयोग होना चाहिए। संचार तकनीकी का प्रयोग विकसित देशों को आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं करना चाहिए। संचार और सांस्कृतिक नीतियों को आश्वस्त करना चाहिए कि रचनात्मक कलाकारों और विभिन्न जमीन से जुड़े समूह मीडिया के द्वारा अपने आवाज को सुन सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों द्वारा फिल्म, टेलीविजन और रेडियो की सहायता से परिवर्तनात्मक प्रयोग का अध्ययन करना चाहिए। निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा मास मीडिया के व्यवसायिकरण के सामाजिक प्रयोग के प्रभाव पर नीति निर्माता और निर्णय लेने वालों को ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के अंदर तकनीकी सूचना प्रभावों के सामाजिक प्रभावों पर ध्यान देना होगा।

हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच तकनीकी सूचनाओं के प्रभाव विकास का एक प्रमुख स्रोत हैं। विकसित देशों को तकनीकी सूचना के प्रसार पर सभी देशों का समान अधिकार समझना चाहिए। सूचना की स्वतंत्रता बिना किसी जवाबदेही के विकृति लाता है और हानि पहुँचाता है। उत्तरदायित्वों के साथ-साथ सूचना की अवधारण, पेशेवर नैतिकता, समान स्तर पर सूचना का प्रसार तथा अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। पत्रकारों को समकालीन संसार के मांग के अनुसार समाज को बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। पत्रकारों को अपने स्तर और योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हर जगह उसे एक विशुद्ध पेशे के रूप में पहचाना जाए। इन सब के अलावा संचार के लिए पेशेवर

नैतिकता, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग को सुधारने, पत्रकारों की सुरक्षा, संचार का लोकतांत्रिकरण, संचार से सम्बन्धित बाधाओं को खत्म करना, एकीकरण और प्रतिभागी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का बढ़ावा देने आदि के लिए सुझाव इस रिपोर्ट में दिये गए हैं। रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया है कि "हम जिस चीज में विश्वास करते हैं उससे हम क्या सीखते हैं और इन सब के ऊपर यह दृढ़ चेतना है कि हम क्या संचारित करने की इच्छा रखते हैं।"

आज आधुनिक युग में विशेष रूप से मीडिया प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और उपग्रह संचार ने एक बड़ा तथा वैश्विक बाजार दे दिया है जिसमें विश्व की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचार भी प्रभावित हो रहे हैं। विकसित शक्तियां वैश्विक गरीबी को बढ़ाने तथा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास संचार माध्यमों द्वारा कर रही हैं। 1970 में संचार को लेकर हो रही अंतरराष्ट्रीय बहसों में भी ऐसे मुद्दे उठाए गए थे। जब मीडिया पर नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथ में होने, पत्रकारीय स्वतंत्रता का हनन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग, औद्योगिक देशों का मीडिया, समाचार पत्रों के उत्पाद तथा प्रसारण तथा आर्थिक एवं सामाजिक एवं क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ने से तीसरी दुनिया ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही मैकब्राइड कमीशन का गठन किया गया। पश्चिम देशों द्वारा इस रिपोर्ट पर भले ही यह आरोप लगाया जाता है कि मैकब्राइड रिपोर्ट पक्षपाती है तथा इसमें निजी मीडिया घरानों को अपने रिपोर्ट के लिए शोध का विषय नहीं बनाया है, लेकिन इस रिपोर्ट में विकसित देशों द्वारा संचार माध्यमों का प्रयोग अपने आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के लिए किये जाने की जाँच पड़ताल की है। संचार और मीडिया के संरचना में सूचना का प्रवाह किस तरह होगा इस पर भी ध्यान

दिया गया है। आज 34 सालों बाद भी इस रिपोर्ट की प्रासंगिकता नई पीढ़ी के लिए उपयोगी है।

अध्याय-दो

मैकब्राइड कमीशन रिपोर्ट "मेनी वॉयसेसे वन वर्ल्ड" का अनुवाद

आमुख

एमडो-मैटर मबो
महानिदेशक, यूनेस्को

संचार सभी सामाजिक समागम के केंद्र में है। जब भी लोग एक-दूसरे के साथ नियमित संबंध स्थापित करते हैं तो उनके बीच निर्मित संचार प्रणाली की प्रकृति, उनके घटित होने के तरीके और उनसे हुए प्रभावों का मूल्यांकन, सामान्यतः समुदायों को समीप लाने या उन्हें एकजुट करने के अवसरों और यदाकदा उत्पन्न होने वाले तनावों को घटाने और विवादों के निपटारे की संभावनाओं से निर्धारित होता है।

आरंभ में स्थायी संचार केवल एक सीमित समुदाय, आस-पास रहने वाले लोगों के समूहों या किसी राजनीतिक इकाई के हिस्से के बीच ही संभव था। हालाँकि आजकल सूचना मीडिया जिस गति से काम करता है और दुनिया भर में विकसित हुए सभी तरह के संबंधों के संजाल के परिणामस्वरूप संचार पूरी दुनिया के लिए अनिवार्य तत्व बन गया है।

इसके चलते ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पहुँचना खासतौर से मुश्किल है, वहाँ कुछ बेहद छोटे समूहों के अलावा कोई भी अलग-थलग नहीं रह सकता है। आज हर देश हर दूसरे देश की दिन-प्रति-दिन की वास्तविकताओं का हिस्सा बन सकता है। भले ही इसके सामाजिक एकजुटता को लेकर वास्तविक जागरूकता न आई हो, लेकिन दुनिया निरंतर अधिकाधिक परस्पर निर्भर हो रही है।

यह पारस्परिक निर्भरता हालाँकि असंतुलन भी लाती है और बहुधा अत्यधिक असमानता को बढ़ाती है, भ्रांतियों को बढ़ावा देती है और तनाव बढ़ने की आशंकाओं को कई गुना बढ़ा देती है, जिसके साथ वैश्विक उथल-पुथल जुड़ी हुई है।

यह सही है कि इससे उत्पन्न वाले प्रभुत्व की रूपरेखा और हितों के टकराव को महज इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि संचार का दायरा काफी व्यापक हो चुका है, लेकिन संचार की बढ़ी हुई गुंजाइश के चलते प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की समस्याओं और आकांक्षाओं के प्रति अधिक सजग बनाकर और प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष एक वैश्विक समुदाय के रूप में जो खतरें हैं, उनके प्रति जागरूक बना कर इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है।

इन स्थितियों में संचार का बुनियादी महत्व है | इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण हुई अत्यधिक प्रगति के फलस्वरूप इस आवश्यकता को पूरा करने के साधन मौजूद हैं। उपग्रह युग में जनसंचार सभी लोगों को ये अवसर मुहैया कराता है कि वे एक ही समय में किसी आयोजन के गवाह बन सकें, सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकें, अपनी-अपनी विशेषताओं के बावजूद एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने मतभेदों को स्वीकार करते हुए भी एक दूसरे को महत्व दें।

ठीक इसी समय, मीडिया प्रत्येक देश में सामाजिक संचार के बुनियादी आँकड़ों को परिवर्तित करने, नई विनिमय प्रणाली की स्थापना करने, ज्ञान के हस्तांतरण को प्रशासित करने वाली दशाओं में पूर्णतया परिवर्तित करने, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की व्यापक संभावनाओं को खोलने, बड़े स्तर पर लोगों तक संस्कृति को पहुंचाने, और ज्ञान तथा प्रायोगिक ज्ञान के बढ़ावा देने की प्रक्रिया में हैं। वे ऐसी दशाएं सृजित कर रहे हैं जिससे अनवरत व्यक्तिगत संवर्धन हो रहा है और सभी देशों के लोग अपनी खुद की प्रगति में सहभागी बन रहे हैं और समग्र वैश्विक समुदाय को देखने के अपने नजरिए को व्यापक बना रहे हैं।

ऐसे में ये महज काल्पनिक इच्छा नहीं है कि लोग अधिक से अधिक ये महसूस करेंगे कि राष्ट्रीय नियति घनिष्ठ रूप से गूंथी हुई है। भविष्य में वे एक दूसरे के

साथ मेलजोल को बढ़ाने के लिए गठजोड़ विकसित करेंगे और आपसी सम्मान और सहयोग स्थापित पर आधारित मजबूत सम्बंध स्थापित करेंगे।

हालाँकि ये ऐसे युग की कुछ संभावनाएं मात्र हैं, जो भविष्य के लिए कुछ बेहतरीन या बेहद बुरा करने की समान रूप से क्षमता रखती हैं। हालाँकि ऐसा तभी संभव होगा जबकि संकीर्ण सांप्रदायिक हितों को बढ़ाने और मानवीय गरिमा पर प्रहार को न्यायोचित ठहराने तथा असमानता को बढ़ाने, जो पहले ही राष्ट्रों के बीच और प्रत्येक देश के भीतर मौजूद है, के लिए जनसंचार को शक्ति के नए साधन के रूप में परिवर्तित करने का प्रलोभन होगा। और, ऐसा केवल उस स्थिति में होगा जब संपर्क साधनों की सघनता को रोकने के हर संभव उपाय किए जाएं, इसमें अंतर्वैयक्तिक संचार की गुंजाइश में उत्तरोतर कटौती से लेकर माध्यमों की बहुलता को आखिरकार पूरी तरह से ख़त्म कर देना शामिल है। फिर चाहे पारंपरिक माध्यम हो या आधुनिक और जिनके द्वारा लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे।

सूचना मीडिया व्यक्तिगत स्तर पर इंसानों के लिए सभी क्षेत्रों में सम्मानजनक स्थिति हासिल करने में योगदान कर सकता है, उनमें दिखने वाले विविध मतभेदों के साथ, और स्वकेंद्रित राष्ट्रवाद वाले स्थानों में सभी लोगों की साझा आकांक्षाओं की स्वीकार्यता हासिल करते हुए। वे समुदायों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच निर्बाध संचार को बढ़ावा भी दे सकते हैं, ताकि अवसरों की समानता और द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें ये पूर्व धारणा शामिल है कि सभी क्षेत्रों से आने वाली सूचनाएं किसी तरह के बंधन से मुक्त होंगी। लेकिन हम सिर्फ इस बात की पुष्टि करके ही नहीं रुक सकते हैं क्योंकि इस तरह की आजादी तब तक पूरी तरह प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक कि ये सभी के लिए वास्तविकता न बन जाए।

यूनेस्को अपनी स्थापना के साथ ही ऐसी परिस्थितियों को लाने के लिए निष्ठावान रहा है। संस्था का संविधान "सत्य और विचारों तथा ज्ञान के मुक्त आदान-प्रदान के लक्ष्य के पाने के लिए निर्बाध रूप से काम करने..." और इसके लिए लोगों के बीच संचार के साधनों को बढ़ाने के लिए काम करने का अधिकार देता है।

हालाँकि खासतौर से पिछले दो दशकों के दौरान आधुनिक समाज में मास मीडिया का महत्व बढ़ने और उनके द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ, खासतौर से नव-स्वतंत्र राष्ट्रों में हुए विकास के चलते संगठन ने अधिक प्रखर विचारों को बढ़ावा दिया है और इसके क्रियान्वयन को मजबूती दी है। संस्था ने वैश्विक स्तर पर और प्रत्येक समाजों के भीतर सूचना के अधिक संतुलित प्रवाह की जरूरत को रेखांकित करने के लिए सक्रिय रूप से योगदान किया है।

नैरोबी में 1976 में हुई संस्था की आमसभा के 19वें सत्र में इस राय के अनुरूप मुझे निर्देश दिया गया था कि तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हुए हालिया बदलावों की पृष्ठभूमि में समकालीन समाज के संचार की सभी समस्याओं की समीक्षा उनकी जटिलताओं और तीव्रताओं को ध्यान में रखते हुए की जाए। ऐसे में मैंने इस काम को करने के लिए ये उचित समझा कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के अत्यधिक सक्षम और ख्याति प्राप्त लोगों का एक विशेषज्ञ मंडल बनाया जाए और इसी के अनुरूप मैंने श्रीमान सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में संचार की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की और उसमें निम्न सदस्य शामिल थे:

एली एबल (अमेरिका), ह्यूबर्ट ब्यूव-मेरी (फ्रांस), एल्बे मा एकोंजो (ज़ैरे), गेब्रियल गार्सिया मार्कोएज़ (कोलंबिया), सर्जी लेसेव (यूएसएसआर), मोक्तर ल्युबिस (इंडोनेशिया), मुस्तफा मासमौउदी (ट्यूनिशिया), मिशियो नगाई (जापान), फ्रेड आईसेक एक्पोरूआरो ओमू (नाइजीरिया), बॉग्डेन ओसोल्निक (युगोस्लाविया),

जमाल अल ओतिफी (मिस्र), जोहानेस पीटर प्रोंक (नीदरलैंड), हुआन सोमाविया (चिली), बूबली जार्ज वर्गीज (भारत) और बैटी जिमरमैन (कनाडा)।

आयोग, जिसे शर्तों और प्रक्रियाओं के लिहाज से पूरी बौद्धिक स्वतंत्रता और अधिकतम संभव विस्तार हासिल था, जिससे उसने समस्या की जांच की और अपने काम को तय समय से पहले पूरा किया। ऐसे उपक्रम को पूरा करने के लिए कम समय उपलब्ध होने के बावजूद ये दो वर्ष और दो महीने के दौरान आठ सत्रों में पूरा हुआ। यहाँ अंतिम रिपोर्ट आपको सौंपते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।

इस अवसर पर मैं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूं कि मैं श्रीमान मैकब्राइड और आयोग के सभी सदस्यों का आभारी हूं, जो दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र से थे और विभिन्न पेशेवर और राजनीतिक पृष्ठभूमियों से थे। साथ ही ये सदस्य अत्यधिक बौद्धिक ईमानदारी और सहिष्णुता से सम्पन्न थे, ताकि वे विस्तृत श्रृंखलाओं वाली समस्यओं के सामूहिक रूप से समाधान तलाश सकें और आज की दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ तलाश सकें।

ऐसे में इस रिपोर्ट को उन चुनौतियों पर व्यावहारिक नजरिए से विचार करने और उनका मुकाबला करने के लिए हम जो कदम उठा सकते हैं, उस बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा समग्र रूप से उठाया गया पहला कदम माना जा सकता है, जो 1978 में संस्था के 20वें सत्र में आम सभा के दौरान मीडिया के बारे में सर्वसम्मति से अपनाए गए घोषणा पत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप है।

जब समकालीन समाज की विविधता के बारे में विचार किया जाए तो संचार के संबंध में उपस्थित होने वाली समस्याएं ऐसी नहीं हैं कि उनका समाधान किसी एक अकेले अध्ययन के जरिए किया जा सके, हालांकि ये सम्यक और समग्र हो सकती है। ऐसे में निश्चित रूप से आयोग का काम जारी है और प्रगाढ़ हो रहा है।

इन कारणों से रिपोर्ट विभिन्न आधारों पर न सिर्फ संचार के लिए जिम्मेदार अधिकारी वर्ग और संबंधित संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी बल्कि अध्ययन

की सभी शाखाओं के प्रशासकों और शोधार्थियों, गैर-सरकारी संगठनों और अंतर-प्रशासकीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों, और सभी देशों के आम नागरिकों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत में इसे यूनेस्को की विचारात्मक निकायों के कार्यकारी भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, अरबी, रूसी और चीनी हैं, लेकिन इसे दूसरी भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए हम हर संभव उपाय करेंगे।

प्रत्येक सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल में सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए ये अनिवार्य है कि उन्हें सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए, नए विचार विकसित होने चाहिए और प्रचलित जड़ता को तोड़ने के लिए अधिक सकारात्मक उपाय करने होंगे। नई वैश्विक संचार व्यवस्था के आने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से सीख सकेगा, जबकि ठीक उसी समय विश्व मामलों को लेकर अपनी राय और दशाओं के लेकर अपनी समझ से उन्हें अवगत करा रहे हैं। मानवता को स्वतंत्रता, लोकतंत्र और साहचर्य के रास्ते पर आगे की ओर निर्णायक कदम बढ़ाना होगा।

भूमिका

सीन मैकब्राइड

संचार की समस्याओं के अध्ययन के अंतरराष्ट्रीय आयोग ने दिसम्बर 1977 में अपने कार्य की शुरूआत की। जब संचार के संसार में हमारी लम्बी यात्रा की शुरूआत हुई तब मेरी भावनाएं उत्तेजना और घबराहट का मिला जुला रूप थी। उत्साह का कारण शांति और मानव विकास पर आधारित एक विषय की खोज में दुनिया के सभी हिस्सों के 16 सदस्यी विद्वानों के समूह का संचालन करने का अवसर मिलना था, घबराहट विषय का विस्तृत क्षेत्र और समस्याओं की जटिल प्रकृति के कारण थी।

पूर्वानुमान में कार्य की कठिनाईयों को आगे बढ़ाने या किसी सहमति के निष्कर्ष पर पहुंचने में आयोग को स्थापित करने वाली पृष्ठभूमि किसी आशावादी साहस का अवसर नहीं दे रही थी।

1970 में अंतरराष्ट्रीय बहस संचार के मुद्दों पर कई क्षेत्रों में टकराहट के बिन्दु पर मुखरता के साथ पहुंच गया। (1970 के दशक तक संचार के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय बहसें कई क्षेत्रों में टकराव की हद तक पहुंच गईं थी।) तीसरी दुनिया के देश मुक्त सूचना प्रवाह पर हमला करने वाले औद्योगिक देशों के समाचारों के वर्चस्वशाली प्रवाह का खुलकर विरोध कर रहे थे। पत्रकारिक स्वतंत्रता के समर्थक राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर घुसपैठियों की तरह चिन्हित होने लगे। समाचार मूल्यों की बदलती अवधारणाएं और पत्रकारों की भूमिका, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रती विस्तृत रूप से संघर्ष कर रहे थे मानों कि मास-मीडिया का संभावित योगदान बड़े विश्व की समस्याओं का समाधान था।

इन प्रदत्त परिस्थितियों में जो कि आयोग के कार्य की शुरूआत से ही था कैसे एक संतुलित ग़ैरपक्षपातपूर्ण, वर्तमान संचार परिदृश्य का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्राप्त किया जाए और कैसे विश्व की प्रमुख समस्या पर हमारे विचारों में यथासंभव व्यापक आम सहमति तक पहुँचने की चुनौती का सामना किया जाए इस की चिन्ता प्रारम्भ से ही थी।

अन्य प्राथमिक चिंता आधुनिक समाजों में संचार की सम्पूर्ण समस्याओं का अध्ययन हमारे जनादेश की व्यापकता में करना था। आयोग ने अपने कार्य के दौरान इस क्षेत्र के सभी दस्तावेज़ों और साहित्यों को ध्यान से पढ़ा जिसे किसी ने भी व्यापक दायरे में समीक्षा करने का प्रयास नहीं किया था। हमारा उद्देश्य किसी निश्चित कार्य के पास पहुँच जाना नहीं है, लेकिन हमने औपचारिक मुद्दों से आगे बढ़ने का प्रयास किया है और अपने अधिदेश के शर्तों के नजदीक पहुँचना चाहते हैं।

यद्यपि इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं हमारे विचार-विमर्श के लिए प्रारम्भ बिन्दु रहा है इसलिए हमारा प्रतिवेदन साधारण रूप से समाचार के संग्रह और प्रसार या जन- मीडिया पर नहीं है। हम शीघ्र ही एक व्यापक ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में सम्मिलित हो चुके हैं। इसी तरह समस्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में विचार करते हुए संचार के सभी पहलुओं को सम्मिलित करके सूचना पर एकाग्रता को विस्तार दिया गया। इसके अतिरिक्त जैसा कि संचार समुदाय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि में सर्वप्रमुख है, मैं एच. वी. लेल्स के कथन का भावानुवाद करते हुए यह कहता हूं कि मानव इतिहास संचार और विध्वंस के बीच होड़ शुरू हो गई है। संचार और इसके सभी बदलते गतिरोधों का प्रयोग यह आश्वस्त

करता है कि मानवता एक इतिहास से बड़ी है जो कि हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती है।

आयोग के सोलह सदस्य जो बड़े पैमाने पर दुनिया के वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्पेक्ट्रम के प्रतिनिधि हैं, प्रमुख मुद्दों पर आश्चर्यजनक रूप से उन समझौते के लिए सुझाए गए उपायों पर विचार करने लगे जो पहले असंगत लग रहे थे। यह सिर्फ निष्कर्ष तक पहुँचने की बात नहीं थी। शायद इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था समस्याओं और संभावित समाधानों की पहचान और उनका विश्लेषण किया जाना। हम उम्मीद करते हैं कि विकासशील नई दुनिया में सूचना और संचार क्रम के पहलुओं पर अपरिहार्य जारी बहस शायद मददगार हो।

मेरे लिए सबसे अच्छा अनुभव अपने काम के दौरान एक दूसरे के लिए सम्मान और दोस्ती की आपसी समझ का विकसित होना था, और मैं यह सोचने का जोखिम उठा पा रहा हूं कि यह सब आयोग में काम करने वाले अपने सभी सहयोगियों पर लागू होता है। मुझे उम्मीद है कि यह रचनात्मक प्रयास जो कि हमारे काम पर हावी रहा तब भी जारी रहेगा जब हमारी रिपोर्ट सरकारों और अन्य लोगों द्वारा जांच के लिए जायेगी।

जब रिपोर्ट का अंतिम मसौदा अनुमोदन से पहले हमारे पास आया तो मेरे अंदर इसको शुरू से लेकर अंत तक फिर से दोबारा लिखने की इच्छा हुई। मुझे यकीन है कि मेरे सारे साथी और सचिवालय के सदस्यों ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। लिखने की शैली भिन्न थी, अंश भी बहुत बड़े थे। इसके अलावा यह भी एक सच्चाई थी कि इस कार्य को करने के लिए हमारे पास जरूरी समय नहीं था, हमने यह महसूस किया कि शैली में एकरूपता नहीं होने के बावजूद रिर्पोट स्पष्ट रूप से हमारे विचारों को अवगत करा रही थी। पाठकों को यह बात दिमाग में जरूर रखनी चाहिए कि संचार के लिए कई

भाषाई, सांस्कृतिक और दार्शनिक किस्मों को इस विशाल मोजेक में बुना गया है।

एक बड़े हिस्से की महत्त्वपूर्ण विषयों पर आम सहमति होने के बावजूद, बहुत सारे सवालों पर स्पष्टता नहीं बनी, बहुत सारे विषयों में विश्लेषण की आवश्यकता है। बहुत सारी कठिनाइयां आगे हैं, विशेष रूप से नई व्यवस्था के निर्माण में मदद हेतु उनको व्यवस्थित करने और ठोस उपायों को लागू करने में, जो सतत समीक्षा की मांग करती है।" नये क्रम "के अर्थ और इनको किस रूप में शामिल करना चाहिए इस पर बहुत सारे अलग-अलग विचार है जैसे इसको प्राप्त करने के तरीके एवं साधन के लिए सिर्फ एक विविध राय के रूप में। लेकिन, इन मतभेदों के बावजूद आयोग में कोई भी संचार क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है मानने को आश्वस्त नहीं है और यह कि मौजूदा क्रम किसी भी रूप में सक्षम नहीं है।

स्पष्ट रूप से कोई ऐसा जादुई समाधान नहीं है कि एक ही झटके में संचार से जुड़ी मौजूदा जटिल और आपस में जुड़ी समस्याओं को मिटा दिया जाए। बहुत सारे चरण होंगे, रणनीतियां और पहलुओं की कदम दर कदम नई संरचनाओं, तरीकों और दृष्टिकोण की स्थापना की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, 'नई दुनिया सूचना और संचार व्यवस्था' को किसी दिए गए सेट की स्थिति और प्रथाओं के बजाए एक प्रक्रिया के रूप में और अधिक सही तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।

प्रक्रिया के ब्यौरे लगातार बदलते जाएंगे, अभी तक इसके लक्ष्यों में स्थिरता मिलेगी। और अधिक न्याय, और अधिक समानता, जानकारी के आदान प्रदान में अधिक पारस्परिकता, संचार प्रवाह में कम निर्भरता, संदेशों के प्रसार के नीचे की तरफ जाने में कमी होगी, अधिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान होगी, सभी मानव जाति के लिए और अधिक लाभ होगा।

एक लंबी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आयोग का विश्लेषण और एक नई विश्व सूचना और संचार क्रम के विकास के लिए प्रमुख दिशानिर्देशों पर आम सहमति खुद से हो गयी थी। राजदूत मुस्तफा मसमौदी और डा. बोगडन ओस्लिंक के हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने न सिर्फ "नये क्रम "के लिए लगातार वकालत की, बल्कि इसके प्रमुख पहलुओं पर अपनी रचनात्मक व्याख्या की लेकिन आयोग के सदस्यों के बीच दिसंबर 1977 से नवंबर 1979 में आठ सत्रों के दौरान हुई समृद्ध चर्चाओं के अलावा, हमारा बुनियादी दृष्टिकोण, लगातार आगे की ओर बढ़ने की तरफ था। एक व्यावहारिक रूप से संभव सीमा तक सीधे तौर पर व्यापक विषयों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के प्रतिनिधित्व के साथ पेशेवर और विशेषज्ञ शामिल थे।

हमने विभिन्न मुद्दों जैसे जानकारी की सामग्री, सटीकता और तथ्यों में संतुलन और छवियों का प्रस्तुतीकरण, खबरों की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा, समाचार एकत्र करने और वितरण में लगे पत्रकारों और संगठनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ ही साथ उनके अभियान में तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय सभा के आयोजन की शुरूआत की।

इस प्रयोजन के लिए समाचार संग्रह और प्रसार के बुनियादी ढांचे पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी स्टॉकहोम में अप्रैल 1978 में आयोजित की गई। स्वीडिश सरकार की उदार सहायता से क्षेत्रीय या दुनियां भर की समाचार एजेंसियों, प्रसारण संगठनों, प्रमुख समाचार पत्रों, अनुसंधान संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय एवं गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित बैठकों के अलावा, आयोग ने स्वीडन, यूगोस्लाविया, भारत और मेक्सिको जैसे विभिन्न देशों में चार

सत्रों का आयोजन किया। इसकी वजह से इसमें शामिल असमान सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को नजदीक से परखने का मौका मिला। पेशेवरों और शोधकर्ताओं को विभिन्न समाजों में संचार की बुनियादी पहलुओं पर अलग विचारों को बांटने के साथ-साथ संपर्क बनाने का भी मौका मिला। आयोग के लिए विशेष महत्व के विषयों पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई। युगोस्लाविया की मीडिया और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हमने समाज और संचार मीडिया के बीच संचार पर चर्चा की। हमने इसी अवसर पर विकासशील देशों के बीच सहयोग पर एक और बहस की। हमारे भारतीय मेजबान ने संचार और विकास के बीच के रिश्ते पर एक व्यापक चर्चा का आयोजन किया। हमने भी उनके साथ भविष्य में तकनीकी विकास के प्रभाव पर चर्चा की। लैटिन अमेरिकी लेखकों, प्रोफेसरों और मीडिया कर्मियों के एक बड़े समूह के साथ हमने संस्कृति और संचार के बीच संबंध पर जोर दिया।

केंद्रीय विषयों पर ये प्रत्यक्ष परामर्श संचार में बुनियादी मुद्दों की इंटरलॉकिंग प्रकृति में अमूल्य गहरी परख प्रदान करने के साथ विशेष रूप से, इन मुद्दों में संरचना की दृष्टि से व्यापक सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पद्धति से जुड़े होने की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार, अंत में और अनिवार्य रूप से, संचार की समस्याओं में एक अत्यधिक राजनीतिक चरित्र को मूल कारण मान लेते हैं क्योंकि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र के केंद्र बिंदु में है।

इसके बाद पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में हमारे विचार विमर्श के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा संचार के विशिष्ट पहलुओं पर तैयार कुछ एक सौ वर्णनात्मक और विचार पत्रों को हमें प्रदान किया गया। यह विशेष रूप से तुलनात्मक विश्लेषण के लिए मौलिक सामग्री और संचार मुद्दों पर प्रेरक पुनर्विचारों को दर्शाता था।

हमारे पेशेवर संपर्क आगे और भी समृद्ध हुए, जब अपने आप को और आयोग और सचिवालय के अन्य सदस्यों के साथ सूचना और संचार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, अंतरराष्ट्रीय पेशेवर संगठनों, गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा आयोजित सम्मेलनों, बैठकों, सेमिनारों और चर्चा समूहों में शामिल होने का और अधिक अवसर मिला।

इसके अलावा, आयोग के काम के दौरान, अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के दर्जनों अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्रों, पत्रकारिता के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक संगठनों और इसी तरह के निकायों- सबके सहयोग से अनुसंधान के निष्कर्ष, सामयिक प्रलेखन और पर्याप्त कमेंटरी की उदार आपूर्ति सक्रिय रूप से हुई।

अंत में, सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत, संस्थागत और सरकारी टिप्पणियों का लाभ हमारी अंतरिम रिपोर्ट को मिला जिसको यूनेस्को के आम सम्मेलन के बीसवें अधिवेशन में 1978 में प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकार हमारी रिपोर्ट आयोग के संचार परिदृश्य पर सामूहिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। यह वस्तुतः दुनिया भर के सर्वेक्षणों के मतों, व्यक्तिगत और संस्थागत, और असंख्य स्रोतों से आए दस्तावेजों के संग्रह पर आधारित थी। सूचना की इस बहुलता में वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रंगों के व्यापक संभव स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। आयोग का प्रत्येक सदस्य अपने स्वयं के दृष्टिकोण से इसको मानता है, तो यह हमारे सामूहिक विचार विमर्श द्वारा की गई समीक्षा हैं।

परिणामस्वरूप आसवन हमारी रिपोर्ट का निर्माण करता है। आम तौर पर इस बारे में आम सहमति होती है कि आयोग वर्तमान में संचार क्रम को कैसे देखता है जहां एक नयी उम्मीद होती है। जहां मतभेद थे वहां टिप्पणी

या असहमति के माध्यम से परिलक्षित होते हैं, लेकिन इसका व्यापक आधार और साथ में आयोग द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि समूह द्वारा सूत्रीकरण, हमारी रिपोर्ट-इसकी प्रस्तुतियों, निष्कर्ष और प्रस्तावों कि एक यह व्यापक समान विचारधारा वाले दर्शकों तक पहुंच जाएगी। इस विश्वास के साथ, मेरी प्रारंभिक बेचैनी दूर हो गयी है। मुझे विश्वास है कि भविष्य के संवादों का संचालन अच्छा होगा, सभी मानवता को लाभ देकर एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।

भाग-1

संचार और समाज

अध्याय 1

ऐतिहासिक आयाम

संचार जीवन को चलाता और आगे बढ़ाता है| ये सामाजिक गतिविधियों और सभ्यता की अभिव्यक्ति और उसका प्रेरक है। ये लोगों को दिशा देता है और उनकी सहज प्रवृतियों को विभिन्न प्रकार से देख-परख करने के बाद आदेश और निर्देश से उसे प्रेरणा का रूप देता है। ये विचारों का एक साझा मंच तैयार करता है, संदेशों के आदान-प्रदान के जरिए मिलकर जीने की भावना को मजबूत करता और उसे हकीकत में तब्दील करता है। संचार मनुष्य के अस्तित्व की नाजुक कड़ी, भावनाओं और जरूरतों को प्रदर्शित करता है। उसकी चरम रचनात्मकता या विश्वंसकारिता को दर्शाता है। संचार, ज्ञान, संगठन और शक्ति को जोड़ कर एक बेहतर जीवन के लिए निरंतर प्रयास के जरिए मानव की एकदम आरम्भिक स्मृति को उसकी श्रेष्ठतम आकांक्षाओं से मिलाता है| दुनिया के आधुनिक होने के साथ ही संचार का कार्य और अधिक मुश्किल और गूढ़ हो गया है। इससे अपेक्षा की जाती है कि यह लोगों को इच्छा, उत्पीड़न और डर से आजाद कराए और उन्हें समझदारी से एकजुट कर सामुदायिक और समूह के रूप में जोड़े रखे। हालांकि कुछ बुनियादी संरचनात्मक बदलावों को लागू किये बिना तकनीकी और संचारात्मक विकास के संभावित लाभों को मुश्किल से ही बहुसंख्यक लोगों के उपयोग में लाया जा सकेगा।

1.

एक अतीत जो अभी भी है

मानव जाति को इस बात के लिए खुले दिल से आभारी होना चाहिए कि उसे संचार का जन्मजात उपहार मिला है। मानव एक जाति के रूप में इसकी सफलता के लिए आभारी है, इसमें संगठनात्मक क्षमता और इन प्राकृतिक उपहारों के सुधार, विकास और विस्तार के लिए दिखाई गई क्षमताएं शामिल हैं, जिससे उसका अपना जैविक विकास प्रभावित हुआ है। शुरू के दिनों में लोगों के पास ये काम था कि वे अपनी बात या संदेश को इस तरह से तैयार करें जिससे की उसका प्रभाव, उसकी विविधता और समझ में आ सकने की क्षमता बढ़े और उन्होंने लगातार प्रयास के जरिये संदेशों में रुकावट को दूर किया और उसके अर्थ निकालने की क्षमता विकसित कर ली।

इतिहास में अब तक, मनुष्यों ने अपने चारों तरफ से आने वाली सूचनाओं को हासिल करने और उन्हें समझ पाने की योग्यता में लगातार सुधार करते रहने की कोशिश की है, साथ ही साथ सूचनाएं भेजने की अपनी गति, स्पष्टता और सूचनाओं को भेजने के तरीके को बढ़ाया है। इसके लिए जरूरी था कि सबसे पहले इसके छिपे हुए खतरों या गलत प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा की जाए और उसके बाद उन जोखिमों से निपटने की सामाजिक संभावनाओं को साझा किया जाए।

मानव जाति ने आवाज और अपने शारीरिक हाव-भाव से शुरू करते हुए बाद में गैर-शाब्दिक संचार के साधनों के कई सारे माध्यम खोजे जैसे कि संगीत, नृत्य, ड्रम संदेश, अग्नि संकेत, चित्र और ग्राफिक संकेतों के दूसरे प्रकार,

जिसमें पिक्टोग्राम[1]और उसके बाद आने वाली चित्रलिपि भी शामिल हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अमूर्त विचार के साथ किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वे चीज जिसने मानव संचार को खासतौर से शक्तिशाली बनाया, और मनुष्यों को पशुओं से अलग विशेष स्थिति प्रदान की, वे है भाषाओं का विकास। भाषा का महत्व उस संभावित विस्तार और गहराई के चलते है जो उसने संचार की विषयवस्तु को दिया और अभिव्यक्ति को सटीक बनाने के साथ ही उसे विस्तार दिया है। विभिन्न तरह के समाजों में किसी व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वे संचार के इन सभी साधनों और तरीकों का लगातार उपयोग करता रहे और इसी वजह से सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अंतर्वैयक्तिक और अंतर-सामुदायिक संचार विधि की जरूरत होती है।

वास्तव में, इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संचार के तरीकों की विविधता और प्रयोग की कोई सीमा नहीं है। संचार के कई रूपों और उनकी सामग्रियों का विकास हुआ है और उसमें लगातार बदलाव हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क की कमी के चलते विभिन्न भाषाओं का उदय हुआ, लेकिन ऐसा खासतौर से विभिन्न आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक परंपराओं वाले समाजों के चलते हुआ, जिसके लिए विशिष्ट शब्दावलियों और भाषाई संरचनाओं की आवश्यकता थी। लेकिन ठीक उसी समय, विभिन्न सामाजिक समूहों यहां तक कि समुदायों के भीतर भी कुछ भेद नजर आएं- इसे खासतौर से प्रभावशाली संभ्रांत वर्ग और आम जनता के बीच- मुहावरों और शब्दावलियों में अंतर के रूप में देखा जा सकता है। यह भेद कुछ शब्दों के अर्थ के साथ ही उच्चारण में भी दिखता है। आज लाखों लोग ऐसी

[1] पिक्टोग्राम- लेखन शैली का एक स्वरूप हैं जो सुमेरिया, युनान एवं चीन की सभ्यताओं में मिलता है ।

भाषाएं बोलते हैं, जिसे उनके पड़ोस के लोग ही नहीं समझ पाते हैं, हालांकि उनके बीच घनिष्ठ सामाजिक और आर्थिक संबंध होता है और आबादी परस्पर मिलीजुली होती है। हालांकि विडंबना ये भी है कि भाषाओं के बहुत सारे प्रकार और विविधता, संचार को इतना कठिन बना सकती है कि इसका विस्तार विशेषाधिकार को बनाए रख सकता है।

धार्मिक नेताओं, विद्वानों या जीतने वालों द्वारा पेश की गईं कुछ भाषाओं ने विशेष दर्जा हासिल कर लिया जो कभी-कभी शक्ति और विशेषाधिकार का आधार बनती है। छोटे अल्पसंख्यक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा- जैसे भारत में संस्कृत और मध्यकालीन यूरोप में लैटिन, विद्वता, अभिलेख को दर्ज करने और धार्मिक आयोजनों का माध्यम बन सकीं। किसी क्षेत्र में जीतने वाले और सत्तारूढ़ तथा अभिजात्य वर्ग द्वारा पेश की गई भाषा का इस्तेमाल वाणिज्य, प्रशासन और कानून के क्षेत्र में किया जाने लगा। साम्राज्यवाद के युग में उपनिवेशिक शक्तियों की भाषा उनके उपनिवेशों में प्रशासन, कानूनों को लिखने, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा बन गई। ऐसे में इन क्षेत्रों से बाहर कर दी गईं पुरानी भाषाओं का विकास रुक गया। एशिया और अफ्रीका के कुछ स्वतंत्र हो चुके राष्ट्रों में एक हद तक अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाओं की स्थिति आज भी यही है। ये इन राज्यों में और साथ ही पड़ोसी देशों के बीच समस्याएं खड़ी कर सकती हैं - खासतौर से पश्चिम अफ्रीका और कैरिबियन देशों में, जो अभी-अभी विभिन्न देशों के कब्जे से मुक्त हुए हैं।

शब्द मानवीय अभिव्यक्तियों के प्रतीक हैं, उनमें अंतर्निहित धारणा समय के साथ और नई परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बदलती रही है। इतना ही नहीं, सभी भाषाएं लगातार परिवर्तन की अवस्था में हैं- कभी क्रमिक और

कभी बहुत तेज। वे विचारों और ज्ञान में, उत्पादक तकनीक में, सामाजिक संबंधों में, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में बदलावों से उठने वाली आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करती हैं। इसलिए शब्द अपने अर्थों को बदलते हैं और नए अर्थ अपनाते हैं, विशेष तकनीकी शब्दावलियां आम इस्तेमाल में आ जाती हैं, और नए शब्दों को गढ़ा जाता है। किसी खास समय में औपचारिक भाषा और रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में, और पुरानी तथा नई पीढ़ी की बातचीत में अंतर होता है। ये प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि भाषा सीखने की चीज नहीं है बल्कि एक साधन है, जिसे मानवीय उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है।

मनुष्य की दूसरी प्रमुख उपलब्धि लेखन ने मौखिक शब्दों को स्थायित्व दिया। बहुत पहले, समाज के किसी समुदाय की अभिव्यक्ति और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए औपचारिक संस्कार और धार्मिक क्रियाकलापों के विधि और निर्देशों के विवरण मिट्टी की पट्टी, पत्थर की नक्काशी या स्क्रॉल[2] पर दर्ज कर दिए जाते थे ताकि वे लंबे समय तक मौजूद रह सकें। लेखन के विकास से सर्वाधिक अर्थपूर्ण, संकेतों से भरे हुए संदेशों के संरक्षण की गुंजाइश बनी, जिसने समुदाय के स्थाई अस्तित्व को सुनिश्चित किया। हस्तलिखित और प्रतिलिपि के रूप में किताबों का इतिहास 30वीं शताब्दी से मिलता है। विस्तार के साथ ही किताबें प्राचीनकाल की कई महान सभ्यताओं में विचारों और ज्ञान की अमूल्य भंडार बन गईं। दो हजार साल से अधिक पहले चीन के शासकों ने उस समय उपलब्ध सभी ज्ञान- मुख्य रूप से वैज्ञानिक और ऐतिहासिक- का अभिलेख पुस्तकों की श्रृंखला के

[2] स्क्राल- स्क्राल शब्द पुरानी इजिप्ट सभ्यता में होता था। संदर्भों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने वाले भोजपत्रों, चर्मपत्रों और कग़ज़ों के मुड्ठों को स्क्राल कहतें हैं।

रूप में तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरू की। ये पहला विश्वकोष बना। हालांकि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाल के महान पुस्तकालयों का इस्तेमाल सामान्य और धार्मिक विद्वान, और प्रशासकों की सुविधा की नियत से था। इस विशेषाधिकार प्राप्त समूह के बाहर पुस्तकों के प्रसार की प्रयास काफी बाद में शुरु हुए।

बेहद शुरुआती दौर में एक सामाजिक कार्य के रूप में संचार किसी खास समाज या समाज के किसी क्षेत्र की परंपराओं, नियमों, संस्कारों और वर्जनाओं के अधीन था। ऐसे में, एक सभ्यता या संस्कृति से अलग दूसरी सभ्यता या संस्कृति में संचार के परंपरागत माध्यमों और उसके तरीकों के विषयों में पर्याप्त भिन्नता थी। मिट चुके और अभी भी मौजूद उन परंपरागत समाज का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि उनमें परंपरागत संचार ने अलग-अलग तरह से आकार लिया, जिसके तहत संस्कृति, विधि, नैतिक और धार्मिक संस्थान विकसित हुए।

कई शताब्दियों से, और कुछ जगहों पर लाखों सालों से, धरती के निवासियों का बहुसंख्यक हिस्सा पूरी तरह से अपनी छोटी सामाजिक इकाइयों मसलन कोई आदिवासी समूह या गांव में जीवन-यापन करता रहा। तब उनके बीच सामाजिक संपर्क के लिए केवल अंतर्वैयक्तिक संचार का तरीका ही प्रचलन में था। केवल अजनबियों (यात्रियों, तीर्थयात्रियों, खानाबदोश, सैनिक) की कभी-कभार आने-जाने के क्रम ने ही उनके पूरी तरह से बंद जीवन में थोड़े समय के लिए हस्तक्षेप किया। ऐसा अंतर्वैयक्तिक संचार आज भी मौजूद है और खासतौर से छोटे समुदायों में इसका महत्व बेजोड़ है। अतीत में, इसने बाहरी शासकों द्वारा थोपे गए बिखराव के खिलाफ भाईचारे के मूल्यों को मजबूत करने और समाज को पुनर्संतुलित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया।

किसी भी दशा में संचार के अपने सामाजिक आयाम होते हैं, ये काम को प्रोत्साहन, सामंजस्यपूर्ण रहन और प्राकृतिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता तथा सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। यह मानव संचार का एक अनमोल पहलू रहा है।

धारे-धीरे, संचार ने पहले परंपरागत और बाद में समाज में संस्थागत रूप ले लिया। नियमों और रीति-रिवाजों के प्रसार के रूप में अंतर्वैयक्तिक संचार और सार्वजनिक संस्थागत संचार अपने सर्वोच्च स्थिति में मौजूद था। संचार के इस तरह संस्थागत रूप लेने के चलते एक पेशेवर श्रेणी का उदय हुआ, जो सामूहिक यादों को सहेजे रखे और कुछ खास तरह के संदेशों को आगे भी भेजते रहने के लिए जवाबदेह हो, जैसे कथाकार, पेशेवर कवि, जादूगर, आदिवासी मुखिया, यात्रा करने वाले व्यापारी,पंचायत सरपंच, स्थानीय प्रशासक, नर्तक, लेखक आदि। शुरू में संचार के संस्थानबद्ध होते जाने के साथ ही समाज भी अधिक जटिल होता जा रहा था और संचार ने इसे और बढ़ावा दिया।

लेकिन इस अंतराल में संचार अपनी धीमी गति के कारण सीमित था। इंसानों की आवाज केवल उन तक पहुंचती थी, जो इसके दायरे में थे। तब लिखे संदेश किसी धावक, किसी घोड़े, किसी पक्षी या किसी नौका से अधिक तेजी से नहीं जा पाते थे। ये सही है कि इस धीमी गति के बावजूद ज्ञान और विचार अपने मूल स्थान से बहुत दूर तक गहराई से फैला। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के हिंदू मंदिर, विचारों की गतिशीलता और सूचनाओं के प्रवाह के चौंकने वाले प्रमाण हैं। बुद्ध, ईसा और मुहम्मद के उपदेश उस समय भी तेजी से दूरदराज के इलाकों तक पहुंचे, जब यात्राएं धीमी, कठिन और खतरनाक हुआ करती थीं। लाखों लोगों की सोच और विश्वास में बदलाव

लाने के लिए किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की जरूरत नहीं थी। फिर भी ज्यादातर समाजों यहां तक कि उच्च सांस्कृतिक उपलब्धियों वाले समाजों में भी बदलाव के धीमे होने का कारण उन समाजों और एक समाज से दूसरे समाज में संचार के धीमे होने की वजह से है।

हालांकि, यहां तक कि इस शुरुआती स्तर पर भी, प्रत्येक संगठित समाज में समाचारों का प्रसार एक पहलू था, जिसमें सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों का समाचार शामिल थे। ये कल्पना करना मुश्किल है कि प्रशासन, व्यापार, शिक्षा, आर्थिक और सैन्य विकास में हुई सभी प्रगति खबरों के प्रसार के बिना हासिल की जा सकती थी। लेकिन जो भी खबरें आती थीं, उनका दायरा सीमित था, जिससे उसके स्रोत और श्रोता दोनों ही निश्चित नहीं थे। ऐसे में समाजों में और समाजों के बीच अच्छे विचारों के प्रसार, शासक और बहुसंख्यक निवासियों के बीच संबंधों के साथ ही उनसे बातचीत और स्थायित्व के लिए संचार का महत्व था।

अतीत की संक्षिप्त झलक देखने की कवायद यह अनावश्यक नहीं है। इसे यह बताने के लिए तैयार किया गया है कि आधुनिक संचार की बुराइयों के साथ-साथ बहुत पहले उसके फायदें भी रहे हैं। लेकिन एक अतीत जो आज भी हमारे साथ है जिसमें की दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में संचार के इन दोनों अर्थों का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। ये एक सामाजिक विरासत के रूप में है जो संचार के विकास की वजह और परिणाम दोनों है। संचार के परंपरागत प्रकार कुछ विशेष दशाओं में न सिर्फ आज भी हमारे इस्तेमाल लायक हो सकते हैं बल्कि आधुनिक संचार में गड़बड़ियों को उसने सीखते हुए ठीक भी किया जा सकता है। जिस तरह से संचार का विकास हुआ, उसकी एक बात के लिए प्रशंसा की जा सकती है कि अतीत में इसने जितने

भी रूप अपनाए, उसमें वे अपने उद्देश्य और तरीकों से भविष्य के लिए आश्वासन शामिल होता था। यहां तक कि हमारे सर्वेक्षण के इस शुरुआती स्तर पर भी, उन मुद्दों को चिह्नित किया जा सकता है जो आगे हमारी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे, ये हैं- (क) संचार को नियंत्रित और निर्देशित करने वालों द्वारा हासिल की गई शक्ति, (ख) सामाजिक मान्यताओं और आगे चलकर सामाजिक घटनाक्रम पर इसका असर, (ग) प्रत्येक समाज के भीतर विभिन्न समूहों या वर्गों के बीच असमानताएं, (घ) उपनिवेशिक शासन द्वारा स्थापित किया गया वर्चस्व, या कम से कम विकास की तेज और जल्द शुरू हुई प्रक्रिया से हासिल हुई बढ़त। जैसे ही हम इन समस्याओं चर्चा करेंगे, हम उन्हें अधिक सकारात्मक और आशावादी दिशा में फिर से बयान कर सकेंगे। इस बारे में सोचना संभव है- (क) संचार की प्रक्रिया तक व्यापक पहुंच और उसमें भागीदारी के जरिए सत्ता का विस्तार, (ख) शैक्षणिक और सामाजिक हथियार के रूप में संचार के लाभों का उपयोग, (ग) लोकतांत्रिकरण के जरिए असमानताओं में कमी, (घ) राष्ट्रों की पूर्ण स्वतंत्रता के हकीकत में बदलने के साथ वर्चस्व का अंत ।

2.

वर्तमान की जड़ें

आमतौर पर संचार के आधुनिक युग की शुरुआत छपाई के आविष्कार की तारीख से मानी जाती है। हालांकि ये धारणा सही है, लेकिन दो बातों का उल्लेख जरूरी है। पहला कि, ये जान लेना जरूरी है कि पत्थरों या लकड़ियों पर उकेर कर चित्रों और लिखावट की छपाई के जरिए बहु पुर्नोत्पादन की तकनीक शुरुआत करीब 25 शताब्दी पहले गई। दूसरा कि, इस आविष्कार का प्रभाव पहले तो ज्ञान और विचारों (पुस्तकों के जरिए) के प्रचार और प्रसार

को शानदार तरीके से बढ़ावा देने पर हुआ और बाद में ये समझ में आया कि इसे जन सूचना के लिए भी विकसित किया जा सकता है।

चीन, भारत, मिस्र या ग्रीक-रोमन जैसी सभ्यताओं में विचारों और ज्ञान के अमूल्य भंडार पुस्तकें थीं। इसके जरिए एक ऐसा माध्यम मिला जो थोड़ी सी जगह और टिकाऊ रूप में पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं का संग्रह कर सके। कागज के आविष्कार के साथ ही किताबों के उत्पादन में पहली महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कागज ने पुराने भोजपत्रों या चर्मपत्रों की जगह ले ली। ईसा की पहली शताब्दी में चीन में कागज का इस्तेमाल शुरू हुआ। अरब में कागज का इस्तेमाल 8वीं शताब्दी में और यूरोप में 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कागज की किताब में पन्ने लपेटे होने की जगह बंधे रहते थे, जिससे संदर्भ कार्यों के लिए उनका इस्तेमाल काफी आसान हो गया। पत्थरों और लकड़ियों पर उकेर कर चित्रों और लेखों के पुर्नोत्पादन की तकनीक 500 ईसा पूर्व में ईजाद की गई थी। इसके बाद अगला बड़ा कदम छपाई का आविष्कार था। इस तकनीक का विकास पहले चीन में 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ और उसके बाद 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में हुआ। इसके साथ ही एक ही किताब की कई प्रतियां तैयार करना संभव हो गया। इससे हस्तनिर्मित प्रतियों को तैयार करने में लगने वाली मेहनत से छूट मिल गई। कुछ प्रभावशाली पुस्तकें धीरे-धीरे एक खास शैक्षिक स्तर के ऊपर कइयों के लिए साझा बैद्धिक सामग्री बन गईं। और उनकी उपलब्धता ने साक्षरता को प्रोत्साहित किया, जो 16वीं शताब्दी तक कुछ देशों में कम से कम शहरी आबादी के व्यापक वर्गों तक फैल गई।

ये बदलाव धार्मिक या राजनीतिक संरक्षकों की मदद के बिना संभव नहीं थे। विचारों की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर हमेशा से ही

जनता और निजी शासकों और आजाद मिजाज के बीच टकराव रहा है। भारत में अशोक के समय में स्वतंत्रता की संभावित सीमाओं पर बहस देखने को मिलती है, असंतुष्ट हिब्रू संप्रदाय के लोगों को गुफाओं में शरण लेनी पड़ी जहां उन्होंने अपना धार्मिक दस्तावेज छिपाया। एथेंस में, 'युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए' सुकरात को अपनी जान गवानी पड़ी। छपाई के आने से इस बात की संभावना बढ़ गई की 'खतरनाक विचारों' को उनके प्रवर्तक तत्काल प्रभाव से कई क्षेत्र में प्रचारित कर सकते हैं, इसको देखते हुए इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। तब प्रौद्योगिकीय प्रगति को अक्सर चुनौती के रूप में देखा जाता था, ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस जो उस समय अक्सर निषिद्ध थे उन्हें आमतौर पर केवल लाइसेंस के लेने के बाद ही लगाने की अनुमति मिलती थी। कभी-कभी उन्हें वास्तव में नष्ट कर दिया जाता था। दर्शन या प्राकृतिक विज्ञान में किसी नई खोज को नास्तिकता या विधर्म के रूप में बदनाम किया जाता था। कई लोग जिन्हें आज अग्रणी बुद्धिजीवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्रकाशन करने से मना किया गया, वे विश्वविद्यालयों से बर्खास्त हुए, सख्त दंड के हिदायत के साथ उन्हें अपने विचारों को छोड़ने का आदेश दिया गया, जेल में डाला गया, या मार तक डाला गया। मध्य यूरोप के अंधकारवाद ने लंबे समय तक बौद्धिक खोजों के खिलाफ कड़े अवरोध लगाये और ये खोजें पहले पहल अरब या पर्शियन देशों में हुईं। जब प्रिंटिंग और किताबों के व्यापक प्रसार के युग की शुरुआत हुई तो सत्ताधारियों के कोई भी फरमान इस ज्वार को रोक नहीं सके, और बदलाव का रास्ता खुल गया, जिसने नवजागरण और सुधार की शुरुआत की।

17वीं शताब्दी में किताबों के बाद सामयिक पर्चों और फिर समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। कुछ शुरुआती समाचार पत्रों की स्थापना व्यापार, मालों,

जहाजों के आवागमन और इसी तरह की दूसरी सूचनाओं के लिए हुई। उन्होंने नवजात पूंजीवादी व्यवस्था के लिए आवश्यक सेवाएं मुहैया कराईं। कुछ दूसरे पत्रों ने खुलासों, भंडाफोड़ और सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर उपहासात्मक टिप्पणियां की। इसके अलावा कुछ ने किसी लोकप्रिय या लोकतांत्रिक उद्देश्य के समर्थन में जनमत तैयार करने की राह पकड़ी। ऐसे में हम पत्रकारिता के उन प्रकारों के मूल तक पहुंच सकते हैं, जिन्हें हम आज मान्यता देते हैं आर्थिक पत्रकारिता, सनसनीखेज पत्रकारिता, वैचारिक पत्रकारिता, और प्रचार या धार्मिक मकसद की पत्रकारिता। लेकिन राजनीतिक टकराव और खासतौर से स्थापित व्यवस्था के लिए चुनौती होने की स्थिति में प्रेस ने अकसर लोकप्रिय कारण के प्रवक्ता की भूमिका को अपनाया। उदाहरण के लिए टॉम पेन के *कॉमन सेंस* ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह का नैतिक समर्थन दिया। इसी तरह लैटिन अमेरिका में स्पेनिश प्रभुत्व के खिलाफ हुए संघर्ष में प्रेस के एक हिस्से की सामग्री और जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी और जिसने आजादी का नेतृत्व किया। पत्रकारिता का यह ऐतिहासिक रिश्ता आज भी अपने रिपोर्टिंग की सामग्री के रूप में मौजूद है। दुनिया में पत्रकारों को सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारी का एहसास करने में भी इस ऐतिहासिक रिश्ते को देखा जा सकता है।

शुरुआती समाचार पत्रों के बिल्कुल अलग व्यक्तिगत स्वर थे। पाठकों और लेखकों, संपादकों या प्रकाशकों (जो एक ही व्यक्ति हो सकते थे) के बीच कई कड़ियां मौजूद थीं। कोई लिखित सामग्री जिसे शुरू से अंत तक एक ही लेखक ने अपने नाम के साथ लिखा हो वे लोगों पर असाधारण प्रभाव छोड़ सकती है। चाहें वे बहुत जानकार खबरनवीस हों या गपशप लिखने वाला, विधायक और कल के समाज निर्माता हों, नैतिकताओं का मजाक उड़ाने वाले

हों या अंधविश्वास और पादरियों के दुश्मन, इस तरह के पत्रकार साहस और ईमानदारी से जनहित में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से वे सत्ता का अपमान करने वाले थे और उनकी गतिविधियां सत्ता के लिए खीझ पैदा करने वाली या चुनौती भरी थीं। सरकारों ने इससे निपटने के लिए प्रतिबंधक कानूनों तहत जब्ती, निषेधाज्ञा और मुकदमों तथा कभी-कभी संपादकों को कारावास के रूप में से जवाबी प्रहार किया।

ब्रिटेन, अमेरिका और क्रांतिकारी फ्रांस में प्रेस की आजादी की लड़ाई को 18वीं शताब्दी के अंत में सैद्धान्तिक रूप से जीत मिली। हालांकि इसके बाद भी इसे नियंत्रित करने और काबू में करने के प्रयास होते रहे और ऐसा आज भी जारी है। उन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर नजर डालना महत्वपूर्ण होगा जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा का उभार हुआ। सत्ता प्रतिष्ठान, जो पूर्व सेंसरशिप या दूसरे जरियों से नियंत्रण के अधिकार का दावा करते थे, उनके खिलाफ विचारों के प्रसार के लिए मुख्य माध्यम प्रिंटिंग प्रेस थे। विरोधियों ने प्रिंटिंग प्रेस के बिना रुकावट के इस्तेमाल और छपने वाली सामग्री के मुक्त प्रसार की मांग की। इस प्रकार, एकदम शुरुआत से ही संचार का राजनीतिक आयाम महत्वपूर्ण बन गया। इसने स्थापित सत्ता से अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपने ही तरीकों का इस्तेमाल किया। तकनीक के इस्तेमाल पर जीत एक तरह से सत्ता को प्रभुत्व और उसके एकाधिकार को चुनौती थी।

फ्रांस में 1789ई. में घोषित "मनुष्य के अधिकार घोषणा पत्र" की मुख्य मांग विचारों और मत की अभिव्यक्ति और प्रसार को लेकर थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता का सवाल उठाना और प्रचारित करना शुरू किया उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब अनिवार्य रूप से विचारों की आजादी थी। इसलिए ये

स्वतंत्रता का एक संभ्रांतवादी रूप था, जिसने 'ऊपर से नीचे' संचार की अनुमति दी। इसमें राजनीतिक और बौद्धिक नेता ऊपर थे जहां से नीचे जनता की तरफ संचार का प्रवाह था। हालांकि यह बड़ी आबादी में उन लोगों के लिए था जिनकी छपी हुई सामग्री तक पहुंच थी। अपने हर पाठक तक एक विचारधाराओं की विस्तृत फलक रखे और व्यक्तिगत पसंद और गंभीर सूझ-बूझ को संभव बनाया। शुरुआती दौर में ऐसी आजादी नहीं थी। छपाई उपकरणों की कलात्मक प्रकृति ने इसे उन लोगों की पहुंच में भी ला दिया जो संपन्नता से काफी दूर थे। उन दिनों के प्रकाशित हैंडबिल, पर्चों और घोषणा पत्रों के प्रसार इस बात के गवाह हैं। तकनीकी विकास के उस दौर में प्रेस की आजादी के लिए लड़ाई प्रमुख रूप से अधिकारवादी शासकों के खिलाफ थी। शासक उन खतरों से पूरी तरह सचेत थे जो गैररूढ़िवादी मतों और विचारों के मुक्त प्रसार से उनकी सच्चाई को उजागर कर सकते थे। 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में रूस के जारों जैसे निरंकुश शासन वाले देश में प्रेस को कोई आजादी नहीं थी। न ही औपनिवेशिक दर्जे वाले एशिया और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में कोई वास्तविक प्रेस की आजादी थी। इन देशों में शुरू हुए समाचार पत्रों का स्वामित्व और संपादन यूरोपीय लोगों के पास था और उनका मकसद शासक समुदाय की सूचना संबंधी जरूरतों और उनके परिदृश्य को प्रस्तुत करना था। धीरे-धीरे एशियाई और अफ्रीकी स्वामित्व वाले समाचार पत्र आने लगे और उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में योगदान दिया। उन्हें सभी प्रकार के दमनकारी उपायों का सामना करना पड़ा और अकसर अशांति के समय उन्हें जब्त या प्रतिबंधित कर दिया जाता। इतना ही नहीं, औपनिवेशिक शासन का संचार की संरचना पर जोरदार असर हुआ, ठीक यूरोपीय राष्ट्रों की तरह। इस तरह का औपनिवेशिक प्रभाव

राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी जारी रहा। ये प्रभाव तब भी रहा जब दूसरी केंद्रीय शक्तियों ने संचार के तरीकों पर अधिक या कम ही सही, नियंत्रण करके आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव में इजाफा किया। जहां इस तरह के प्रभाव आज भी मौजूद हैं वहां की मूल समस्या की जड़ यही है।

सभी बाधाओं के बावजूद पूंजीवादी विश्व में समाजवादी आन्दोलन के लिए, तानाशाही के लोकतांत्रिक विरोध के लिए और औपनिवेशवाद के खिलाफ बढ़ते विद्रोह के प्रवक्ता के रूप में काम करके राष्ट्रवादी, उग्र सुधारवादी या क्रांतिकारी विचारों की पत्रिकाओं ने अपना प्रभाव छोड़ा। कैवर के *रिसोर्जिमेंटो (Il Risorgimento)*, लेनिन की *इस्क्रा (Iskra)*, गांधी की *हरिजन,* के साथ ही कई अन्य पत्र-पत्रिकाओं ने वैचारिक क्रांति की अगुवाई की और निष्क्रिय पड़े लाखों लोगों को जगाकर और उन्हें संगठित कर स्थापित शक्ति संरचना को झुकाने में मदद की। इन दशाओं में पत्रकारिता एक पेशे की जगह एक मिशन अधिक बन गई। ये पत्र न केवल एक हाथ से दूसरे हाथ में गए, बल्कि उन्हें साक्षर से लेकर निरक्षर तक, सब ने जोर से पढ़ा। इसलिए उनका प्रभाव उनकी सामान्य प्रसार संख्या के मुकाबले कहीं अधिक था।

धनी राष्ट्रों में, अब समाचार पत्रों का बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन होने लगा जिसे बहु-प्रसार प्रेस कहा जा रहा है। शिक्षा में उन्नति ने साक्षरता को बढ़ावा दिया और अधिक से अधिक लोग समाचार पत्र खरीदने में सक्षम हुए। ऐसा दो वजहों- वेतन में वृद्धि और समाचार पत्रों के सस्ता होने से हुआ। प्रेस की आम पहुंच के जो अन्य कारक थे, उनमें 'लांग रन' छपाई की तकनीक को अपनाना, रेलवे के जरिए प्रसार करना, विज्ञापनों से मिला वित्तीय सहयोग और टेलीग्राफ़ के जरिए प्रेषित ताजा खबरों का तेज प्रवाह जैसी वजहें शामिल हैं।

समाचार एजेंसियों ने वाजिब कीमतों पर खबरें उपलब्ध कराया। इनका विकास 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने परिचालन का विस्तार किया। इन समाचार एजेंसियों का अग्रणी प्रयास जन दैनिक प्रेस के उदय और उसके चालू रखने में एक साथ किए गए योगदान के रूप में था| व्यापार और वाणिज्य को आगे और बढ़ावा देने और दुनिया को अधिक से अधिक छोटा करने में उनका उल्लेखनीय योगदान था। चूंकि ये उपनिवेशवाद के उत्कर्ष का समय था, इसलिए ठीक उसी समय उन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के हितों को बढ़ावा दिया, मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने और केंद्रीय शक्तियों के वाणिज्यिक और राजनीतिक हितों के विस्तार में मदद की।

जहां एक तरफ प्रेस का विकास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका प्रभाव बदली सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं में भी दिख रहा था जिसमें लंबे समय से बहुसंख्यक आबादी राजनीतिक उदासीनता का शिकार होकर अलग-थलग थी। घनी आबादी वाले औद्योगिक कस्बों और यहां तक कि गांवों में भी कामकाजी लोग पहले के मुकाबले कहीं अधिक अच्छी तरह से सूचनाएं पा रहे थे और बहस वाले मसलों पर भी वे अपनी राय कायम कर सकते थे। आज हम जनमत को जिस रूप में देख-समझते रहे हैं, वे वास्तविकता बन गई। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाने लगा और उसने खुद के आधुनिक संवैधानिक राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित कर लिया। जिसमें सरकारें आमतौर पर चुनाव परिणामों के साथ बदलती हैं न कि कुलीन वर्ग के आपसी दांवपेंच के जरिए या एक सम्राट की लहर के चलते। साथ ही समाचार पत्र अब इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि वे सत्ता प्रतिष्ठानों के दबावों की अवहेलना कर सकते थे। ये विचार कि उनके पास अधिकार है और

इस वजह से उनका कर्तव्य भी है कि वे अपनी आजादी को बरकरार रखें यह एक स्वीकार्य सिद्धांत बन गया।[1] प्रेस को सरकारी हस्तक्षेप से आजादी मिली, जिसने प्रेस को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया, लेकिन ये हमेशा उन निजी हितों से स्वतंत्रता नहीं हो सका जिसका इन पर नियंत्रण था।

लेकिन नई परिस्थितियों में यह भी दिखा कि एक तरफ तो अच्छे पढ़े-लिखे लोग ऐसे गंभीर या गुणवत्तापूर्ण समाचार पत्र पढ़ रहे थे जो अपने प्रसार क्षेत्र से बाहर भी अपना प्रभाव छोड़ने का दमखम रखते था, वहीं दूसरी तरफ लोकप्रिय समाचार पत्र थे जो राजनीतिक या सामाजिक घटनाक्रम की कीमत पर मुख्य रूप से अपराध, घपलों और सनसनीखेज घटनाओं को जगह देते थे। इनके बीच खाई बढ़नी शुरू हो गई। मालिक जो ज्यादातर इस धंधे ज्यादातर अपने पाठक बढ़ाने के मकसद से आए थे ताकि कमाई ज्यादा हो सके। ऐसे मालिक अकसर अपने ग्राहकों के हितों और उनकी बुद्धि को कमतर समझते थे।

ऐसे देशों में जहां 20वीं शताब्दी के बाद समाजवादी राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, वहां प्रेस का स्वामित्व, चरित्र और उद्देश्य उसी के अनुरूप अलग-अलग मात्रा में बदल गया। इससे न सिर्फ जनता के एक बड़े तबके तक पाठकसंख्या को बढ़ाने में मदद मिली बल्कि साथ ही एक ऐसा वृहद प्रेस तैयार हुआ जिसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था। इसने एक ऐसे प्रेस को भी बढ़ावा दिया जिसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न जानकारियों के विस्तार, अलग-अलग दृष्टिकोणों का प्रसार और महत्वपूर्ण स्वतंत्र पाठकों को बढ़ावा देने की जगह लोगों को शिक्षित करना और रायशुमारी करना,

सरकार और सत्ताधारी शक्तियों द्वारा तैयार किए गए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाना था।

यद्यपि वृहद पैमाने पर प्रसार वाले प्रेस अभी भी अपने उफान पर है, लेकिन इस दौर का एक अन्य महत्वपूर्ण खोज बिजली से चलने वाले संचार माध्यमों का उदय और विकास है। इन माध्यमों में टेलीग्राफ़, टेलीफोन, रेडियो और सिनेमा शामिल हैं। प्रेस की तुलना में अधिक तेजी से और इसके स्थापित बुनियादी ढांचे की मौजूदगी और अनुभव का फायदा उठाते हुए नई तकनीकों ने जन संचार और व्यापक उपभोग के औद्योगिक युग में सीधे प्रवेश कर लिया है। इस तरह के तकनीकी विकास दुनियाभर के कई देशों में व्यापक राजनीतिक आर्थिक बदलावों के साथ-साथ ही हुए।

इस संक्षिप्त ऐतिहासिक अवलोकन में, हमने लिखित संचार को थोड़े से लोगों से बढ़कर व्यापक स्तर पर होते देखा। हमने प्रेस को उसके संभ्रांतवादी आरंभ से लोकतांत्रिक ढंग से बढ़ते हुए देखा, कम से कम प्रेस के दायरा और अपील के संदर्भ में। और जिन देशों में वृहद प्रेस का जन्म हुआ, वहां हमने एक व्यावसायिक संरचना और व्यावसायिक नजरिए की बढ़ती प्रभाव को भी देखा। हालांकि, इन सभी बदवालों की गति ने देशों के बीच और उनके भीतर नुकसानदेह असमानताओं को बढ़ावा दिया। इसने विविधता, बहुलतावाद और संचार के ढांचे के स्तर पर भी असमानता को बढ़ाया। विकास के विभिन्न स्तरों तथा देश के भीतर अलग-अलग सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया। यहां हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस तरह का आकलन जो कि वास्तव में हमारे वर्तमान की जड़ है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए इस तरह के गंभीर अध्ययन और मूल्यांकन को सही ठहरता है।

3.

भविष्य का निर्माण

आधुनिक युग संचार के क्षेत्र में नए संसाधनों, तकनीक और तकनीकी उपकरणों के तेजी से हो रहे विकास का गवाह है, खासतौर से ऐसे उपकरण जो संकेत और संदेशों को भेजने और उन्हें प्राप्त करने से जुड़े हैं। काफी तेजी से एक के बाद एक खोजें हो रही हैं। एडिसन ने बीती शताब्दी के दूसरे हिस्से के शुरुआती दौर में फोनोग्राफ़ का आविष्कार किया। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन और शमूएल मोर्स ने करीब 1840 में टेलीग्राफी का आविष्कार किया। पहला टेलीग्राफिक संदेश 1844 में भेजा गया, वर्ष 1876 में बेल ने तार के जरिए पहला टेलीफोन संदेश भेजा। करीब 1895 में मार्कोनी और पोपोफ, स्वतंत्र रूप से एक और वायरलेस संदेश भेजने और उसे प्राप्त करने में सफल रहे। वर्ष 1906 में फेसेंडेन ने रेडियो के जरिए इंसानी आवाज को भेजा। वर्ष 1839 में डागेयर ने फोटोग्राफी के लिए एक खास तरीके को खोजा। 1894 में पहली फिल्म प्रदर्शित हुई। 1904 में फोटोटेलीग्राफिक ऐपरेटस (बेलिन सिस्टम) के जरिए पहली फोटो प्रेषित की गई, जबकि 1923 में पहली बार पिक्चर प्रसारित हुई। 1920 में पहला रेडियो प्रसारण नेटवर्क स्थापित हुआ। 1930 में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई और 1954 तक रंगीन टेलीविजन का नियमित प्रसारण शुरु हो गया। अमेरिका और यूरोप के बीच 1857 में पानी के नीचे बिछाए गए टेलीग्राफ केबिल के साथ ही त्वरित अंतर महाद्वीपीय संचार शुरू हुआ। जब कि पहली अंतरअटलांटिक टेलीफोन केबिल सेवा 1956 में जाकर शुरू हो पाई। अंतरमहाद्वीपीय रेडियो टेलीफोन और टेलीग्राफ प्रणाली पहले ही 1920 तक नियमित रूप से काम करने लगी

थी, टेलीप्रिंटिंग 1930 के दशक के आरंभ में शुरू हुई। आखिरकार 1962 में पहले वाणिज्यिक संचार उपग्रह अर्ली बर्ड का प्रक्षेपण हुआ।

20वीं शताब्दी के पहले दशक में रेडियो के आविष्कार के साथ एक लंबी दूरी का संचार साधन तैयार हुआ, जो प्रेस की तरह प्रिंटिंग या भूतल परिवहन पर निर्भर नहीं था, खासतौर से समय की कमी होने के दौरान। जल्द ही समाचार पत्रों में छपने के लिए अपने बयानों को लिखने की जगह लोगों से सीधे संवाद करने के फायदे सामने आए। शुरुआती दिनों में रेडियो सैद्धान्तिक रूप से एक मनोरंजन का माध्यम था। खासतौर से इसने संगीत और नाटक के लिए नई जनता को तैयार किया। लेकिन रेडियो के जरिए समाचारों की रिपोर्टिंग 1930 के दशक से महत्वपूर्ण होने लगी, जिससे पत्रकारिता के पेशे की नई शाखा की शुरुआत हुई।

हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के चलते टेलीविजन में देरी हुई, लेकिन वे 1940 के दशक के अंत में और 1950 के दशक के आरंभ में विकसित देशों की जीवनशैली की विशेषता बन चुका था। रेडियो की तरह इसने भी मोटेतौर पर सस्ते और सुविधाजनक रूप में मनोरंजन को पेश कर अपने लिए दर्शक सुरक्षित कर लिए। हालांकि टेलीविजन के समाचार प्रसारण ने घटनाएं जैसे घटी थीं, उन्हें उसी रूप में दर्शकों को दिखाकर शक्तिशाली प्रभाव डाला, जबकि वृत्तचित्र कार्यक्रमों (चाहें फिल्म के रूप में हो या वीडियो टेप के रूप में) ने वास्तविकताओं की लोकप्रिय धारणा को साझा किया। इसमें दूर स्थित देशों में होने वाली घटनाएं शामिल थीं। स्पष्टता में सुधार, रंगीन चित्रों के आविष्कार और पिछले दो दशकों में वीडियो कैसेट के आविष्कार से अनुभूति की जीवंतता और टेलीविजन के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा है।

बीते डेढ़ शताब्दियों के दौरान संचार के लिए तकनीकी सुविधाओं में भारी बदलाव हुए हैं। हाल के डेढ़ दशक बहुत खोजी, उत्पादक और कल्पनाशीलता के रहे हैं। दो बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपग्रह प्रणालियों इंटेलसेट और इंटरस्पुतनिक की शुरुआत क्रमशः 1965 और 1971 में हुई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मानवसहित और मानवरहित दोनों ही तरह के अंतरिक्षयान 1969 में चाँद तक पहुंचने में सफल रहे और हाल में शुक्र और मंगलग्रह पर भी अंतरिक्षयान उतरे हैं। ऐसे में संचार के मकसद से नई संभावनाएं दिखी हैं। टेलीकम्युनिकेशन के मकसद से और कम लागत वाले अर्थ स्टेशन तथा निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के जरिए टेलीविजन कार्यक्रम के वितरण और उन्हें प्राप्त करने के लिए दुनिया के पहले घरेलू उपग्रह प्रणाली का उद्घाटन 1973 में कनाडा में हुआ। इसके अगले साल अमेरिका ने वेस्टार । (WESTAR ।) का प्रक्षेपण किया, जो 80 लाख शब्द प्रति सेकेंड प्रसारित करने में सक्षम था। ये ध्वनि, वीडियो, फैक्स और डाटा संप्रेषित कर सकता था। वर्ष 1977 में एक अलग किस्म के उपग्रह नेटवर्क की सुविधा तैयार हुई, जो मौजूदा प्रणालियों के विपरीत ध्वनि, फैक्स और डाटा को सीधे अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचा सकता था। इसके लिए टेलीफोन लाइन की भी जरूरत नहीं थी। निश्चित दूरी तक संप्रेषण की तकनीक का आविष्कार हुआ- वर्ष 1970 में एक गैलियम आर्सेनाइड लेजर का परीक्षण हुआ जो आदमी के बाल जितने मोटे फाइबर के जरिए अनेकों टेलीविजन कार्यक्रमों को संप्रेषित करने में सक्षम था। वर्ष 1976 में टेलीफोन ट्रैफिक और टेलीविजन सिग्नल के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबिल्स का जमीनी परीक्षण किया गया। ठीक उसी समय जापान में कंप्यूटर नियंत्रित फाइबर ऑप्टिक इंटरएक्टिव तैयार किया गया, ताकि घरों के लिए और घरों से दोतरफा वीडियो सूचनाएं ले जाई जा सके। एक अन्य क्षेत्र में, 1969 में वीडियो कैसेट का आविष्कार हुआ। 1971 में

ऑडियो-वीडियो कैसेट का बाजार हकीकत बन गया। 1979 में उपभोक्ताओं तक पहली वीडियोडिस्क उपलब्ध हो गई। छोटे इलेक्ट्रानिक कैल्कुलेटर के डाटा को भेजने के लिए मशीन बनी। पिछले दस सालों में कई खास तरह के माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं जो आंकड़ों को जुटाने, उन्हें संरक्षित रखने, उनमें सुधार करने और प्रसार करने में सक्षम हैं।

नए सूचना विज्ञान के विकास से उन लोगों के पास सूचनाओं की मात्रा बढ़ी है जिनकी पहुंच इस तरह के तकनीकों तक है। कंप्यूटर और डाटा बैंक का इस्तेमाल लाखों मदों की सूचनाओं को जुटाने, संरक्षित करने और संप्रेषित करने में किया जा सकता है। सिलिकॉन चिप के आविष्कार ने जगह की आवश्यकता घटकर बहुत कम रह गई है। देरी को दूर करने के लिए संप्रेषण के बाइनरी कोड ने एक नई भाषा सृजित की। इस तरह के विकास कई गुना बढ़े हैं, जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इस तरह के संसाधन न सिर्फ सूचना और मनोरंजन से संबंधित थे बल्कि विज्ञान, चिकित्सा, विद्वता और पेशेवर जीवन की सभी शाखाओं और सामान्य रूप से सामाजिक संगठनों से भी जुड़े थे।

इन नई तकनीकों का इस्तेमाल अभी तक मुख्य रूप से कुछ औद्योगिक देशों तक सीमित था, लेकिन अब उन्होंने संचार के नए युग का रास्ता खोला है। अब दूरी एक बाधा नहीं रह गई और अगर सामूहिक इच्छाशक्ति है तो इस ग्रह के किसी एक बिंदु से दूसरे को जोड़ने वाली सार्वभौमिक संचार प्रणाली की गुंजाइश मौजूद है। शुरुआती दिनों में ये तकनीके बोझिल और महंगी थी, लेकिन तेजी से सस्ती हो रही हैं। यह अपनी प्रकृति में ज्यादा सहज हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार लंबे समय तक व्यक्तियों के बीच संचार के लिए सीमित रहने के बाद अब सामूहिक संचार में उपयोग के लिए सहज

रूप से उपलब्ध है। इसके विपरीत, एक वैश्विक प्रणाली की जगह एकीकृत स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त, विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में संचार नेटवर्क के संजाल (वेब) की कल्पना करना संभव है। संदेश के व्यापक विस्तार के लिए उसकी सामग्री में विविधता लाई जा सकती है, उसे स्थानीय और व्यक्तिगत किया जा सकता है। अब इस तरह की नई तकनीकें मौजूद हैं जो सूचना केंद्रों को कई गुना बढ़ाने और व्यक्तियों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान को तेज कर सकने में सक्षम हैं। टेली-प्रोसेसिंग या टेलीमैट्रिक्स और दो या अधिक उपग्रहों के बीच लिंक और संपर्क स्थापित होने से व्यवस्थित एकीकरण की अंतहीन संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। हालांकि, मौजूदा सामाजिक संरचना के तहत, गरीब और सीमांत समूह, जिनका कई समाजों की आबादी में बड़ा हिस्सा है, आने वाले लंबे समय तक इस 'नए युग' से कोई संपर्क नहीं होगा। उनकी मुख्य समस्या वैश्विक संचार प्रणाली से जुड़े मसलों को सुलझाने की बजाए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और जीवन स्तर में सुधार के मुद्दे से अधिक जुड़ी है।

इस प्रक्रिया का महत्व और उसकी असलियत न सिर्फ संप्रेषण की सुविधा और कवरेज के आकार में है, बल्कि मुख्यतः मानव संचार की भाषा की प्रकृति के बुनियादी परिवर्तन में है। जैसे मनुष्य खानाबदोशी और शिकार से कृषि की ओर बढ़ा, उसके साथ ही उसने सीधे प्रकृति के साथ संचार करने की एक समरूपता आधारित प्रणाली विकासित कर ली। औद्योगिक युग में उसने अक्षरों और अंकों की सूचनाओं और संचार प्रणाली का संचालन करना सीखा। अब उसने एकदम नए युग में प्रवेश किया है, जहां सूचनाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। जिसकी वजह से मौजूदा एनालॉजिकल तकनीक को बाइनरी भाषा के विभिन्न रूपों में तेजी से बदलते हुए अपनाने की

जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि एनालॉगिकल भाषा विलुप्त होने के लिए अभिशप्त होगी ठीक वैसे ही जैसे कि मनुष्य ने प्रकृति से संवाद की क्षमता खो दिया है। संचार में मोटे तौर पर जोड़ने का स्वभाव होता है, इसमें हर नई भाषा, पुरानी भाषा को नुकसान पहुंचाए बिना मिलती जाती है।

इससे पहले कि ज्यादातर विकासशील देश इन सभी तकनीकी बढ़त का फायदा लेने में सक्षम हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई सारे बदलाव करने होंगे। क्योंकि फिलहाल तो ये बढ़त उनके लिए मोटे तौर पर सैद्धान्तिक ही है। वास्तव में, कुछ निश्चित परिस्थितियों में या अगर हो सके तो कुछ निश्चित परिस्थितियां बनाकर, हर जगह पुरुषों और महिलाओं को साथ ही साथ समुदायों को इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। ऐसा विकासशील और विकसित दोनों देशों में किया जा सकता है। हालांकि हाल के समय में ऐसी तकनीक केवल कुछ देशों और उनमें भी कुछ लोगों के नियंत्रण में हैं। कुछ देश जहां इनके आविष्कार हुए वे दूसरे देशों के मुकाबले लगातार भारी बढ़त का आनंद ले रहे हैं। जिन देशों में विकास अभी भी कछुआ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वे गरीबी से प्रताड़ित हैं। वहां जरूरी बुनियादी ढांचे का अभाव है। वास्तव में सूचना और प्रौद्योगिकी जिस तरह आज संपत्ति निर्माण का साधन बन गई है, वैसा पहले कभी नहीं था। इस दौर में मौजूद संचार विषमता और असमानता के लिए जिम्मेदार प्रणाली के चलते धनी और गरीब के बीच खाई के और अधिक चौड़ा होने का खतरा पैदा हो गया है।

संचार के क्षेत्र में विकास सिर्फ तकनीकी खोजों से नहीं हुआ है। यह चेतना और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जरूरतों को चलते हुआ है। संचार को नियंत्रित करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग और संचार

के असर से प्रभावित होने वाली जनता के बीच खाई बढ़ रही है। साथ ही साथ समाज और राज्य तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और सरकारी एजेंसियां तथा मीडिया दोनों ही निजी जीवन में धड़ल्ले से बिना इजाजत घुस रही हैं। देशों के अंदर और देशों के बीच संपर्क और ज्ञान तथा विचारों के आदान-प्रदान की आवश्यकता कहीं अधिक अनिवार्य हो गई है। हालांकि ये खतरा भी बरकरार है कि जिसके पास ज्यादा तकनीकी ताकत होगी वे अपने ही विचारों को थोपेंगे। विकासशील देशों में आजादी की लड़ाई और फिर सामाजिक संरचना में बदलाव और आर्थिक समस्याओं के समाधान में संचार एक हथियार की तरह रहा है। सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की तलाश कर रहे लोग संचार प्रणाली के मौजूदा तरीकों से असंतुष्ट हैं। वे मीडिया तक व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर व्यापक पहुंच चाहते हैं। इस जटिल स्थिति ने कई जगहों पर आलोचना और खारिज करने का दिमाग बना दिया है। मास मीडिया लोगों को खारिज कर रहा है। सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रणाली के कार्यकलाप और उस पर बाहरी प्रभुत्व के खिलाफ असंतोष और विरोध है।

संचार के क्षेत्र में वर्तमान और निकट भविष्य की समस्याएं सिद्धांत के रूप में हैं और ये उन पर बहस का मौका देती हैं लेकिन इसके बावजूद दुनिया की बहुसंख्यक आबादी को इनकार ही मिला है। समाज के उत्पादक क्षेत्र सोच-समझकर बनाए गए श्रम संगठनों पर निर्भर होंगे। वे अपनी समझदारी तथा अनुभवों और जब और जहां सूचना की जरूरत होगी तब भी वह उन्हीं पर निर्भर होंगे। हालांकि भोजन, ऊर्जा और अन्य सामग्रियों की कमी वर्तमान की प्रमुख चिंताएं हैं। संचार के संसाधन लगातार बढ़ रहे हैं। अभाव का पुराना सारा इतिहास संपन्नता में तब्दील हो जाएगा। 1980 के दशक

और उसके बाद की दुनिया अवसरों से भरी दुनिया होगी। हालांकि लाखों लोगों की जिंदगी, खासतौर से विकासशील देशों में, अभी भी कठिन और व्यर्थ के परिश्रम तथा अल्पविकसित जीवन-यापन के साधनों से भरी है, निश्चित रूप से तब ये बहुमूल्य संसाधन मौजूद नहीं थे। संचार के संसाधन वास्तव में मानवीय लाभों को बढ़ावा देन के लिए हैं, ये उन फैसलों पर निर्भर करेगा, जो अब लिए जाने हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इन फैसलों को कौन, किन इरादों से लेगा और किसके हित में लेगा। हर समाज को अपनी पसंद तय करनी होगी और प्रगति को बाधित करने वाले भौतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दबाव से उबरने के तरीके तलाशने होंगे। लेकिन विकसित देशों के साथ ही विकासशील देशों में हर समुदायों में पुरुषों और महिलाओं के बेहतर भविष्य के बुनियादी फैसले सैद्धान्तिक रूप से तकनीकी विकास से नहीं जुड़े हैं। बेहतर भविष्य की बुनियाद निश्चित रूप से उस जवाब में है जहां हर समाज को अपने विकास के लिए वैचारिक और राजनीतिक नींव प्रदान की जाए।

अध्याय 2

समकालीन आयाम

1. संचार के कार्य

अगर संचार को उसके व्यापक अर्थों में लिया जाए तो ये केवल समाचारों और संदेशों के लेन-देन नहीं है बल्कि ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि है जिसमें विचारों, तथ्यों तथा आंकड़ों के सभी संप्रेषण और उन्हें साझा किया जाना शामिल है। किसी भी सामाजिक प्रणाली में संचार के मुख्य कार्य को निम्न रूप में चिह्नित किया जा सकता है-

- सूचनाः समाचारों, आंकड़ों, तस्वीरों, तथ्यों और संदेशों, विचार और टिप्पणियों को जुटाना, संग्रहित करना, उनको तैयार करना और उन्हें इस तरह से प्रसारित करना कि वे समझ में आ सके। व्यक्तिगत, पर्यावरणीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर समझदारी से प्रतिक्रिया देना साथ ही साथ इस स्थिति के लिए तैयार करना जिसमें सही फैसले लिए जा सके।

- समाजीकरणः ज्ञान का एक साझा खजाना तैयार करना जो लोगों को उस समाज के प्रभावी सदस्य के रूप में काम करने में सक्षम बनाए जिसमें वे रहते हैं। सामाजिक एकता तथा जागरूकता को बढ़ावा दे, जिससे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी की अनुमति मिले।

- प्रेरणाः प्रत्येक समाज के तात्कालिक और परम लक्ष्य को बढ़ावा देना और निजी पसंद तथा आकांक्षाओं का प्रोत्साहन, व्यक्तिगत या सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सहमति वाले लक्ष्यों को पाने की दिशा में प्रयास करना।

- बहस और चर्चा: सार्वजनिक मुद्दों पर कोई मतभेद होने या किसी सहमति तक पहुंचने के लिए तथ्यों के आदान-प्रदान का प्रावधान करना। व्याप्त लोकप्रिय हितों को बढ़ावा देने और साझा सरोकारों वाले सभी स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में भागीदारी के लिए जरूरी साक्ष्य उपलब्ध कराना।

- शिक्षाः ज्ञान का प्रसार, ताकि बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, जीवन के प्रत्येक स्तर पर चरित्र निर्माण और कौशल तथा क्षमताओं को हासिल करना।

- सांस्कृतिक तरक्कीः अतीत की विरासत को संजोने के मकसद से सांस्कृतिक और कलात्मक उत्पादों का प्रसार। लोगों के व्यक्तिगत फलक को विस्तार देकर, उनमें कल्पनाशीलता को जगा कर और उनके सौंदर्यपरक प्रयोजनों और सृजनात्मकता को बढ़ावा देकर संस्कृति का विकास करना।

- मनोरंजनः व्यक्तिगत और सामूहिक मनोरंजन तथा आनंद के लिए संकेतों, प्रतीकों, ध्वनियों और चित्रों के जरिए नाटक, नृत्य, कला, साहित्य, संगीत, हास्य, खेल आदि का प्रसार करना।

- एकताबद्ध करनाः सभी व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों तक ऐसी विविधतापूर्ण खबरें पहुंचाना जिससे कि वे एक-दूसरे के बारे में जान सके, समझ सकें। एक दूसरे के रहन-सहन की परिस्थितियों, विचारधाराओं और आकांक्षाओं को सराह सकें।

ये कार्य व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अनिवार्य दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही नई घटनाओं पर भी जोर होना चाहिए, या कम से कम वे जिनका महत्व तेजी से

बढ़ रहा हैः सामूहिक संस्थाओं और समुदायों के लिए संचार महत्वपूर्ण जरूरत बन गई है। आज कोई भी समाज तब तक अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता जब तक कि वे राजनीतिक मामलों, अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय घटनाओं या मौसम की सही जानकारी से वाकिफ नहीं है। अगर सरकारों को भविष्य में गतिशील रूप से योजना बनाने में सक्षम बनना है तो उन्हें अपने देश के साथ ही दुनिया के प्रत्येक हिस्से की विभिन्न में होने वाली घटनाओं की सूचना रखने की जरूरत है। इसमें जनसंख्या वृद्धि के चिंताजनक रुझान, पैदावार के नतीजे, पानी की आपूर्ति आदि शामिल है। वैश्विक उत्पादों और मुद्रा बाजार के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना सार्वजनिक प्रशासन अपनी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और समझौते में खुद को असहाय पाएगा। औद्योगिक उद्यमों को भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन की प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए कई स्रोतों से त्वरित सूचनाओं की जरूरत है। बैंक, मुद्रा के उतार-चढ़ाव आदि के बारे में जानकारी के लिए अधिक से अधिक वैश्विक नेटवर्क पर निर्भर हैं। आज सशस्त्र सेवाएं, राजनीतिक दल, एयरलाइन कंपनियां, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और सभी तरह की दूसरी संस्थाएं नियमित और सही सूचनाओं के आदान-प्रदान के बिना काम नहीं कर सकती। हालांकि कई मामलों में सामूहिक सूचना और आंकड़ा प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन या निजी निकायों की जरूरतों के अनुरूप नहीं होती है। मुख्य सरकारी सेवाओं और बड़े उद्यमों और बैंकों को आमतौर पर हमेशा नई सूचनाओं से लैस होने की जरूरत रहती है। लेकिन इनके अलावा कई स्थानीय निकायों, फैक्ट्रियों, फर्मों और एजेंसियों के पास ठोस सूचनाओं की कमी रहती है। इसलिए कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें सूचना प्रणाली पर अभी भी जोर रहता है, जिसका मकसद व्यक्तिगत संचार की जरूरतों को पूरा करना है। इस स्थिति को ठीक करना काफी

महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लाखों लोगों की विकास से जुड़ी संभावनाओं को खासतौर से विकासशील देशों में नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

ऐसा खासतौर से इसलिए है क्योंकि संचार सभी लोगों की जरूरतों से जुड़ा है। इसमें भौतिक और गैर-भौतिक जरूरतें शामिल हैं। मनुष्य सिर्फ रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता है। संचार की जरूरत इसीलिए होती है कि व्यक्ति अपने मन से जीवन को समृद्ध बनाने के लिए दूसरों का सहयोग ले। लोग भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मानव विकास की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। आत्म-निर्भरता, सांस्कृतिक पहचान, आजादी, स्वतंत्रता, मानव गरिमा के प्रति सम्मान, साझा सहायता, माहौल को नया आकार देने में भागीदारी आदि कुछ ऐसी गैर-भौतिक आकांक्षाएं हैं, जिसे सब लोग संचार के जरिए पाना चाहते हैं। बहुत से लोगों का मकसद अधिक उत्पादकता, बेहतर फसल, काबिलीयत में बढ़ोतरी, प्रतिस्पर्धा, बेहतर स्वास्थ्य, ठीक-ठाक बाजार, सिंचाई सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करना होता है। जो कि पर्याप्त संचार और आवश्यक सूचनाओं के बिना संभव नहीं है।

इस बात को भी मानना होगा कि हो सकता है कि ये सब काम पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हों और इनके अलग और विपरित गुण भी हों। सूचनाओं में आधी-अधूरी सच्चाई और झूठ, एकतरफा विश्वास और प्रचार के मिलने से उसे आसानी से भ्रष्ट बनाया जा सकता है। इसी तरह संस्थागत संचार नागरिकों को सूचित करने, उन्हें नियंत्रित करने या उन्हें चढ़ाने-बढ़ाने का काम कर सकता है। हालांकि विषय-वस्तु अकसर व्यक्तिगत पहचान को कायम रखती है लेकिन ये दृष्टिकोण और आकांक्षाओं के बेहतर बनाने का काम कर सकती है। कई तरह के स्रोत और संदेशों का इस्तेमाल करने वाली सूचना प्रणाली खुली सोच को बढ़ावा दे सकती है (हालांकि अति होने की

दशा में विरक्ति या अलगाव का भी खतरा है), जबकि अगर व्यवस्था इस जरूरत को नज़रअंदाज करती है तो दिमाग को वश में करने या किसी बुरे से प्रभावित होने को बढ़ावा मिलता है। सीधा बात ये है कि संचार विभिन्न समुदायों और देशों की तरह-तरह की जरूरतों से अनिवार्य रूप से जुड़ा है। इसे अकसर नज़रअंदाज किया जाता है और कमतर आंका जाता है। हालांकि इसे स्वीकार किए बिना मुख़्तलिफ़, विभाजित और परस्पर निर्भर विश्व में संचार की समस्याओं के प्रति कोई भी यथार्थपरक नजरिया नहीं हो सकता है। इसलिए संचार प्रत्येक समाज की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग प्रभाव छोड़ता है। वास्तव में, समकालीन समाज जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि कई समकालीन समाज एक साथ होते हैं।

संचार के कार्यों के बारे में विचार करते हुए जो एक अन्य घटक इसमें शामिल है वे है विषयवस्तु, संदर्भ और मीडिया के महत्व के बारे में बहस करना। कुछ सिद्धान्त ये मानते हैं कि संचार के साधन और खासतौर से मास मीडिया का प्रभाव विषय-वस्तु के मुकाबले अधिक होता है। वास्तव में उनका मानना है कि माध्यम ही संदेश है। दूसरे तरह के लोग विषयवस्तु को ही मुख्य मानते हैं। उनका मानना है कि इसके प्रभाव पर माध्यम का केवल मामूली सा असर ही होता है। इसके अलावा कुछ अन्य उन सामाजिक संदर्भों को देखते हैं, जिसमें संदेश निर्धारित कारक के रूप में संप्रेषित किया जाता है। ये नजरिया अधिक पूर्ण और अधिक सामाजिक है। ये संचार की भूमिका के बारे में सवाल का जवाब देने में अधिक सफल प्रतीत होता है।

यद्यपि पहला प्रभाव ये हो सकता है कि ऐसा मुद्दा प्रधानतः सिद्धान्तवादियों और शोधकर्ताओं की चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इस पर समाज के व्यापक हिस्से द्वारा पर्याप्त विचार किया गया है। इसमें राजनीतिज्ञ, निर्णय

लेने वाले, योजनाकार, पेशेवर और स्वयं आम जनता शामिल है- जिसे समाधान की खोज के लिए सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। वास्तव में, इस तरह के रुझान के उभार की शुरुआत हुई है। आज की सोच मीडिया पर कम केंद्रित है, बल्कि तकनीकी के आधुनिकीरण तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के साथ-साथ स्वयं संदेश पर अधिक है। संदेश की प्रकृति, भूमिका और विषय-वस्तु, क्या वे छिपा हुआ है या प्रकट है, अस्पष्ट या स्पष्ट है।

ये वे दिशा है जिस ओर चिंतन और बहस बढ़नी चाहिए, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि मानव संचार के विकास से संबंधित सभी लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनके प्रयासों को इस राह पर आगे बढ़ाया जा सके।

2. **सामाजिक जरूरत**

अतीत में संचार व्यवस्था को अकसर समाज के भीतर एक अलग घटना के रूप में देखा जाता था। तब संचार व्यवस्था का मतलब तकनीकी से था जिसका समाज के अन्य पहलुओं से कमोबेश कटा हुआ था। राजनीतिक व्यवस्था में इसका स्थान, सामाजिक संरचना के साथ इसका जुड़ाव और सांस्कृतिक जीवन पर उसकी निर्भरता पर शायद ही कभी ठीक से विचार किया गया हो। ऐसे में हो सकता है कि समाज गलत रास्ते की ओर बढ़े या गलत प्राथमिकताओं को अपना ले। हो सकता है कि अपनी सारी मेहनत इस तरह के बुनियादी ढांचे और तकनीकी खोजों में लगा दे जिसकी वास्तव में उसे कोई जरूरत ही ना हो। आज इसे अधिक व्यापक रूप लिया जा रहा है और इसे एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। इसके बारे में किसी एक पहलू से नहीं बल्कि हर पहलू से और व्यापक सामाजिक संदर्भों में अध्ययन

होना चाहिए। आधुनिक विश्व में, इन अंतरसंबंधों को लेकर जागरूकता पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ी है।

यह स्वाभाविक ही है कि संचार को जल्द ही एक ऐसी ताकत के रूप में देखा जाने लगा जो पूर्ण और सर्वव्यापी है। आधुनिक शोध ने ऐसे अति-सरलीकरण को बेकार सिद्ध कर दिया है। सक्रिय करने, सामाजिक बनाने, एकरूप बनाने और यहां तक कि लोगों द्वारा अपनी संस्कृति को अपनाने में संचार की क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि ठीक उसी समय श्रव्य-दृश्य मीडिया के मानक स्थापित करने और गलत प्रभाव छोड़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस पर नजर रखने वाले बाकी लोग इस बात से आश्वस्त थे कि मीडिया का ऐसा शक्तिशाली सामाजिक प्रभाव है जो कि अपने लक्षित समूह को बता सकता है कि कैसे सोचा जाए और कैसा व्यवहार किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि मास मीडिया- प्रेस, रेडियो और टेलीविजन- में न सिर्फ प्रतिबिंबित करने बल्कि जनमत तथा नजरिया को आकार देने की क्षमता भी है। लेकिन कई पर्यवेक्षक मानते हैं कि मीडिया ज्ञान का व्यापक संसार और दृष्टिकोणों के विकल्प पेश करने की जगह वास्तविक दुनिया के प्रति एक भ्रामक धारणा ही पैदा करता है। एक हद तक, जानबूझकर या अनजाने में वो सामाजिक एकरूपता और सांस्कृतिक अलगाव को बढ़ा सकता है और दुनिया का कोई भी हिस्सा इन जोखिमों से मुक्त नहीं है। खासतौर से, मीडिया के उद्योग बनने के बाद से अलगाव को लेकर ये दबाव बढ़ गया है। बड़े बाजार तक पहुंचने की होड़ में और जनता जो चाहती है या ऐसा मान लिया जाता है कि जनता यही चाहती है और उसे वो देना, इस चक्कर में निरपवाद रूप से नहीं तो भी अक्सर जो उसे परोसा जाता है वो बहुत ही घटिया किस्म का होता है। चाहें सार्वजनिक हो या

निजी स्वामित्व वाला मीडिया हो, विज्ञापनों पर उनकी बढ़ती निर्भरता के चलते व्यावसायिक मानसिकता का रुझान बन गया है, जिसमें उपभोग ही अंतिम मकसद है। कई लोगों का कहना है कि विचारों की बहुलता और ज्ञान के बढ़ते हुए प्रसार पर आधारित संस्कृति को बढ़ावा देने की बजाए मीडिया दुनिया को लेकर एक मिथकीय दृष्टि तैयार करता है। कुछ मामलों में, संदेशों की एकरूपता और मानकीकरण बाजार के कानूनों की कमी को दर्शाता है। ऐसे ही प्रभाव वहां देखने को मिलते हैं जहां सूचना देने की शक्ति एक छोटे वर्ग के हाथों में है और जो तथ्यों तथा सूचना के स्रोत दोनों को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक या नौकरशाही के फैसले बौद्धिक बाँझपन को बढ़ावा दे सकते हैं। जहां सत्ता का प्रवाह मुख्य रूप से ऊपर से नीचे की तरफ है, वहां मीडिया स्वतंत्र विचारों और आलोचनात्मक मूल्यांकन की जगह किसी के द्वारा मंजूर की गई बातों या विचारों की बढ़ावा देती है। एक तरफा दिशा में काम करने के दौरान कभी-कभी मीडिया आम जनता के बीच ऐसे मूल्यों और मान्यताओं को संप्रेषित करने में कामयाब हो जाता है जिसे प्रभावशाली वर्ग बढ़ावा देना चाहता है। मोटे तौर पर जनता उनमें अपनी वाजिब चिंताओं और आकांक्षाओं का अक्स खोज पाने में विफल रहती है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि मीडिया, खासतौर से टेलीविजन ने कई बार लोगों को अलग तरह की जीवनशैली और आकांक्षाओं को भड़कीले रूप में दिखता है, हालांकि ऐसा हर बार जानबूझकर नहीं करता है। इसका असर ये होता है कि असंतोष, प्रतिकूल सांस्कृतिक मूल्यों और विरोध के विभिन्न रूपों को जायज ठहराया जाने लगता है।

फिर भी, कुछ हद तक इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। हाल के अध्ययन बताते हैं कि कई कारक और कई विपरीत धारणाएं काम कर रही हैं, जो एक

दूसरे पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। ये अब साफ होता जा रहा है कि संचार माध्यमों के बुरे कामों या गड़बड़ियों का रिश्ता वास्तव में समकालीन समाजों में शामिल विरोधाभासों से है। सामाजीकरण की प्रक्रिया के कई प्रभाव हैं- वास्तविक या आभासी, गहरे या उथले, स्थाई या अल्पकालिक- जिसके लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इनमें से संचार केवल एक कारक है।

सरसरी तौर पर मीडिया जैसा दिखता है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो समाज में जो हो रहा है उसकी गलत तस्वीर ही हमें दिखेगी। ये सवाल पूछने की जरूरत है कि संचार और खासतौर से जनसंचार कैसे और किन परिस्थितियों में सामाजिक बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में ठीक से काम करेगा। ये कहना तो अति होगी कि सभी अच्छे बदलाव मीडिया की वजह से हैं या फिर जो भी हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है वह मीडिया की देन है। दूसरी ओर उन लोगों का हो-हल्ला भी अतिरंजित लगता है जो प्राथमिक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में गिरावट, स्थानीय परंपराओं के विलुप्त होने और संस्कृति में सेंध के लिए मीडिया को दोषी बताते हैं। संचार के पर्याप्त प्रभाव के बावजूद इसके पास वास्तव में जितनी शक्ति है, उससे कहीं अधिक अच्छा, बुरा या इसे बहुत अधिक शक्तिशाली कहना गलत होगा।

ऐसे में इस निष्कर्ष तक पहुंचना गलत लगता है कि संचार स्वयं में अच्छा है या स्वयं बुरा है। संचार की संरचना मीडिया द्वारा संप्रेषित संदेशों की तुलना में अधिक निष्पक्ष नहीं है। बुनियादी ढांचे और तकनीकी के इस्तेमाल के बारे में कोई फैसला करना ठीक उसी तरह से है जैसे कि समाचार, आंकड़ों और किसी कार्यक्रम की विषयवस्तु के बारे में फैसला लिया जाता है। एक दूसरा भ्रम, संदेश को पूरी तरह तटस्थता के साथ प्रसारित करने को लेकर

है। ज्यादातर मामलों में संदेश किसी के व्यक्तिगत फैसले होते हैं। उन्हें व्यक्त करने के लिए बस उन्हें शब्दों में गूंथ दिया जाता है। मीडिया पर जो लोग पूरा या कुछ हद तक भरोसा करते हैं, उन्हें जो सच्चाई दिखाई देती है वो झूठ है। ये भी जरूर याद रखना चाहिए कि संचार शक्तिशाली है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं। ये न तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों को और न ही सामाजिक जीवन के सार-तत्व को बदल सकता है। संचार उस समय सबसे अधिक प्रभावी होता है जब उसके प्रभाव को अन्य सामाजिक कारक मजबूती देते हैं और सूचित किया गया संदेश पहले ही जनमत या उभरते हितों में दिखाई दे चुका हो। जैसा कि ईसप (यूनान के पुराने कहानीकार) ने कहा है कि संचार की सभी सुविधाओं का इस्तेमाल बेहतरी या बुरे के लिए किया जा सकता है। ये देखना संचार नीति निर्माताओं और इस पेशे से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि जोखिम कम हों और गलतियों को ठीक कर लिया जाए। लेकिन प्रत्येक समाज में कुछ अन्य ताकत भी होते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, कई समाजों में ऐसी ताकत होती हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है खतरों पर नजर रखें और गलतियों को सही करें। कई सरकारों ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षण देने के लिए तैयार की गई नीतियों को अपनाया है। राजनीतिक गुणागणित से हो सकने वाले खतरों को जमीनी स्तर पर सक्रियता लोगों की संचार की 'वैकल्पिक' प्रणालियों से चुनौती मिली है। अब सीधे उनकी अनदेखी करनी मुश्किल है। प्रतिरोध और विरोध के संसाधन संचार के आधिकारिक तंत्र के मुकाबले अधिक व्यापक हैं। यहां इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा कि संचार नीति के नियंत्रण और तंत्र में

लगे लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि आखिरकार जब सामाजिक ताकत जागकर एकजुट हो जाती है तो चलती उसकी है।

ये बातें इन पंक्तियों के अनुरूप है कि हमारी सोच हमें आगे ले जा रही है। शुरुआत से अब तक दो मुख्य निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं। एक तरफ तो विविधता और बहुलतावाद ऐसे मूल्य हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचाने की जगह बढ़ावा देना चाहिए। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कई तरह के सामाजिक मॉडल और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच, दोनों ही जगह विकास के विभिन्न स्तर और विकास के विभिन्न रास्ते मौजूद हैं, ठीक उसी तरह संचार के संसाधनों की अवधारणा और इस्तेमाल को लेकर भी मतभेद है। दूसरी तरफ, शैली और विषयवस्तु के लिहाज से संचार में सुधार के उपायों की सफलता जटिल रूप से उन उपायों से जुड़ी है, जिनका मकसद समाज को कम दमनकारी और असमान तथा अधिक न्यायपूर्ण व लोकतांत्रिक बनाना है। इस तथ्य को छिपाने की जगह उसे उभारना चाहिए।

3. **राजनीतिक औजार**

समग्रता में संचार को इसके राजनीतिक आयामों, इसकी समस्याओं के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखे बिना उनका समाधान भी नहीं किया जा सकता है। अगर राजनीति शब्द का इस्तेमाल 'उच्च' भाव के रूप में किया जाए तो उसके संचार के साथ बेहद मजबूत संबंध हैं।

दो अलग, हालांकि एक दूसरे से संबंधित सवालों पर भी गौर करने की जरूरत है। राजनीति कितना और किस तरह संचार को प्रभावित करें? और

तब कितना और किस तरह से संचार राजनीति को प्रभावित कर सकता है? संचार और शक्ति तथा संचार और स्वतंत्रता के बीच नाजुक संबंध हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वहां की परंपराओं, संसाधनों, सामाजिक व्यवस्थाओं और विकास की जरूरतों के अनुसार इस तरह के संबंध होने चाहिए की नहीं, इस बात को लेकर विभिन्न अवधारणाएं दी गईं हैं। फिर व्यापक आम सहमति की कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। खासतौर से तब जब बहस में यथार्थवाद अधिक और बयानबाजी को कम, लचीलेपन को अधिक और पक्षपात को कम जगह मिले। आमतौर पर बहसें अंतर्मुखी और असहिष्णु होती हैं।

आजादी का आनंद लेने या उसका उपभोग करने का तरीका अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय विधि व्यवस्था या संविधान के अनुसार होना चाहिए। आमतौर पर ये माना जाता है कि आजादी कानूनों का पालन करने के वादे के साथ मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से दूसरों की आजादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आजादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करने की जरूरत है। संचार के क्षेत्र में इसका अर्थ है कि मुख्यरूप से सत्य के प्रति सचेत रहना और सच्चाई को बताने के लिए शक्ति का न्यायसंगत इस्तेमाल करना। हमें ये पूछना चाहिए कि किस आधार पर हम आजादी का दावा कर रहे हैं। संचार को ग्रहण करने वाला और संचार करने वाले नागरिक या सामाजिक समूह के रूप में मिलने वाली आजादी की तुलना एक ऐसे निवेशक को मिलने वाली आजादी से नहीं की जा सकती है, जिसका मकसद मीडिया से मुनाफा कमाना है। इसमें पहला, बुनियादी मानवाधिकारों को संरक्षण देता है जबकि दूसरा, एक सामाजिक जरूरत के व्यावसायीकरण की इजाजत देता है। अब जब कि ये सभी बातें साफ हो चुकी हैं तो यह

समझ लेना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी का सिद्धान्त में कोई अपवाद नहीं है और मानवीय गरिमा के अनुरूप ये दुनिया भर के लोगों पर लागू होता है।[2] ये आजादी लोकतंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक है, जिसे लगातार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के साथ कठिन संघर्ष और भारी बलिदान की कीमत पर हासिल किया गया है। यहां तक की जान की कीमत पर भी। साथ ही ये लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा आवरण भी है। किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आजादी की मौजूदगी या उसकी गैर-मौजूदगी उस देश में आजादी के बारे में सभी पहलुओं में सर्वाधिक भरोसेमंद प्रतीक है। आज, दुनिया भर के कई देशों में, नौकरशाही या वाणिज्यिक सेंसरशिप के द्वारा, इसके पक्षकारों को धमकियों और सजा द्वारा और एक समान व्यवस्था के द्वारा आजादी को पैरों तले रौंदा जाता है और इसका उल्लंघन किया जाता है। सच्चाई ये है कि एक ऐसे देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही जाती है जहां व्यवहार में उसके होने की कोई गारंटी नहीं है। इसी रह दूसरी स्वतंत्रताओं (संघ की आजादी, सभा करने की आजादी, शिकायतों के निपटारे के लिए प्रदर्शन की आजादी, मजदूर संघों में शामिल होने की आजादी) का होना मनुष्य के संचार के अधिकार के अनिवार्य घटक हैं। इन स्वतंत्रताओं में किसी तरह की बाधा का परिणाम अभिव्यक्ति की आजादी में अवरोध के रूप में होगा।

जहां सत्ता द्वारा आजादी पर सीधे हमला नहीं किये जाते हैं वहां हो सकता है कि संचारकों पर स्व-नियंत्रण के जरिए आजादी को सीमित कर दिया जाए। पत्रकार अपने पास मौजूद तथ्यों को कई वजहों से नहीं प्रकाशित कर सकते हैं। इसमें सरासर कायरता, सत्ता संरचना के प्रति अत्यधिक सम्मान या कुछ मामलों में तो कहीं अफसरशाही के प्रति कोई अपराध न हो जाए ये

डर भी बना रहता है। ऐसे में सूचना के स्रोत तक पहुंच खोने का जोखिम बना रहता है। फिर भी सेंसरशिप की तरह ही स्व-नियंत्रण जैसे नाजुक विषय जिसे थोड़े अच्छे शब्दों में संयम भी कहा जाता है पर बहस होनी चाहिए।[3][4]

किसी भी स्थिति में, आधुनिक दुनिया की हर राजनीतिक बहस में स्वतंत्रता की अवधारणा केंद्रीय बिंदु होता है। नीतियों तथा निर्णयों से संबंधित ढेर सारे विवादों से ये जुड़ा होता है। इसे बहुत अधिक सम्मान मिला है, इसके बावजूद कुछ मामलों में ये सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह जाती है। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में इसे साकार रूप देने या कम से कम उस दिशा में आगे बढ़ने का वादा किया जाता है। ये सही है कि 'स्वतंत्रता' शब्द (साथ ही 'लोकतंत्र' 'समाजवाद' और 'शांति' जैसे दूसरे शब्द) की व्याख्या विभिन्न तरीके से की जाती है। ऐसे में स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वभौमिक स्वीकार्य तरीके से परिभाषित करना बहुत कठिन काम लगता है। जब स्वतंत्रता की व्याख्या की जाती है तो उसमें हितों को अलग करके नहीं देखा जाता और हाल के इतिहास में तो इस तरह की व्याख्या ने एक ठोस आकार ले लिया है।

शुरुआती दिनों में केवल 'विचारों और मत' की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता था। बड़े स्तर पर प्रेस के विकास और उसके स्थायी रूप होने के साथ सूचनाओं के प्रसार पर जोर दिया जाने लगा। जिसमें तथ्यों और ताजा घटनाओं के बारे में समाचार शामिल थे। सूचना की आजादी को सर्वोच्चता दी गई, नागरिकों के सूचना का अधिकार का मतलब है उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली बातों से सूचित होना, उन्हें फैसले लेने और सोच-विचार करने मदद करना। नई तकनीक ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर

सूचनाओं तक पहुंच को बेहतर बनाया, जिससे सूचना के अधिकार के लिए संभावनाएं व्यापक हुईं। इस स्वतंत्रता का दूसरा पहलू पत्रकारों के लिए तथ्यों और दस्तावेज के रूप में सूचना हासिल करने की आजादी है। गोपनीयता को दूर करने की आजादी है, जिसके पर्दे से राजनीतिक कृत्य ढंके हुए हैं। पत्रकारों को ऐसी सूचनाओं को प्रकाशित करने की आजादी है।

लेकिन विकसित तकनीकी ने उस व्यवस्था को भी बदला है, जिसके तहत बुनियादी सिद्धान्त लागू किए जा सकते हैं। इसने स्वतंत्रता के लिए एक नया खतरा पेश किया है। प्रत्येक नई खोज इस बात का उदाहरण है कि उसके लिए जिस स्तर पर निवेश की आवश्यकता है, वो केवल पर्याप्त पूंजी के मालिकों के लिए ही संभव है। फिर चाहें वो निजी हो या सार्वजनिक हो। ज्यादातर देशों में लगातार महंगे हो रहे छापाखानों और खासतौर से रेडियो तथा टेलीविजन जैसे नए मीडिया तक इस विशेषाधिकार का अर्थ है कि सीमित धन वाले लोग इस प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठा सकते हैं। सिद्धान्त के रूप में हर कोई अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का आनंद ले रहा है, लेकिन हर कोई इसका समान रूप से आनंद नहीं उठा सकता। इस बीच राज्य ने जनता के धन के इस्तेमाल से मीडिया द्वारा पेश की गई उन नई संभावनाओं पर संज्ञान लिया, जो नागरिकों की सोच को प्रभावित करने के लिए थीं। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए नई तकनीक को अपनाया गया जिसने पुरानी रणनीतियों की जगह अधिक सक्रिय नीति (कुछ निरंकुश शासकों द्वारा ये साधन पहले ही अमल में लाए गए, क्योंकि वो उनके स्वार्थों को साधती थीं) का रूप ले लिया। इस तरह की असमानताओं ने केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित नहीं किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

भी इसका प्रभाव दिखता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अमीर और गरीब देशों में संचार तकनीकों को लेकर इस तरह की असमानता है।

इस तरह से देखें तो संचार की समस्याएं जिसे हम बारी-बारी से प्रेस की आजादी, सूचना की आजादी और सूचना के अधिकार के रूप में देखते हैं, अपने मूल में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू लिए हुए है। इनमें बुनियादी विरोधाभास भी दिखाई देते हैं। दुनिया भर के प्रत्येक राष्ट्र में साक्षरता अभियान, जागरूकता बढ़ रही है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता हासिल होने से ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक बढ़ी है जो अब सूचना चाहते हैं और यहां तक कि जो सूचना का हस्तांतरण करने में सक्षम हैं। हालांकि इस वृद्धि के समांतर ही तकनीकी प्रगति की वित्तीय आवश्यकताओं का केंद्रीकरण भी तेजी से बढ़ा है। इस केंद्रीकरण के परिणामस्वरूप संदेशों का हस्तांतरण करने वाले ट्रांसमीटर्स, कम से कम तुलनात्मक रूप से बोलने वालों की संख्या घटी है। लेकिन इसके साथ ही किसी पर निर्भर ट्रांसमीटर्स की शक्ति अधिक मजबूत हुई है।

एक बात तो तय है कि संचार को जबर्दस्त महत्व मिला है। यहां तक कि ऐसे समाज में भी जहां मीडिया निजी हाथों में है और राज्य थोड़ा बहुत ही उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ये हर तरह से हस्तक्षेप कर सकता है, पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण से लेकर बहुलतावाद के बढ़ाने के उपायों तक। कुछ सरकारें अपनी विचारधारा को जायज ठहराने के लिए सूचना की विषयवस्तु पर पूरी तरह से नियंत्रण को स्वाभाविक मानती हैं। यहां तक कि उन सूचनाओं पर भी जो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होती हैं। इसमें संदेह है कि क्या ऐसी प्रणाली को यथार्थवादी कहा जा सकता है। अनुभव बताते हैं कि सूचना साधनों पर व्यावसायिक या राजनीतिक एकाधिकार के

प्रभाव या राज्य द्वारा थोपे गए विचार कभी भी संपूर्ण नहीं होते हैं। लगातार एक अलाप या अपनी ही बात कहते रहने से आलोचनात्मक बुद्धिमानी या स्वतंत्र निर्णय को खत्म नहीं किया सकता है। मीडिया धुंधली एकरसता से ढका हुआ है, जो विश्वास के बजाए अविश्वास पैदा करता है।[5] जब असंतुष्ट आवाजें खामोश हो जाएं तो मीडिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। राज्य विवादों से डरा हुआ लगता है और वो सच्चाई पर ढुलमुल ढंग से यकीन करता है, जिसे वो सत्य के रूप में आगे बढ़ता है। खैर फिर भी किसी न किसी तरह से नियंत्रित मीडिया का एकाधिकार संचार के दूसरे तरीकों से टूटा हैः खबरें मुंहजबानी आगे बढ़ती हैं, गैरकानूनी पर्चे बंटते हैं। ये तरीके बहुत शुरुआती दौर के हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभी जान बाकी है और दमन से इसकी विश्वसनीयता ही बढ़ती है। और अंत में, राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर कायम किए गए एकाधिकार में विदेशी प्रसारक दखलंदाजी करते हैं।

जबकि कुछ सरकारें कुछ खास तरह के नियामक कार्यों से राज्य को अलग रखती हैं। वो वैकल्पिक मीडिया, नागरिकों की भागीदारी, सूचना के स्रोत तक लोगों की पहुंच, समूह संचार, सूचना के साधनों का विकेंद्रीकरण आदि को न सिर्फ इजाजत देती हैं, बल्कि प्रोत्साहित भी करती हैं।

थोड़ा हटकर लेकिन एक मत ये भी है कि राज्य को विविधता कायम रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वित्तीय रूप से कमजोर, लेकिन प्रतिनिधि समूहों को सब्सिडी मुहैया करानी चाहिए। भले ही उनका राजनीतिक दृष्टिकोण स्थापित सत्ताधारियों के प्रति आलोचनात्मक हो। उन्हें आर्थिक प्रभुत्व से इसलिए भी मुक्त कराया जाना चाहिए ताकि विचारों और सूचनाओं की अधिकतम विविधता सुनिश्चित की जा सके। इस नीति में भी

ढेर सारी समस्याएं हैं (जिनमें से कुछ तकनीकी हैं, जैसे सीमित संख्या में रेडियो तरंगदैर्ध्य का आवंटन)। कोई भी समुदाय सबके लिए मान्य विचारों का बुनियादी ढांचे तय कर सकता है। इसे शायद ही माना जाए कि कोई बहुत उदार राज्य बहुलतावाद के नाम पर किसी नस्लवादी प्रकाशन को सब्सिडी दे। न ही ये स्वीकार्य होगा कि एक लोकतांत्रिक ढंग से संगठित राज्य अपने तय राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मीडिया के जरिए अपनी नीतियों की व्याख्या और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नियमन के अनुसार अपनी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करे। वास्तव में, ये तब अनिवार्यता बन जाती है जब राष्ट्रीय लक्ष्य सामूहिक प्रयासों की मांग करते हैं। प्रगति और विकास निश्चित रूप से ऐसे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर होने चाहिए, जिसके लिए बड़ी पैमाने पर जनता को सूचित करके प्राप्त सहमति और समर्थन की जरूरत होती है।

संचार जिस ढांचे के भीतर काम करता है वो आखिरकार राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष द्वारा निर्धारित होती है। यही ढांचा किसी समाज में प्रचलित सामाजिक सहमति को आकार देता है। लोकतांत्रिक समाजों में संचार जिस तरह संगठित है वो मूलतः एक राजनीतिक निर्णय है जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों को दर्शाता है। व्यवहारिक स्तर पर संचार की राजनीतिक समस्याओं का समाधान राज्य के वाजिब हितों और सूचना तक पहुंच के अधिकार के बीच संतुलन तलाशने पर निर्भर है। इसमें सूचना के अधिकार को विचारों के विभिन्न वर्गों तक बढ़ाया जा सकता है। ये समाधान अनिवार्य रूप से उस देश समाज की राजनीतिक संरचना, विकास की स्थिति और प्रत्येक राष्ट्र के आकार तथा संसाधनों के अनुसार अलग होंगे। लेकिन

अभिव्यक्ति की आजादी को उसकी उपयुक्त जगह से हटाने के लिए न तो व्यवहारिक जरूरतों और न ही विचारधारा के दावों का उपयोग करना चाहिए।

अगर इस संतुलन को बना भी लिया जाए तो भी कुछ खतरों के खिलाफ बचाव करने की अनिवार्य रूप से जरूरत होगी। इनमें से एक उच्चवर्गवाद है, इसके बारे में मुक्त प्रेस के शुरुआती दिनों से ही चिंता जाहिर की जा रही है। संचार जो मुख्य रूप से ऊपर से नीचे की तरफ है- वो राजनीतिक नेताओं, राष्ट्रीय जीवन के अन्य हिस्सों में शक्तिशाली स्थिति हासिल करने वाले व्यक्तियों या नामी बुद्धिजीवियों के विचारों को विस्तार देता है। अक्सर धैर्यवान श्रोता या पाठक के रूप में आम नागरिकों की भूमिका को कमतर करता जाता है और उनकी चिंताओं, उनकी इच्छाओं तथा उनके अनुभवों को धूमिल कर देता है। संचार के लिए ऊपर के साथ-साथ नीचे के रास्तों को भी साफ करना कठिन काम है। इसके अलावा साथ ही साथ उच्चवर्गवाद के जोखिम के साथ ही केंद्रीकरण भी बढ़ता है। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मीडिया तक कुछ थोड़े से राजनीतिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व वाले समूहों की ही पहुंच सीमित हो तो नस्लीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ मूल्यों को लेकर टकराव की स्थिति में वर्चस्वशाली तबके द्वारा अपने विचार और मूल्यों को थोपने का गंभीर खतरा रहेगा। बहुलतावाद के लिए दूसरी जरूरी बात है कि इन मूल्यों को समर्थन देने के लिए उन्हें आवाज दी जाए।

एक अन्य खतरा उस समय उठता है जब मीडिया तक पहुंच रखने वाले अपने लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। वो जनता के प्रति किसी भी तरह की जवाबदेही से इनकार करते हैं और उनका मानना है कि सूचना के कार्यों को पूरी तरह खुला छोड़ देना चाहिए। ज्यादातर मामलों में दोनों

अवधारणाओं, स्वतंत्रता और जवाबदेही, को एक दूसरे के साथ उलझा हुआ देखा और माना जा रहा है, जबकि वास्तव में दोनों सभ्यता के मुख्य घटक हैं। कभी-कभी सूचना के प्रसार के नतीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, न ही उनकी कोई जवाबदेही मानी जाती है। ऐसी स्थिति दूसरे संचार के क्षेत्र में आजादी और जिम्मेदारी के अभिन्न रिश्ते की घनिष्ठता को धुंधला करती है। स्वतंत्रता के हनन के खिलाफ सबसे बढ़िया हथियार है जिम्मेदारी है जिसे जो लोग अपने आचार-व्यवहार में स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं, उन्हें उठाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब आजादी नहीं होती है तो हर व्यक्ति अपने पसंद के काम नहीं कर पाता है और तब उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं हो सकती। हालांकि, ये भी सही है कि आजादी के एक अनिवार्य पहलू को उस समय इनकार किया जाता है जंब दिए गए घटनाक्रम को नज़रअंदाज किया जाता है। सूचना के अधिकार को नैतिक मांगों के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है अगर व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान और समाज की प्राथमिकताओं के मुश्किल काम को कर लिया जाए। जिम्मेदारी को सच्चाई के सम्मान के तौर पर ज्यादा महत्व देना चाहिए बजाए की संवैधानिक अधिकारों के।

यद्यपि इस तरह के विचारों का दुनिया भर में कई सारे रूप हैं, फिर भी ऐसे बदलावों के प्रति उदासीन रहना असंभव हैं जो स्वतंत्रता और जवाबदेही की तुलनात्मकता को दर्शाने और उसे बदलते रहने का रास्ता अपनाते हैं। उन्हें नए आयाम देने के लिए इन बातें को ध्यान में रखते हैः (क) ऐतिहासिक घटनाक्रम, (ख) ये बात कि अभिव्यक्ति का अधिकार धीरे-धीरे औद्योगिक संचार के हाथों संचालित होने लगा है, (ग) सामाजिक प्रक्रिया में व्यक्ति और समाज की भूमिका में बदलाव। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान

में रखे बिना सार्वभौमिक समाधान की सलाह देना व्यर्थ है। इस पर बहुत विवाद हो सकता है लेकिन फिर ये कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की एक अनिवार्य कसौटी स्रोतों की विविधता के साथ ही इन स्रोतों तक मुक्त पहुंच है। चाहें कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, ऐसे स्रोतों पर प्रभुत्वशाली समूह का नियंत्रण होने पर आज़ादी का मजाक ही बन कर रह जाएगा। नागरिक किसी सार्वजनिक मसले पर सही फैसले ले सकें इसके लिए जरूरी है कि उन्हें व्यापक सूचनाओं और विचारों से लैस रखा जाए। किसी लोकतांत्रिक समाज में ये संचार व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर विविध स्रोतों तक पहुंच जरूरी होती है। फिर भी दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, स्रोतों की विविधता से अपने आप सूचना की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं मिल जाती है, हालांकि इसके होने से जानबूझकर फर्जीवाड़ा करना अधिक मुश्किल हो जाता है। दूसरा, विविधता प्रत्येक मामले में बहुलता के समान चीज नहीं है, खासतौर से विचारों की बहुलता। संचार के नेटवर्क और तरीके विविधिकृत होने चाहिए और स्रोत की तरह ही एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो विविधता महज छलावा है।[6]

संचार और शक्ति के बीच संबंधों को लेकर भी अलग-अलग विचार हैं। एक राय ये है कि सूचना सत्ता-प्रतिष्ठानों पर अंकुश रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यहां तक कि सत्ता की ताकत को संतुलित भी करता है। इसमें मीडिया का मिशन सरकारों को आईना दिखाना है।[7] लेकिन ठीक इसके उलट एक विचार ये भी है कि सूचना राज्य की सेवा के लिए होनी चाहिए, ताकि वो शक्ति और स्थायित्व के साथ एक नई सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था मुहैया कराने में योगदान कर सके। निश्चित रूप से

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कई देशों का अनुभव बताता है कि मीडिया की स्वतंत्रता अभी भी लोकतांत्रिक को बहाल करने का मुख्य आधार है, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किस दिशा में बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों ने संचार और शक्ति के बीच संबंधों को पहले के मुकाबले कहीं अधिक केंद्रीय मसला बना दिया है। नेताओं और जनता के बीच का विरोध एक अन्य बुनियादी टकराव के चलते जटिल हो गया है। ये टकराव सूचना के विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण करने वाले उद्यमों और उन व्यक्तियों के बीच है, जिनका जीवन उन फैसलों से प्रभावित होता है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। कई संस्थानों में आंकड़ों के इस्तेमाल की बुनियादी भूमिका होती है, जिसमें सूचना का ढांचा (प्रेस एजेंसियां, जनमत संस्थान, प्रलेखन केंद्र) और साथ ही कई विषय (सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, परिचालनात्मक शोध, प्रणालीगत विश्लेषण) शामिल हैं। इस तरह काफी हद तक संचार संकेतों और निर्देशों का एक शस्त्रागार बन गया है और बड़े संगठनों भले ही वो सार्वजनिक या निजी, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हों, की शक्ति को सुदृढ़ करने में सहायता कर रहा है। इस तरह के संगठन में पहले से योजना बना लेने और फैसले करने की क्षमता होती है इसलिए वो नियंत्रण भी कर लेते हैं। जबकि नागरिकों के बंटे हुए समूह, सूचना के केवल एक हिस्से को ही प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे में सभी सूचनाएं जिनका उपयोग किया जा सकता है, वो शक्ति का एक स्रोत हैं। इस वजह से, जो लोग सूचना के स्रोत और प्रसारण के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके बर्ताव और दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है।

संचार पर मौजूदा वैश्विक बहस अपरिहार्य रूप से राजनीतिक है, क्योंकि जिस तरह की चिंताएं, उद्देश्य और दलीलें दी जा रही हैं वो मुख्यतः राजनीतिक

गुण लिए हुए हैं। समस्या की वास्तविक प्रकृति को छिपाने से न तो कुछ मिला है, न ही यथास्थिति के खतरों को स्वीकार करने में असफल रहने से कुछ मिलेगा। अगर हमें व्यावहारिक और यथार्थवादी समाधान तक पहुंचना है तो हमें बहस में प्रत्येक घटक को शामिल करना ही होगा।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र में ये बात कई बार आई है और खासतौर से अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में ये मुहावरा मशहूर है कि "सबको अधिकार है..." यूनेस्को का घोषणापत्र 1978 कहता है कि "विचार रखने, अभिव्यक्ति और सूचना के अधिकार को मानवाधिकार और मूलभूत अधिकारों का अभिन्न अंग माना गया है।"

4. आर्थिक शक्ति

अपनी संरचना और विषयवस्तु, दोनों ही लिहाज से संचार कई तरह से अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा है और उसपर निर्भर भी है। आर्थिक जीवन के लिए सूचना का सतत प्रवाह महत्वपूर्ण है। बेहिसाब संभावनाओं के साथ बड़ी आर्थिक शक्ति होने के कारण, विकास में भी ये निर्णायक कारक है। प्रत्येक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते महत्व वाले घटक के रूप में संचार, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक बढ़ते हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादकता तथा रोजगार पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। खासतौर से, दूरसंचार में प्रगति से सूचनाओं का तत्काल संप्रेषण शुरू हुआ है। ऐसे में कुछ स्थानों में कुशल श्रमिकों के बिना काम चल रहा है, जबकि अन्य स्थानों पर इसकी प्रकृति बदली है। ये संचार ही है जो अब औद्योगिक समाजों में विकास की सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं को थामे हुए है। उसे विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक संचार के साधनों ने उद्यम स्थल को अक्सर अप्रासंगिक बना दिया है। दूर की फैक्टरियों को हस्तांतरित करने की गुंजाइश बढ़ी है। अब विभिन्न उद्योगों

और अन्य गतिविधियों जैसे व्यापार, बैंकिंग और एयरलाइंस के लिए जगह का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। संचार और सूचना द्वारा अर्थव्यवस्था में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को आम आदमी महसूस कर सकता है। हालांकि आम आदमी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है और आने वाले समय में ये सच्चाई और पुख्ता होगी।

ये सही है कि संचार और सूचना के विभिन्न रूपों को हमेशा जोड़ा गया है, कम से कम काम करने और उत्पादन के लिए। लेकिन अब इस संबंध को देख पाना अधिक आसान हो गया है।

ऐसे में सूचना और खासकर ऐसी सूचना जो प्रसारण, भंडारण और इस्तेमाल करने लायक हो वो ऊर्जा या कच्चे माल की तरह ही एक मुख्य संसाधन है। लेकिन कुछ समाजों या लगभग सभी समाजों में थोड़े से समूह के लिए संचार कुछ अर्थों में नासमझ में आने वाली बात है, जैसा कि एक अर्थशास्त्री ने कहा है, लोग मौद्रिक संकेतों और भौतिक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में संचार के बिना बातचीत नहीं कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचार की नई संरचना कुछ समाजों की जीवन-शैली, मूल्यों और प्रतीकों को प्रतिबिंबित करती है। ये दुनिया के बाकी हिस्से को कुछ खास तरह के उपभोग और बाकियों से अलग विकास के रास्ते सुझाती है। ऐसे में संचार की बिगड़ी हुई ताकत से खतरा काफी बढ़ गया है।

इन कारकों को कमतर आंक कर कुछ विकासशील देशों ने संचार के क्षेत्र में अपनी आज़ादी के बनाए रखने को नज़रअंदाज किया है। जिस तरह से विभिन्न देशों और क्षेत्रों में आर्थिक असंतुलन देखने को मिलता है वो इस क्षेत्र में भी चिंता की वजह है। इन सब से उबर कर ऐसे देश तकनीकी प्रगति से अपने को और अधिक चमका सकेंगे। विकासित देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद खाली हुई जगह को नई तकनीक ने भरा, लेकिन

विकासशील देश इस क्रम को दोहरा नहीं सके। खासतौर से इसलिए क्योंकि वो अपने विकास को गति देने के दबाव से गुजर रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि ठीक उसी समय औद्योगिक क्रांति और सूचना क्रांति का उनसे सामना हो रहा था। कई देशों को संचार के लिए ठोस विकास रणनीति बनाने और समुचित बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने की जरूरत है।

इस क्षेत्र में विकास संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की मांग करता है, जो फिलहाल आधाअधूरा है। हालात को देखते हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संचार के संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। कुछ देशों के पास अपनी जरूरतों के मुताबिक सूचना जुटाने की पूरी क्षमता है, जबकि कई के पास ऐसा करने की बहुत कम क्षमता है और ये उनके विकास में एक बड़ी बाधा है।(8)

वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में इन असमानताओं को खासतौर से चिन्हित किया गया है जिसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। वैज्ञानिक शोध और उसके इस्तेमाल से संबंधित सूचना की समस्या के कई पहलू हैं। उपलब्ध सूचना की मात्रा के लगातार कम होते जाने की बढ़ती प्रवृत्ति और उसकी बढ़ती जटिलता ने भी कई शोध परियोजनाओं और एक व्यापक बहुविषयक स्वरूप की संभावना पैदा की है। आज एसटीआई (ऽा। 'वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना' का संक्षिप्त रूप) एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, जिसे अधिक उदारता और व्यापकता के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि ये अतीत और वर्तमान में कई देशों में पुरुषों और महिलाओं के प्रयासों और उनकी सोच का नतीजा है। निश्चित रूप से ये सभी मुक्त राष्ट्रीय विकास की चाभी हैं और साथ ही मानवता की समन्वित प्रगति में बुनियादी कारक भी हैं। जाहिर तौर पर सूचना विज्ञान, वैज्ञानिक आंकड़ों को एकत्र करने,

उनका वर्गीकरण करने और विश्लेषण को नियंत्रित करता है। हालांकि, ये गति और उसकी वजह से विश्वसनीयता की एक तरह से गारंटी है, लेकिन इसमें ये निश्चित नहीं है कि आंकड़ें हमेशा सच होंगे। ऐसे में विश्व स्तर पर एसटीआई के संगठन के लिए सूचना के उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए काम करने की जरूरत है। उपयोगकर्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए सूचनाओं का मूल्यांकन और उनका परीक्षण करने की जरूरत है। उन्हें विभिन्न समाजों के लिए कारगर ज्ञान को उनके लायक बनाने की एसआईटी की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि सूचना को कौन नियंत्रित करेगा और सूचना के चयन और वितरण की प्रक्रिया किस तरह से नियमबद्ध होगी। इस बात की जरूरत है कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दुनिया भर के एसटीआई संसाधनों का लाभ लिया जाए। सूचना का वैश्विक संग्रह स्थानीय ज्ञान में इजाफा कर सकता है जो आगे चलकर मुक्त राष्ट्रीय विकास की सफलता का एक कारक होगा।

ये समस्याएं इस तथ्य से कई गुना बढ़ जाती हैं कि यद्यपि कई संचार उत्पादों की प्रति इकाई लागत में कमी हुई है, लेकिन उनका निर्माण करने के लिए आवश्यक निवेश बढ़ रहा है। इसके चलते इन हालात में पूंजी संपन्न राष्ट्रों को भविष्य में एक बनी बनाई संरचनात्मक बढ़त हासिल होगी। ये आर्थिक हकीकत संचार की समस्याओं को नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जोड़ती है। आर्थिक और संचार के क्षेत्र में आवश्यक बदलाव एक ही प्रक्रिया के हिस्से के रूप में घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से गूंथे हुए हैं। इसी के जरिये समान और श्रम के अंतरराष्ट्रीय तरह के विभाजन की तरफ बढ़ा जा सकता है।

इन मुद्दों में व्यवहारिक के साथ ही सैद्धान्तिक मूल्य हैं। संचार, आर्थिक विकास के साधन या फिर आर्थिक शोध के विषय के रूप में नया और

प्रासंगिक अध्ययन की मांग करता है। यह जहां तक संभव हो सके तुलनात्मक रूप में तैयार होना चाहिए। लेकिन इन अध्ययनों से राजनीतिक सक्रियता को बढ़ावा मिलना चाहिए। आर्थिक योजनाओं में संचार को जो भूमिका निभानी चाहिए इसको लेकर कोई अनिश्चितता की गुंजाइश नहीं है। न ही विकास की रणनीति में इसकी भूमिका के बारे में, न ही उन संसाधनों की जरूरत के बारे में जिन्हें हर राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसमें समर्पित करना चाहिए।

5. शिक्षा संबंधी संभावना

ज्यादातर देशों में संचार के तीव्र विकास, जनसंचार के विभिन्न रूपों के विस्तार और खासतौर से श्रव्य-दृश्य संचार के साथ ही सूचना विज्ञान के प्रसार ने नई संभावनाएं खोली हैं। शिक्षा तथा संचार के बीच संबंधों को कई गुना बढ़ा दिया है। संचार का शिक्षा के लिए इस्तेमाल करने की संभावनाओं में स्पष्ट बढ़ोतरी हुई है। व्यापक शैक्षणिक मूल्यों से लैस होकर संचार ने 'शैक्षणिक माहौल' तैयार किया है। जबकि शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा पर से एकाधिकार कमजोर हुआ है, संचार स्वयं में शिक्षा का वाहक और विषय बन गया है। जबकि शिक्षा मनुष्यों को बेहतर ढंग से संवाद करना सिखाने और उनके बीच आदान-प्रदान के रिश्ते को बेहतर बनाकर अधिकाधिक लाभ पाने के लिए अनिवार्य साधन है। इस तरह, संचार और शिक्षा के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ रहे हैं।

सबसे पहले, सूचना और संचार का शैक्षणिक मूल्य और बौद्धिक विकास पर प्रभाव को कई विचारकों, शोधकर्ताओं और सरकारी प्रतिष्ठानों ने बुनियादी महत्व के रुप में माना है। खासतौर से तीसरी दुनिया में असंख्य वंचित पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए स्कूल मीडिया के समान ही है, भले ही वो इससे केवल उन्हीं तत्वों को ले सकें जिनकी प्रासंगिकता कम हो और जो

सर्वाधिक सरल विषयवस्तु के रूप में हो। इससे उन्हें मिलता तो है लेकिन बस इतना ही जैसे दावत में कुछ टुकड़े मिल जाएं। दुनिया भर में प्रसारित संदेशों और समाचारों के शैक्षणिक महत्व को देखिये या इसके ठीक उलट उनके शिक्षा विरोधी या समाज विरोधी निहितार्थों को भी देखें। मीडिया और संचार के शैक्षणिक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे ऐसे मामलों में भी देखा जा सकता है जिसमें संदेश की विषयवस्तु शैक्षणिक प्रकृति की नहीं है। संचार से संबंधित शैक्षणिक और सामाजिक भूमिका से तात्पर्य है कि उसे समाज की विकास संबंधी जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए और संचार को सामाजिक वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए।

दूसरी बात, आधुनिक समाज[9] में संचार की हर जगह मौजूदगी, सशक्त शैक्षणिक सुगंध के साथ व्यक्तित्व की एक नई रूपरेखा के उभरने का संकेत है। नागरिकों पर बढ़ती मात्रा में सूचना की बौछार और सबसे बढ़कर नई सामाजिक या भौगोलिक श्रेणियों तक समाचार के प्रवाह के विस्तार ने इस तरह की धारणा बनाई है कि ज्ञान तक पहुंच अब मुफ्त है, ये सामाजिक दूरियों को खत्म करता है और पेशागत रहस्यों को उजागर कर सकता है। 'वीडियो सभ्यता', 'वैकल्पिक शिक्षा', 'कंप्यूटरीकृत समाज' और 'वैश्विक गांव' जैसी अवधारणाएं इस बात को लेकर बढ़ती जागरूकता को दर्शाती हैं कि तकनीकी माहौल ने समाचार प्रस्तुति और ज्ञान तक पहुंच के स्थाई रूप का सृजन किया है। इस माहौल के चलते एक 'नए मानव' के उदय की बातें हो रही हैं जो दिन-प्रति-दिन अपनी सोचने की आदतों, अपने महत्वपूर्ण नजरियों और अपनी तकनीकी जानकारी को विभिन्न सीमा तक ढलने में सक्षम है।

तीसरी बात, इस तरह संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रतिदिन पेश और संकलित किया जाने वाला ज्ञान 'पच्चीकारी' की तरह है, जिसकी परंपरागत बौद्धिक मापदंडों से अब कोई समानता नहीं है। इस तरह हासिल किए गए

ज्ञान के स्पष्ट या अस्पष्ट मूल्यों से इनकार किए बगैर, सूचनाओं की गड्डमड्ड प्रकृति पर जोर देना भी नाजायज नहीं होगा। फालतू और सनसनीखेज खबरों के प्रसार को दिया जा रहा बढ़ावा एक तरह से वास्तविक संदेश की कीमत पर बढ़ता 'शोर' है। इसके अतिरिक्त मास मीडिया नए तरीके से अभिव्यक्त और समझदारी की हमारी साझी सांकेतिक प्रणाली (Symbolic systems) को मजबूती दे, समृद्ध कर रहा है। ऐसा करके, इसने समूहों के विशिष्ट गुणों को धुंधला और पुरानी रूढ़ियों को मजबूत किया है। आमतौर पर प्रक्रिया की शुरुआत के मुकाबले ऊपरी स्तर पर बौद्धिक मानकीकरण की स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि समसामयिक अनुभवों पर हुए शोध में ऐसा कुछ नहीं पता चला है कि मानकीकरण की ओर ये रुझान या तो अनवरत या अपरिवर्तनीय हैं, जो आजकल संचार उद्योग की एक विशेषता हैं। जिस तरह सूचना थोपी जाती है, उससे इस धारणा को बल मिला है कि उपयोगकर्ता इसका नियंत्रक होने की जगह इसका गुलाम है (महत्व की जिस भावना का वह अनुभव करता है वह सूचना विज्ञान के तय माहौल से प्रभावित होकर ही किसी चीज को महत्वपूर्ण मानने का मन बनाता है)। किसी व्यक्तिगत नजरिए से देखें तो जनसंचार द्वारा थोपी गई लाचारी के मुकाबले ज्ञान की बातों को कम महत्वपूर्ण माना जाता है।

ठीक इसी समय, कई देशों के प्रसारण केंद्रों ने रोचक, उपयोगी और कल्पनाशील शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किए, उसमें कुछ 'औपचारिक' प्रकृति के (स्कूली पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालयी अध्ययन के पूरक या संवर्धक के रूप में थे) और दूसरे 'अनौपचारिक' (खासतौर से किसानों, व्यस्कों और तकनीकी ज्ञान के जरूरतमंद लोगों के लिए) किस्म के थे। कुछ विकासशील और विकसित दोनों तरह के देशों ने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए रेडियो और टेलीविजन में अलग से प्रसारण चैनल शुरू किए। जबकि बाकी देशों ने शैक्षणिक, प्रशिक्षण और सीखने के उद्देश्य से अपने सामान्य प्रसारण कार्यक्रम

में थोड़ा या ज्यादा समय निश्चित कर दिया। सामान्य तौर पर ये कार्यक्रम शिक्षाविदों और प्रसारकों ने साथ मिलकर तैयार किए। लेकिन कई बार इस तरह का सहयोग नदारद रहा, जिसने शैक्षणिक प्रसारण की प्रकृति या शैली को प्रभावित किया।

शैक्षणिक उद्देश्य के लिए अचानक संचार तकनीकों के इस्तेमाल से व्यक्तियों और समूहों में कई तरह के बदलाव आए। अब लोग अपने ऊपर पड़ने वाले किसी तरह के 'प्रभावों' और 'असर' को पहले की अपेक्षा ज्यादा समझ सकते थे। इससे मीडिया का 'संज्ञानात्मक विकास' और व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव जिसे तकनीकी शब्दों में उद्दीपन प्रतिक्रिया कहते हैं, इस पर बातचीत होने लगी। आज इस तरह के नजरिया को बढ़ावा मिल रहा है कि माहौल में क्रमिक बदलावों के चलते संचार परिवर्तन के एक व्यापक समूह के एक हिस्से को गढ़ रहा है। इस निष्कर्ष को भी बढ़ावा मिला है कि व्यक्तियों पर तकनीक का प्रभाव उनके मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होता है। इस लिहाज से, मीडिया की 'अनौपचारिक' शैक्षणिक गतिविधि आमतौर पर शैक्षणिक सोच की प्रवृत्तियों की तरह ही दिखाई दे रही है जैसे कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर जोर देना और समूह के साझा मूल्यों को प्रभावित करना और कुछ इसी तरह के लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव जिनकी प्रकृति के बारे में अभी पूरी तरह से कुछ पता नहीं है।

चौथा, लगभग सभी समाजों में स्कूलों और कॉलेजों को शिक्षा पर अपने एकाधिकार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अब काफी हद तक संचार स्कूलों के परंपरागत दायित्व का निर्वाह कर रहा है। ये स्कूलों के कामकाज को लेकर पुनर्विचार करने का सवाल उठता है।

यहां तक कि औद्योगिक समाजों में भी इस शताब्दी की शुरुआत तक स्कूल, ज्ञान के प्राथमिक स्रोत और शिक्षक इसके लाइसेंस प्राप्त वितरक थे। व्यक्ति ज्ञान की दुनिया के बारे में जानने के लिए स्कूलों पर ही निर्भर था। उसे अपनी कोई मंजिल हासिल करने और उसके लिए व्यवहार का तरीका सीखने के लिए स्कूल जाना जरूरी था। आज ज्यादातर समाजों में खुले या दबे-छिपे दो व्यवस्थाएं प्रतिस्पर्धी रूप में काम कर रही हैं। इसलिए वो लोगों के दिमाग में विरोधाभासों और मुश्किल पैदा कर रही हैं। शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने, उसकी तकनीक और 'प्रोग्रामिंग' करने में व्यक्तिगत प्रयास और किसी की लगन होती है। ये संचार व्यवस्था के विरोध में है, जो सामयिक, अनूठेपन को दिखाना और दुनिया की तनातनी, आसान समझ और सुखवादी मूल्यों को दर्शाता है। इस विरोध को स्वस्थ समाजों में सहन किया जा सकता है, जहां कूड़ा-कचरा भी चलता है लेकिन इसे आज के विकासशील देशों के हालात के मद्देनजर असंगत माना जाता है। व्यावहारिक तौर पर अभी तक मीडिया सूचना और ज्ञान के प्रसार की ऐसी शक्तिशाली क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बिना कोई भी समुदाय रह नहीं सकता।

स्कूलों में ज्ञानदर्शन (इपिस्टमालजी) संबंधी ऐसे काम होते हैं जो इस बात की शिक्षा देते हैं कि ज्ञान को कैसे बढ़ाया, संवारा और उसका विश्लेषण किया जाए। अनुभवों से कैसे ज्ञान पाया जाए और उस भाषा को कैसे समझें जो दुनिया के बारे में बताती है। लेकिन आंशिक रूप से ये संचार के कार्य हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पढ़ाने में अनिवार्य रूप से संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है जो संप्रेषण की प्रक्रिया है। हालांकि आज के स्कूल, शाब्दिक भाषा का किस तरह इस्तेमाल किया जाए, ये तो सीखाते हैं लेकिन शारीरिक, ग्राफिक और सचित्र संचार के अन्य रूपों को नज़रअंदाज करते दिखते हैं। चित्रों की भाषा वस्तुतः जन संचार प्रणाली की रक्षक है।

स्कूलों से ये उम्मीद की जाती है कि वो संदेशों को अर्थ समझ सकने की क्षमता विकसित करेंगे। खासतौर से ऐसे संदेश जो किसी खास तरह की बात कहते हों। यहां तक कि अगर संदेश का कोई खास अर्थ [10] न हो तो भी इसके एक या कई अर्थ होते हैं। संदेशों का अर्थ प्राप्तकर्ता द्वारा अब तक हासिल अनुभव से सृजित किया गया एक तथ्य है। इस तरह अनुभव और भाषा संचार के सभी कार्यों के लिए पूर्व शर्त हैं। स्कूलों की भूमिका, वास्तव में वैकल्पिक शिक्षा या शिक्षा और अध्ययन के अनौपचारिक तरीके, संदेशों को समझ पाने में मदद के मकसद से हैं न कि उसे थोपने के लिए। उत्तरदायित्व, सहिष्णुता, सामाजिक जागरूकता, सृजनात्मक गतिविधियों और संवाद का आनंद लेने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है।

शिक्षा और संचार के बीच संतुलन कायम करने की कोशिशें विभिन्न रूप लेती है- कुछ का मानना है कि मीडिया, समकालीन ज्ञान उपलब्ध कराने का काम करता है, जबकि शिक्षा, परंपरा के जरिए संचित विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदेह है। दूसरे लोग ये मानते हैं कि स्कूलों को प्रभावशाली सामाजिक जागरूकता पैदा करने, जिम्मेदारियां उठा सकने वाले लोग तैयार करने चाहिए और राष्ट्र के आर्थिक विकास में मदद करनी चाहिए जबकि संचार का इस्तेमाल मौज-मस्ती के लिए और साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध और समझ बनाने के लिए होना चाहिए। हालांकि कुछ दूसरे लोगों को लगता है कि संचार के शोरगुल के मुकाबले स्कूल का काम शांति, बौद्धिक विमर्श और एकीकरण का स्वर्ग तैयार करना है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य काम संचार के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए सभी दिशाओं में बिखरे ज्ञान को व्यवस्थित करना है। क्योंकि इस तरह की प्रणाली का गठन मूल्यों की व्यवस्था और उस पद्धति पर आधारित है जो अपने शिष्यों को ये सिखाती है कि आवश्यक चीजों का चयन कैसे किया जाए। संक्षेप में कहें तो वो सिखाते हैं कि अध्ययन कैसे किया जाए। ऐसे में

स्कूलों को अध्ययन की नई रणनीति खोजनी होगी। साथ ही बाकी जगहों पर पहले से इस्तेमाल किए जा रहे व्यवहारिक अनुभवों से भी सिखना होगा।

कार्यों का पुनर्वितरण अभी तक किसी व्यवस्थित नीति-निर्माण का विषय नहीं बना है। दो तरह की व्यवस्थाएं अभी भी एक दूसरे से अलग-थलग हैं या कोई एक अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दूसरे से या आपस में मोलतोल कर रही है। एकदम साफ है कि नई जिम्मेदारियों के लिए सभी तरह के शिक्षकों को फिर से प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ संचारकों को भी शैक्षणिक मामलों संबंधी जरूरी खुलेपन के लिए तैयार करना होगा।

व्यवहारिक तौर पर शैक्षणिक संस्थानों को अपनी समझ और पसंद के आधार पर अपने संस्थानों में संचार के ज्यादातर आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए। कुछ देशों ने प्राथमिक स्कूली आयु से माध्यमिक शिक्षा पूरी होने तक ज्ञान और संचार के साधनों के इस्तेमाल को शामिल करने की पहल शुरू की है, खासतौर से स्कूलों में प्रेस को शामिल करके। इन पहलों का उद्देश्य बच्चों को इस तरह पढ़ाना है ताकि वो सूचना पर आलोचनात्मक ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। साथ ही गुणात्मक और सांस्कृतिक पैमानों के मुताबिक अपनी पठन सामग्री, कार्यक्रमों और अवकाशकालीन गतिविधियों का चयन कर सकें। खासतौर से टेलीविजन को लेकर। शिक्षा व्यवस्था के स्तर पर दुनिया के सभी हिस्सों में ऐसे ढेर सारे वैकल्पिक प्रयोग और नजरिया इस्तेमाल किया गया है और किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्तरों पर सफलता भी मिली है। ऐसा देखा गया है कि मीडिया आधारित प्रमुख शैक्षणिक अभियान अपने लक्ष्यों, कठिनाइयों को लेकर अपनी समझदारी, जटिलताओं और जरूरी संसाधनों की भारीभरकम मात्रा को लेकर ज्यादा ही आशावादी रहते हैं। आज भंडारण और वितरण के लिहाज से अधिक हल्की

तकनीक (स्थानीय रेडियो ट्रांसमीटर, टेप रिकॉर्डर, प्ले-बैक क्षमता के साथ पोर्टेबल वीडियो कैमरा आदि) के इस्तेमाल में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई जा रही है। इसके बावजूद, किसी स्थाई सांस्कृतिक नीति के अभाव और शैक्षणिक रणनीतियों की कठोरता ने मीडिया के प्रभावशाली उपयोग की संभावना को धूमिल किया है।

समाज में संचार के बढ़ते वजन के साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था में इसकी जो नई जिम्मेदारी भी तैयार हुई है- वो ये कि संचार के सही इस्तेमाल के बारे में बताए और ध्वनि-दृश्य छद्म ज्ञान के खतरों और सूचना विज्ञान की शक्तियों को लेकर भ्रांतियों के खतरों से आगाह करे। यहां शिक्षा के अधिक आलोचनात्मक तरीके के बारे में बात की जा रही है जो कि किसी व्यक्ति को तकनीक के जादू से मुक्त कर पाए, उसको अधिक विविधतापूर्ण और जिज्ञासु बना सके। शिक्षा व्यक्ति को संचार प्रक्रिया के ढेर सारे उत्पादों में सही का चुनाव करने योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। अब इस बात को ऐसे ही ले लिया गया है कि प्रेस और रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार को शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के ढेर सारे संस्थान भविष्य में सही मायनों में भागीदारीपूर्ण संचार की एक आदर्शवादी दुनिया का सपना देख रहे हैं जहां हर कोई एक साथ सूचना का निर्माता और उपभोक्ता हो सकता है।

आखिरकार, संचार और शिक्षा की परस्पर निर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद ये है कि सभी स्तरों पर शिष्यों और छात्रों के लिए अध्ययन की प्रक्रिया में संचार का मतलब ज्ञान के एकतरफा प्रसार की जगह मानवीय संबंधों को समझने और किसी को लेने-देने या मिलने-जुलने से होना चाहिए। ये निश्चित रूप से लोगों, वर्गों, समूहों और राष्ट्रों के बीच के रुकावटों को तोड़ने का एक साधन होना चाहिए। संचार के ज्ञान और अनुभव का सबसे

अच्छा योगदान ये है कि अध्ययन, प्रशिक्षण और शिक्षा को समृद्ध बना सके। क्योंकि दोनों की आपसी साझेदारी और संकेतों के जरिए परस्पर सामाजिक क्रिया इसकी अनिवार्य प्रासंगिकता है।

शिक्षा, संचार से थोड़ा अधिक और कम दोनों है। इसकी अनुपस्थिति में निरक्षरता बनी रहती है, जिसके चलते संचार की योग्यता दहलीज तक सिमटी रहती है। इसका विस्तार आगे संचार के लिए बुनियाद बनता है। संचार में असंतुलन के उपाय के बारे में कोई बात हो तो उसमें सार्वभौमिक रूप से शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह विकासशील देशों संचार की कमी को लेकर होने वाली चर्चा के दौरान शिक्षा की क्षमता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी से मानव विकास और तकनीकी को चलाने वाले लोग मिलते हैं। इसी तरह, अगर संचार के क्षेत्र में लोकप्रिय भागीदारी को एक हकीकत बनाना है तो निश्चित रूप से इसमें भागीदार होने वाले लोगों, उपभोक्ताओं, प्रबंधकों और निर्णय करने वालों की क्षमता को शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिये बढ़ाया जा सकता है।

संचार और शिक्षा के बीच इस तरह के बढ़ते संपर्कों से हम पर ये पूछने का दबाव बढ़ा है कि इस संबंध को किस तरह अधिक लाभप्रद और सकारात्मक बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही हर प्रक्रिया की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी है। अपनी सहज प्रकृति के अनुसार शिक्षा परंपरा और अतीत से विरासत में मिले सांस्कृतिक मूल्यों के संप्रेषण के प्रति उदासीन नहीं रह सकती है। फिर भी उसे एक ऐसी दुनिया में काम करना है, जो सत्ता प्रतिष्ठानों के प्रति कम से कम आज्ञाकारी और परंपराओं का कम से कम सम्मान करने वाली हो, एक ऐसी दुनिया जो एक नया भविष्य बनाने के कार्य के प्रति सजग हो। स्कूलों का बुनियादी कार्य युवाओं को इस बात की

शिक्षा देना है कि दुनिया क्या है। दुनिया के बारे में बताते हुए इसमें निश्चित तौर पर अतीत से मिले दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए। संचार ने अपनी निगाहें आधुनिकीकरण पर गड़ा दी हैं। ये युवाओं को एक ऐसी दुनिया के सपने दिखाता है जो फिर से तैयार की जा रही है। इसका मिशन ऐसी सामाजिक संभावनाओं को लाना है जिसका पर अब तक अन्वेषण या प्रयोग न किया गया हो। इस तरह, व्यक्ति, समूह और समुदाय अपने स्वयं के मूल्यों और अपनी संस्कृति के बारे में विस्तार से समझने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। उन्हें ये याद दिलाना होगा कि वो ये तब तक नहीं जा सकेंगे जब तक कि शिक्षा के जरिये ज्ञान और विचारों का हथियार नहीं प्राप्त कर लेते।

6. संस्कृति पर प्रभाव और खतरा

संस्कृति और संचार की अंतर-निर्भरता काफी अधिक साफ है। खासकर अगर 'संस्कृति' शब्द का इस्तेमाल मानवीय सृजनात्मकता की संपूर्ण उपलब्धियों के अर्थ है- जिसमें "सभी मनुष्यों ने प्रकृति में योगदान किया है" का बोध होगा अगर इसमें हर उस चीज को शामिल कर लिया जाये जिसने मानव जीवन को पशुओं के स्तर से ऊपर उठाया और जीवन के हर पहलुओं और समझ के हर तरीकों को अपनाया है। इसी आलोक में संचार ने लोगों और राष्ट्रों दोनों के बीच जीवन के हर तरीकों और संस्कृतियों का महत्वपूर्ण घटक है। संचार की भूमिका संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले के रूप में मानी जा सकती है। संचार के माध्यम सांस्कृतिक उपकरण हैं जो नजरिये को बढ़ाने या उसे प्रभावित करने, मनोबल बढ़ाने, व्यावहारिक तरीकों के प्रसार को बढ़ावा देने और सामाजिक एकीकरण लाने के लिए काम करता है। वो सांस्कृतिक नीतियों के कार्यान्वयन और संस्कृति को लोकतांत्रिक बनाने के लिए मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं या उन्हें निभानी चाहिए। वो

लाखों लोगों के लिए संस्कृति और सृजनात्मक अभिव्यक्तियों के सभी रूपों तक पहुंचने का मुख्य साधन है। संचार, ज्ञान के प्रबंधन, समाज की सामूहिक चेतना के संगठन और खासतौर से वैज्ञानिक सूचना को संग्रहित करने, उसमें सुधार करने और उपयोग में भी शामिल है। संभवतः कम से कम ये समाज के सांस्कृतिक स्वभाव को नई भूमिका दे सकता है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों की तरह ही इस क्षेत्र में नई तकनीक के तेज विकास और औद्योगिकृत संरचना की वृद्धि, जिसने संस्कृति के साथ ही सूचना पर अपनी पकड़ को बढ़ाया है, से समस्याओं और जोखिमों की शुरुआत भी हुई है।

हालांकि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की एक बड़ी व्यवस्था इसके पारंपरिक और अंतर-वैयक्तिक रूपों का देखरेख करती है, लेकिन ये भी सही है कि आधुनिक विश्व में मास मीडिया कई लाख लोगों की सांस्कृतिक जरूरत की पूर्ति करता है और सांस्कृतिक अनुभवों को आकार देता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक नई संस्कृति का सृजन कर रहा है इसके चरित्र को परिभाषित करना आसान नहीं है, फिर भी इसका मूल्य कम ही आंका जाता है। अतीत से लेकर अब तक का ये सृजनात्मकता का ऐसा नायाब नमूना है जिसे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नए दर्शकों के सामने पेश किया गया है। मनोरंजन विभिन्न रूपों में कहीं अधिक आसानी से उपलब्ध है। निःसंदेह यह मानवीय जरूरतों और मांगों के अनुरूप होता है। लेकिन इस मनोरंजन का एक बड़ा हिस्सा इतना साधारण और घिसापिटा है कि ये कल्पनाशीलता को बढ़ाने की बजाए उसे धूमिल करता है। सांस्कृतिक जीवन पर कई तरह से खतरा है। व्यावसायिक और विज्ञापन में छिपे हितों का प्रभाव, सभी तरह की नौकरशाही द्वारा संस्कृति को उसर करने की प्रवृत्ति से सांस्कृतिक जीवन को खतरा है। इसे सब धोपोछकर बराबर कर देने, दरिद्रता और खोखलापन का भी खतरा है। केवल इतने ही विरोधाभास नहीं हैं। व्यक्तिगत सृजनात्मकता कभी-कभी नए अवसर मिलने पर जाग उठती है और कभी-

कभी नकल और दर्शक की निष्क्रियता से बुझ भी जाती है। कभी-कभी अभिव्यक्ति के नए रास्तों का सहारा लेकर आदिम जातीय और अन्य अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि की जाती है, लेकिन ये लोग अकसर बाहरी प्रभावों से घबरा जाते हैं। अच्छाई या बुराई के लिए मास मीडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो केवल संस्कृति का संप्रेषण और प्रचार-प्रसार ही नहीं करता है, बल्कि उसके विषयवस्तु का चयन और उसे तैयार करने का काम भी करता है।

जनसंचार और जन संस्कृति काफी हद तक पिछली दो शताब्दियों की विशेष घटनाएं हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से उनके विकास को औद्योगिक क्रांति द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में लाए गए बदलावों के औजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तकनीक और संस्थानों के जरिये व्यापक पैमाने पर उत्पादन और वितरण को इसके परिणाम के रूप में देखा जा सकता है जो संदेशों के निरंतर प्रवाह से संभव हुआ है। जन संस्कृति निश्चित रूप से लोकप्रिय संस्कृति की तरह नहीं है। इसे अक्सर प्रभावशाली अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाई गई संस्कृति और फिर उसका बड़े स्तर पर प्रसार के खिलाफ एक मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसके बावजूद, जन संस्कृति की अवधारणा अस्पष्टता है। जब हम इसकी आम स्वीकार्यता पर विचार करते हैं, तो बहुत से लोग स्वर में स्वर मिलाते हैं या जब हम इसके उथलेपन पर आंसू बहते हैं तो बुराई शुरू हो जाती है। ये बताना आसान नहीं है कि क्या कोई सांस्कृतिक उत्पाद 'जन संस्कृति' का हिस्सा है या नहीं- इसके उद्गम या प्रसार के वर्तमान रूपों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए? निश्चित रूप से एक पुराना गीत सिर्फ इसलिए जन संस्कृति का हिस्सा नहीं बन जाता है क्योंकि उसे ट्रांजिस्टर रेडियो पर सुना गया है।

एक अन्य जोखिम जिसके बहुत पहले ही ठीक से अनुमान लगा लिया गया है वो सांस्कृतिक प्रभुत्व का है, जो आयातित मॉडल पर निर्भरता के रूप में आता है और अजनबी जीवनशैली तथा मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। कुछ राष्ट्रीय संस्कृतियों के सांस्कृतिक पहचान को जोरदार प्रभाव और समावेश से भी खतरा हो सकता है। हालांकि ये देश काफी प्राचीन और बहुत समृद्ध संस्कृति के वारिस हो सकते हैं। चूंकि विविधता संस्कृति की सर्वाधिक कीमती विशेषताओं में शामिल है, इसलिए पूरी दुनिया गरीब है। प्रभावित कर सकने वाली ऐसी शक्तियां जो सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ावा दे सकती हैं उन्हें रोकना आज की तत्काल जिम्मेदारी है। हालांकि समस्या बहुत आसान नहीं है। इतिहास बताता है कि संकीर्णता सांस्कृतिक गतिहीनता को बढ़ावा देती है। एक संस्कृति अपने खोल में रहकर विकसित नहीं हो सकती है। दूसरी संस्कृतियों के साथ मुक्त साझेदारी और मानव प्रगति की सभी शक्तियों के साथ संपर्क बनाकर विकास किया जा सकता है। लेकिन मुक्त साझेदारी, एक समान लेन-देन के साथ आपसी सम्मान के आधार पर होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए ये भी जरूरी होगा कि संकटग्रस्त संस्कृति को संरक्षण और मजबूती दी जाए, स्थानीय स्तर पर संचार का विकास हो और बड़े मीडिया के दबावों के बदले संचार के वैकल्पिक रूपों की शुरुआत की जाए। इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि एक और दूसरे राष्ट्र के बीच संबंधों में समस्या धीमे-धीमे नहीं आती है, अक्सर तेजी से फैलती है। इसी तरह से यह उन देशों में ज्यादा तीव्र और बहुत खतरनाक होती है जिसकी आबादी में सांस्कृतिक अल्पसंख्यक शामिल होते हैं।

हम अपने समृद्ध सांस्कृतिक भविष्य का निर्माण सिर्फ बहुलतावादी रूप में ही कर सकते हैं। जिसमें संस्कृतियां दुनिया की विविधता का प्रतिनिधित्व करेंगी। वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और अपनी मौलिकता को बचाने के लिए मेहनत करेंगी। इसमें संदेह नहीं है कि परंपराओं के घुलने-मिलने से

एक हद तक संस्कृति के संकर रूप को बनाने में खास मदद मिलेगी। वास्तव में, ऐसा पूरे सांस्कृतिक इतिहास में हुआ है। हालांकि, बदलाव की तेज गति और मानकीकरण के जोखिमों के चलते, यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि प्राथमिक और आम संस्कृति की बजाय हर संस्कृति में सबसे खास और सबसे विकसित संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। सांस्कृतिक विकास अपरिहार्य है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि किन घटकों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए ताकि अधिकतम लाभ मिल सके।

7. तकनीकी दुविधा

सामान्य तौर पर तकनीकी प्रगति और खासतौर से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल ने पहले ही भविष्यवाणी करने और संभावनाओं को समझने में सक्षम बनाया है। साथ ही संभावित जोखिमों और बाधाओं की पहचान भी की जा सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिक लगातार ऐसी प्रगति कर रहे हैं कि वो एक दिन व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच के रुकावटों को तोड़ पाना आसान कर देंगे। बिना किसी संदेह के ऐसे रुझान अपरिहार्य हैं। लेकिन इसके जो नतीजे अब देखे जा सकते हैं वो जरूरी नहीं है कि अनिवार्य रूप से लाभदायक हों।

इसमें कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में हुई तकनीकी प्रगति ने कई सारे असाधारण मौकों के रास्ते खोले हैं जिसमें सभी औद्योगिक देशों और बहुत सारे विकासशील देशों की दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि, राजनीतिक और आर्थिक कारणों के चलते ये अवसर अभी तक सभी की पहुंच में नहीं हैं। कई वैज्ञानिक खोजों और शुरू किए गए तकनीकी नए अविष्कारों पर बहुत थोड़े से देशों और कुछ बहुराष्ट्रीय फार्मों का नियंत्रण है। ये नियंत्रण आने वाले लंबे समय तक बना रह सकता है। ऐसे में ये निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि इस तकनीकी विकास का किस तरह सभी राष्ट्रों और हर राष्ट्र में

प्रत्येक समुदाय को और अंततः सभी पुरुषों और महिलाओं को इसका अधिकतम फायदा मिल सके। इससे असमानता और अन्याय को घटाने में मदद मिल सकती है।

कई सदियों पहले विचारकों द्वारा कही गई बात कि तकनीकी प्रगति मनुष्य की क्षमता से इतनी ज्यादा आगे चल रही है कि वो इसको पूरी तरह से समझ पाने में ही सक्षम नहीं है। ये बात अब और तेजी से फैल रही है। जीव विज्ञान, जेनेटिक्स, परमाणु भौतिकी और साइबरनेटिक्स जैसे क्षेत्रों में ये अंतर परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। नई तकनीक, अपनी गति से या फिर राजनीतिक दबाव और आर्थिक जरूरतों के चलते आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले कि उन्हें आत्मसात किया जाए वो खुद को थोप देती है और नैतिक तथा सामाजिक, दोनों ही नियंत्रणों से बच निकलती है।(11)

नई तकनीकियों का प्रभाव संदिग्ध है क्योंकि वो अपने साथ मौजूदा संचार प्रणाली को अधिक कठोर बनाने का जोखिम लाती हैं और उसकी गड़बड़ियों को और अधिक बढ़ा और दुष्कर कर देती हैं। पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली, एक तरह के और केंद्रीकृत नेटवर्क की स्थापना में सूचना के सार्वजनिक या संस्थागत स्रोतों के केंद्रीकरण पर जोर देने, असमानता तथा असंतुलत के बढ़ने और व्यक्तियों तथा समुदायों, दोनों में लापरवाही और बेबसी की भावना बढ़ने का जोखिम है। सीधा प्रसारण करने वाले सैटलाइट ने रेडियो और चैनलों की उपलब्धता को बढ़ा दिया है। इससे इसके उद्देश्यों और दर्शकों में विविधता लाई जा सकती है। हालांकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने से विषयवस्तु की बेहतरी को बढ़ावा मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आयातित कार्यक्रमों के अधिक इस्तेमाल से सांस्कृतिक निर्भरता को बढ़ावा मिलता है। एक बार फिर, प्रसारण लागत में दूरी के लगातार घटते जाने से (खासतौर से उपग्रह से प्रसारण होने पर, लेकिन माइक्रोवेव, लाइट

कंडक्टर और केबल द्वारा ब्रॉडबैंड डिजिटल प्रसारण में भी) विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानताएं घट सकती हैं। लेकिन इन संसाधनों का बहुसंख्यकों के हाथ में केंद्रित रहने पर ये असमानताएं बढ़ भी सकती हैं। यह भी हो सकता है कि कम्प्यूटर के साथ डाटाबैंक तैयार होने से देशों और क्षेत्रों के बीच की खाई बढ़ सकती है। इसे गरीब देशों की सूचना तक पहुंच बढ़ा कम किया जा सकता है। टेली-इंफोर्मेटिक्स के उभार ने बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा है। इससे राष्ट्रों की दूसरे पर बढ़ती अंतरनिर्भरता और विवाद ज्यादा मजबूत होंगे। परिस्थितियों पर निर्भरता और इस्तेमाल के तरीकों के चलते कम्प्यूटर सेवक भी बन सकता है और स्वामी भी। टेली-इंफोर्मेटिक्स का इस्तेमाल दुनिया को अधिक बांटने और नौकरशाही वाला बनाने के लिए, तकनीकी तंत्र और केंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक और वित्तीय शक्तियों द्वारा लागू किए जाने वाले सामाजिक नियंत्रण को बढ़ाने के लिए और असमानताओं को बरकरार रखने (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर) के लिए किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ये फैसले लेने वालों में विविधता और मीडिया केंद्रों को सुरक्षित बचाकर सामाजिक जीवन को और अधिक खुला, सहज और लोकतांत्रिक बना सकता है। हम इन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं।

संचार के मानवीय पहलू और उसकी तकनीक को सुरक्षित करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नई तकनीक बड़ी संरचनाओं को बढ़ावा देती हैं और काफी हद तक प्रभावित करती हैं। इससे कुछ अर्थों में संचार के अमानवीयकरण को बढ़ावा मिलता है। इस सिलसिले में ऐसा लगता है कि कुछ देश हल्के और दृश्य-श्रव्य मीडिया के इस्तेमाल के पक्ष में हैं।

एक जैसे हितों वाले छोटे समूहों को ध्यान में रख कर बनाए गए हल्के दृश्य-श्रव्य तकनीकों ने मिलकर फैसला करने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

यह अब सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा है। इससे आर्थिक पुर्नविकास वाली परियोजनाओं, स्थानीय और कामकाजी समुदायों के लिए स्वतंत्र सूचना परिपथों (सर्किट) के संगठन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में मदद मिलती है। हल्के, इस्तेमाल करने में आसान और तुलनात्मक रूप से सस्ती वीडियो तकनीक, जिन्हें विभिन्न तरह का काम लिया जा सकता है, ने सांस्कृतिक श्रम के औजार और वस्तुओं के बड़े स्तर पर उत्पादन के बीच दूरी को खत्म किया है। इसने दूरदराज के क्षेत्रों में छितराए लोगों को भी करीब लाया है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ देश संचार मीडिया में उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, सूचना विनिमय में लोकतांत्रिक लोगों की सहभागिता, मीडिया प्रबंधन में भागीदारी आदि को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की सफलता सामाजिक संचार के क्षेत्र में निर्माण तथा वितरण की संरचनाओं के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिकरण का रास्ता बना सकते हैं।

इस दुविधा का समाधान करने के लिए, कड़े निर्णयों और विकल्पों को अपनाना होगा। ये विकल्प न सिर्फ आर्थिक तथा तकनीकों से जुड़े होंगे बल्कि सबसे पहले तो राजनीतिक विकल्पों के बारे में भी फैसला करना होगा। राजनीतिक निर्णय इस तरह लेने होंगे कि कुछ अवांछित आर्थिक और तकनीकी भटकावों को नज़रअंदाज किया जा सके। सभी सामाजिक स्तरों और राष्ट्रीय संस्थाओं की जरूरतों को सुरक्षा दी जा सके और भविष्य की पीढ़ियों के साथ ही पूरी दुनिया के हितों की रक्षा की जा सके।[12]

इस सवाल की जटिलता नई तकनीक के उदय से जुड़ी हुई है और उन बुनियादी मुद्दों को उठाती है जिनका सामना सभी समाजों को करना होगा या पहले ही कर रहे हैं। हालांकि आधुनिक तकनीक, संचार के विकास के लिए नई संभावनाओं की पेशकश करती हैं, लेकिन साथ ही ये समस्या और जोखिम भी तैयार करती हैं। हमें निश्चित रूप से तकनीक के लुभावने पहलू

को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यह हर तरह के काम में इस्तेमाल होने वाला ऐसा औजार है जो सामाजिक गतिविधियों का अतिक्रमण कर सकता है और विकसित तथा विकासशील देशों में संरचनात्मक बदलावों को रोक सकता है। भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि उपलब्ध विकल्पों को लेकर कितने जागरूकता हैं, सामाजिक शक्तियों का संतुलन कैसा है। भविष्य देशों में तथा उनके बीच संचार प्रणाली के लिए जरूरी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के सजग प्रयासों पर निर्भर करेगा।

अध्याय तीन

अंतरराष्ट्रीय आयाम

पहले के अध्यायों में उठाए गए या उठने वाले ज्यादातर सवालों के अंतरराष्ट्रीय पहलू भी हैं। इन सवालों पर नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा इस पेशे से जुड़े लोगों के बीच विश्वव्यापी बहस की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है।

1. मुद्दा

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की प्रमुख घटना संभवतः लगभग 80 देशों का स्वतंत्र होना है। इससे करीब दो अरब लोग उपनिवेशवादी वर्चस्व से आजाद हुए। इसके बावजूद वर्तमान विश्व की हालत राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैन्य के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ देशों के स्थिति और प्रभाव के बढ़ने की तरफ है। ऐसे थोड़े से देशों पर बड़ी संख्या में अन्य देशों की निर्भरता बढ़ने के रुझान दिख रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक आजादी सीमित है जो आर्थिक निर्भरता द्वारा खोखली कर दी गई है। खासतौर से विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों की प्रकृति तथा श्रम के अंतरराष्ट्रीय विभाजन के चलते ऐसा हुआ है। इतना ही नहीं, ये भी लगातार साफ होता जा रहा है कि बौद्धिक तथा सांस्कृतिक निर्भरता के प्रभाव भी उतने ही गंभीर है जितने की राजनीतिक अधीनता या आर्थिक निर्भरता के। संचार के साधनों द्वारा इसे संरक्षण दिए बिना कोई भी वास्तविक, प्रभावशाली आजादी नहीं हो सकती है। ये दलील दी जाती है कि जिस देश का मास मीडिया विदेशी वर्चस्व के अधीन है, वो एक राष्ट्र होने का दावा नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से आज की दुनिया में, संचार प्रायः दो असमान साझेदारों की बीच लेन-देन हो गया है। इससे अधिक शक्तिशाली,

अधिक धनी और बेहतर ढंग के उपकरणों से लैस पक्ष के वर्चस्व को मंजूरी मिल रही है। शक्ति और समृद्धि में अंतर चाहें अपने आप हो या जानबूझकर की गई हो, उसका संचार की संरचना और संचार के प्रवाह पर प्रभाव और असर होता है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय संचार की विशेषताओं में असमानता, विषमता और असंतुलन के कई अंतर्निहित कारण भी हैं, खासतौर से औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच ऐसी असमानताओं में इस तरह के कारण देखे जा सकते हैं।

तकनीकी प्रगति को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि देशों के बीच का संबंध इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और करीबी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का ग्लोबल वेब संभवतः लाखों व्यक्तिगत दिमागों को एक विशाल सामूहिक प्रजा के रूप में जोड़कर तंत्र की तरह काम कर सकता है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक इस पारस्परिक निर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े संरचनात्मक बदलावों किए बिना मुक्त विनिमय, समानता, और सभी के लिए संतुलित लाभ की उम्मीद करना मुश्किल है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या उन बातों से निपटने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है जिसे बाधा के रूप में चिह्नित किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी संचार की भूमिका महत्वपूर्ण और वास्तव में अपरिहार्य है। क्योंकि संचार मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनमत बनाने की क्षमता रखता है। हथियारों की दौड़, अकाल, गरीबी, निरक्षरता, नस्लवाद, बेरोजगारी, आर्थिक अन्याय, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण का विनाश, महिलाओं के प्रति भेदभाव- ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान देशों के बीच सलाह और सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। ये ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनके बारे में यह बताना अनिवार्य है कि वो कितनी गंभीर,

गहरी और दूरगामी हैं। इसके अलावा, किस तरह इसकी समान चुनौतियां और समान खतरे सभी देशों को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया को इस समस्याओं और दूसरी समस्याओं के प्रति अंतरराष्ट्रीय जनमत को सचेत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें बेहतर ढंग से समझने में, उनके समाधान के लिए इच्छाशक्ति तैयार करने में और अगर जरूरी हुआ तो समुचित समाधान के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आम लोगों को तैयार करना है। अगर मीडिया, कौन सी बातें लोगों को बांटती है इसकी जगह सिर्फ इस बात पर अधिक जोर दे कि कौन सी बातें लोगों को जोड़ती हैं, तो दुनिया के लोग शांतिपूर्ण साझेदारी और आपसी समझ के जरिए एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं।

इन उद्देश्यों को हासिल करने में संचार के महत्व को लगातार स्वीकार किया जा रहा है। अपने पेशे से पूरी तरह से जुड़े संचारक (मीडियाकर्मी) अपने उत्तरदायित्व को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। फिर भी, इन उत्तरदायित्वों की सीमा और उनके निर्वाह के तरीकों को लेकर अलग-अलग राय है। समस्या दो अनिवार्यताओं को मिलाने की है। पहला, सूचना के साधनों से सकारात्मक योगदान की उम्मीद, जिसे कुछ लोग मनुष्य के विकास और मानव जाति के अस्तित्व से जुड़े कुछ बड़े सवालों के संदर्भ में जनमत जुटाने या लोगों को एकजुट करने को अपने कर्तव्य की तरह लेंगे। दूसरा, प्रेस की आजादी है, इसे भी एक कर्तव्य के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि तथ्यों को महज इसलिए उजागर करना भी जरूरी है क्योंकि वो तथ्य हैं। हालांकि आयोग की राय है कि सैद्धान्तिक रूप से इन दोनों अवधारणाओं के बीच कोई दुर्लभ दुविधा और मुश्किल संघर्ष नहीं है।

2. असंतुलन और असमानताएं

संचार के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं के मुद्दों का मूल नई विश्व परिस्थितियों की हकीकत में है। विशेषकर चिंताएं, दावा और संघर्ष पैदा करने वाली तत्काल की अंतरराष्ट्रीय बहसों की जड़ बहुत पहले अपनाए गए सिद्धान्तों के कुछ नकारात्मक नतीजों में है।

संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के गठन के समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने खुद के लिए कुछ निश्चित लक्ष्य तय किए थे इसमें स्वतंत्रता और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह की गारंटी और उसे बढ़ावा देना शामिल था। इस सिद्धान्त को दृढ़ता से मानव अधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय साधनों के लिए घोषित किया गया।[13] उनकी वैधता पर फिर से जोर दिए जाने और फिर से पुष्टि करने की जरूरत है।

हालांकि, संचार में जगजाहिर असंतुलन इस राय का समर्थन करता है कि 'मुक्त प्रवाह' कुछ और नहीं बल्कि 'एक तरफा प्रवाह' है, और ये जिस सिद्धान्त पर आधारित था उसे फिर से दोहराना चाहिए ताकि 'मुक्त और संतुलित प्रवाह' की गारंटी की जा सके। पीछे 1950 के दशक में जाएं तो इन सिद्धान्तों की कुछ धुंधली शुरुआत दिखती है, 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरू में ये अधिक स्पष्टता के साथ परिभाषित होने लगे। समय के साथ औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच समाचारों और सूचनाओं के प्रवाह में असंतुलन अंतरराष्ट्रीय बैठकों का प्रमुख मुद्दा था। ठीक वैसे ही जैसे ऐसी बैठकों में समकालीन विश्व में बुनियादी राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बहस होती थी। आज वास्तव में इस असंतुलन की सच्चाई पर अब कोई विवाद नहीं है। हालांकि इस अवधारणा के ठोस इस्तेमाल के बावजूद इस पर कोई आम सहमति नहीं है। समस्या के उपचार और आवश्यक नीतियों की कमी है। यही वजह है कि मुक्त प्रवाह और एकतरफा

प्रवाह, संतुलन और असंतुलन की अवधारणा बहस का मुद्दा और अंतरराष्ट्रीय विवाद का विषय बन गई है।

समाचारों के प्रसार में असंतुलन एक जटिल और बदलते रहने वाली परिघटना है। मात्रात्मक और गुणात्मक की तरह ये विभिन्न स्तरों और विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैः (क) विकसित और विकासशील देशों के बीच, जहां सूचना का प्रवाह उपलब्ध और अनुपलब्ध समुचित बुनियादी ढांचे से तय होती है, (ख) भिन्न राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के बीच, (ग) समान राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विकसित देशों के बीच, खासतौर से छोटे और बड़े देशों के बीच (घ) स्वयं तीसरी दुनिया के देशों के बीच, (च) अल्पविकास की बीमारी से जूझ रहे देशों में राजनीतिक खबरों और उन खबरों के बीच जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित हैं, (छ) उनके बीच जिसे परंपरागत रूप से 'अच्छी' खबर और 'बुरी' खबर कहा जाता है जैसे आपदाओं, विफलताओं, संघर्ष, बाधाओं, गलतियों और ज्यादतियों की खबरें और अंत में (ज) समसामयिक घटनाओं की खबरों और उन सूचनाओं के बीच जो लोगों और राष्ट्रों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ अधिक गहराई से काम करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोई एकमात्र, सार्वभौमिक कसौटी नहीं है जिसके जरिए असंतुलन और विषमताओं को मापा जा सके, चूंकि खबरों का महत्व एक देश से दूसरे देश में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, और यहां तक कि कभी एक ही देश में अलग-अलग होता है। ऐसे में खबरों के महत्व को लेकर कोई भी सामान्यीकरण अस्पष्ट होगा, भले ही पेशेवर संचारक खबरें बनाने के लिए कई कारकों पर विचार करने के लिए सहमत हो जाएं तो भी।

आज ऐसे असंतुलन सामान्य अर्थों में खबरों के प्रवाह तक सीमित नहीं हैं। ये लगातार बढ़ते हुए अब एक गंभीर स्तर तक वैज्ञानिक उद्देश्यों, नए

तकनीकी खोजों, वाणिज्यिक जरूरतों, व्यापार के विकास, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, मौसम की भविष्यवाणी, सैन्य उद्देश्यों आदि के लिए आवश्यक आंकड़ों के संग्रहण और प्रसार को भी प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने के लिए सामरिक जानकारी को लेकर एक असंतुलन है।

पूरी तरह से सूचना रखने वाले और थोड़ी बहुत सूचना रखने वाले देशों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जो सूचना दे रहे हैं और जो पा रहे हैं उनके बीच असंतुलन अधिक स्पष्ट हो गया है। हालांकि ये मानना सही होगा कि सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह बहुत बढ़ा है और इससे सूचना स्रोतों के काम में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इस बात पर जोर देना भी जरूरी है कि संचार ने संप्रेषित संदेश के प्रभाव को नियंत्रित करने के साथ ही उपलब्ध सूचना के चयन की अपनी शक्ति में बढ़ोतरी की है। साथ ही इससे जुड़ी गड़बड़ियां और असंतुलन कुछ हद तक उन समाजों के वर्चस्वशाली हितों को दिखाते हैं, जिनमें वो पैदा हुए हैं।

ये हालात अंतरराष्ट्रीय समझ और राष्ट्रों के बीच सहयोग को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रह सकती। विभिन्न देशों में प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक दशाओं को प्रभावित किए बिना और दुनिया की आबादी तथा विश्व शांति की रक्षा से संबंधित अनिवार्य समस्याओं के समाधान के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के उपायों को नुकसान पहुंचाए बिना ये हालत जारी नहीं रह सकते हैं।

3. अंतरराष्ट्रीय बहस

ऐसे में, 1970 के आस-पास पहली बार वो अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई, जिस पर आज की अंतरराष्ट्रीय बहस केंद्रित है। इस बहस के इतिहास के प्रत्येक चरण को न भी दोहराए जाए तो भी उन प्रमुख थीमों को याद

कर लेना भी काफी होगा जिस पर कई सारे धुरंधर (अग्रणी पक्ष) अब विचार कर रहे हैं। ऐसे धुरंधरों में सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, विशेषज्ञ एजेंसियां, क्षेत्रीय संगठन, शोध केंद्र, राजनीतिक आन्दोलन, पेशेवर संघ, मास मीडिया, पत्रकार और राजनीतिज्ञ आदि शामिल हैं।

सबसे पहले, वो आलोचनाएं जो कई विकासशील देशों में हो रही हैं कि कुछ शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत देश अपनी उन्नति का इस्तेमाल सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व कायम करने के लिए कर रहे हैं, जिसने दूसरे देशों की राष्ट्रीय पहचान को खतरे में डाल दिया है। इस तरह की आलोचना का कुछ समाजवादी और पश्चिमी देशों के भी कुछ शोधकर्ताओं और पत्रकारों ने समर्थन किया है। सूचनाओं के एकतरफा प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय प्रवाह [14] पर एकाधिकार रखने और थोड़ा सा अधिकार देने की प्रवृत्ति से उठी समस्याओं पर कई अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में व्यापक चर्चा हुई। खासतौर से ये भी बार-बार कहा गया कि ज्यादातर विषयवस्तु का निर्माण प्रमुख विकसित देशों द्वारा किया जाता है जिसके चलते विकासशील देशों की छवि अक्सर झूठी और विकृत हुई है। कुछ बड़े आलोचकों के मुताबिक सबसे गंभीर बात ये है कि इस झूठी छवि ने उनके आंतरिक संतुलन को नुकसान पहुंचाया है, जो विकासशील देशों के लिए खुद प्रस्तुत की जाती है। सैटलाइट से सीधे प्रसारण की क्षमता से पैदा हुए जोखिम और डर ने सूचना के संतुलित प्रवाह की मांग को बढ़ावा दिया है। उस समय पहली बार इन सवालों पर चर्चा हुई कि संप्रेषित सूचना की विषयवस्तु और गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही विकासशील देशों में समाचार के निर्माण और संप्रेषण को लेकर जागरूकता की कमी को भी रेखांकित किया गया।

दूसरी ओर मीडिया से जुड़े कई लोग मानते हैं कि इन असंतुलन और जोखिम, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, के साथ ही एकतरफा समाचार प्रवाह पर ज्यादा जोर देने का मतलब है कि आगे चलकर सूचना की आजादी पर रोक लगाना है। इससे उन लोगों के हाथ मजबूत हो सकते हैं जो सूचना के अंतर्प्रवाह को सीमित करने के पक्षधर हैं। इसका नतीजा मुक्त प्रवाह की अवधारणा में एक तीखे रुकावट के रूप में होगा। ये मानते हुए कि विचारों, समाचारों, संदेशों और स्रोतों की विभिन्नता एक वास्तविक लोकतांत्रिक संचार की पूर्व शर्त है, ये विचारक इस बात को भी मानते हैं कि 'सूचनाओं की उपनिवेशिक स्वतंत्रता' सरकारी अधिकारियों के विशेष नियंत्रण के तहत सूचना देने के बहाने के रूप में नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने लोगों पर अपनी छवि थोपने के लिए इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय संचार की बहस में, पारदेशीय (transnational) की भूमिका महत्वपूर्ण है।[15] ये मिश्रण न सिर्फ पूंजी और तकनीकों को जुटाते हैं और उन्हें संचार बाजार के रूप में परिवर्तित करते हैं। ये अनगिनत सामाजिक-सांस्कृतिक वस्तुओं की भी मार्केटिंग करते हैं जो विचारों, स्वाद, मूल्यों और विश्वासों के मिश्रण के लिए संवाहक के रूप में काम करता है। पारदेशीय का उन देशों के आर्थिक उत्पादन उपकरणों पर सीधा प्रभाव होता है, जहां से वो काम कर रहे होते हैं। साथ ही वो उनकी संस्कृति के वाणिज्यिकरण में भी भूमिका निभाते हैं और इस तरह पूरे समाज के सामाजिक-संस्कृति केंद्र बिंदु (Focus) को ही बदल देते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विकास की अवधारणात्मक बुनियाद में शामिल कारक के रूप में अंतरराष्ट्रीय संचार की संरचना में बदलाव पर अक्सर जोर दिया जाता है। ये दलील दी जाती है कि आपसी सहमति, विविधता को

अपनाने, शांति तथा सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने, वास्तविक आजादी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाली दुनिया बनाने के लिए न केवल अंतरराष्ट्रीय संचार की जरूरत होगी बल्कि नए और अलग तरह के अंतरराष्ट्रीय संचार के लिए जगह बनानी होगी। अगर विकास का खाका रेखीय, मात्रात्मक और बढ़ाने वाली प्रक्रिया के रूप में आयात हुई और तेजी से बदलने वाली तकनीक पर आधारित हो तो उसे देशज गुणात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए बदल देना चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मानव के व्यापक जरूरतों के अनुरूप हो, उसका उद्देश्य गैर बराबरी को खत्म करने वाला हो और इस तरह की उचित तकनीकों पर आधारित जो सांस्कृतिक संदर्भों का सम्मान करती हों और उस संस्कृति के लोगों की भागीदारी कराने व बढ़ाने वाली हो। तब इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता और राष्ट्र के बीच संचार कुछ अलग तरह का होगा।

निर्गुट देशों ने मीडिया की निर्भरता, समाचारों के प्रवाह तथा वैश्विक संचार ढांचे में असंतुलन और इस असंतुलन के नकारात्मक प्रभावों को लेकर विचारों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने ये बात कही की दुनिया भर के बहुत सारे देशों की भूमिका घटकर सूचनाओं के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की रह गई है, जबकि सूचनाएं कुछ थोड़े से केंद्रों पर तैयार होती हैं।

इस प्रकार संचार और सूचना के क्षेत्र में 'पुरानी व्यवस्था' से अलग एक 'नई व्यवस्था' की मांग उठी है। नई व्यवस्था की जरूरत के पीछे यह दृढ़ विश्वास भी काम कर रहा है कि सभी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सूचना और संचार महत्वपूर्ण कारक हैं। नई व्यवस्था खासतौर से बराबर अधिकारों के साथ और देशों तथा लोगों की आजाद और मुक्त विकास के सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए संचार में बदलाव का मामला नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बुनियादी अवधारणा से जुड़ा है। कुछ

मामलों में विकास और संचार एक जैसे ही सिद्धान्तों पर चलते या आधारित होते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि अपनी अर्थव्यवस्था और संचार के मामले में आज के विकासशील देशों की निर्भरता इस तरह की है जो अब तक सबसे ज्यादा असमानताओं को बढ़ाने वाली है। प्राकृतिक वस्तुओं और मानव संसाधन (खासतौर से फिर से इस्तेमाल न की जा सकने वाली) को हानि पहुंचाने वाली तकनीक को राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ सहयोग और एक-दूसरे पर निर्भरता वाले संबंधों के साथ बदल देना चाहिए ताकि वो क्रमशः स्वायत्त और देशज विकास में सक्षम होते जाते हैं। नई संचार व्यवस्था को निश्चित रूप से नई आर्थिक व्यवस्था के घटक के तौर पर माना जाना चाहिए और दोनों का विश्लेषण करने के लिए समान पद्धति लागू की जानी चाहिए। खासतौर से वैश्विक और सार्वभौमिक दोनों स्तर पर बहुलतावादी नज़रिए की मांग करते हैं क्योंकि मानवता जिन प्रमुख समस्याओं से जूझ रही है उनका समाधान केवल विश्व स्तर पर ही हो सकता है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण सहसंबंध है, जिसे इस तथ्य से बल मिलता है कि सूचना एक खास और बुनियादी किस्म का आर्थिक संसाधन है (और सिर्फ उत्पाद नहीं) जो हर सामाजिक गतिविधि के लिए अनिवार्य है लेकिन आज वो असमान रूप से वितरित, बहुत ही खराब तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। कुछ अलग रूपों में नई संचार व्यवस्था नई आर्थिक व्यवस्था की पूर्व शर्त है, क्योंकि संचार समूहों, लोगों और राष्ट्रों के बीच सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य घटक है।

बहस के इस स्तर पर, नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था एक खुला वैचारिक ढांचा है, जो उन लोगों का ध्यान खींच सकता है, जो इन बातों के लिए चिंतित हैं (क) संप्रभु संस्थाओं के बीच बराबरी के संबंधों की स्थापना के लिए तैयार किए गए लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर स्वतंत्र, अधिक न्यायपूर्ण, अधिक प्रभावशाली और बेहतर संतुलित अंतरराष्ट्रीय संचार प्रणाली

के निर्माण को प्रभावित करने वाली समस्याओं को चिन्हित और परिभाषित करना, (ख) शुरुआत में अधिक तात्कालिक और व्यवहारिक कार्यों पर ध्यान देते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहभागी चर्चा को बढ़ावा देना, (ग) इसमें शामिल राजनीतिक विकल्प को स्पष्ट करना। वास्तव में ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया शुरू करने का मसला है, जिसमें प्रमुख रूप से न सिर्फ संबंधित लोगों बल्कि सभी समाजों को शामिल करना है, जो अकादमिक चर्चाओं को कम बल्कि प्रभावशाली, व्यवहारिक कदमों को अधिक महत्व देते हों। हालांकि, हमें इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नई व्यवस्था की स्थापना से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था में बड़े बदलाव आएंगे। इसे वैश्विक आबादी के गरीब से गरीब तबके की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और ये मान कर चला जा रहा है कि उनके महत्वपूर्ण अधिकारों और जरूरतों के मुताबिक उपलब्ध संसाधनों का नए ढंग से वितरण होगा।

ये चिंताएं और कई दूसरे संबंधित दावे, अंतरराष्ट्रीय बहस को बढ़ावा देते हैं। स्वाभाविक है कि ऊपर जिन दावों और विकल्पों की चर्चा हुई है उनका कुछ लोग जोरदार ढंग से बचाव करते और दूसरे लोग उतने ही जोरदार ढंग से उस पर विवाद करते दिखेंगे। हालांकि इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस तरह के दावे और प्रतिदावे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूनेस्को द्वारा अपनाए गए कई निर्णयों और संकल्पों की बुनियाद तैयार करते हैं। खासतौर से ऐसे फैसले जिसने इस अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई।

4. यूनेस्कोः दुनिया के लिए एक खुला मंच

संचार के क्षेत्र में यूनेस्को एक ऐसा मंच बन गया है जहां मुद्दे उठाए जा सकते हैं और गंभीरता से चर्चा की जा सकती है। इसकी कार्रवाई और पहल कदमियों का काफी हद तक शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसके चलते हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हुआ है। समस्याओं की जटिलताओं को महसूस किया गया है और इस बात की समझ बनी है कि मामले की गहराई में जाकर पड़ताल करने और जहां तक संभव हो सके प्रभावशाली ढंग से केंद्रित प्रयासों की कितनी आवश्यकता है जाना जाये। अंतरराष्ट्रीय संचार के मामलों में स्थितियों के मूल्यांकन के दौरान उल्लेखनीय रूप से सामंजस्यपूर्ण संबंधों की बहाली देखने को मिली है।

1960 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को ने कुछ प्रमुख पेशेवर संगठनों की मदद से समाचारों के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह की व्यवस्था के लिए काफी प्रयास किए। विकासशील दुनिया में राष्ट्रीय समाचार एजेंसी स्थापित करने और अभिव्यक्ति के साधनों को बढ़ाने का काम शुरू हुआ। इन देशों के साझा हितों के लिए समाचारों, फिल्मों और विभिन्न प्रसारणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके बीच संपर्क स्थापित की परियोजनाओं पर भी काम शुरू हुआ। खासतौर से क्षेत्रीय प्रेस एजेंसियों और शिक्षा तथा विकास के लिए उपग्रह प्रसारण प्रणाली की स्थापना के लिए क्षेत्रीय सहयोग की विभिन्न संभावनाओं को खंगाला गया। खासतौर से आम सभा (1970) के 16वें सत्र में ऐसा हुआ कि कई विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से मीडिया के असमान वितरण के मुद्दे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे और संतुलित अंतरराष्ट्रीय समाचार के प्रवाह की प्रणाली गठित होनी चाहिए और सांस्कृतिक पहचान के अधिकार पर जोर देना चाहिए।[16] दो

साल बाद, सदस्य देशों के बहुसंख्यक प्रतिनिधिमंडल ने दृढ़तापूर्वक समाचार के प्रवाह में असंतुलन की आशंका से होने वाले जोखिमों पर जोर दिया। यूनेस्को के महासचिव को इस बात का अधिकार दिया गया कि वो संचार शोध और खासतौर से संचार नीतियों को तय करने में संभावित मूल्यों से जुड़ा शोध कराएं। विकास के काम से जुड़ी राष्ट्रीय रणनीतियों तय करते समय उसमें संचार को स्थान देना के बारे में शोध कराने के लिए भी महासचिव को अधिकृत किया गया। वर्ष 1974 में इसके 18वें सत्र में राष्ट्रों के बीच और लोगों के बीच संचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय विकास नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में मीडिया द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए आम सभा ने सिफारिश की कि लैटिन अमेरिका में 1975 में संचार नीतियों पर प्रथम अंतरसरकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इसी तरह के एक अंतरसरकारी सम्मेलन की तैयारी और आयोजन 1977 में एशिया में किया जाए।

संचार नीतियों पर पहले सम्मेलन का आयोजन जुलाई 1976 में सैनजोस डी कोस्टा रिका में किया गया। इसमें सर्वसम्मति से नई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संचार नीतियों के गठन सिफारिश की गई। सम्मेलन में खासतौर से कहा गया कि राष्ट्रीय संचार परिषद की स्थापना होनी चाहिए, इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध का विकास होना चाहिए और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय समाचार एजेंसियों की स्थापना होनी चाहिए। उस अवसर पर स्वीकार किए गए सैन जोस घोषणा पत्र में इस तथ्य को रेखांकित किया कि आज संचार ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्रीय नवजागरण के पहले आता है और साथ ही वो राष्ट्रों के बीच संबंधों में शक्तिशाली कारक की भूमिका निभा रहा है। इस बात पर जोर दिया गया कि "राष्ट्रीय संचार नीतियों को राष्ट्रीय हकीकत, विचारों की बेरोकटोक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत तथा सामाजिक अधिकारों के सम्मान के मुताबिक तैयार करना चाहिए।" ऐसा ही एक

सम्मेलन फरवरी 1979 में कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन खासतौर से एशिया और ओशिनिया के संदर्भ में था। इस सम्मेलन में संचार नीति के सभी पहलुओं पर विचार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि संचार, राष्ट्र की सामूहिक पहचान और सामाजिक एकता को कायम रखने का माध्यम है। इसकी सामाजिक संबंधों के लोकतांत्रिकरण में अहम भूमिका है। यह संदेशों को कई तरह से प्रसारित होने की छूट देता है सीधे और लंबवत दोनों तरह से, मीडिया से जनता तक और उस जनता से मीडिया तक। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरल और सामंजस्यपूर्ण संचार नीतियों को ठीक से परिभाषित करने का ये प्रयास आने वाले वर्षों में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा।

दुनिया के मौजूदा हालत में ये सभी मुद्दे जाहिर तौर पर विवाद के विषय हैं और इस पर गरमागरम बहस और यहां तक की भीषण टकराव का भी मौका दिया गया है। हालांकि ऐसे मसलों पर यूनेस्को में लिए गए ज्यादातर फैसलों में सर्वसम्मति रही है, लेकिन उन्हें वास्तव में लागू करना एक कठिन प्रक्रिया थी। मानव जाति जिन प्रमुख समस्याओं का सामना कर रही है और उनके संभावित समाधान को लेकर जनमत को सतर्क करने में अधिक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मास मीडिया को प्रेरित कर सकने वाले सामान्य नियमों और सिद्धान्तों को तैयार करने के लिए इसी दौरान समन्वित रूप से उठाए गए कुछ कदमों को लेकर तीव्र विवाद भी हुए। इसके पीछे ऐसे मानक तरीकों को अपनाने का विचार था जिसमें ऐसे सिद्धान्त शामिल होंगे जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बौद्धिक और नैतिक एकता मिली होगी। हालांकि ये तरीके सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगे। इस दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया लंबी और कठिन थी।

विकसित और विकासशील दोनों देशों के सरकारी प्रतिनिधियों और पेशागत लोगों ने कई आपत्तियां और नए सुझाव दिए। पश्चिमी देशों के कई मझे लोग, खासतौर से पत्रकारों ने मसौदा घोषणापत्र में शामिल विचारों की प्रवृत्ति को लेकर अपनी आशंका, आलोचना और विरोध खुलकर जाहिर किया। वो कुछ सरकारों को लेकर चिंतित थे, जिन्होंने खुलकर या दबे-छिपे प्रेस की आजादी का विरोध किया था। उनका तर्क था कि ऐसी सरकारें असंतुलन को सही करने के नाम पर ऐसे कदम उठा सकती हैं जो सूचना और मीडिया पर नियंत्रण थोपने के समान हो सकते हैं। वे सेंसरशिप लागू कर सकती हैं और "गैर-जिम्मेदार" का ठप्पा लगाकर खासतौर से विदेशी संवाददाताओं के काम में रुकावट डाल सकती हैं। यहां तक कि उन्हें रोक भी सकती हैं। उनका कहना था कि मसौदा घोषणा पत्र में मानव अधिकारों को लेकर किसी सकारात्मक संदर्भ की कमी है। उसमें विविध समाचार सूत्रों तक पत्रकारों की बेरोकटोक पहुंच की गारंटी नहीं की गई है। उसमें समाचार केंद्रों की विविधता की वांछनीयता का भी उल्लेख नहीं है। अंत में, उन्होंने यूनेस्को द्वारा सोची गई भूमिका पर आपत्ति की, उसके उद्देश्यों को "समाचारों के प्रवाह पर नियंत्रण" की इच्छा के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने यूनेस्को पर वास्तविक मुद्दों से भ्रमित करने का आरोप लगाया। कुछ सूचना संस्थानों ने इससे आगे बढ़कर यूनेस्को को दुश्मन बता डाला और "बहुत देर होने से पहले ही यूनेस्को को रोकने" का आह्वान किया।

बारी-बारी से कई मसौदे प्रकाशित किए गए। इन मसौदों पर पहले विशेषज्ञों की बैठक में तथा बाद में सरकारी स्तर पर गर्मजोशी से उन पर चर्चा और आलोचनाएं हुईं। विरोध सिर्फ साधन या तरीकों को लेकर नहीं था बल्कि सिद्धान्तों के गठन और इन सिद्धान्तों को लागू करने के तरीकों को लेकर भी था। दुनिया में इस तरह के किसी मसौदे की संभावना को लेकर उनमें भी अविश्वास था। वो भी इस मुद्दे पर हमारी ही तरह बंटे हुए थे। आम सभा के

19वें सत्र (नौरोबी, 1976) में कुछ सरकारों और कई देशों के पेशेवर समुदायों की तरफ से आया ये विरोध इतना अधिक मजबूत था कि उचित समाधान केवल यही लगा कि समस्या को लेकर और अध्ययन किया जाए और तब तक के लिए सभी फैसलों को टाल दिया जाए। इस तरह कोई फैसला नहीं करने का फैसला उस समय बुद्धिमानीपूर्ण और लाभदायक साबित हुआ। अगले सत्र (पेरिस, 1978) के दौरान शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ को मजबूत करने के लिए, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, जातिवाद तथा रंगभेद का मुकाबला करने और युद्ध को मात देने के लिए मास मीडिया के योगदान के विषय में बुनियादी सिद्धान्तों के बारे में घोषणा पत्र के मसौदे को सहमति के साथ स्वीकार कर लिया गया। सदस्य देशों ने यूनेस्को के कार्यक्रमों को संचार के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से समर्थन दिया।

इसके बावजूद, केवल सरकारों की सहमति मिल जाने से सभी पेशेवरों और अन्य संबंधित समूहों तथा जनमत के सभी वर्गों का समर्थन अपने आप नहीं मिल गया। घोषणा पत्र में शामिल सिद्धान्तों और दिशानिर्देशों की व्याख्या के साथ ही उसके संभावित दुरुपयोग को लेकर अभी भी चिंताएं थीं। यूनेस्को के अच्छे इरादों को स्वीकार करने के बावजूद कुछ लोग अभी भी ये सोचते थे कि इस घोषणापत्र से फायदे के मुकाबले नुकसान अधिक होंगे। ये प्रेस की आजादी में हस्तक्षेप को वैध ठहरा सकता है। इस क्षेत्र में डर और चिंताओं को गंभीरता से लेना और समाचारों के समर्थन में गलतियों को दूर करने के अधिकतम संभव उपायों को सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि बहस अभी भी जारी है। ये भी सही और जरूरी है कि बहस आगे भी जारी रहनी चाहिए।

सभी राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बावजूद, इस बहस ने संचार की समस्याओं और उसके बहुत से दुष्प्रभावों को रेखांकित किया है जो निश्चित

रूप से उसमें शामिल हैं। ये वो समस्याएं हैं जिन्हें इस रिपोर्ट के पहले हिस्से में उनकी विविधताओं और जटिलताओं के साथ रेखांकित किया गया है और इसके अगले हिस्सों में उनका व्यापक गहराई और विस्तार के साथ वर्णन और विश्लेषण किया जाएगा।

इस बहस के संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि नौरोबी बैठक में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने दलील दी कि आधुनिक समाज में संचार की समस्याओं का अध्ययन अधिक विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। इसके फलस्वरूप महानिदेशक ने बैठक के समापन के अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा: "वास्तव में आपने सचिवालय से कार्रवाई करने के लिए कहा है लेकिन आपने संचार की भूमिका, उद्देश्य और दशाओं की अधिक गहराई के साथ जांच करने के लिए भी कहा है। जैसा कि इस बारे में इससे पहले हुई चर्चा में मैंने कहा था कि आपने मुझे जो जनादेश दिया है उसके दायरे में रहते हुए हमें जो काम करने के लिए कहा गया है उसके समर्थन में मैं व्यापक विचार-विमर्श करना चाहता हूं और जरूरी हो तो एक चर्चा समूह भी बनाया जाएगा। "

कुछ महीनों बाद ही महानिदेशक ने आयरलैंड के सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में एक अंतरराष्ट्रीय आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। आयोग का काम वर्तमान समाज में संचार की सभी समस्याओं का अध्ययन करना था। आयोग को मिले आदेश में विशेष रूप से चार मुख्य बातों की जांच और उस पर चर्चा करना शामिल था, जो इस प्रकार हैं:

(क) संचार और सूचना के क्षेत्र में मौजूदा स्थितियों का अध्ययन करना और उन समस्याओं की पहचान करना जो राष्ट्रीय स्तर पर और सम्मिलित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताजा कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सामाजिक-आर्थिक दशाओं व स्तरों और विकास के प्रकारों की विविधता को ध्यान में

रखते हुए आज के विश्व में संचार की अवस्था और खासतौर से समग्र रूप से सूचना की समस्याओं का विश्लेषण।

(ख) आम सभा के निर्णयों के अनुरूप दुनिया में सूचना के मुक्त और संतुलित प्रवाह से संबंधित समस्याओं के साथ ही खासतौर से विकासशील देशों की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना।

(ग) नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रतिष्ठानों और "नई विश्व सूचना व्यवस्था" के संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उपायों के परिप्रेक्ष्य में संचार की समस्याओं का उसके विभिन्न पहलुओं के अनुसार विश्लेषण करना।

(घ) संचार की उस भूमिका को परिभाषित करना, जिसे वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित कार्रवाई के जरिए दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख समस्याओं के प्रति जनमत को जागरूक बनाने में, इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने में और क्रमिक रूप से उनका समाधान करने में निभा सकता है।

इन सवालों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को की आम सभा के 20वें सत्र (पेरिस, अक्तूबर-नवंबर 1978) में एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए आम सभा ने प्रस्ताव 4/9.1/3 को मंजूरी दी, जिसके अनुच्छेद 1 में आयोग को मिले आदेश को स्पष्ट किया गया है। जिसमें महानिदेशक ने अंतरराष्ट्रीय आयोग के सदस्यों से अपील की है कि "वो संचार की समस्याओं का अध्ययन करें और अपनी अंतिम रिपोर्ट में प्रभावी विश्व सूचना व्यवस्था की स्थापना के लिए ठोस और व्यावहारिक तरीकों के बारे में बताएं।"

संक्षेप में, अंतरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना एक ऐसे समय में हुई जब विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां दिख और उभर रही थीं। ये प्रवृत्तियां दिखाती हैं कि- (क) सामाजिक परिघटना के रूप में संचार का महत्व बढ़ रहा है और

फलस्वरूप संचार मीडिया के विकास में रुचि देखने को मिल रही है (ख) इस क्षेत्र में तकनीक का बढ़ता प्रभाव और उसकी प्रतिक्रिया (ग) राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वर्चस्व और निर्भरता की परिस्थितियों को दूर करते हुए अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रवाह का पुनर्मूल्यांकन (घ) 1960 के दशक में उपनिवेशों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया के बाद कई विकासशील देशों में संचार के मामलों को लेकर अपनी निर्भरता को घटाने के बारे में जागरूकता बढ़ी है; (च) दुनिया की प्रमुख समस्याओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय समझ और जागरूकता को बढ़ावा देने में संचार की बढ़ती क्षमता। इन प्रवृत्तियों ने संचार से संबंधित कुछ सीधे और पूर्वाग्रहों पर आधारित सवालों को बढ़ावा दिया है। ठीक इसी समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक अनुभवों से कई संदेह और सवाल उठे। कई लोगों को ऐसा लगने लगा है कि संप्रभुता, अस्मिता और स्वतंत्रता सिर्फ औपचारिक राजनीतिक निर्णयों से नहीं मिल सकती है। बल्कि ये सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर भी निर्भर है और शायद उन पर अधिक निर्भर है। संक्षेप में कहें तो ये उन परिस्थितियों पर निर्भर है जो लगातार बढ़ते हुए सभी के और सभी देशों के संपूर्ण विकास को जोड़ती है।

भाग – 2

आज के समय में संचार

अध्याय 1

संचार के साधन

समकालीन समाज में संचार के विशाल आकर और विविधता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है क्योंकि इसमें निरंतर बदलाव हो रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से मानव क्षमता, सरल संचार उपकरण और संचार की सेवा देने वाले व्यक्ति, समूह और लोग; जटिल आधारभूत संरचनाएं और प्रणालियां; उन्नत प्रौद्योगिकी, संदेशों को इकट्ठा करने, उत्पादन करने, भेजने और प्राप्त करने वाली मशीनें और अन्य सामग्री; संचार की दुनिया में भाग लेने वाले अनगिनत व्यक्तिगत और संस्थागत साझेदार और प्रतिभागी शामिल हैं।[17]

जो सांकेतिक चिन्ह या साधन किसी संदेश को ले जाते हैं वे बस एक वास्तविकता के दो पहलू उजागर करते हैं। सांकेतिक चिन्ह, इशारे, संख्या, शब्द, चित्र, सब अपने आप में संचार के साधन हैं और मध्यम भी, चाहे वह हाथ से लिखा कागज हो, छपा पन्ना हो, रेडियो हो या टेलीविजन ये न केवल संदेश को ले जाते हैं बल्कि, साथ ही संचार का एक प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए संचार एक सर्वव्यापी 'वैश्विक' घटना है जिसे संक्षेप में अलग-अलग, स्वतंत्र भागों में वर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी उस सम्पूर्ण घटना के अभिन्न अंग हैं। लेकिन ये सभी तत्व दुनिया के हर हिस्से में - जाहिर है अलग-अलग अनुपात में और अलग महत्व और प्रभाव के साथ- वर्तमान में मौजूद हैं।

1. संकेत और शब्द

प्राचीन काल से मानव जाति ने संचार के क्षेत्र आदिम और साधारण तरीके अपनाए। आगे चलकर ये तरीके धीरे-धीरे और बेहतर हुए, बढ़े और उनमें सुधार हुआ जो आज भी सभी समाजों में प्रचलन में है, केवल उन नई तकनीकों जिनमें लगातार आविष्कार और उसमें नए सुधार होते जा रहे हैं और लोगों की बातचीत में आ रही जटिलताओं को छोड़कर। अपनी भावनाओं और जरूरतों को जाहिर करने के लिए लोगों ने संचार स्थापित करने के लिए पहले अपने शरीर का इस्तेमाल किया। "शारीरिक भाषा" और अन्य गैर मौखिक भाषा [18] का इस्तेमाल बहुत से उद्देश्यों से पारंपरिक समाज में सदियों से किया जा रहा है। अपनी स्पष्ट सीमाओं के बावजूद आज भी इसकी वैधता और महत्व कम नहीं हुए हैं। इसलिए, न केवल मनोरंजन करने के लिए बल्कि नजरिए और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए घुमंतू नृत्य और मूक प्रदर्शन समूहों, कठपुतली शो और अन्य लोक संचार के माध्यम कई देशों में लोकप्रिय हो रहे हैं।

चित्र अक्सर शब्दों से पहले प्रभाव डालते हैं। लेकिन मानवीय संचार में भाषा का विशेष महत्व है, विशेष रूप से याद करने और ज्ञान को आगे ले जाने की क्षमता में और अपेक्षाकृत जटिल अवधारणाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता में। यह वास्तव में, पारस्परिक संचार का केवल एक माध्यम ही नहीं है बल्कि अपरिहार्य माध्यम है। बोली में अभी भी वह शक्ति है जो प्रौद्योगिकी या जनसंचार माध्यमों के द्वारा बदली नहीं जा सकता है। यह संपर्क के असंख्य नेटवर्क की जीवन रेखा है।

उन समुदायों में जो अलगाव में रहे या आकार में छोटे रहे या वहां निरंतर निरक्षरता बनी रही वहां परंपरा, बोली और प्रदर्शन के अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। उन समाजों में सूचना के आदान-प्रदान के ये इकलौते नहीं फिर भी

बहुत ही आम उदाहरण हैं। औद्योगिक देशों में केवल उन कुछ अलग-थलग क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों से सूचना के स्रोतों के रूप में सीधे संचार के परंपरागत माध्यम गायब हो गए। लेकिन ऐसी बात अन्य परस्पर संचार के नेटवर्क के लिए नहीं कही जा सकती, भले ही वे परिवार या बड़े परिवार में, पड़ोस में, समुदायों में और जातीय समूहों में, विभिन्न क्लबों में, व्यावसायिक समूहों में, सरकारों, विभिन्न प्रकार के संगठनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए जा रहे सम्मेलनों या बैठकों में सूचना के आदान प्रदान [19] को लेकर हो। ये सभी और कई अन्य संचार के तरीके सूचना के आदान-प्रदान, मुद्दों को सुलझाने, किसी के अंदर पनप रहे दुख के गुबार को निकालने और व्यक्तियों, समूहों या समग्र रूप में समाज के लिए आम सहमती के मामलों पर फैसला लेने में सहायता करते हैं। इस प्रकार के पारस्परिक संचार के रूपों को कई बार व्यावसायिक पर्यवेक्षकों और जांचकर्ताओं द्वारा अनदेखा किया जाता है क्योंकि इनका सारा ध्यान जनसंचार के माध्यम में लगा होता है, जिन्हें ये समाचार, तथ्यों, विचारों, और वास्तव में सभी महत्वपूर्ण जानकारी का एकमात्र स्रोत मानते हैं।

वैसे यहां इस तरह की बातों पर चिंता जाहिर करने की मुख्य या प्राथमिक वजह अन्तर्वैयक्तिक या पारस्परिक संचार नहीं है। लेकिन इससे उठने वाले कुछ मुद्दों को अनदेखा नहीं करने की भी पर्याप्त वजहें हैं। पहला, संचार और विशेष रूप से पारस्परिक संचार के परंपरागत साधन, विकासशील और विकसित, दोनों तरह के देशों में अपनी महत्ता बनाए हुए हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा, दुनिया के अधिकतर लोग, विशेष रूप से विकासशील देशों के गाँवों में रहने वाले लोग जो विश्व की आबादी का 60- 70 प्रतिशत हैं, संचार के पारंपरिक माध्यमों में ही संदेश लेते और भेजते हैं। तीसरा, आधुनिक मीडिया के फायदे और सीमाओं को समझने के लिए इसे पारस्परिक संचार से अलग हटकर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि संचार के नेटवर्क सबको

जोड़ते हुए रूप से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नई प्रणाली आगे बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि वह पुरानी प्रणाली को खत्म कर देती है। इसके विपरीत पारस्परिक संचार आधुनिक प्रौद्योगिकी की मानवीयतारहित होने के कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। इसको नया आयाम मिल रहा है। पारस्परिक संचार के माध्यम समाज के भीतर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में एक आवश्यकता बन कर सामने आए हैं।

2. भाषाएँ

दुनिया भर में मौखिक संचार में इस्तेमाल की जाने वाली अब तक पहचानी गई भाषाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 3500 से अधिक। सभी समाजों में बोली आम है और लिखना आम नहीं है। क्योंकि दुनिया भर में लिखित भाषा की संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के अनुसार लिखी जाने वाली भाषाएं 500 से अधिक नहीं है।[20]

सदियों से, इतिहास की धारा ने कुछ भाषाओं के प्रयोग में लगातार विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। इनमें से कुछ भाषाओं का जानकारी देने, कार्यक्रमों और लिखित सामग्री [21] के लिए प्रमुखता से इस्तेमाल होता रहा है।

यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व में कम से कम 16 भाषाएँ हैं जो 50 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं- चीनी परिवार की भाषा, अंग्रेज़ी, रूसी, स्पेनिश, हिन्दी, पुर्तगाली, बंगाली, जर्मन, जापानी, अरबी, उर्दू,फ्रेंच, मलय-बहासा, इतालवी, तेलगू और तमिल।

अफ्रीकी महाद्वीप पर करीब 1,250 भाषाओं बोली जाती हैं। जैसे स्वाहिली, वोलोफ और हौसा भाषाएँ यहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र और वास्तव में कई देशों में प्रयोग की जाती हैं। यूरोप में 28 सरकारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। दक्षिण एशिया के लोग 23 प्रमुख भाषाओं का उपयोग करते हैं। अरब क्षेत्र एक निश्चित

अर्थ में एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं पर उनकी स्थानीय भाषाएँ ठेठ अरबी से कुछ हद तक बदलती हैं जैसे बरबर जुबान जो उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों में बोली जाती है, अरबी भाषा से भिन्नता रखती है। लैटिन अमेरिका स्पेनिश और पुर्तगाली दो प्रमुख भाषाओं का उपयोग करता है, लेकिन वहाँ भारतीय भाषाओं और बोलियों समेत सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं। उनमें से कुछ जैसे पेरू में क्वेचा और पराग्वे में गूआरानी आदि बोलियाँ स्थानीय आबादी द्वारा बड़े पैमाने पर बोली जा रही हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी, फ्रेंच और डच इस क्षेत्र और कैरेबियन के पूर्व उपनिवेशों में काफी ज्यादा बोली जाती है। कई देशों की भाषाएं आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा हैं- सोवियत संघ में 89; भारत में 1650 से अधिक भाषाओं और बोलियों की पहचान की गई है। भारत में 15 भाषाओं को सरकारी और शैक्षणिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। घाना में कुल 56 भाषाएँ है और मैक्सिकन इंडियन की 200 से अधिक भाषाएँ हैं। इनमें से कई ज़ुबानों को अब लिखित रूप दे दिया गया है, लेकिन बहुत सी बाकी भी हैं।

भाषाओं और बोलियों की एक बड़ी संख्या के प्रसार के लिए कई ऐतिहासिक, आदिम, धार्मिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार हैं। लेकिन समय के साथ, दुनिया के बड़े हिस्से पर वर्चस्वशाली शक्तियों के दबाव और साम्राज्यवादी प्रभुत्व से बनने वाले नए राष्ट्र राज्यों के निर्माण के साथ कई देशों में भाषाओं में तेजी से बदलाव होते रहे जिसकी वजह से धीरे-धीरे कई सारी बोलियां और स्थानीय ज़ुबान गायब होती गईं। इसके उलट, उपनिवेशवाद ने कुछ यूरोपीय भाषाओं को सारी दुनिया में फैलाया। छोटी और कमजोर संस्कृतियों को निगल जाने की प्रवृत्तियां अभी भी जारी हैं।

भाषा की बहुलता, जिसमें से हर एक भाषा की लंबी परंपरा रही है, दुनिया की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता की अभिव्यक्ति है। एक भाषा के लापता

होने से हमेशा नुक़सान ही हुआ है। इसका संरक्षण बुनियादी मानव अधिकार के लिए किए गए संघर्ष का परिणाम है। इसके अलावा, आधुनिक जनसंचार और इसी तरह से पारंपरिक संचार में भी विभिन्न तरह की भाषाओं का इस्तेमाल एक तरह से लाभप्रद था जो सभी लोगों में एक तरह की समझ लाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार की बहुलता से कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर " सम्पर्क भाषा (Link Language)" या एक भाषा और अन्य भाषाओं के बीच संबंधों का चुनाव मुश्किल भरा और संघर्ष की वजह रहा है (केवल तीन देशों भारत, कनाडा और बेल्जियम का उदाहरण ले लें)। भाषा की बहुलता संचार में स्पष्ट रूप से रुकावट पैदा करता है, सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म देता है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी प्रभावित कर सकता है। थोड़ी सी भाषाओं का दुनिया भर में व्यापक उपयोग अन्य भाषाओं के खिलाफ एक निश्चित भेदभाव की ओर ले जाता है और एक प्रकार के भाषाई वर्णक्रम का निर्माण होता है। इस प्रकार, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी भाषाई साधन के अभाव में सबसे आधुनिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के पूरा फायदा उठाने में पीछे रह जाती है।[22]

थोड़ी सी भाषाओं तक सिमटने से यह बात निकल कर आ सकती है कि "भाषा अवरोध" की समस्या को बहुत ही ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। लेकिन तथ्य यह है कि उन थोड़ी सी भाषाओं को बोलने वाले मूल लोगों और कुछ उन स्थानीय कुलीन लोग जो दो या कई भाषाएं जानते हैं को छोड़ दें तो दुनिया भर के लाखों लोगों को वास्तव में इन भाषाओं की वजह से अकल्पनीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके साथ इस रूप में भी भेदभाव होता है कि वर्तमान में सूचना के प्रसार की प्रवृत्ति 'शक्तिशाली भाषाओं' के मुहावरों और शब्दों में देखने को मिल रही है।

भविष्य की ओर देखने पर, विकास के कई संभव तरीके सामने दिखाई देते हैं। कई ऐसी राष्ट्रीय भाषाएं, जिन्होंने वर्तमान में अक्सर खुद को स्थानीय कुलीन वर्ग की भाषा के रूप में सीमित कर लिया है, उनका विशेष रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल हो सकता है। वैकल्पिक रूप से प्रौद्योगिकी के तेजी से फैलने से भाषाओं की संख्या में कमी आ सकती है, विशेष रूप से कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए। बहुभाषावाद एक आकर्षक समाधान है, शायद ज्यादातर देशों में यही एक यथार्थवादी विचार है। लेकिन फिर भी एक आसान और सार्वभौमिक जुबान जो सभी को समझ में आने लायक और सभी की पहुंच तक हो, का प्रसार होता है तो इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न तरह के लोगों के बीच संचार की बाधाओं को तेजी से खत्म कर सकती है। फिर, खासतौर से रेडियो और रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके विदेशी भाषा के शिक्षण और शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने की अपार संभावनाएं हैं। ये सभी संभावनाएं तभी सार्थक हैं जब एक बुनियादी सिद्धांत का सम्मान किया जाए- सभी भाषाओं को संचार के साधन के रूप में समान गरिमा प्रदान की जाए। अपनी भाषाई नीति तैयार करने में, प्रत्येक देश के पास विभिन्न विकल्पों के बीच एक विकल्प हो और उसके फैसले को बिना कोई नुकसान पहुँचाए लंबे समय के लिए स्थगित या टाला नहीं जाना चाहिए।

अभी तक सभी भाषाओं में मुद्रण, प्रसंस्करण और संदेश भेजने और जानकारी के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल शुरू नहीं हो सका है। आधुनिक संचार में इस्तेमाल होने वाली कई भाषाओं को अब तक इससे भी नुकसान होता रहा है। लैटिन या सिरिलिक लिपि का उपयोग करने वाली भाषाओं को ही अब तक प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, मानकीकरण (Standardization), संहिताकरण (Codification) और मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई हाल के सुधार से जापानी, चीनी और अरबी जैसी भाषाओं को संचार के सभी

आधुनिक साधन के अनुकूल बनाना संभव हो गया है। शंघाई के एक भाषा अनुसंधान संस्थान ने कंप्यूटिंग प्रणाली [23] में इस्तेमाल के लिए 26 अक्षरीय रोमन लिपि का उपयोग करके लगभग 2,000 भाषाचित्रों में से प्रत्येक के लिए एक 4 अक्षर का कोड विकसित किया है जिसे "ऑनसाइट एनकोडिंग" के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा के लिए एएसवी-कोडार (ASV-CODAR) नामक एक प्रणाली विकसित की गई है जो कोड का मानकीकरण करके अरबी लिपि के अक्षरों की संख्या कम कर देती है जिससे टाइपराइटिंग, मुद्रण, डाटा प्रोसेसिंग और दूरसंचार अरबी लिपि का उपयोग आसान उपयोग हो जाता है। वास्तव में कई अन्य भाषाओं के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।

इस प्रकार से हम विशेष रूप से इन कुछ वजहों से भाषा की समस्याओं के बारे में चिंतित हैं- (क) जब तक अधिक भाषाओं को जानकारी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तब तक सही मायने की उस राष्ट्रीय संचार प्रणालियों के विकास को हासिल नहीं किया जा सकता है जो पूरी आबादी तक पहुँचने वाला हो (ख) भाषा नीति, संचार नीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि भाषा का चुनाव और प्रसार इसके व्यापक और समान संचार के लिए संभावनाएं लाता है; (ग) विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय भाषाओं को लिखने के लिए लिपि तैयार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है, इसी तरह से विभिन्न भाषा समूहों के अनुकूल संचार उपकरणों (टाइपराइटर, लिनोटाइप, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर, आदि) को अपनाने की जरूरत है (घ) कुछ तथाकथित विश्वव्यापी भाषाओं का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय संचार में आवश्यक हो गया है, हालांकि यह अब व्यक्तिगत रूप से और कुछ देशों की राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के विषय में भी संवेदनशील प्रश्न बन गया है।

3. पढ़ाई-लिखाई

यदि भाषा, (बोलने और लिखने वाली दोनों) मानव संचार का प्राथमिक तरीका है, तो निरक्षरता संचार के विकास के लिए प्रमुख बाधा है। पढ़ने और लिखने के कौशल की कमी एक व्यक्ति की समग्र क्षमता और योग्यता के विस्तार की सीमा को तेजी से घटाती है।[24]

निरक्षरता के लिए कई कारण हैं- लाखों लोग गैर-लिपि वाली भाषा बोलते हैं; कई लोग ऐसे वातावरण या विशेष परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ लिखित संचार अभी तक आवश्यक नहीं है या उपलब्ध नहीं है; कई लोगों को उनके बचपन या वयस्क होने पर पढ़ने और लिखना सीखने का मौका ही नहीं मिला है; कुछ लोगों ने ये कौशल हासिल किया पर अपने जीवनकाल के दौरान ही विभिन्न कारणों से निरक्षरता की अवस्था में फिर लौट आए। सीमित संसाधन व्यापक साक्षरता कार्यक्रमों को स्थापित होने से रोक देते हैं। निरक्षरता उन्मूलन के प्रयासों के लिए उठाए जाने वाले कदमों का फैसला करने के स्तरों पर राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।

हालांकि निरक्षरता, लगभग सभी देशों में अधिक से अधिक या कम हद तक मौजूद है, पर इसे वैश्विक स्तर पर ठीक से परिभाषित करना और इसके आयाम तय कर पाना मुश्किल है। एक साक्षर व्यक्ति की अवधारणा हर देश में अलग-अलग होती है। पूर्ण प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए होने वाले एक साधारण परीक्षण, समझने की क्षमता से लेकर नागरिक और सामाजिक जीवन में काम करने में "व्यावहारिक" मकसद के लिए साक्षरता कौशल का उपयोग करने की क्षमता तक इसके विभिन्न पैमाने हो सकते हैं। हालांकि दुनिया भर में निरक्षरता की पहचान को दर्शाने वाले पैमाने उपलब्ध हैं जो आम तौर पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर स्वीकार भी किए जाते हैं।

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों और अनुमानों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की दुनिया की आबादी के बीच निरक्षरता की दर में लगातार कमी देखी गई है। यह 1950 के 40 प्रतिशत से गिरकर 1960 में 36 प्रतिशत के आसपास तक हो गई। इसके 1970 में 32.4 प्रतिशत से 1980 में 28.9 प्रतिशत तक गिर जाने और 1990 में प्रतिशत 25.7 तक गिर जाने की उम्मीद है। अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा के लगातार बढ़ने और आंशिक रूप से कई देशों में चल रहे प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम इसी तरह से प्रेस और प्रसारण माध्यमों के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों और शिक्षा कार्यक्रमों का है जिसने एशिया और अफ्रीका के विभिन्न भागों में निरक्षरता के खिलाफ अभियान में मदद की है। ऐसे कार्यक्रमों को कई जगहों पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहायता भी मिली तो कई जगह बिना ऐसी सहायता के ही ये अभियान चले। निरक्षरता के प्रतिशत में कमी अंत नहीं है क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि निरक्षरों की संख्या में वृद्धि जारी रहेगी। 1970 में 74.2 करोड़ से बढ़ कर 1980 में 81.4 करोड़ और 1990 में 88.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार के डराने वाले विकास के आँकड़े का डर इससे कम किया जा सकता है कि साक्षरों की पूर्ण संख्या में 1970 और 1980 के बीच 45.6 करोड़ की और उसके अगले दशक 55.6 करोड़ की वृद्धि होगी।

15 और अधिक आयु वर्ग के साक्षरों और निरक्षरों के अनुपात के बारे में नीचे दिया गए ग्राफ से पता चलता है कि 1970 से 1990 तक साक्षर व्यक्तियों की संख्या जहाँ 100 करोड़ बढ़ेगी वहीं निरक्षरों की संख्या में भी लगभग 150 करोड़ की वृद्धि होगी।[25]

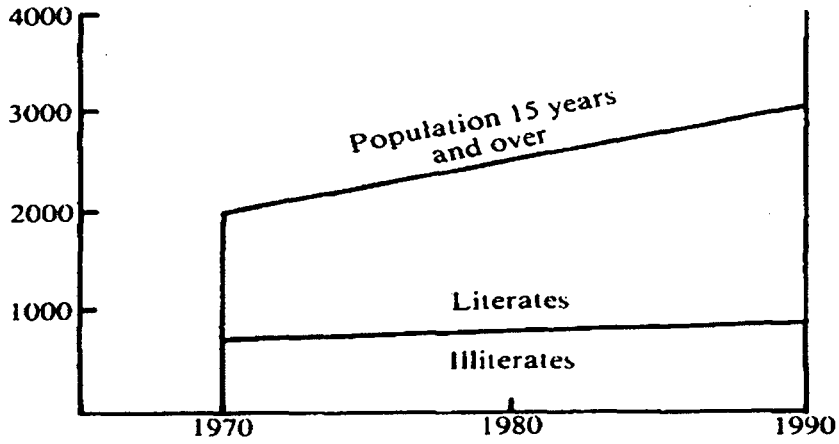

इस प्रकार, निरक्षरता की दर में कटौती के बावजूद, निरक्षरों की कुल संख्या में वृद्धि जारी है। अब यह चौंकाने वाले 80 करोड़ के आंकड़े पर है, जो दुनिया की वयस्क आबादी की लगभग एक तिहाई है। इस समस्या के विशाल आकार के बारे में बताने के लिए यह पर्याप्त है।

सच्चाई यह है कि दुनिया के स्तर पर साक्षरता की दर, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण इसके साथ तालमेल नहीं रख पा रही है। एक और बात परेशान करने वाली है कि वर्तमान में चार में से लगभग हर एक युवा न्यूनतम शिक्षा प्राप्त किए बिना ही रोजगार पा जाता है।

कई देशों में पुरुष और महिला साक्षरों के अनुपात के बीच असमानता देखी गई है। परंपरावादी सोच अक्सर यह निर्धारित करती है कि महिलाओं को उनके हितों को घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित करना चाहिए। अकुशल स्तर पर काम करने को छोड़कर बाकी कामों के लिए पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। इसलिए महिलाओं को पढ़ने-लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। लड़कियां, कभी-कभी लड़कों की तुलना में घटिया और मामूली शिक्षा प्राप्त करती हैं और उनसे खुद को केवल शादी के लिए तैयार करने की उम्मीद की जाती है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो बुनियादी साक्षरता हासिल

करने के बाद उसे भी भूल जाते हैं क्योंकि वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे युवाओं में ज्यादातर शायद महिलाएं ही होती हैं। सरकारें जब वयस्क साक्षरता अभियान आरंभ करती हैं तब महिलाओं को कभी-कभी अपने पति द्वारा इसमें भागीदारी करने से रोक दिया जाता है या प्रचलित सामाजिक मानदंडों द्वारा महिलाओं को हतोत्साहित किया जाता है। विश्वस्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि सभी निरक्षरों की 60% महिलाएँ हैं। उनकी संख्या पुरुष निरक्षरों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इस असमानता को मिटाना मुश्किल काम है। इसके लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। इसमें मानव मुक्ति के सभी मुद्दों को शामिल करने की भी जरूरत है।

यह सुझाव दिया गया है कि निरक्षरता एक बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक बुराई अब नहीं रह गई है क्योंकि नई मीडिया ने बोले गए शब्दों और चित्रों के इस्तेमाल से निरक्षर लोगों को भी संचार के दायरे में ला सकती है। संचार की दृश्य-श्रव्य माध्यम की शक्ति को नकारे बिना यह स्पष्ट है कि भाषा, बोलने और लिखने दोनों रूप में, संचार का एक अपरिहार्य तरीका है। साक्षरता सिर्फ एक पढ़ने की आदत नहीं है। हम यह विचार रखना चाहते हैं कि साक्षरता का मतलब बहुत अधिक "शब्दों को पढ़ने के बजाय दुनिया को पढ़ने" [(26)] से है। इस प्रकार, अशिक्षा का मतलब है कि 80 करोड़ मनुष्य, अपने समाज और दुनिया में सही मायने में पूर्ण भागीदारी से बाहर रहकर, द्वितीय श्रेणी के नागरिक बने हुए हैं।

लाखों करोड़ों पुरुषों और महिलाओं को महत्वपूर्ण संचार के तरीकों से दूर रखना, सूचना के अधिकार या सूचित करने के अधिकार का मजाक बनाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि सभी संभव तरीकों चाहे वे शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हो, को विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों और जन संचार से

जोड़ें ताकि इसकी शक्तिशाली क्षमता से दुनिया में हर देशों पर लगा ये दाग जड़ से मिटाया जा सके। साथ ही, चूंकि निरक्षर लोगों की संख्या में दशकों तक वृद्धि होगी और वे छपी चीजों को नहीं पढ़ सकते इसलिए उन लोगों के लिए पर्याप्त संचार चैनलों, विशेष दृश्य-श्रव्य वाहनों का विकास करना होगा। जिससे उन तक सूचना पहुँचा कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक जीवन की मुख्यधारा में लाया जा सके।

4. डाक और दूरसंचार

अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक संचार विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में संचार नेटवर्क का एक अनिवार्य अंग बना हुआ है। जैसा की पहले ही उल्लेख किया गया है, सभी समाजों में पारस्परिक संचार के अनगिनत तरीके और चैनलों का प्रयोग हो रहा है, जिसमें प्रतीकों, भाषाओं और मानव अभिव्यक्तियों के अन्य साधनों का उपयोग करते हुए सूचना का दी जाती है। समकालीन दुनिया में आधुनिक संचार माध्यमों और दूरसंचार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं द्वारा पारस्परिक संचार को सहयोग किया गया है या इसे आसान बनाया गया है।

पत्रों का आवागमन (दस लाख में)

	1968	**1976**
अफ्रीका	3.029	4.293
उत्तरी अमेरिका	85,522	96, 630
दक्षिणी अमेरिका	2,236	3, 350
एशिया	23, 488	26, 117
यूरोप	60, 073	70, 420
सोवियत संघ	6, 954	7, 923
ओशानिया	3,169	2,980
विश्व	184, 471	211, 713

स्रोत: स्टेटिस्टिकल ईयरबुक 1977, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के आधार पर

(दक्षिण अमेरिका के आंकड़े में केवल नौ देश शामिल हैं, सोवियत संघ के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की सांख्यिकी कार्यालय को सीधे तौर पर बताए गए सरकारी आंकड़े हैं)

एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश को पहुँचाने के लिए सबसे बड़ी संगठित प्रणाली डाक व्यवस्था है। डाक सेवाओं की शुरुआत आज से हजारों साल पहले हुई थी। आज हर समाज में उसका महत्वपूर्ण नेटवर्क है। ऊपर दी गई तालिका पत्रों के आवागमन की मात्रा और 1968 से 1976 तक हुए इसके विस्तार की दिशा में सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती है।

जबकि डाक सेवाएं विकसित देशों में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी हैं। जबकि अधिकांश विकासशील देशों में यह थोड़े बहुत स्तर पर है क्योंकि गांवों के बहुत दूर होने और सड़क व रेल नेटवर्क की खराब गुणवत्ता के कारण हर क्षेत्र तक इसकी उपलब्धता नहीं है। इन देशों में अब भी कई ऐसे रिहाइशी इलाके हैं जहाँ अभी भी कोई डाकघर मौजूद नहीं है।[27] इस क्षेत्र में प्रगति सामाजिक एकता का एक कारक भी हो सकती है और वाणिज्य और उद्योग की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी योगदान कर सकती है। डाकघर भी सरकार के सूचना केंद्र के रूप में सेवा दे सकते हैं। डाकघर विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामकाज के लिए मुख्य बिंदु के रूप में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं।

हाल के दशकों में कुछ विकसित देशों में डाक सेवाओं में आश्चर्यजनक रूप से तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। एक कारण यह है अतीत की उत्कृष्ट सेवाएं मानव शक्ति की भरपूर उपयोग पर निर्भर करती थीं। एक अन्य कारण यह है कि संचार अधिकारी अब डाक व्यवस्था के रखरखाव से ज्यादा, टेलीफोन प्रणाली के सुधार में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि

यह ज्यादा लाभप्रद है। इसलिए, व्यक्तियों, जातियों और महाद्वीपों के बीच डाक सेवाओं में तेजी से गिरावट आई है। विमान जितने तेज हुए हैं, ऐसा लगता है, डाक उतनी ही धीमी हुई है। इस गिरावट ने अक्सर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार में गंभीर अवरोधों को जन्म दिया है। यहाँ यह सोचने के लिए भी आधार मिलता है कि पत्र लिखने की आदत में गिरावट भी निरक्षरता का एक कारक है, क्योंकि इसके कम होने से एक साक्षर तरीके से खुद को अभिव्यक्त करने की कई लोगों की क्षमता कम हो जाती है और यह भी सांस्कृतिक क्षति को दर्शाता है।

पारस्परिक संचार के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठित नेटवर्क टेलीफोन प्रणाली है। यह ठीक ही कहा गया है कि टेलीफोन पारंपरिक मौखिक संचार का एक परिष्कृत विस्तार है और उसी को बढ़ाने वाला माध्यम है। कोई अन्य संचार माध्यम सीधे और सहज संवाद के लिए टेलीफोन से टक्कर नहीं ले सकता है।[28]

इस समय दुनिया में कुछ 40 करोड़ टेलीफोन हैं, जिनमें 1945 के बाद से लगभग 1,000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लगभग सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय वेब में बनाए गए डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम से जुड़े हैं, जो अब तक की बनाई गई सबसे बड़ी एकीकृत मशीन है। दुनिया के टेलीफोन का लगभग अस्सी प्रतिशत उत्तरी अमेरिका और यूरोप के केवल दस देशों में हैं जहां इससे लगभग 75 करोड़ की कुल आबादी जुड़ी है। इन टेलीफोन का लगभग आधा अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहाँ कई शहरों में लोगों की संख्या से ज्यादा फोन हैं। समाजवादी दुनिया के पास टेलीफोनों की कुल संख्या का महज 7% है, जबकि यहां की आबादी 1,30 करोड़ के करीब है। दुनिया के विकासशील देशों में 2,00 करोड़ की आबादी के पास महज 7 फीसदी टेलीफोन हैं।[29]

टेलीफोन संचार का विकास भी समान रूप से तेजी से हुआ है। आईटीयू के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष करीब 440 अरब टेलीफोन कॉल (संयुक्त राज्य

अमेरिका में इसका 50%) किए जाते हैं। इसमें खास बात तो अंतरराष्ट्रीय कॉल की संख्या का है- उदाहरण के लिए, 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए और यहाँ से विदेशों को गई कॉल की संख्या को 773,000 थी, लेकिन 1977 में अकेले बाहर की जाने वाली कॉल की संख्या 50 लाख से अधिक थी। 1956 में जब पहली बार पानी के भीतर अंटलांटिक महासागर में केबल बिछाई गई जो एक समय में 50 टेलीफोन कॉल ले जाने की क्षमता रखती थी। इसके बाद ऐसी पांच और केबलों को महासागर में डाला गया जिसमें अंतिम केबल को एक साथ 4,000 कॉल से निपटने के लिए सक्षम बनाया गया है। कुल मिलाकर 30 अंतरराष्ट्रीय केबल, महासागरों में डाली गई हैं जिसमें कुल मिलाकर 17,074 टेलीफोन सर्किट की क्षमता है। इस बीच, पिछले एक दशक में, अंतरराष्ट्रीय उपग्रह संचार की क्षमता छलांग मार कर 150 से बढ़कर 10,000 से अधिक सर्किट की हो गई है। टेलीफोन संदेश प्रसारण के लिए इस्तेमाल उपग्रह के नवीनतम पीढ़ी से एक साथ 6,000 कॉल कर सकते हैं।

टेलीफोन यातायात में ऐसी वृद्धि व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों की वजह से हुई। साथ ही सुविधाओं में तकनीकी सुधार आने की वजह से भी इसमें वृद्धि हुई। एक और प्रभाव था- वास्तव में टेलीफोन की दरों में कमी आई है जिसने फोन काल की महंगी दरों का डर लोगों के मन से हटा दिया। टेलीफोन के उपयोग में वृद्धि और इसकी उपयोगिता की अनन्त सीमा के पीछे सुविधाओं में तेजी से हुई वृद्धि, लगातार कम होती लागत और उच्च गुणवत्ता सेवा है।

हमें यह दिखाई देता है कि कई देशों में डाक और दूरसंचार सुविधाओं और सेवाओं की धीमी गति, व्यक्तियों और समाज दोनों के विकास में रुकावट है। इस विचार को अभी भी मान्यता नहीं मिली है कि यह सुविधाएं और सेवाएं केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं हैं, बल्कि यह समग्र विकास और

यहां तक कि लोकतांत्रिक जीवन की एक पूर्व शर्त है। दूरसंचार के विस्तार में असमानता, विकसित और विकासशील देशों के बीच संचार में एक बढ़ती हुई बाधा बन गई है। इसी तरह, अभी तक कई सेवाओं की दर लागत के मुकाबले घटी नहीं हैं जो गरीब उपभोक्ताओं को उसका उपयोग करने में बाधा पहुँचा रही है। संचार एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर कई देशों में फिर से विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उनके अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए।

5. समूह और स्थानीय संचार के माध्यम

सामाजिक संचार को संगठित करने में अगला कदम समूहों या स्थानीय समुदायों के स्तर पर उठाना होगा। समूह के बीच सामंजस्य बनाने, स्थानीय संसाधनों को जुटाने और छोटे या बड़े समूहों को प्रभावित करने वाली समस्याओं को हल करने के लिए संचार जरूरी है। इसके लिए विभिन्न संचार साधनों का उपयोग किया जाता है। इस स्तर पर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देशों में संचार बढ़ रहा है। अक्सर, स्थानीय स्तर पर संचार का माध्यम मास मीडिया है। आधुनिक तकनीकों के आने से मास मीडिया को ये सहूलियत हुई है कि वो दूर-दराज के इलाकों में रह रहे समुदायों को भी सुविधाएं दे सके। जैसे कि रेडियो स्टेशन स्थापित करना जिसे आर्थिक सहायता केंद्रीय संगठनों से मिलती है और उसका प्रबंधन स्थानीय स्तर पर होता है। लेकिन समुदायों और व्यक्तियों ने भी संचार के अपने साधन बनाने में पहल की है। ये साधन संचार की एक विस्तृत श्रृंखला को समेटते हैं, जिसमें स्थानीय और दीवार पर चिपकाने वाले अखबार, छोटे मुद्रित पत्र, फोटो, छोटे-बड़े पोस्टर, स्थानीय रेडियो और घुमंतू लाउडस्पीकरों से लेकर पर्चे, स्लाइड, टेप रिकार्डर, प्रदर्शनियों, स्थानीय मेले, फिल्म और संगीत समारोह, कठपुतली शो, घुमंतू जानकारी गाड़ी, नुक्कड़ नाटक और इसी तरह के उपकरणों और साधनों की एक अंतहीन सूची है। इनका अक्सर सामाजिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य

अभियानों के लिए, स्थानीय विकास योजनाओं के लिए सहायता के रूप में, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों के लिए, साथ ही उन सभी कार्यों में जहाँ स्थानीय आबादी की इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक भागीदारी की आवश्यकता महसूस की जाती है। इस प्रकार सूचना के साधन और समूह संचार के माध्यम को बढ़ावा देने वालों में सरकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, पेशेवर विशेषज्ञ जैसे कृषि विशेषज्ञ और बेयरफूट डॉक्टर [3], शिक्षक और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता, पुजारी और कारीगर आदि शामिल हैं।

इस प्रकार के संचार के साधनों और स्थानीय गतिविधियों पर इन चार वजहों से और जोर देने की जरूरत है-

1. ऐसे स्थानीय संचार साधनों को बड़े मीडिया समूह द्वारा गर्त में धकेल दिया जा सकता है;

2. जनसंचार के बड़े माध्यमों से जिस प्रकार के कार्यों और लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद की गई है, वे उसके लिए ठीक (अनुरूप) नहीं हैं;

3. क्योंकि कई देश अपने विविधता भरे दर्शकों के लिहाज से बेकार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं और बड़े और छोटे मीडिया के बीच जरूरी संतुलन को नज़रअंदाज करके दुर्लभ संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं।

4. उनके बीच संबंध स्थापित करके एक व्यापक क्षैतिज संचार विकसित किया जा सकता है।

इस तरह का बदलाव ये समग्र विकास रणनीतियों में बदलाव से जुड़ा हो सकता है। हाल के दशकों में विकास का ऊपर से नीचे बहने वाला मॉडल

---

[3] बेयरफुट डॉक्टर चाइना के किसान होते हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाव तथा साफ-सुधरा रहने की जानकारी देते हैं।

(Top-down Model) को हटाकर इस प्रक्रिया में समुदायों के अधिक से अधिक भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इससे उनकी मौजूदगी का एहसास होता है और अपनी जरूरतों को जाहिर करने का मौका मिलता है। उसी के मुताबिक योजनाएं बनती हैं और काम होता है।

इस तरह के बदलाव का न केवल स्थानीय मीडिया की शुरुआत या विस्तार पर असर होता है बल्कि विकास के काम में मीडिया के इस्तेमाल पर भी व्यापक असर होता है। इस प्रकार संचार, बहुत अलग तरीके से विकास के काम और हर इलाके में सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। इस अर्थ में, विकास से जुड़ी मीडिया गतिविधियां किसी भी तरह से मुक्त सूचना प्रवाह के लिए "खतरा" नहीं बनती हैं। बल्कि इसके उलट लोकतंत्र के लिए जरूरी शर्तों में से एक जरूरत हो जाती है क्योंकि विकास के विकल्प चुनने और विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी लोकतांत्रिक जीवन का रास्ता है। ऐसे में इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े दर्शक-समूहों को बटोरने वाले बड़े मीडिया समूहों की भूमिका खत्म हो गई है या देशों और समुदायों को इन दोनों के बीच में एक को चुनना होगा। अलग-अलग मकसद के लिए अलग-अलग साधन - समूह मीडिया और मास मीडिया का जुटाव शायद इसका उपयुक्त जवाब है।[30]

कई विकासशील देशों में महत्वपूर्ण अनुभवों और पहल वाले कार्यक्रम अलग नतीजे रहे लेकिन उन नतीजों को नगण्य नहीं कहा जा सकता। पेरू, मेक्सिको, तंजानिया, सेनेगल, फिलीपींस, भारत [31], बोत्सवाना [32], थाईलैंड, [33] चीन [34], माली [35] और अन्य देशों के उदाहरणों को कई अन्य देशों में काफी बड़े पैमाने पर जाना जाता है।

ये उदाहरण समूह संचार के अनिवार्य तत्वों के बारे में जानने के काम आते हैं- सभी मीडिया कार्य सामूहिक प्रक्रिया में होते हैं जिसे समाजशास्त्रीय आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए ना कि तकनीकी आधार पर। वो चाहे पारंपरिक मीडिया हो या सबसे आधुनिक मास मीडिया, लेकिन उसे

आत्म अभिव्यक्ति, विश्वास, बातचीत और समूह स्थितियों की चर्चा को सहयोग करने के मकसद से काम करना चाहिए।[36]

बहुत बार स्थानीय समूह अपने को वातावरण की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों की विविधता के अनुरूप अपने को ढाल कर आधुनिक संचार साधनों (रेडियो या टेलीविजन, नई मुद्रण तकनीक, यहां तक कि माइक्रोप्रोसेसर और वीडियो टेप) का उपयोग करते हैं।

विकसित देशों में भी इस तरह के मीडिया की जरूरत के लिए एक प्रकार की जागरूकता बढ़ी है। खासकर अल्पसंख्यकों, विशेष रुचि समूहों और समुदाय या राजनीतिक गतिविधियों में इनका ज्यादा उपयोग हो रहा है। औद्योगिक देशों में लोगों खुद को पर्यावरण संबंधी समस्याओं,मुद्दों, प्रदूषण, ऊर्जा संकट, बेरोजगारी, तकनीकी परिवर्तन के लिए उचित माहौल और इसी तरह के मुद्दों से जूझते हुए पाते हैं। वे इनके निपटान के लिए कोई देरी किए बिना इस तरह के साधन के साथ खुद को अभिव्यक्त करने की जरूरत महसूस करते हैं।

सामूहिक मीडिया जिसे कभी-कभी छोटा मीडिया भी कहा जाता है, संचार के माध्यमों, साधनों और तकनीक के पूरे शस्त्रागार में अपनी जगह रखते हैं। इन्हें जगह-जगह पर जनसंचार के माध्यम समझ कर भ्रमित नहीं होना चाहिए। सामूहिक मीडिया की अपनी उचित जगह है और इसी रूप में उनकी योजना बनाना, उसे वित्त उपलब्ध कराना और उपयोग करना चाहिए।

6. जनसंचार के माध्यम

प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद से इस समय विभिन्न संचार माध्यम की भीड़ जिसमें तार, टेलीफोन, टेलेक्स, कैमरा और फिल्म, फोनोग्राफ, रेडियो और टेलीविजन के आने के बाद तक दुनिया वास्तव में बहुत बदल गई है। प्राप्तकर्ताओं तक सभी प्रकार के संदेश लगातार बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं।

मास मीडिया का आना और उसकी हमारे दैनिक जीवन में उपस्थिति समकालीन दुनिया की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।

तुलनात्मक रुप में हाल के दशकों में संचार का विस्तार जनसंख्या, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक रुझान के अनुरूप स्थायी और निरंतर हो रहा है। सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में इस तेजी से होने वाले विकास, जहाँ इसे आत्मसात करने के लिए एक बढ़ती दर्शकों की संख्या है, के नतीजे का अनुमान लगाना निश्चित रूप से मुश्किल है। निम्नलिखित आंकड़े इसके विस्तार के पैमाने संकेत हो सकते हैं:

वृद्धि (1950-1975)	**प्रतिशत**
प्रेस (प्रतियों की संख्या, दैनिक समाचार पत्र)	+77
रेडियो (रिसीवरों की संख्या)	+417
टेलीविज़न (रिसीवरों की संख्या)	+ 3235
किताबें (प्रति वर्ष निकलने वाले शीर्षक)	+ 111

यूनेस्को स्टेटिस्टिकल इयरबुक, 1977

इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य दर्शकों/श्रोताओं/पाठकों की संख्या को लेकर है जो कि ये दर्शाता है कि मीडिया की पहुंच पूरी दुनिया में है। केवल 25 वर्षों में मास मीडिया से अछूते रहे लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है। प्रगति की वर्तमान दर से देखा जाए, तो कुछ ही दशकों में लगभग हर कोई इनका दर्शक/पाठक/श्रोता बन जाएगा।

जनसंचार माध्यम के दर्शक/पाठक/श्रोता की संख्या में वृद्धि 1960-1975 प्रतिशत

संख्या में वृद्धि (1960-1975)	प्रतिशत
विश्व की कुल जनसंख्या	+ 33
दैनिक समाचारपत्र (प्रति एक हजार निवासियों पर वितरण की मात्रा)	+ 5
रेडियो रिसीवर (प्रति हजार निवासियों पर संख्या)	+95
टेलीविज़न रिसीवर (प्रति हजार निवासियों पर संख्या)	+185
किताबों के शीर्षक (प्रति दस लाख निवासियों पर प्रतिवर्ष प्रकाशित	+30

यूनेस्को स्टेटिस्टिकल इयरबुक, 1977

भौगोलिक विस्तार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसका मतलब यह है कि मास मीडिया पर अब खाली शहरी आबादी का विशेषाधिकार नहीं रह गया है। इसका विस्तार आंशिक रूप से सभी देशों और वहाँ के विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों तक हुआ है। इसकी पहुंच में न केवल क्षेत्रीय इलाकों और राष्ट्रीय राजधानियों तक हुई है बल्कि दुनिया के दूर-दूर के कोनों तक यह पहुंचा है। इस व्यापक पहुंच ने भेजे जाने वाले संदेशों की प्रकृति में भी बड़ा परिवर्तन किया है, खासतौर से रेडियो और प्रेस के संदेशों में। ग्रामीण अखबार और अपनी व्यापक पहुंच होने की वजह से खासतौर से रेडियो कार्यक्रम, स्थानीय भाषाओं में बनाए जा रहे हैं। भौगोलिक दूरी के कारण अलगाव में पड़े लाखों लोग अपने से दूर घटने वाली घटनाओं से दूर हो गए थे। वे अब तेजी से राष्ट्रीय और यहाँ तक की वैश्विक समुदाय के सदस्य होते जा रहे हैं। ये और इसके साथ ही, विकसित देशों में टेलीविजन का आश्चर्यजनक तेजी से फैलना और तीसरी दुनिया में इसके तेजी से बढ़ते प्रभाव ने, विविध सामाजिक (व्यापक अर्थ में) परिवर्तन लाया है, जिसका पूरी तरह से पता लगाया जाना और आकलन किया जाना अभी बाकी है।

संचार के विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार और खासतौर से बड़े पैमाने पर मास मीडिया के विस्तार से अखबारों और टीवी प्रसारकों को समाचार की आपूर्ति और वितरण करने वाली एजेंसियों का भी महत्व बढ़ा है व विस्तार हुआ है। किसी उत्पाद को खरीदने वाले विशेष उपभोक्ताओं और आम जनता अप्रत्यक्ष तरीके से सामान्य खबरों को प्राप्त कर रही है। मीडिया के लिए प्रेस एजेंसिया सूचना की प्रमुख और कई बार तो इकलौती स्रोत होती हैं, विशेष रूप से विदेशी खबरों के लिए। 100 से अधिक देशों की अब अपनी खुद की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है। पिछले 10 वर्षों में यह बहुत बड़ी वृद्धि है.

राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों का वितरण

अफ्रीका	अरब देश	एशिया	यूरोप	लैटिन अमेरिका	उत्तरी अमेरिका	ओशानिया
26	18	19	28	11	3	2

पांच समाचार एजेंसियाँ- एजेंसी फ्रांस-प्रेस (फ्रांस), एसोसिएटेड प्रेस (संरा. अमेरिका), रायटर (यूके), तास (सोवियत संघ) और संयुक्त प्रेस इंटरनेशनल (संरा. अमेरिका) अपने आकार, समाचार इकट्ठा करने और दुनिया भर में कई भाषाओं में वितरण की अपनी प्रणाली की तकनीकी ताकत के कारण व्यापक अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभा रही हैं। प्रत्येक का सौ से अधिक देशों में कार्यालय है, जहाँ हजारों पूर्णकालिक कर्मचारी और अंशकालिक संवाददाता कार्यरत हैं। वे एक दिन में सैकड़ों-हजारों शब्द इकट्ठा करती हैं और घरेलू वितरण समेत पूरे विश्व में लाखों शब्द खबरों का वितरण करती हैं। प्रत्येक एजेंसी चौबीसों घंटे राष्ट्रीय एजेंसियों और सौ से अधिक देशों के समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन संगठन को समाचार देती रहती हैं। सभी आमतौर पर अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश भाषा में दैनिक नियमित सेवाएं देती हैं; कुछ अन्य भाषाओं में भी अपनी सेवा प्रदान करती हैं।

दुनिया के सभी क्षेत्रों के कई अन्य देशों में राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों का महत्व बढ़ रहा है। उनमें से कई व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से विदेश में अपना खुद का दफ्तर या संवाददाता रख रही हैं जो खबर एकत्र करने या भेजने का काम करते हैं। अधिकांश राष्ट्रीय एजेंसियों का देश में संवाददाताओं का एक नेटवर्क है। बाहरी खबर के लिए वे दो या और अधिक वैश्विक एजेंसियों के साथ आदान-प्रदान करती हैं। वे इनसे विदेशी समाचार प्राप्त करती हैं और इन्हें घरेलू खबरें देती हैं। कई एजेंसियां अपने पड़ोसी या गहरे संबंधी देशों की छोटी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की भी सदस्यता ले लेती हैं। हालांकि, कई देशों में समाचार सेवा अभी तक उचित रूप से एजेंसियों की प्रणाली में नहीं ढल पाई है। लेकिन उनके ज्यादातर दफ्तर आधिकारिक खबरें जुटाने और देने तथा बाहरी खबरों को छांटने के लिए स्थापित किए जाते हैं।

दुनिया भर में समाचार पत्रों का कुल दैनिक प्रसार 40 करोड़ [37] प्रतियों से भी अधिक है। इसमें पिछले दस वर्षों में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। प्रसार का प्रति हजार निवासियों पर औसत दुनिया के औसत से भी अधिक बढ़कर 104 से 130 तक हो गया है। दैनिक समाचार पत्रों की कुल संख्या 8000 के आसपास है। देश के स्तर पर (प्रति 1,000 निवासियों पर) सबसे ज्यादा दैनिक समाचार पत्र का प्रसार स्वीडन और जापान (लगभग 600) में होता है। क्षेत्रीय स्तर पर (प्रति1,000 निवासियों पर) सबसे ज्यादा प्रसार सोवियत संघ (396) में है। दैनिक समाचार पत्रों की सबसे अधिक संख्या उत्तरी अमेरिका (1935) में है। अखबारों का सबसे कम प्रसार अफ्रीका में है, जहां प्रति 1,000 निवासियों पर 14 प्रतियां ही बंटती हैं। कई स्थानीय अखबार अपने पाठकों को गंभीर रिपोर्टिंग, विदेशी समाचार और विचारों के आदान-प्रदान से मरहूम रखते हैं। अक्सर इसकी वजह इन अखबारों का छोटा होना बताया जाता है। लेकिन ऐसे ही 4-6 पेज के कुछ अखबार अपने पाठकों को अच्छी तरह से बाख़बर रखने में सफल हुए हैं।

उपलब्ध आंकड़ें बताते हैं कि प्रसार में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन विश्व भर में दैनिक समाचार पत्रों के प्रसार का आंकड़ा पिछले सालों की तरह स्थिर बना हुआ है। यह आंकड़ा- मुख्य रूप से छोटे स्थानीय अखबारों के विलय या बंद हो जाने खत्म होने के कारण और बड़े पैमाने पर रेडियो और टेलीविजन के प्रसार के कारण पैदा हुई प्रतिस्पर्धा से स्थिर बना हुआ है। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में तो यही सारे कारक रहे हैं।

समाचार के प्रसारण में समाचार पत्रों की भूमिका कम होती जा रही हैं क्योंकि विकसित देशों में विशेष रूप से टेलीविजन ने अपनी रिपोर्टिंग तेज कर दी है और एक समाचार स्रोत के रूप में अपनी माँग को बढ़ाया है। लेकिन अखबारों की अहमियत अभी भी इसीलिए कायम है क्योंकि वे सामाजिक घटनाओं को समझाते हैं, उनकी व्याख्या और उन पर टिप्पणी करते हैं। खास तौर से जब किसी प्रमुख सामाजिक मुद्दों या विश्व मामलों पर व्यापक बहस हो रही हो तो वो सीधी-सपाट रिपोर्टिंग न करके जब जरूरत होती है, विस्तारित विश्लेषण करते हैं। इन सबके साथ ही प्रेस के काम के बारे में कुछ धारणओं को जान लेना चाहिए और पत्रकारों के ढेर सारे कामों को एक निश्चित दायरे में बांधना होगा।[38]

आवधिक (Periodicals) प्रेस इतना विविधता भरा है कि इसकी संरचना, सामग्री या सही आकार का अनुमान लगाना तथा इसके प्रभाव[39] के बारे में सामान्यीकरण करना असंभव है। आकार को छोड़ भी दें तो भी यह स्पष्ट है कि आवधिक प्रेस, सामग्री की लगभग अनंत विविधता के साथ बहुत से पाठकों की सेवा करता है। कई देशों से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आवधिक प्रेस का प्रभाव और अपील, जन संदेशों की एकरसता को दूर करने और इसको जवाब देने के रूप में सामने आ रहा है।

किताबें, जैसा की वे पहले भी थीं, ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों का एक कभी ना सूखने वाला सोता हैं। इस सदी ने किताबों के उत्पादन में महान और अभी तक जारी तेज वृद्धि देखी है, जिसका श्रेय साक्षरों की कुल संख्या में

वृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, पेपरबैक्स के आगमन, उत्पादन और वितरण तकनीकों में सुधार और पुस्तकालयों के प्रसार और यहां तक कि दूरदराज की जगहों पर घूमंतू पुस्तकालय को दिया जा सकता है। 1955 और 1975 के बीच विश्व पुस्तक उत्पादन को देखें तो सालाना प्रकाशित किताबों की संख्या बढ़कर दोगुनी और मुद्रित प्रतियों की संख्या में तीन गुनी हो गई है। अब हर साल प्रेस से आठ अरब किताबें और 590,000 नए शीर्षक आते हैं। हालांकि, काफी हद तक कागज की लागत में वृद्धि से किताब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जिसने किताबों के जरूरी विकास को धीमा किया है। यह स्थिति भी चिन्हित असंतुलन और निर्भरता के मामलों में से एक है। किताबों का बंटवारा, देशों में और देशों के बाहर बहुत ही असमान रूप से हो रहा है। विकासशील देश दुनिया की आबादी के 70 प्रतिशत के साथ प्रकाशित पुस्तकों का 20 फीसदी उत्पादन कर रहे हैं और इनमें से कई विकसित देशों में केंद्रित कंपनियों की सहायक कंपनियों द्वारा मुद्रित हो रही हैं। आयातित किताबें, विभिन्न वजहों से कभी-कभी ठीक न होते हुए भी स्कूलों में प्रयोग की जाती हैं। प्रकाशन संसाधनों की कमी की वजह से किताबों की दुकानों और पुस्तकालयों में राष्ट्रीय साहित्य बहुत ही घटिया किस्म का होता है।।

दुनिया के सभी क्षेत्रों में रेडियो ही जनसंचार का सर्वव्यापी माध्यम है। सदी के अंतिम 25 वर्षों में इसकी प्रसारण क्षमता तीन गुना से भी अधिक बढ़ी है। 1950 में दुनिया में कुछ 50 देशों के पास प्रसारण की सुविधाएं नहीं थीं; इनमें से 23 देश अफ्रीका में थे। 1960 के आसपास बिना किसी रेडियो ट्रांसमीटर वाले देशों की संख्या घटकर 12 रह गई, जिनमें से 7 अफ्रीका में थे। 1973 के आसपास 187 देशों के क्षेत्रों में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में केवल तीन देश- भूटान, लिकटेंस्टीन और सैन मैरिनो ऐसे थे जहां प्रसारण की कोई सुविधा नहीं थी। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में एक अरब रिसीवर हैं, इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर हर चार व्यक्तियों में से एक पर एक रिसीवर है। दुनिया भर में रिसीवर के इस प्रसार से रेडियो की लंबी

पहुँच होने का एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। विकासशील देशों ने पिछले दो दशकों में इस माध्यम का विशेष प्रयोग किया है।

विकासशील देशों में, रेडियो ही वास्तव में केवल एक माध्यम है, जिसको "जनता के लिए" का ठप्पा लगाया जा सकता है। क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा रेडियो प्रसारण तक पहुंच और उन्हें प्राप्त करने के साधन को पा सकता है।

प्रयोग में आने वाले रेडियो रिसीवरों की अनुमानित संख्या

प्रायद्वीप	वर्ष	कुल संख्या	महाद्वीप	वर्ष	कुल संख्या
अफ्रीका	लगभग 1960	4	एशिया	लगभग 1960	22
	1970	16		1970	58
	1976	30		1976	113
उत्तरी अमेरिका	लगभग 1960	184	यूरोप	लगभग 1960	136
	1970	326		1970	233
	1976	30		1976	284
दक्षिणी अमेरिका	लगभग 1960	14	ओशिनिया	लगभग 1960	3
	1970	31		1970	8
	1976	58		1976	14

स्रोत: यूनेस्को स्टेटिस्टिक्स ऑन रेडियो एण्ड टेलीविजन 1960-1976, ऑफिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, पब्लिकेशन न. 23

कोई भी अन्य माध्यम इतनी कुशलता से जानकारी, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन के लिए इतने सारे लोगों तक पहुंचने की क्षमता नहीं रखता है। रेडियो को विकासशील देशों में दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने और कई स्थानीय भाषा में संचार के लिए करने के लिए (अक्सर स्थानीय बोलियों में) आसानी से और कम खर्च में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग सभी देश अपनी राजनीतिक जरूरतों, सांस्कृतिक ढांचे और बुनियादी मूल्यों के साथ तारतम्य रखते हुए रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण करने की एक निश्चित

क्षमता रखते हैं। आज रेडियो, स्वामित्व और कार्यक्रम दोनों के मामले में अतंरराष्ट्रीय संचार माध्यम है। इन फायदों के बावजूद, रेडियो भाषा और तकनीकी बाधाओं के कारण संचार के एक अंतरराष्ट्रीय माध्यम के रूप में एक दायरे तक सीमित है। केवल संगीत के क्षेत्र को छोड़कर जहां यह एक सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देता है। संगीत के लिए किसी दुभाषिया की जरूरत नहीं है। रेडियो ने विभिन्न देशों के संगीत, विशेष रूप से लोक संगीत को संरक्षित करने, प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने में भारी सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए एशिया पैसेफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने लोक संगीत की रिकॉर्डिंग का एक प्रमुख संग्रह बनाया है जिसका इससे जुड़ी यूनियनों के बीच प्रसारण के लिए आदान-प्रदान किया जाता है। संचार के माध्यम के रूप में टेलीविजन का आना और अधिक उल्लेखनीय है क्योंकि यह केवल कुछ दशक पहले शून्य से शुरू हुआ था। इसका अभूतपूर्व विकास न केवल रिसीविंग सेट के प्रसार में है, बल्कि इसके उत्पादन की गुणवत्ता में भी दिखता है। टेलीविजन एक बहुत बड़े स्तर पर दर्शकों के पास उपलब्ध दृश्य सूचनाओं और मनोरंजन को कई गुना बढ़ा देता है। यह दर्शकों में नई उत्तेजना भर देता है जो उन्हें घटनाओं के रंग में डुबो देती है। टेलीविजन पिछले 25 वर्षों में किसी भी अन्य माध्यम की तुलना में संचार में हुई प्रगति का प्रतीक है।

टेलीविजन का युग 1936 में आया जब फ्रांस और ब्रिटेन से कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। 1950 तक 5 देशों के पास नियमित टीवी प्रसारण सेवा थी और 1955 तक आते-आते यह संख्या 17 हो गई। 1960 तक यह आंकड़ा चार गुना बढ़ गया था। एक दशक बाद 100 से भी अधिक देश टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे थे और आज टीवी सेवाएं दुनिया भर के 138 देशों में मौजूद है। दुनिया भर में टेलीविजन रिसीवरों की संख्या एक 40 करोड़ तक पहुंच गई है, जो इस आविष्कार के लाखों लोगों के जीवन और जानकारी के प्रसार पर पड़ने वाले अथाह असर का सबूत है। सबसे हाल के आंकड़े बताते हैं कि 1960 और 1976 के बीच दस लाख से अधिक

टेलीविजन रिसीवर वाले देशों की संख्या में 13 से 34 तक की वृद्धि हुई है। कम से कम नौ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा रिसीवर हैं। ज्यादातर विकसित देशों में सेटों की संख्या वहाँ के परिवारों की संख्या के बराबर पहुंच गई है।

हालांकि, विकासशील देशों में यह एक बहुत छोटी सी जनसंख्या की पहुंच में हैं। कुछ देशों में तो बहुत ही कम लोगों तक इसकी पहुंच है। कुछ देशों में टीवी के कार्यक्रमों की सामग्री से यह पता चलता है कि यह मुख्य रूप से वहां के स्थानीय कुलीन और प्रवासी समुदाय की सेवा के लिए बना है। अपनी अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद, करीब 40 देशों में टेलीविजन 10 प्रतिशत से भी कम घरों में पहुंच पाया है। आधे से अधिक देशों में आधे से भी कम परिवारों के पास टीवी रिसीवर है। रेडियो के विपरीत, एक टीवी सेट की कीमत किसी औसत परिवार की आय से ज्यादा होती है। समुदायिक सेट, उदाहरण के लिए गांव के हॉल में रखे हुए सेट केवल आंशिक रूप से इस सीमा को कम करते हैं। इसके अलावा इसके सीमित क्षेत्र का मतलब है कि यह मुख्यतः शहर में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है और ग्रामीण जनसंख्या के केवल एक अंश तक पहुंच पाता है। फिर से रेडियो के विपरीत, टेलीविजन कार्यक्रमों का उत्पादन एक महंगा काम है। स्वाभाविक रूप से गरीब देशों की अन्य प्राथमिकताएं हैं। इसलिए टेलीविज़न स्क्रीन पर कई घंटे ऐसे आयातित कार्यक्रमों दिखाये जाते रहते हैं जो मूल रूप से विकसित देशों के दर्शकों के लिए बना होता है। ज्यादातर विकासशील देशों में, प्रसारण का आधा से अधिक समय आयात किए गए कार्यक्रमों के खाते में जाता है। किसी अन्य क्षेत्र के मुकाबले कम से कम टेलीविजन के क्षेत्र में तो सांस्कृतिक वर्चस्व और सांस्कृतिक पहचान को खतरे की चिंता तो होती ही है।

सभी तरह की तकनीकी खोजों की जड़ में या उसके साथ मास मीडिया का व्यापक प्रसार जुड़ा रहा है। यह दर्शकों के एक बड़े दायरे तक पहुंच का दरवाजा खोलता है। इससे सूचना और मनोरंजन के स्रोतों और संसाधनों के

विस्तार को भी रास्ता मिलता है। इसने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का समर्थन किया है। जब यह स्पष्ट है कि जनसंचार के माध्यमों ने बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, तो उनका विकास इतनी ही जरूरी है। इसके लिए अनुसंधान बहुत आवश्यक है, न केवल विकासशील देशों में बल्कि विकिसित देशों में भी। क्योंकि जनसंचार के माध्यमों का विस्तार और उनकी दिशा केवल राजनीतिक फैसलों या उपलब्ध संसाधनों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। सभी देशों में भविष्य के संचार माध्यमों के विकास की रूपरेखा के लिए आधारभूत अनुसंधान होने चाहिए।

7- उपग्रह

भूमंडलीय उपग्रहों से संचार ने एक उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो नीचे दी गई दो तालिकाओं से पता लगता है-

इण्टेलसेट सेटेलाइट प्रणाली की वृद्धि

वर्ष	एण्टीना वाले देश	हाफ-सर्किट
1965	5	150
1970	30	4,259
1975	71	13,369
1979	114	उपलब्ध नहीं

स्रोत: इण्टेलसेट वार्षिक रिपोर्ट, 1979

इण्टरस्पुतनिक सैटेलाइट प्रणाली की वृद्धि

वर्ष	जमीन से संचालित स्टेशन वाले देश	सैटेलाइट का प्रकार
1973	3	"मोलनिया"- 2
1975	6	और "मोनलिया"-3
1979	9	"स्टेशनर"
1980	12	"स्टेशनर"

स्रोत: इण्टरस्पुतनिक द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े, 1979

बहुत कम समय में ही ग्रह, उपग्रहों और संदेशों से भर गए (1957 से 1979 के अंत तक करीब 2,100 उपग्रह भेजे गए)। ये उपग्रह अब कई क्षेत्रों का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं मसलन- समाचार एजेंसियां और प्रेस, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, टेलीफोन और दूरसंचार [40], व्यापार, बैंकिंग, वाणिज्य, कृषि, खनन, विमान, नौपरिवहन, मौसम विज्ञान, मनोरंजन। ये सब पहले से ही मनुष्य की बहुसंख्यक आबादी के दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित कर रहे हैं।[41]

दुनिया में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय संभावना से भरी 33 से अधिक संचार उपग्रह प्रणालियां काम कर रही हैं या निर्माणाधीन हैं। एक और बड़ी उपलब्धि है जिसे प्रयोग के आधार पर चार भागों में बाँटा जा सकता है

(क) अंतरराष्ट्रीय उपग्रह प्रणालियाँ। इस समय केवल इण्टेलसेट और इण्टरस्पुतनिक ही इस तरह की प्रणाली है। इण्टेलसेट नामक प्रणाली तीन महासागरों के 100 से अधिक देशों को सीधे उपग्रह संचार प्रदान करती है। इण्टरस्पुतनिक मुख्य रूप से एक घरेलू प्रणाली है जो समाजवादी और कुछ अन्य देशों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

(ख) घरेलू और क्षेत्रीय उपग्रह प्रणालियां। सोवियत संघ के मोल्निया (Molnia) और एकरान (Ecran), कनाडा के अनिक (Anik), इंडोनेशिया के पालपा (Palpa) और अमरीका के वेस्टर (Westar), कोमस्टर (Comstar) और आरसीए घरेलू और क्षेत्रीय उपग्रह के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो काम कर रहे हैं। पश्चिमी यूरोपीय, अरब और नॉर्डिक देश भी इस परिचालन प्रणाली से जुड़ने वाले हैं।

(ग) समुद्री और विमान संबंधी उपग्रह प्रणालियां। इस तरह की मोबाइल संचार उपग्रह प्रणालियों का उदाहरण समुद्र में जहाजों के लिए इस्तेमाल होने वाला मरिसेट (Marisat) प्रणाली, वाणिज्यिक विमान के लिए ऐरोसेट

(Aerosat) है (जिसकी अभी योजना बन रही है) चरण में) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मरेक्स (Marecs) (एक समुद्री उपग्रह का उत्पाद) है।

(घ) सैन्य उपग्रह प्रणाली।

यूरोपीय संचार उपग्रह प्रणाली 1980 के मध्य तक चालू हो जाएगी। कई और यूरोपीय उपग्रह प्रणालियों पर पहले से ही काम चल रहा है। बहुत सी प्रमुख उपग्रह प्रणालियों में अब फ्रेंको-जर्मन सिम्फनी प्रयोगात्मक प्रणाली में सिम्फनी I और II (Symphonie I, II) हैं जो 1974 के अंत में शुरू हो जाएगीं। इटली का सीरियो (Sirio) प्रणाली और यूरोपीय और उत्तर अफ्रीकी देशों के बीच अंतर्देशीय टेलीफोन संचार के लिए क्षेत्रीय ओटीएस प्रणाली भी इनमें शामिल है। नासा द्वारा एक प्रयोगात्मक जापानी संचार उपग्रह अप्रैल 1978 में लांच किया गया जिसका मकसद व्यक्तिगत टीवी सेट तक सीधे टीवी कार्यक्रमों भेजने की संभावना तलाशना था।[42] तीन प्रायोगिक संचार उपग्रह प्रणालियों के प्रदर्शन को देखने के बाद एक या एक से अधिक घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों को अगले दो साल में शुरू होने की योजना बनाई गई है। अन्य संभावित क्षेत्रीय संचार उपग्रह प्रणालियों में अफ़्रीकी सेटेलाइट सिस्टम और रेडियन सेटेलाइट सिस्टम हैं। कुछ अन्य देशों में भी इस तरह की परियोजनाओं के विकास पर काम चल रहा है। इन देशों में अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, कोलम्बिया, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, लीबिया, मलेशिया, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पेरू, फिली-पींस, सऊदी अरब, स्पेन, सूडान, थाईलैंड, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, वेनेजुएला और ज़ैरे शामिल हैं। 120 से अधिक देशों के पास उपग्रहों से ट्रांसमीशन और संकेत प्राप्त करने लायक पृथ्वी पर स्टेशन (अर्थ स्टेशन) हैं।

संचार उपग्रहों ने अपनी अद्भुत क्षमता, तेजी से बढ़ी संख्या और सबसे महत्वपूर्ण, टीवी और कम्प्यूटर के लिए एक साथ इस्तेमाल हो सकने की क्षमता के चलते कामकाज के नए क्षेत्र खुले हैं जहां अथाह संभावनाएं हैं। कई सारे देश अपने आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय संचार के लिए उपग्रहों का

उपयोग करने में रुचि रखते हैं। यही वजह है कि हमें इसके कानूनी, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक,मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं पर व्यापक चर्चा करने और जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत है।

8. कम्प्यूटर

इस कड़ी में यह अंतिम है, लेकिन किसी मामले में कम नहीं है। क्योंकि सूचना विज्ञान इस तेजी से आगे बढ़ेगा यह तो इस क्षेत्र में काम करने वालों ने भी नहीं सोचा था। बड़े संस्थानों की केंद्रीकृत व्यवस्था में कम्प्यूटर प्रणाली के आने से सूचनाओं के प्रसारण (बाइनरी या डिजीटल इंफोर्मेशन) की धारा में बहुत तेजी से विस्तार होता है। वे पहले जमीनी संपर्क (Earth Link, को-एक्सेल केबल और रेडियो लिंक) द्वारा और बाद में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह संपर्कों से प्रभावित हुए। इस विकास ने विभिन्न रूप अपनाए- टेलीप्रोसेसिंग (तारे के आकार की आकृति) के विभिन्न संभावित रूप बनाने वाले कई टर्मिनल; कम्प्यूटरों को एक-दूसरा से जोड़ना (डेटा ट्रांसमिशन); या बहुत से डेटा प्रोसेसिंग सर्विस नेटवर्क (डेटा बेस, कस्टमाइज डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और फाइलिंग)। इस तरह से कम्प्यूटर नेटवर्क और/ या सिस्टम ने संचार के क्षेत्र में काम करता है। हालांकि, तीन बुनियादी क्रियाएं लगातार होती रहती हैं और अब यह और तेजी से "बटी" हैं- स्टोरेज यानि भंडारण (मेमोरी), अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशनल यूनिट (प्रोसेसिंग), पेरिफेरल इनपुट/आउटपुट यूनिट्स (एक्सेस)। इसके बाद वाले कार्य में संभावित उपयोगकर्ता और कम्प्यूटर प्रणाली के बीच संचार स्थापित किया। कम्प्यूटर सिस्टम और इसके उपयोगकर्ता के बीच संचार बाद में जाकर संभव हुआ। इसकी लागत, काम, विश्वसनीयता और कम्प्यूटर हार्डवेयर के आकार में लगातार सुधार हुए और इसी तरह से उसकी क्षमता और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीकों में भी बहुत विविधता आई। दरअसल, अब छोटे से सिस्टम में ही सभी कुछ समाए हुए कंप्यूटर तेजी से कई गुना बढ़ते जा रहे हैं।

कम्प्यूटर अब एक सेकेण्ड में एक अरब काम करने में सक्षम हैं। या यूं कहें कि 1944 के अग्रणी कम्प्यूटर की तुलना में एक लाख गुना अधिक तेजी से काम करने में सक्षम हैं। प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट का आकार 10,000 गुना तक सिकुड़ गया है, जबकि इन यूनिट की गति (निर्देशों की संख्या या प्रति सेकंड प्रोसेसिंग के आधार पर) में लगभग 50,000 गुना की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के अनुसार, ये रुझान कम से कम 1980 के दशक तक जारी रहने की उम्मीद है। पांच मिलीमीटर के सिलिकॉन चिप की सतह पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसे माइक्रोसर्किट भी कहते हैं, को एक यूनिट के रूप में निर्मित किया जा सकता है। एक चिप द्वारा ले जा सकने वाले अंशों (components) की संख्या में हाल के वर्षों में 10 से 64,000 तक की वृद्धि हुई है। निर्माताओं को 1985 तक इसके दस लाख तक की वृद्धि की उम्मीद की है। 10X15 सेंटीमीटर के एक बहुत पतले तत्व में एक बड़े शहर की टेलीफोन निर्देशिका (डाइरेक्टरी) से अधिक जानकारी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से एक कम्प्यूटर या डेटा बैंक से एक टर्मिनल यानि अंतिम स्थान तक ट्रांसमिशन की गति भी बढ़ी है। इसके लिए पहले एनालॉग सिस्टम (संकेतों को एनालॉग से प्रासंगिक सूचना के रूप में इस्तेमाल करना) और फिर डिजीटल बाइनरी सिस्टम को धन्यवाद देना चाहिए। बाद में सारी सूचनाएं अंकों में बदल दी गईं जिसे 'बाइनरी' कहा जाता है क्योंकि इसमें दस अंकों के बदले केवल दो चिन्हों का इस्तेमाल होता है। शब्दों में बंधी सूचनाओं को बाइनरी में भेजा जाता है जो अपने गंतव्य स्थान पर तुरंत पहुंच जाती है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया उसी क्षण संपन्न हो जाती है। रिपीटर्स का इस्तेमाल करके बहुत दूर से भी संकेतों को भेजा जा सकता है और इससे उसकी गुणवत्ता पर बहुत कम असर पड़ता है या नहीं भी पड़ता है। पहले एक-दूसरे में गूंथे और फिर खुद ही अलग हो जाने वाले कई हजार संकेतों को एक ही समय में ले जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट की लागत में पिछले 25 वर्षों में नाटकीय रूप से गिरावट आई है, उदाहरण के लिए हर कम्प्यूटर गणना की लागत 180 गुना नीचे गिरी है।

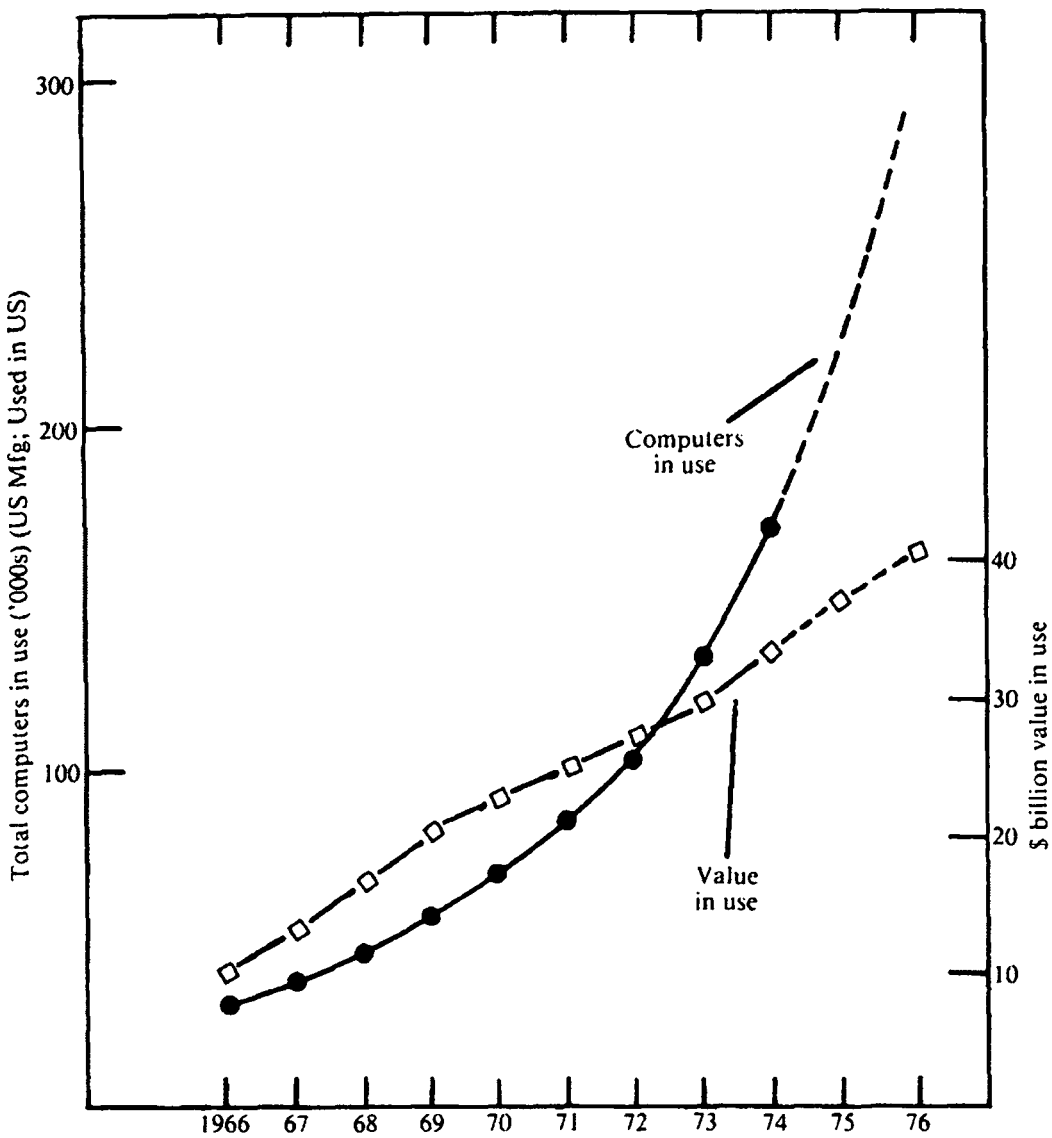

शुरुआती दिनों में एक कम्प्यूटर पर दस लाख डॉलर खर्च हो सकता था, जो अब 300 डॉलर के अंदर ही मिल सकता है। दस लाख गणना के काम की लागत एक दशक पहले दस डॉलर थी जो अब दो सेंट तक हो गई। एक सिलिकॉन चिप पर जा सकने वाले घटक की लागत दस डॉलर से कम होते-होते एक सेंट के पांचवें हिस्से तक पहुंच गई है। सूचना विज्ञान, जिस पर

पहले केवल धनी निगमों और प्रमुख सरकारी विभागों का विशेषाधिकार था, अब छोटे व्यवसाय, पड़ोस के स्कूलों और यहां तक कि हमारे घर की पहुंच में आ गया है।

पिछले दस साल के दौरान (1966-1976) में अमेरिका में प्रयोग किए कम्प्यूटरों और उनके दाम की तुलना करने वाले पिछले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट से यह साफ हो जाता है कि डाटा प्रोसेसिंग की लागत में तेजी से कमी आई है।

औद्योगिक देश तेजी से कम्प्यूटर में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। यह नीचे दिए गए आंकड़े से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हैं क्योंकि कम्प्यूटरों की लागत में पिछले कई वर्षों में तेजी से कमी हुई है। इस तालिका से कुछ विकसित देशों द्वारा कम्प्यूटर में किए गए निवेश (जीएनपी के प्रतिशत के रूप में) का पता चलता है।

देश	**1970**	**1979**
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.11%	3.2%
जर्मन गणराज्य	1.34%	2.45%
यूनाइटेड किंगडम	1.55%	2.83%
फ्रांस	1.18%	2.65%
इटली	0.77%	1.5%
बेनेलक्स	1.15%	2.3%

यह देखना विशेष रूप से दिलचस्प है कि अगर डाक सेवाओं के द्वारा पूरे टेलीकम्यूनिकेशन में किए निवेश की तुलना कम्प्यूटर में इसके इस्तेमाल करने वालों द्वारा किए गए निवेश से की जाए तो वे कई गुना ज्यादा है। कई विकसित देशों के आँकड़े बताते हैं कि इन दो उद्देश्यों के लिए खर्च किए गए संसाधन धीरे-धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यह दूसरे देशों विशेष

रूप से विकासशील देशों के लिए इस बात का इशारा हो सकता है कि वे भविष्य में संचार के विकास के लिए अपने निवेश की नीतियों पर पुनर्विचार करें।

इसके अलावा समग्र राजनीतिक और आर्थिक विकास के अलावा हाल की गतिविधियों ने उन्नत संचार सुविधाओं की मात्रा में बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, जिसके लिए तीन तरह के विकास को शुक्रिया करना जरूरी है- (क) विकास, विस्तार और संचार के आधारभूत ढांचे के लिए तेजी से बढ़ता कुशल संगठन; (ख) संदेशों का उत्पादन करने, भेजने और प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और मशीनों के नए रूपों का उपयोग; (ग) संचार में इस्तेमाल होने वाले तरीकों और संकेतों में बदलाव (यानी डिजीटल सिग्नल)।

डिजीटल डेटा ट्रांसमिशन विधि का उपयोग तकनीकी अर्थों में सबसे महत्वपूर्ण चरण के रूप में माना जा सकता क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर की भाषा में तैयार सभी मौखिक और दृश्यात्मक संदेशों का स्टोरेज कर पाना, उन्हें भेजकर पुनः प्राप्त कर पाना और उनका प्रसार कर पाना संभव हो सका है। यह अपने आप में इस क्षेत्र की क्षमता और व्यवहार में एक बहुत बड़ी छलांग है।

संचार माध्यमों के लगातार और नियमित विकास से दो मुख्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं- एक, ये परिवर्तन संचार माध्यमों के विकास में एक ऐसी प्रवृत्ति को दिखाते हैं जो अब बदली नहीं जा सकती यानी कि इसमें अब पीछे नहीं लौटा जा सकता; दूसरा यह कि अलग-अलग मीडिया के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक तकनीक पर ध्यान देते हुए, किसी राष्ट्र को दूसरी तकनीक या माध्यम की उपेक्षा करके खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अक्सर कहा जाता है कि हम 'इलेक्ट्रॉनिक युग' में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इस युग में प्रिंट मीडिया के अंत होने के कोई संकेत मिलते हैं। अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें दशकों तक जानकारी, ज्ञान और खुशी का प्रमुख स्रोत बनी

रहेंगी; उनकी संख्या में बढ़ोतरी करके तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाकर, उनकी निरंतरता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। रेडियो और टेलीविजन को भी सभी विकासशील देशों में सबसे ऊपर स्थान देकर इनके विस्तार और इसमें बड़े निवेश की जरूरत है। इसी तरह की जरूरत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधानों के बारे में भी है। सभी देशों को चाहिए की वे इन सब बातों को धीरे-धीरे लागू करें। विशेष रूप से विकासशील देशों को इसे तात्कालिक जरूरत मानते हुए अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि वे नई तकनीकों का फायदा ले सकें और अपनी विशेष जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से उसे अपना सकें।

टिप्पणियां

(1) यह सिद्धांत 1852 में टाइम्स आफ के सम्पादक जोहन डेलैन के द्वारा प्रतिपादित किया था : "हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी अख़बार का उद्देश्य राज्यसत्ता के काम में साझीदारी करना है। हम यह भी नहीं मान सकते कि अख़बार भी उन्हीं सीमाओं, उन्हीं कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों और से बंधा है जिससे राज्य के मंत्री बंधे होते हैं। दोनों सत्ताओं का उद्देश्य और कर्तव्य हमेशा ही अलग रहा है, आमतौर पर दोनों स्वतंत्र रहे हैं और कई बार तो दोनों बिल्कुल उलट होते हैं। मीडिया की सम्मान और स्वतंत्रता उस वक़्त से ही ख़तरे में पड़ गए जब से इसने अपने आपको एक सेवक की भूमिका में स्वीकार कर लिया। पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने और परिणामस्वरूप पूरी तरह से जनहित में समर्पित होने के बाद मीडिया राज्यसत्ता के साथ किसी तरह से करीब नहीं हो सकता, न ही उसके साथ किसी तरह का गठबंधन कर सकता है।"

(2) संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों में कई बार यह बात कही जाती है, खासतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में यह बात अक्सर प्रयोग की जाती है कि "हर किसी को अधिकार है..." यूनेस्को के 1978 की घोषणा में कहा गया है कि "अपने विचार, अभिव्यक्ति और जानकारी को व्यक्त करने का अधिकार मानवाधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता का अभिन्न और अंग है।"

(3) वाशिंगटन पोस्ट की तत्कालीन मालिक कैथरीन ग्राहम ने लिखा है, "अगर सूचनाओं को सार्वजनिक करने पर अगर कोई रोक लगानी है तो यह कानून बनाने वालों पर लगनी चाहिए न कि हम पर। पत्रकारों का चुनाव जनता नहीं करती। सार्वजनिक जीवन में उनका एकमात्र कार्य है ये बताना कि कौन सी घटनाएं घट रही हैं। निस्संदेह रूप से यह सिद्धांत इस विश्वास

पर आधारित है कि अंततोगत्वा किसी भी समाज में तथ्यों के प्रति अज्ञानता हमेशा ही हानिकारक साबित होती है।" (एल'एक्सप्रेस)

(4) अभी हाल ही में हमारे अधिकृत सदस्यों में से एक हुबर्ट बिववे-मेरी ने इसी समस्या को सामने रखा। उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह रखी, "...क्या रिपोर्टर और जर्नलिस्ट क्या अपने पेशे के सबसे व्यापक अर्थों में और उनके पास जो साधन उपलब्ध हैं उनके अनुसार अपने काम को निम्न सिद्धांत के तहत न्यायोचित समझते हैं: 'कानून, संपूर्ण कानून और कानून के सिवा और कुछ नहीं।'?" या फिर इसके उलट उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारियों और ऐसी सूचनाओं को प्रकाशित करने से होने वाले परिणामों की सीमा का विस्तार करना चाहिए जिनके सच होने के बार में उन्हें पता है?... क़ानूनी उपाय खोजते समय (अगर ऐसा कोई क़ानून मिल भी जाए तो वह क़ानून कुछ सिद्धांतों पर ज़ोर देने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वह भी खुद को तथ्यों को बोझ से दबे दिए बिना),इसलिए इस बात को जरूर रेखांकित किया जाना चाहिए कि पत्रकार ऐसी स्थिति में केवल एक संवाददाता बनकर रह जाता है जिसके लिए सब कुछ बस अपने काम साधने का तरीका है, और इस तरह वह सदिच्छा के साथ जो कुछ घट रहा उसका निर्णायक बन जाता है, विशेषकर जो यहाँ अभी हो रहा है क्योंकि आमतौर पर यह केवल प्रकाशन को टालने भर का मामला होता है, उन सभी मुसीबतों के साथ जो इसमें शामिल होती हैं...कोई भी सूचना पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं होती, न ही हो सकती है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम एक छोटे खतरे से बचने के चक्कर में बड़े खतरे में न फंस जाएं ! क्योंकि फिर तथाकथित नैतिक आधार पर अपनी जिम्मेदारियों से बचना बहुत आसान हो जाएगा। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए इस दृष्टिकोण के आनुषंगिक परिणाम भी होंगे। पत्रकार दूसरे इंसानों जैसा ही एक इंसान होता है और जैसा कि कई लोग मानते हैं उसका काम या तो उन सूचनाओं को प्रकाशित करना होता है जो उसके पास हैं या फिर वह अपने पेशे से मिली सुविधाओं और

जिम्मेदारियों का समाज सेवा के लिए उपयोग करे, जो कि उसे समाज सेवक के समकक्ष बना देगा, लेकिन आखिरकार जनहित किसे कहा जा सकता है। इस संदर्भ में, मैं जापानी एसोसिएशन ऑफ न्यूजपेपर पब्लिकेशन के 1946 में बनाए गए नियमों से पूरी तरह सहमत हूँ।

"यह जनहित, जैसा कि ब्रिटिश रॉयल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी शायद मानती है, मूलतः जनता के जानकारी पाने के अधिकार से तय होता है, इस अधिकार, मानवाधिकार के संदर्भ में, से इस पेशे की वैधानिकता और आवश्यकता स्थापित होती है..."(सीआईसी डॉक्युमेंट नंबर 90 फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट)

(5) "स्वतंत्र मीडिया अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी लेकिन स्वतंत्रता के बिना कोई मीडिया केवल बुरा हो सकता है। मनुष्य की ही तरह मीडिया के लिए स्वतंत्रता बेहतरी का अवसर उपलब्ध कराती है, दासता तयशुदा गिरावट लाती है। (अल्बेयर कामू)

(6) जैसे कि, कुछ देशों में एक ही कंपनी पांच या उससे भी ज्यादा चैनल चला रही है, कुछ दूसरे देशों में एक ही मालिक अखबार और टीवी चैनल दोनों चला रहा है, वहीं कहीं और विभिन्नता के मिलने वाले लाभ तब खत्म हो जाता है जब एक ही स्वामित्व वाले सभी संचार माध्यम एक ही स्वर में बोलने लगते हैं।

(7) "लेकिन हमें कोई मासूम भ्रम नहीं पालना चाहिए। मीडिया व्यवस्था पर नियंत्रण कर सकता है, एक तरह से उसका विरोध कर सकता है उसे खिझा सकता है लेकिन व्यवस्था के पास अपने बचाव के कई तरीके होते हैं। वे कानूनी बंदिशों को तोड़े बगैर यह काम कर सकती है। पत्रकारों का यह पता होना चाहिए कि धूर्ततापूर्ण दबावों, पक्षपातों, मान-सम्मान और घूस का सामना कैसे करना है। स्वतंत्रता यदि स्वीकार कर ली जाए तो भी वह मुफ़्त में नहीं मिलती, हमें हमेशा इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना

चाहिए। अफसोस कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। फ्रांस में 1936 में फ्रंट पाप्युलर सरकार में कुछ साप्ताहिक समाचार पत्रों ने एक मंत्री के खिलाफ ऐसा हिंसक अभियान चलाया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मीडिया की स्वतंत्रता का यह दुखद दूसरा पक्ष है." (हुबर्ट बिउवे-मेरी, सीआईसी के सदस्य, टोक्यो में अक्तूबर, 1979 में दिया गया भाषण)

(8) कम्यूनिकेशन इकॉनमिक्स के एक विशेषज्ञ लिखते हैं, "तीसरी दुनिया के देशों की संचार व्यवस्था इतनी कमजोर है कि उसे मदद की जरूरत है। इन देशों में वैज्ञानिक, तकनीकी, पेशेवर और प्रबंधकीय प्रतिभाओं की भारी कमी है और जो अच्छे लोग यहां हैं वे सभी यूरोप या अमरीका के विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित हैं। तीसरी दुनिया, फिलहाल स्वयं अपनी सुचनाओं का उत्पादन नहीं कर सकती।" (मार्क यूरपोराट, 'पॉलिसी इन एन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी', कम्यूनिकेशन फॉर टुमारो, एस्पेन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमनस्टिक स्टडीज, प्राइजर प्रकाशन, न्यूयॉर्क, 1978)

(9) अति विकसित देशों में सूचनाओं की अकूत संपदा ने पारंपरिक प्राथमिकताओं और पदसोपानिकता को बदल कर रख दिया है। यूरोप में एक दस वर्षीय बच्चा औसतन हर हफ्ते 24 घंटे टीवी देखता है। यह समय उसके स्कूल में बिताए गए समय के लगभग बराबर ही है। अमरीका में तकरीबन 16 साल के किशोर अपने जीवन का 15,000 घंटा टीवी देखने में बिता देते हैं। बहुत से देशों में बहुत सार युवा कैमरा, इलेक्ट्रानिक गैजेट, वीडियो रिकॉर्डर और पॉकेट कैलकुलेटर जैसी चीजों के साथ सहज और सामान्य परिचय बना चुके हैं। इसके उलट, वयस्क जो कि विभिन्न संक्रियाओं(कम्प्यूटर, टीवी, टेलीफोन) के बीच भेद करने में सक्षम होते हैं वे यह समझने में असुविधा महसूस करते हैं कि ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ती जा रही है (टीवी की स्क्रीन कम्प्यूटर का डिस्प्ले और वीडियो गेम्स की स्क्रीन बन जाती है, और साथ ही साथ उसपर फिल्म भी देखी जा सकता है, पॉकेट कैलकुलेटर घड़ी का काम देता है, रेडियो मार्निंग कॉफी

मेकर का), और ऐसे लोग अक्सर सतत 'साउंड इफेक्ट्स' तथा चारों तरफ से आ रही विभिन्न प्रकार सूचनाओं की बाढ़ के आगे खुद को असहाय महसूस करते हैं। (ये आंकड़े विभिन्न संस्थाओं और शोधकर्ताओं के अध्ययन पर आधारित हैं, जैसे, काउंसिल ऑफ यूरोप, एलपोर्चर, जे अर्बायस, जे माउजियो, थॉलॉन पॉमेरॉल इत्यादि)

(10) रेने ला बॉरदियरे द्वारा प्रयोग किए गए पद के अनुसार।

(11) "एक के बाद एक बहुत तेज रफ्तार से होने वाली खोज केवल मनुष्य की नवनिर्माण की जरूरत से नहीं प्रेरित है बल्कि इसमें प्रकृति के रहस्यों को जानने और विज्ञान की क्षमता के प्रयोग से मनुष्य की बेहतरी करने की उम्मीद भी शामिल है लेकिन इसके पीछे एक कारण आर्थिक मांगों से पड़ने वाला दबाव भी है। तकनीकी आविष्कार उत्पादन का एक लाभकारी पक्ष बन चुका है। जिस चीज में कमी आई है वह है विकास के मानसिक और सांस्कृतिक पक्ष पर समाज के नियंत्रण करने की क्षमता में आई गिरावट। मनुष्य अब परिवर्तन की शक्तियों की राह रोकने की कोशिश नहीं करता लेकिन उसने इन शक्तियों को काबू करने में भी हमेशा सफल नहीं होता।" (एमाडोउ महतर एमबॉव का भाषण, यूनस्को के डाइरेक्टर जनरल, 'इनफॉर्मेटिक्स एंड सोसाइटी वीक', 1979 के समापन सत्र में।)

(12) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की एक चेतावनी यहां समीचीन होगी, "...तकनीकी से ज्यादा प्राथमिक है नीतियां, इस बात पर समझाने में हमारी असफलता चेतावनी के स्तर तक पहुंच गई है और आधुनिक विश्व में यह एक खतरनाक और सतत विकसित होती अवधारणा बन चुकी है। यह खतरा संचार के क्षेत्र में मौजूद है। जब तक इसे दूर नहीं किया जाता, संचार के क्षेत्र में होने वाले दूसरे विकास के ऐसे परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं जिसके बार में हमने न तो सोचा होगा न ही एक समग्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए हमने ऐसी कल्पना की होगी..."(कर्ट वाल्धेम)

(13) इनमें से सबसे महत्वपूर्ण निम्न है: यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट (1948) का अनुच्छेद 19 के अनुसार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में "बगैर किसी रोकटोक के विचार रखने की स्वतंत्रता और किसी भी मीडिया या स्रोत से सूचना एवं विचार पाने या देने की स्वतंत्रता।" इसी प्रकार, दी इंटरनेशनल कॉन्वेंटन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स (1966) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ इस तरह व्यक्त किया है, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी तरह की सूचना एवं विचार को पाना या देना शामिल है, चाहे वह मौखिक हो, मुद्रित हो या कलात्मक रूप में हो या किसी की निजी पसंद के अनुसार किसी अन्य रूप में हो।" यूनेस्कोज कन्स्टीट्यूशन में शामिल देशों ने "वस्तुनिष्ठ सत्य की अबाध्य तलाश, और विचारों के मुक्त आदान प्रदान" के लिए "सहमति और प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि वह अपनी जनता के बीच संचार के माध्यमों को बढ़ाने और इन साधनों का उपयोग आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिये करेंगे ताकि लोग एक दूसरे के जीवन बारे में परिपूर्ण और सच्चा ज्ञान पा सकें।" इसके अलावा यूनेस्को की 1966 की आम बैठक में स्वीकार किए गए 'डिक्लेरशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कल्चररल कोऑपरेशन' में कहा गया, "रचनात्मक कार्यों, सत्य के अनुसंधान और व्यक्तित्व के विकास के लिए मुक्त आदान-प्रदान और विचार-विमर्श पर आधारित विचार और ज्ञान का व्यापक प्रसार जरूरी है।" सबसे ताजा डिक्लेरशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मास मीडिया टू स्ट्रेंथनिंग पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, टू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टू काउंटरिंग रेशियलइज़्म, अपार्थिड एंड इनसाइटमेंट ऑफ वार (यूनेस्को) (28 नवंबर, 1978 को स्वीकृत) में कहा गया है, "मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में विचारों, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करना अंतरराष्ट्रीय शांति और समझ की बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है।" (अनुच्छेद II).

(14) इस दौरान किए गए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में कहा गया, "इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना के प्रसार में लंबे समय से भेदभाव भरा बर्ताव होता रहा है...औद्यगोकिक देशों में आम जनता के पास तीसरी दुनिया की मांगों, उम्मीदों और जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जब तक कि सूचना और संचार के प्रारूप बाजारोन्मुख सनसनीवाद से मुक्त नहीं हो जाते और समाचार की प्रस्तुति अपने वर्तमान रूप से उलट किसी भी नस्ल केंद्रित पूर्वाग्रहों से लगातार मुक्त नहीं किया जाता। सूचना देने की क्षमता के बढ़ाने को एक नई दुनिया बनाने का आवश्यक अंग समझा जाना चाहिए और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रसार तंत्र के सूक्ष्म एकाधिकारवादी और भेदभावपूर्ण बर्ताव की भर्त्सना करनी चाहिए।" (आरईओ (रिशेपिंग दी इंटरनेशनल ऑर्डर), अ रिपोर्ट टू क्लब ऑफ रोम, जैन टिंबरजेन, कोऑर्डिनेटर, 1977)।

(15) संयुक्त राष्ट्र के सातवें विशेष सत्र में प्रस्तुत किए गए एक विशेष अध्ययन में कहा गया, "वर्तमान पदसोपानिक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय संचार, यहाँ तक की तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों के बीच के संचार पर भी मल्टीनेशनल कंपनियों का वैचारिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व है। तीसरी दुनिया के ज़्यादातर देशों के जनसंचार पर उनका प्रभुत्व है और ज्यादातर संचार माध्यमों पर उनका प्रभाव है।" (इस अध्ययन डैग हैमरस्कजॉल्ड फाउंडेशन की टीम ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया था। यह अध्ययन, 'व्हाट नाउ? एनद डेवलपमेंट' नाम से प्रकाशित हुआ था।)

(16) ध्यान दें: इस पूरी समीक्षा के दौरान, कुछ सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें सतर्कता से देखना चाहिए। पहली बात यह है कि संचार से संबंधित कई क्षेत्रों में उपलब्ध आंकड़े बहुतायत में होते हैं और सटीकता या सत्यसाधनीयता में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न होते हैं। दूसरी बात यह है कि सांख्यिकीय प्रस्तुतियों आमतौर पर एक विशेष चुनाव होती हैं जो

स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होता है। तीसरी बात यह है कि आंकड़े अक्सर कुल योग या औसत को व्यक्त करते हैं जो कभी-कभी उस सम्पूर्ण योग की अलग इकाइयों में व्यापक अंतर को छिपा लेते हैं। चौथी बात यह है कि किसी दिए गए वर्ष में प्रकाशित आंकड़े अक्सर कई साल पहले इकट्ठे किए गए होते हैं जो पुराने हो जाते हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सम्पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं, जो कुछ हद तक वैध मान्यताओं या निष्कर्ष देते हैं; कुछ अन्य क्षेत्रों में या दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, अधिक चयनात्मक, फिर भी संकेतात्मक आंकड़े दिए जा सकते हैं। इन अस्वीकरणों के बावजूद, कोई भी आंकड़ा जांच की स्थितियों को वर्णन करने और उन्हें समझाने में मदद देता है।

(17) जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव-भाव, संकेत, नृत्य, चित्र, संगीत, गाने, कला, चित्रकारी, मूर्तियां, खेल, आदि। लाखों विकलांग व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही होंठों से भाषा पढ़नें की कला या संकेत भाषा का प्रयोग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

(18) इस तरह की गतिविधियों के विशाल परिमाण को साबित करने के लिए एक उदाहरण यह है कि हर साल लगभग दो लाख वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ केवल अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने का अनुमान लगाया गया है; यदि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों को ध्यान में रखा जाए, तो शायद यह संख्या पांच लाख से अधिक व्यक्तियों के सालाना शामिल होने तक पहुंचेगी।

(19) ये आंकड़े (इनका स्रोत लैन्गुएज ऑफ द वर्ल्ड, कैनेथ काट्जनर, टोरंटो, 1975 है) केवल संकेतात्मक हैं क्योंकि उनका विभिन्न आधारों पर विरोध हुआ है। विभिन्न भाषाओं के मानचित्रण का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अभी भी वैज्ञानिकों के बीच भाषाओं और बोलियों के बीच भेदभाव

में मतभेद आम है। अभी तक कई देशों के एक बहुत बड़े क्षेत्र में सामान्य जनगणना को पूरा नहीं किया गया है। कुछ राजनीतिक कारणों से भी कुछ भिन्नताएँ काफी मुश्किल बन गई हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान साहित्य में, भाषाओं की संख्या करीब दो हजार से चार हजार के बीच है। जहां तक लिखित भाषा का संबंध है, मतभेद इस बात से भी उठता है कि 500 लिखित भाषाओं में से केवल 200 भाषाओं में ही लेखन और साहित्यिक परंपरा है, अन्य 200 भाषाओं में केवल लेखन की परंपरा है, जबकि लगभग 100 से ज्यादा भाषाओं में अक्षरों से थोड़ा ज्यादा एक प्रारंभिक रूप ही विकसित हुआ है।

(20) यह अनुमान लगाया गया है (यूनेस्को सेवाओं द्वारा) कि मुद्रित सामग्री का दो तिहाई से अधिक भाग अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है।

(21) यह अनुमान लगाया गया है कि वैज्ञानिक संचार का लगभग 60% अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है। यहां तक कि, कुछ अनुमानों के अनुसार, फ्रेंच बोलने वाले देशों में 70% से अधिक शोधकर्ता अंग्रेजी स्रोतों का उपयोग करते हैं।

(22) यह पर ध्यान देना दिलचस्प है कि वैसे तो इसने इनपुट-आउटपुट सॉफ्टवेयर के उत्पादन की समस्या का समाधान नहीं किया, जहाँ ज्यादातर कंप्यूटर मुद्रण में अभी भी टाइपराइटर की तरह के मुद्रण का प्रयोग होता है, 2,000 अक्षरों को समायोजित करने के लिए यह एक खराब तंत्र है। अब एक नए विद्युतचुम्बकीय लघु प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिसे "इंकजेट मुद्रण" कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक अक्षर स्याही के लघु बिंदुओं के प्रवाह में बंट जाते हैं और एक नोक से फेंका जाता है इसी उड़ान के

समय विद्युतीय रूप से वांछित मुद्रित चित्र बनाने का काम करता है (इंकजेट मुद्रण के विभिन्न तरीकों को इजाद कर लिया गया है, एक ऐसा मुद्रक प्रति मिनट 45,000 लाइनें मुद्रित करता है!)

(23) "अधिकांश लोग को व्यर्थ दुरुपयोग के भौतिक स्वरूप के बारे में ही सोचते हैं, जैसे संसाधनों, ऊर्जा, या पैसे की बर्बादी के रूप में। वास्तव में, वैश्विक समस्याओं की सोच रखने वालों ने अनवीनकरणीय भौतिक संसाधनों के व्यर्थ दुरुपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पर एक अन्य तरह की व्यर्थता ने वैश्विक समस्याओं की पूरी गांठ पर और भी अधिक गंभीर प्रभाव डाला है: मानव के सीखने की क्षमता की बर्बादी। इस संदर्भ में, बर्बादी केवल दुरूपयोग से नहीं हुई जिसने लोगों को एक हासिये पर धकेल दिया, बल्कि मानव क्षमता के उपयोग की कमी या इसकी उपेक्षा से भी हुई है...न चाहते हुए भी लोग बड़ी संख्या में केवल सीखने की प्रक्रिया को विकसित करने के सबसे अल्पविकसित, अनौपचारिक अवसरों को छोड़कर कुछ भी नहीं पाते हैं... अशिक्षा, अज्ञानता और गरीबी के बढ़ते दुष्चक्र का लक्षण और कारण दोनों ही है, और मानव के सीखने की क्षमता को व्यर्थ करने का सार है।"

(द ह्यूमन गैप, रोम क्लब को दी गई द लर्निंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 1979, पृष्ठ 106-107)।

(24) निरक्षरता पर आंकड़े के लिए स्रोत: यूनेस्को सांख्यिकी कार्यालय। विशेष रूप से अशिक्षा पर हाल ही में प्रकाशित अनुमान और प्रक्षेप, यूनेस्को, सितंबर 1978, (इन आंकड़ों में चीन, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और वियतनाम के आंकड़े शामिल नहीं हैं)।

(25) जैसा ब्राजीली शिक्षाविद् पाउलो फ्रेयर द्वारा व्यक्त किया गया।

(26) औसतन दुनिया भर में हर 7000 व्यक्तियों के लिए एक पोस्ट ऑफिस है; कुछ यूरोपीय देशों (जैसे नार्वे, पुर्तगाल), में प्रति 1,000 व्यक्तियों से कुछ कम पर एक डाकघर है, लेकिन कुछ अफ्रीकी और एशियाई देशों में सैकड़ों हजार लोगों लिए एक ही पोस्ट ऑफिस है (जैसे रवांडा में 300,000 लोगों पर एक पोस्ट ऑफिस) (स्रोतरू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 1974)।

(27) क्योंकि टेलीफोन औद्योगिक समाज में इस तरह से एक आम सुविधा हो गई है। इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को कभी देखा ही नहीं गया, विशेष रूप से तीसरी दुनिया में विकास के लिए एक संभावित शक्तिशाली और वास्तव में आवश्यक उपकरण के रूप में, और इसके सामाजिक - आर्थिक प्रभाव अपर्याप्त विश्लेषण किया गया है। यह ठीक ही कहा गया था: "परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं में टेलीफोन की विशिष्ट प्रौद्योगिकी कैसे महत्वपूर्ण थी। यह असाधारण है कि इस सवाल की खोज में बहुत ही कम लिखा गया है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने न केवल टेलीफोन की उपेक्षा की, बल्कि अन्य प्रौद्योगिकियों के सापेक्ष भी इसे छोटा स्थान दिया? सामाजिक बदलाव का एक कारण के रूप में, परिवहन का संचार से अधिक अध्ययन किया गया। और संचार मीडिया के माध्यमों के रूप में टीवी, रेडियो, सिनेमा, यहां तक कि टेलीग्राफ का टेलीफोन से अधिक अध्ययन किया गया है।" (टेलीफोन के सामाजिक प्रभाव, इथिएल डे सोला पूल, संपादक, एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज, मैसाच्यूसेट्स, 1977)।

(28) सामाजिक आर्थिक विकास में दूरसंचार की भूमिका, हडसन, गोल्डश्मिट, पार्कर और हार्डी, कीवैटिन प्रकाशन, 1979)

(29) इन मुद्दों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा दिया गया एक उद्धरण प्रासंगिक हो सकता है: "जैसे विकास कार्यक्रम का ध्यान केंद्रित स्थानीय

गतिविधि की ओर गया है, एक विकासशील देश के लिए बड़ी-बड़े दर्शक समूहों वाले मीडिया से ज्यादा स्थानीय दर्शकों की चिंता से संबंधित विषयों वाले मीडिया समूह के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह के एक देश को बड़े और छोटे से मीडिया के बीच चयन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसे दोनों की जरूरत है लेकिन इसे बड़े मीडिया के साथ छोटे मीडिया का संतुलन बैठाने के लिए, राष्ट्रीय रेडियो से स्थानीय रेडियो का, दीवार और परिपत्र अखबारों के साथ राष्ट्रीय अखबारों में संतुलन बैठाने में बुद्धि और दूरदर्शिता प्रदर्शन करना होगा। इस तरह के ज्यादातर देशों में पहले से ही कुछ बड़े मीडिया समूह हैं, और वे उन्हें नाली में नहीं फेंकने वाले हैं। दरअसल, इस तरह के मीडिया का महत्वपूर्ण उपयोग जारी रहेगा। आवश्यक सवाल ये हैं कि (1) उनका कैसे सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, जबकि विकास की रणनीति स्थानीय मुद्दों की ओर मुड़ गई है? (2) स्थानीय संचार आने के कारण बड़े मीडिया की प्रणाली को बनाए रखने और मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? " (विल्बर स्राम, मास मीडिया एण्ड नेशनल डेवलेपमेण्ट-1979, सीआईसी दस्तावेज सं.42)।

(30) 40 से अधिक साल पहले ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) की स्थापना के बाद से, लोक मीडिया, एक विशेष स्टेशन से पारंपरिक पात्रों द्वारा सुनाए गए ग्रामीण क्षेत्र के विशिष्ट जीवन और लोकगीतों में व्यक्त दैनिक कार्यक्रमों के रूप में अपने ग्रामीण प्रसारण में एकीकृत किया गया है।

(31) बोत्सवाना से प्राप्त रिपोर्टों से पता लगता है कि कैसे प्रदर्शन कला-नाटक, कठपुतली, नृत्य, संगीत, का स्थानीय संचार माध्यमों में उपयोग हो रहा है और रेडियो के माध्यम से दुतरफा संचार प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जा रहा है जहाँ इस तरह के प्रदर्शन जिनमें स्थानीय मुद्दों के प्रति संवेदना

होती है, उस समुदाय के प्रति किसी भी तरह के विचार-विमर्श के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो अब तक प्रौढ़ शिक्षा और विकास परियोजनाओं के लिए अधिक संगठित, आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण से समाज की मुख्यधारा से विमुख कर दिया गया था।

(32) चीन में क्रांति से पहले और विशेष रूप से बाद में लोकप्रिय मीडिया, छोटे मीडिया, स्थानीय जानकारी के साधनों को लोगों ने देश भर के सभी भागों में इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, लोक गीत, क्रांतिकारी धारावाहिक फिल्म, और प्रसिद्ध चीनी ओपेरा ने न केवल एक सांस्कृतिक, लेकिन यह भी एक सूचनाप्रद और सामाजिक भूमिका निभाई है। हालांकि इनमें से सबसे उद्धृत उदाहरण 'दजीबाओ' का है जिसका संदेशों और सभी प्रकार की सूचना के लिए प्रयोग किया जाता था तथा इसमें पोस्टर में बड़े अक्षरों या मोटे अक्षरों में संदेश लिखा होता है। यहां एक फ्रांसीसी लेखक द्वारा एक चीनी दुभाषिया के साक्षात्कार को स्पष्टीकरण के रूप में उद्धृत करना दिलचस्प हो सकता है: "हमारी समस्याओं को बाहर पहुँचाने के लिए हमें दसियों वर्ग किलोमीटर कागज की जरूरत है, हमें अपने पाठकों की बात भी लिखित रूप में रखनी है। समस्याओं के प्रति प्रतिक्रियाएं एक गली से दूसरी गली तक, एक शहर से दूसरे शहर तक, और एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक अलग-अलग हो सकते हैं। जब हम इन सभी प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करेंगे तभी हम इस बात का एक विश्वसनीय चित्र विकसित करने में सक्षम हो जाएंगे कि सारा राष्ट्र क्या सोच रहा है। इसके अलावा वे लोग, जो परिवर्तन चाहते हैं, वांछित नियंत्रण में रहते हैं। वे अपनी आवाज को खोजने चाहते थे, पर वे अपने आपको शासित होते नहीं देखना चाहते थे।"

(गॉडविनचू द्वारा संपादित किताब, पापुलर मीडिया इन चाइना, ईस्ट-वेस्ट सेण्टर बुक, 1978 से)।

(33) एक विशिष्ट उदाहरण अफ्रीका में ग्रामीण अखबारों का हाल के वर्षों में विकास हुआ है। 1972 से, 30 से अधिक (यूनेस्को और द्विपक्षीय सहयोग एजेंसियों की सहायता से) स्थापित किया गया है। आमतौर पर मासिक तौर पर प्रकाशित, इन अखबारों की 500 से लेकर 45,000 तक प्रतियां निकलती हैं जो स्थानीय प्रयत्नों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुआ है। अधिक व्यापक पहुंचने वाले अखबार उप-क्षेत्रीय इलाकों में क्षैतिज संचार संपर्क उपलब्ध कराते हैं और कुछ ऊपर से नीचे तक संचार करने के लिए एक चैनल प्रदान करते हैं, जैसे माली में बाम्बारा भाषा का मासिक "किबारू" हर हफ्ते ग्रामीण क्षेत्रों से समाचार और राय के लिए समर्पित राष्ट्रीय रेडियो के पूरे दिन के कार्यक्रम के लिए सूचना का एक स्रोत प्रदान करता है।

(34) एक दिलचस्प उदाहरण बोलीविया से है जहां स्थानीय रेडियो स्टेशन खनन केन्द्रों से संचालित होते हैं। ऐसे खनिकों की यूनियनों द्वारा चलाए कुछ बीस प्रसारण परिचालन उनकी राय व्यक्त करने, उनकी समस्याओं को सामने लाने और सुधारात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव लाने के लिए एक स्रोत प्रदान करते हैं। अपने अभियान के खिलाफ रुक-रुक कर आने वाले सरकारी दबाव के बावजूद, इन मीडिया समूहों का जनता की राय की एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में कार्य करना जारी है। मेक्सिको में, सामुदायिक विकास संस्थान ने ग्वाडलहारा के शहरी इलाकों में एक द्वि-साप्ताहिक बुलेटिन के रूप में विकास गतिविधियों के लिए समूह मीडिया आपरेशन का उपयोग कर एक मल्टी मीडिया प्रयोग शुरू कर दिया जिसमें ग्रामीण प्रवासियों के लिए जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया;

स्थानीय त्योहारों जिसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित संगीत प्रदर्शन, कविता पाठ और चर्चा समूहों को स्थान दिया गया; लोकप्रिय थिएटर समूह; एक फिल्म क्लब और दृश्य-श्रव्य सामग्री के सामुदायिक उत्पादन को प्रमुखता दी गई।

(35) स्रोत: यूनेस्को सांख्यिकीय इयरबुक (1977) और विश्व संचार (यूनेस्को, 1975)। यहाँ उद्धृत आंकड़ों में चीन, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक कोरिया और वियतनाम के समाजवादी गणराज्य को शामिल नहीं किया गया है। चीन के लिए नवीनतम आंकड़ों में बताया गया है कि 1966 में वहाँ 1908 दैनिक समाचार पत्र थे; 1960 के आसपास 1,455 समाचार पत्रों के लिए परिसंचरण आंकड़े 20 लाख प्रतियां या प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 27 प्रतियां थी।

(36) इस अवधारणा को, कि पत्रकारों और समाचार पत्रों का समाचार और तथ्यों को पेश करने से परे कोई और दायित्व नहीं है, अक्सर चुनौती दी गई है। बहुत से तीसरी दुनिया और समाजवादी देशों में, प्रमुख अधिकारी और पत्रकार, मीडिया की भूमिका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं और जरूरतों का समाधान करने के लिए अपना योगदान देने के रूप में देखते हैं। कई पत्रकार पश्चिमी विकसित देशों के अनुरूप उनकी भूमिका को समझते हैं। यहां पर क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के संपादक और अखबार के संपादकों की अमेरिकन सोसायटी के अध्यक्ष जॉन ह्यूजेस की आवाज उद्धृत करना प्रासंगिक हो सकता है, जिन्होंने उनकी भूमिका के बारे में कहा था: "समाचार पत्रों पर अपने पाठकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी है ... संपादकों को समाज की जरूरतों के लिए प्रासंगिक समाचार पत्रों का उत्पादन करने की एक जिम्मेदारी है, जिसमें और अधिक गहराई हो ..."

(37) पत्रिकाओं से संबंधित आंकड़े बहुत ही अपर्याप्त हैं; आंकड़े और अनुमान व्यापक रूप से भिन्न हैं। आवधिक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पीरियाडिकल प्रेस ने बताया है कि 1975 में लगभग 410,000 पत्रिकाएँ थीं। इसी वर्ष के लिए, 137 देशों से आंकड़े देने वाले, यूनेस्को सांख्यिकीय सालाना ने 123,000 पत्रिकाओं का आंकड़ा दिया है। अगर कोई 1960 में केवल वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं के किए गए अनुमान (माउंटबेटन-स्टैमर) स्वीकार को स्वीकार करें जो लगभग 100,000 के आसपास है तो ऊपर के आंकड़ों में से एक की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

(38) एक उदाहरण: पिछले दशक में, अंतरराष्ट्रीय उपग्रह संचार की टेलीफोन क्षमता 150 से एकदम से बढ़कर 10,000 से अधिक सर्किट तक पहुँच गई है; टेलीफोन संदेश प्रसारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपग्रह की नवीनतम पीढ़ी एक साथ 6,000 तक कॉल ले सकते हैं। 1978 में, 1 अरब अंतरराष्ट्रीय कॉलों का 70 प्रतिशत उपग्रह द्वारा नियंत्रित किया गया था।

(39) ये उपग्रहों के सैन्य उपयोग से अलग है- जिसमें से अब लगभग दो-तिहाई से अधिक पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं।

(40) जापान की प्रसारण कंपनी एनएचके लंबे समय से एक सीधी उपग्रह प्रसारण प्रणाली पर काम कर रहा था जो बहुत ही उच्च आवृत्तियों के व्यक्तिगत रिसीवर को गुणवत्तापूर्ण संकेत दे सके, जिसे उपग्रह प्रसारण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रसारण घर के टीवी सेट पर प्राप्त करने के लिए बहुत कमजोर संकेत दे रहा था। फिर भी, एक विशेष कनवर्टर और प्रभावशाली एंटीना का उपयोग कर, इसका अब तक के अनुभव ने बहुत ही संतोषजनक तकनीकी मानकों को हासिल किया है।

(41) "डाटा बेस" और "डाटा बैंक" के बीच एक भेद जरूर किया जाना चाहिए। अब अरबों शब्द का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम चुंबकीय मेमोरी को स्थापित और संचालित करना संभव हो गया है, जिसे कंप्यूटर प्रणाली द्वारा पढ़ा जा सकता है। किसी विषय में ग्रन्थसूची संदर्भ के मामले में जानकारी लेने की प्रक्रिया में, जब वास्तविक दस्तावेज अन्यत्र स्थित हो, किसी सूचना को पुनः लेकर इन्हें जब पढ़ा जाता है तो इस सूचना के स्टॉक को "डाटा बेस" कहा जाता है। इसमें वास्तव में सामान्तया "अंतर्राष्ट्रीय" चैनलों के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी या इसी तरह के दस्तावेज का आम तौर पर, स्वचालन शामिल है। " डेटा बैंक" शब्द प्रत्यक्ष जानकारी के लिए "कम्प्यूटर डेटा" के तत्काल पढ़ने से संबंधित है, इसे अप्रत्यक्ष माध्यम से इस तरह की जानकारी पाने के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। जब से कंप्यूटर प्रणाली पर पहुंच हुई है, तब से अपने टर्मिनल या कंप्यूटर पर संख्यात्मक मूल्यों, सांख्यिकीय श्रृंखला, वर्णनात्मक गुणों को लाना और इसे प्रोसेस करना संभव हो गया है। कंप्यूटर प्रणाली के उपयोग के सुरक्षित हो जाने के बाद से इन डाटा बैंक में ज्यादा रुचि दिखाई गई है, क्योंकि उनके कंप्यूटरीकरण के बाद के उन्हें सभी रूपों में प्रोसेस किया जाता है(छाँटना, फाइलों मिलाना, सांख्यिकीय गणना)। हालांकि उनका तेजी से विकास तीन कारकों से सीमित हो सकता है: डेटा पर कब्जा और उसे मान्यता देने की लागत; अपडेटिंग की लागत; अन्त में विभिन्न गोपनीय सूचनाओं का संरक्षण।

(42) स्रोत: समुदाय में सूचना-विज्ञान के विकास के लिए एक चार साल का कार्यक्रम, यूरोपीय समुदाय आयोग, 1976।

अध्याय तीन

अनूदित रचना में अनुवाद संबंधी समस्याओं का विश्लेषण

अनूदित रचना में अनुवाद संबंधी समस्याओं का विश्लेषण

अनुवाद सम्प्रेषण की एक प्रक्रिया है जो स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करता है। स्रोत भाषा का पाठ जिस तरह अर्थ से जुड़ा होता है वह अनुवाद प्रक्रिया में दूसरे भाषा में अर्थ को अनुवाद करने के लिए आवश्यक होता है। कैटफ़ोर्ड के अनुसार "अर्थ किसी भी भाषा की सम्पत्ति है। एक स्रोत भाषा के पाठ के पास स्रोत भाषा का अर्थ होगा और लक्ष्य भाषा के पास लक्ष्य भाषा का अर्थ होगा। ठीक वैसे ही जैसे जापानी पाठ के पास जापानी अर्थ होगा और अंग्रेजी पाठ के पास अंग्रेज़ी का (Darwish 2003)। "जब कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा के भाषा विज्ञान और संस्कृति के खजाने को लक्ष्य भाषा के भाषा विज्ञान और संस्कृति में स्थानांतरित करता है। स्रोत भाषा की अपनी संस्कृति तथा भाषा विज्ञान होता है और लक्ष्य भाषा का अपना। अनुवाद प्रक्रिया में स्रोत भाषा के भाषायी अर्थ का कोड लक्ष्य भाषा के अर्थ को बताने वाले भाषायी कोड में बदल जाता है तभी अनुवाद सफल होता है। रेनाटो पोगिलाओ ने कहा है कि "अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है (Dooley 2005)"। "इस प्रकार अनुवाद के द्वारा स्रोत भाषा के अर्थ को सहज ढंग से लक्ष्य भाषा में लाने का प्रयत्न अनुवाद के द्वारा होता है। नाइडा ने कहा है कि "अनुवाद का संबन्ध स्रोत भाषा के संदेश का पहले अर्थ और फिर शैली के धरातल पर लक्ष्य भाषा में निकटतम तथा तुल्यार्थक प्रस्तुत करने से होता है (IGNOU 2009)।"

अनुवाद के सम्बन्ध में श्यामसुन्दर दास ने कहा था कि मौलिक रचना की सारी विशिष्टताओं को अनुवादित रचना में लाना संभव नहीं है। अनुवाद का

कार्य करते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि अनुवाद सरल कार्य नहीं है। अनुवाद कभी भी मूलपाठ का स्थान नहीं ले सकता लेकिन मूल के अर्थ को अभिव्यक्त कर सकता है। कैटफ़र्ड ने अनुवाद की भाषा तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर समस्या बतायी है। भाषा के स्तर पर स्रोत भाषा के शब्द, वाक्य रचना आदि का पर्याय लक्ष्य भाषा में नहीं मिलते और सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अनुवाद को भाषा और भाव के स्तर पर समझ कर स्रोत भाषा में स्थानांतरित करते हुए द्विअर्थी शब्दों, भाषा की संरचना और शब्दकोष के स्तर पर समस्याएं आती हैं।

अनुवादक को अनुवाद करते समय विभिन्न प्रकार की भाषिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये समस्याएं अनेकार्थक या द्विआर्थी शब्दों, भाषिक संरचना, सांस्कृतिक शब्दों, अननुवाद्य शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों तथा पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद की समस्या से सम्बन्धित है। मूलपाठ के अर्थ को सम्प्रेषित करते समय अनुवादक लक्ष्य भाषा के अनेकार्थक शब्दों में कौन सा पर्याय उपयुक्त होगा की दुविधा का सामना करता है। भाषा की संरचनात्मकता भी अनुवाद करते समय बड़ी समस्या होती है। प्रत्येक भाषा की अपने देश और काल के अनुसार विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक तत्वों से जुड़ी संरचना होती है और स्रोत भाषा की संरचना के अनुसार लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना सरल नहीं होता। इसलिए भाषा के संरचनात्मक स्तर पर भी अनुवाद में समस्या आती है। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते जिनका अनुवाद नहीं हो सकता है। इन अननुवाद्य शब्दों का अनुवाद करते समय समस्या आती है कि इन्हें लक्ष्य भाषा के शैली के अनुसार कैसे रखा जाए। मुहावरे और लोकोक्तियों के स्तर पर भी समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार अनुवाद एक कठिन कार्य है और जब अनुवादक

के सामने इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो अनुवाद करना और भी दुसाध्य कार्य हो जाता है। मैकब्राइड की उक्त रिपोर्ट "मेनी वॉयसेस वन वर्ल्ड" का अनुवाद करते समय भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिनका विश्लेषण इस प्रकार है:-

"Communication is at the heart of all social intercourse." (पृष्ठ xiii)

हिंदी अनुवाद-

"संचार सभी सामाजिक संबंधों के केन्द्र में है|" इस अनुवाद में "intercourse" का अनुवाद संबन्धों और "heart" के लिए केन्द्र किया गया है। "intercourse" के लिए हिन्दी में समागम, संभोग, मेलजोल, पारस्परिक व्यवहार आदि होता हैं तथा "heart" के लिए केन्द्र, प्रिय, हृदय, बीच आदि पर्याय होते हैं। वाक्य के अर्थ की सूक्ष्मता को देखते हुए तथा दोनों शब्दों का वाक्य में संचार से जुड़े होने के कारण इन दोनों का भावानुवाद केन्द्र और सम्बन्ध किया गया है।

"Create" (पृष्ठ xiii) शब्द का हिन्दी में अर्थ सृजित करना या निर्माण करना होता है। लेकिन स्रोत पाठ में इसका अनुवाद निर्माण करना किया गया है क्योंकि सृजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वयं होता है और निर्माण किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यहाँ "communication" के संदर्भ में "create" का अर्थ "निर्माण" इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संचार दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। अनुवाद करते समय इस सूक्ष्म विषय का ध्यान रख कर अनुवाद किया गया है।

"Side by side" (पृष्ठ-xiii) और "little by little" (पृष्ठ-xiv) मुहावरों का लक्ष्य भाषा में अर्थ की दृष्टि से "मिलकर, साथ-साथ और एक साथ" तथा "little by little" का "धीरे-धीरे" अनुवाद नहीं किया गया है। अनुवाद क्रमशः लोगों के समूह के लिए "आस-पास तथा "सम्बन्ध के लिए मज़बूत" किया गया है जो वाक्य के भाव की सूक्ष्मता के निकट एवं अनुरूप है।

"Wide range of Questions"(पृष्ठ-xv) का अनुवाद "विस्तृत श्रृंखला वाली समस्याओं" किया गया है। यहाँ "Question" का शाब्दिक अनुवाद सवाल या प्रश्न नहीं किया गया है। शब्द के अनुसार अगर अनुवाद कर दिया जाता तो यह वाक्य का भाव व्यक्त नहीं कर पाता। "Question" का अनुवाद 'समस्या' इसलिए किया गया क्योंकि आयोग का निर्माण समस्याओं के लिए हुआ था प्रश्नों के लिए नहीं।

"Shake off the prevailing inertia"(पृष्ठ-xv) का अनुवाद "प्रचलित जड़ता को तोड़ने" किया गया है। यहाँ "Shake off" मुहावरा है जिसका हिन्दी में अर्थ "हिला देना" ज़्यादा प्रचलित है। "Prevailing" का हिन्दी अर्थ साधारण, जायज, जारी, प्रचलित, प्रबल तथा "Inertia" का अर्थ आलस्य, काहिली, जड़ता, निष्क्रियता होती है। वाक्य के अर्थ की सूक्ष्मता तथा भाव के अनुसार उपयुक्त पर्याय के रूप में "shake off" के लिए तोड़ना तथा "Prevailing inertia" को 'प्रचलित जड़ता' किया गया है।

"Report"(पृष्ठ-xv) शब्द का अनुवाद 'रिपोर्ट' तथा प्रतिवेदन दोनों किया गया है। रिपोर्ट शब्द ज्यादा प्रचलित है तथा हिन्दी भाषिक संरचना में इसे इसके मूल रूप में स्वीकार किया गया है।

“Communication maintains and animates life. (पृष्ठ-3) ” का अनुवाद हिंदी में “संचार जीवन को चलाता और आगे बढ़ाता है। “संचार एक गतिशील प्रक्रिया होती है। इसलिए इसका अनुवाद जीवन और संचार को देखते हुए “चलाता और आगे बढ़ाता है”, किया गया है।

“Drum” (पृष्ठ-3) का अनुवाद “ड्रम” ही रखा गया है क्योंकि “ड्रम” पाश्चात्य शैली का एक वाद्ययंत्र हैं जिसे पीट कर बजाया जाता है। भारतीय संस्कृति में पीट कर बजाए जाने वाले वाद्ययंत्रों में ढोलक, तबला, नाल, मृदंग आदि भी आते हैं जिन्हें “ड्रम” की श्रेणी में रखा जाता है। किन्तु इन वाद्य यंत्रों की वादन प्रकृति भिन्न होती है । इसलिए ड्रम की वादन पद्धति की प्रकृति को ध्यान में रख कर ही ड्रम रखा गया है।

"Pictogram" (पृष्ठ-3) लेखन शैली का एक स्वरूप है जो सुमेरिया, युनाना एवं चीन की सभ्यताओं में मिलता है। संस्कृति विशेष से जुड़ा यह शब्द अननुवाद्य है। इसलिए इसे “पिक्टोग्राम” लिखा गया है।

"And gave mankind its pre-eminent position in the animal world"(पृष्ठ-3) का अनुवाद “और मनुष्यों को पशुओं से अलग विशेष स्थिति प्रदान की” किया गया है। Animal-world के लिए यहाँ भाव के अनुसार ‘पशुओं से अलग’ अनुवाद किया गया है। पशु संसार शब्दानुवाद है तथा वह वाक्य के अर्थ को सम्प्रेषित नहीं कर पाता।

"Scroll" (पृष्ठ-4) का प्रयोग पुरानी मिश्र की सभ्यता में किया जाता था। संदर्भों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने वाले भोजपत्रों, चर्मपत्रों और काग़ज़ों के मुट्ठों को "Scroll" कहते हैं। हिन्दी में "Scroll" शब्द के समान पर्याय नहीं है। इसलिए "Scroll" का लिप्यंतरण किया गया है।

पंचायत सरपंच हिन्दी शब्द है जिसे अंग्रेज़ी में Panchayat Serpanches (पृष्ठ- 5) बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। अतः अनुवाद में इसे पंचायत सरपंच ही लिखा गया है।

"Thus, we can trace the origins of types of journalism that we recognise today; the business press, the sensational press, the opinion press and campaigning or crusading press." (पृष्ठ-7)

इस वाक्य के अनुवाद में crusading press को भाव के अनुसार 'धार्मिक मकसद की पत्रकारिता' लिखा गया है। "Crusade" का अर्थ धर्मयुद्ध होता है। अतः शब्दशः अनुवाद करें तो धर्मयुद्ध की पत्रकारिता होती जो एक भ्रामक तथा हास्यास्पद अनुवाद होता। इसलिए वाक्य के भाव के अनुसार यहाँ "धार्मिक पत्रकारिता" उपयुक्त पर्याय है।

"Press" (पृष्ठ-9) का हिन्दी पर्याय बनाना, मुद्रणालय, दबाना, कुचलना, छापाखाना आदि है। प्रेस का नज़दीकी सम्बन्ध संचार और पत्रकारिता से ज़्यादा है। यह जनसंचार के क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है। प्रेस के अंतर्गत मीड़िया, रेडियो, टेलीविजन, प्रकाशन आदि आते हैं। इसलिए अनुवाद में प्रेस और पत्रकारिता दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। Printing Press को लक्ष्य भाषा में प्रिटिंग प्रेस के रूप में लिप्यंतरण किया गया है। Printing के लिए हिन्दी में मुद्रण और छपाई पर्याय है। हिन्दी में इसे मुद्रण प्रेस या छपाई प्रेस करने पर यह जटिल तथा दुर्बोध प्रतीत होता। "Printing Press देश काल तथा परिस्थितिजनित शब्द है। इसलिए इस शब्द का अनुवाद न करके वैसे ही रख दिया गया है।

किसी देश के आविष्कारिक यंत्रों के नाम का अनुवाद संभव नहीं है क्योंकि इन आविष्कारिक यंत्रों के नाम जिस देश में इनका आविष्कार हुआ होगा

वहाँ की सांस्कृति, समाजिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक परिस्थियों के प्रभाव से पड़े होगें। इसलिए उसे जस का तस लिप्यंतरण कर दिया गया है-

पृष्ठ -10.	Phonograph	-	फ़ोनोग्राफ़
पृष्ठ -10.	Signal	-	सिग्नल
पृष्ठ -10.	Telegraphy	-	टेलीग्राफ़
पृष्ठ -10.	Telephone	-	टेलीफोन
पृष्ठ -10.	Wireless	-	वॉयरलेस
पृष्ठ -10.	Photo Telegraphic	-	फोटोटेली ग्राफिक
पृष्ठ -10.	Apparature	-	एपारचर
पृष्ठ -10.	Radio	-	रेडियो
पृष्ठ -10.	Television	-	टेलीविजन
पृष्ठ -11.	Early Bird	-	अर्ली बर्ड
पृष्ठ -11.	Video	-	वीडियो
पृष्ठ -11.	Teleprinting	-	टेलीप्रिंटिग
पृष्ठ -11.	Video Tape	-	वीडियो टेप
पृष्ठ -11.	Orbit	-	ऑरबिट
पृष्ठ -11.	Telecommunication	-	टेलीकम्युनिकेशन
पृष्ठ -11.	Cassette	-	कैसेट
पृष्ठ -11.	Transmiter	-	ट्रांसमीटर
पृष्ठ -11.	Television Signal	-	टेलीविज़न सिग्नल

पृष्ठ -11.	Telephone Traffic	-	टेलीफोन ट्रफिक
पृष्ठ -11.	Telephone line	-	टेलीफोन लाइन
पृष्ठ -11.	Optical Fibre Cables	-	ऑपटिकल फ़ाइबर केबिल
पृष्ठ -11.	Fibre Optic	-	फ़ाइबर ऑप्टिक
पृष्ठ -11.	Optical interactive	-	ऑपटिकल इंट्रएक्टिव
पृष्ठ -11.	Audio-video	-	ऑडियो-वीडियो
पृष्ठ -11.	Data	-	डाटा
पृष्ठ -11.	Electronic Calculator	-	इलेक्ट्रानिक कैल्कुलेटर
पृष्ठ -11.	Micro-processors	-	माइक्रो-प्रोसेसिंग
पृष्ठ -11.	Computer	-	कम्प्यूटर
पृष्ठ -12.	Silicon Chip	-	सिलिकॉन चिप
पृष्ठ -12.	Binary Code	-	बाइनरी कोड
पृष्ठ -12.	Tele - Processing	-	टेली-प्रोसेसिंग
पृष्ठ -12.	Telematics	-	टेलीमेटिक्स
पृष्ठ -12.	Analogical	-	एनालॉजिकल
पृष्ठ -12.	Genetics	-	जेनेटिक्स
पृष्ठ -32.	Cybernetics	-	साइबरनेटिक्स
पृष्ठ -32.	Microwave	-	माइक्रोवेब
पृष्ठ -32.	Light Conductors	-	लाइट कंडक्टर

पृष्ठ -32.	Broadband Digital	-	ब्राडबैंड डिजिटल
पृष्ठ -32.	Tele-informatics	-	टेली-इंफ़ोर्मेटिक्स
पृष्ठ -41.	Censorship	-	सेंसरशिप
पृष्ठ -52.	ASV-CODAR	-	एएसवी-कोडार
पृष्ठ -52.	Computer network	-	कम्प्यूटर
पृष्ठ -64.	Input / output	-	इंपुट-आउटपुट
पृष्ठ -64.	Hardware	-	हार्डवेयर

विभिन्न प्रकार के उपग्रहों के नाम है जिनका अनुवाद नहीं हो सकता। इसलिए इनका लिप्यंतरण किया गया है।

ntelsat (इंटेलसेट), intersputhik (इंटरस्पुतनिक), WESTAR (वेसटर), Gallion Arsenide Laser (गैलियम आर्सेनाइड लेज़र) (पृष्ठ-11) मोल्निया (Molnia) और एकरान (Ecran), अनिक (Anik), पालपा (Palpa),वेस्टर (Westar), कोमस्टर (Comstar) (पृष्ठ -63), मरिसेट (Marist), ऐरोसेट (Aerosat), मरेक्स (Marecs) (पृष्ठ-64).

Binary language and Binary code और Analogical Techniques (पृष्ठ-12) का अनुवाद बाइनरी भाषा, बाइनरी कोड और ऐनालॉजिकल तकनीकी किया गया है। बाइनरी कम्प्यूटर की भाषा है तथा एनालॉजिकल भाषा है जो एनालॉजीके संज्ञात्मक प्रक्रिया में जुड़ा है और अर्थ को एनालॉजिकल तकनीक से प्रसारित करती है। अतः बाइनरी तथा ऐनालॉजिकल अननुवाद्य शब्द हैं जिनका हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुसार बाइनरी भाषा और ऐनालॉजिकल तकनीकी प्रयोग किया गया है।

"Man does not live by bread alone (पृष्ठ-15) " वाक्य में by bread alone मुहावरा है। इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया गया है कि मनुष्य सिर्फ रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता है।

"Self-reliance, cultural identity, freedom, independence, respect for human dignity, mutual aid, participation in the reshaping of the environment - these are some of non-material aspirations which all seek through communication"(पृष्ठ-15)

आत्म-निर्भरता, सांस्कृतिक पहचान, आजादी, स्वतंत्रता, मानव गरिमा के प्रति सम्मान, साझा सहायता, माहौल को नया आकार देने में भागीदारी आदि कुछ ऐसी गैर-भौतिक आकांक्षाएं हैं, जिसे सब लोग संचार के जरिए पाना चाहते हैं। freedom, independence दोनों समानार्थी शब्द एक साथ आएं हैं। अतः वाक्य संरचना को प्रभावपूर्ण तथा अर्थबोधक बनाने के लिए आज़ादी तथा स्वतंत्रता अनुवाद किया गया है। seek शब्द का अर्थ ढूंढना, मांगना, तलाशना होता है। गैर-भौतिक आकांक्षाओं को संचार के द्वारा मांगा नहीं जा सकता। इसलिए "seek" शब्द का अनुवाद वाक्य के भाव के अनुसार "पाना" किया गया है।

"Indoctrination"(पृष्ठ-15) का अर्थ हिंदी में दिमाग को भरने की स्थिति होती है। लेकिन संचार के साथ इसका अनुवाद दिमाग में भरना किया जाए तो वाक्य का अर्थ अटपटा सा हो जाएगा। संदेश संचारित हो कर दिमाग में भरता नहीं है यह हमारे मत को अच्छे या बुरे तौर पर प्रभावित करता है। अतः यहाँ इसका अनुवाद "बुरे से प्रभावित होना" संदर्भ के अनुसार किया गया है।

"Appears to be the most fruitful in answering questions about the role of communication" (पृष्ठ-16) ये संचार की भूमिका के बारे में सवाल का जवाब देने में अधिक सफल प्रतीत होता है।" यहाँ Fruitful का शब्दकोशीय अर्थ लाभ से नहीं लिया गया है। संचार के भूमिका के जवाब की बात करेंगे तो "सफल" अनुवाद अर्थबोधक तथा भावबोधक होगा।

"Divorce" (पृष्ठ-16) शब्द के लिए हिन्दी में अर्थ विवाह-विच्छेद, तलाक या अलग होना होता है। अनुवाद में इसके लिए "कटा हुआ" अनुवाद किया गया है क्योंकि संचार व्यवस्था के साथ कटा हुआ अनुवाद वाक्य के अर्थ को सम्प्रेषित कर रहा है।

"Other observers were convinced that media had such a powerful socializing effect that they could tell their audience how to think and behave." (पृष्ठ-16) का हिन्दी अनुवाद "इस पर नज़र रखने वाले अन्य लोग इस बात से आश्वस्त थे कि मीडिया एक ऐसा शक्तिशाली सामाजिक प्रभाव है जो कि अपने "लक्षित समूह" को बता सकता है कि कैसा सोचा जाए और व्यवहार किया जाए।"

मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र तथा प्रकाशन आदि आते हैं। इसलिए यहाँ श्रोता, दर्शक तथा पाठक शब्द Audience के लिए नहीं लिखा जा सकता । मीडिया के संदर्भ तथा भाव के अनुसार लक्षित समूह ज्यादा अर्थबोधक है।

"Mass-Media" (पृष्ठ-16) का हिन्दी अर्थ जन-मीडिया है लेकिन हिन्दी भाषा में मास मीडिया, जनसंचार तथा जनमीडिया स्वीकृत है। इसलिए अनुवाद में मास मीडिया, जनसंचार और जन मीडिया लिखा गया है।

"Media" (पृष्ठ-16) शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, इंटरनेट, फोटो, मोबाइल, प्रकाशन आदि विभिन्न जनसंचार से जुड़ी शाखाएं शामिल है। मीडिया शब्द की प्रकृति के हिसाब से इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए अननुवाद शब्द को हिन्दी अनुवाद में मीडिया लिखा गया है।

"Black-and-white" (पृष्ठ-17) मुहावरे का हिन्दी में अर्थ सादा, लिखित और ब्लैक एण्ड व्हाइट होता है। लेकिन वाक्य में Black-and-white का अनुवाद "अच्छे और बुरे दोनों पहलू" किया गया है। भावानुवाद "अच्छे और बुरे दोनों पहलू" वाक्य के अर्थ की दृष्टि से किया गया है।

"It is the responsibility of the communication policy makers and professionals to see that such risks are limited and distortions corrected." (पृष्ठ-17) ये देखना संचार नीति-निर्माताओं और इस पेशे से जुड़े लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जोखिम कम हो और गलतियों को ठीक कर दिया जाए।" "Distortion" शब्द का हिन्दी अर्थ विकृति, कुरूपता होती है। लेकिन संचार माध्यमों तथा नीतियों के सम्बन्ध में विकृति या कुरूपता पयार्य का प्रयोग वाक्य के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भाव तथा अर्थ के अनुसार 'गलती' अनुवाद उपयुक्त प्रतीत होता है।

"Even where freedom is not openly attacked by authority, it may be limited by self-censorship on the part of communication themselves." (पृष्ठ-19) जहाँ सत्ता द्वारा आजादी पर सीधे हमले नहीं किये जाते हैं वहाँ हो सकता है कि संचारकों पर स्व-नियंत्रण के जरिए आजादी को सीमित कर दिया जाए।"

"self-censorship" शब्द को हिन्दी अनुवाद में स्व-नियंत्रण किया गया है। इसे हिन्दी में बहुत जगह सेंसरशिप भी लिखा जाता है लेकिन अगर जहाँ स्व-सेंसरशिप लिखा जाता तो यह जटिल लगता।

"Democracy" (पृष्ठ-20) के लिए जनतंत्र, प्रजातंत्र तथा लोकतंत्र तीनों पर्याय हैं। लेकिन पर्याय चयन की समस्या यहाँ बनी हुई है। वाक्य संरचना तथा भाव के अनुरूप 'लोकतंत्र' अनुवाद किया गया है।

"But neither practical necessities nor the claims of ideology should be invoked to exclude freedom of expression." (पृष्ठ-21) लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को उसकी उपयुक्त जगह से हटाने के लिए न तो व्यावहारिक ज़रूरतों और न ही विचारधारा के दावों का उपयोग करना।"

इस वाक्य में 'exclude' को हटाना अनुवाद किया गया है। 'exclude' का हिन्दी में अर्थ अलग करना, वर्णित करना, बाहर करना, निकालना होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ 'हटाना' पर्याय भाव को प्रभावपूर्ण व्यक्त कर पा रहा है।

"In developed countries, the introduction of new technology followed this industrial revolution with an ample breathing - space." (पृष्ठ-24)

"विकसित देश में औद्योगिक क्रांति के बाद खाली हुई जगह को नई तकनीक ने भरा, लेकिन विकासशील देश इस क्रम को दोहरा नहीं सके।"

यहाँ हिंदी अनुवाद में "Breathing space" का अनुवाद 'ख़ाली जगह' किया गया है। "Breathing space" 'विश्राम, साँस लेने की' आदि पर्याय हैं। जो

वाक्य के भाव के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। इसलिए वाक्य के भाव को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिए "ख़ाली जगह" लिखा गया है।

"Interwoven" (पृष्ठ-25) का हिन्दी पर्याय बटना, मिलकर बाटना होता है। लेकिन वाक्य के अर्थ की सूक्ष्मता के हिसाब से इसका अनुवाद "एक-दूसरे में गूंथे हुए" किया गया है।

स्रोत भाषा में ट्रांजिस्टर रेडियो एक साथ आए हैं। " Transistor radio" (पृष्ठ-31) ट्रांजिस्टर शब्द रेडियो के लिए प्रचलित है। इसलिए इसका अनुवाद ट्रांजिस्टर रेडियो किया गया है। लेकिन ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है जो रेडियो में संदेश को सिग्नल में परिवर्तित करके भेजता है। इसलिये यहाँ भावानुवाद किया गया है।

"Impact and influence" (पृष्ठ-34) एक साथ वाक्य में आए हैं जिनका अनुवाद प्रभाव और असर किया गया है। जबकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं।

"Awareness of lag" (पृष्ठ-37) का अनुवाद जागरूकता की कमी की गई हैं। हिन्दी में Lag का धीरे चलना, पिछड़ जाना आदि पर्याय होता है। भाव के अनुसार Lag का अनुवाद 'कमी' की गई है।

"Detent" (पृष्ठ-38) का हिन्दी में अर्थ नरमी, दो देशों के सम्बन्ध को सुधारना' होता है। अंतरराष्ट्रीय संचार के द्वारा वैश्विक स्तर पर 'शांति' को बढ़ावा देने के भाव से अनुवाद किया गया है। "नरमी और दो देशों के सम्बन्ध" अनुवादित होकर वाक्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं लग रहे हैं।

"Link language" (पृष्ठ-38) का अनुवाद "सम्पर्क भाषा" किया गया है, "Link language" का अर्थ ऐसी भाषा से है जो पूरे देश को एक भाषा के

साथ जोड़े। अतः भाव की सूक्ष्मता को देकर सम्पर्क भाषा ही यहाँ अधिक उपयुक्त है।

"On-site encoding" (पृष्ठ-50) का लिप्यंतरण किया गया है। यह कम्प्यूटर में भाषा का नाम है जिसका अनुवाद नहीं हो सकता।

"Itinerant loudspeaker" (पृष्ठ-55) को घुमंतू लाउडस्पीकर अनुवाद किया गया है। itinerant का हिन्दी में अर्थ भ्रमणकारी, यायावर, दौरा करने वाला होता है। loudspeaker अननुवाद्य शब्द है। loudspeaker शब्द की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए itinerant का अनुवाद घुमंतू किया गया है। अतः घुमंतू लाउडस्पीकर प्रभावपूर्ण प्रतीत हो रहा है।

"Slide" (पृष्ठ-55) का हिन्दी में सरकाना, खिसकाना, फिसलन आदि अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ "स्लाइड" एक तकनीक है। जिसपर समाचार, सूचना, दृश्य- विज्ञापन आदि चलते रहते हैं। इसलिए "slide" को स्लाइड ही लिखा गया है। हिन्दी में इस तकनीक के लिए शब्द नहीं है।

"Barefoot doctors" (पृष्ठ-56) को अनुवाद में "बेयरफुट डॉक्टर" ही अनुवाद किया गया है। इसका हिन्दी में अर्थ नंगे या ख़ाली पैर के डॉक्टर नहीं होगा। नंगे पैर के डॉक्टर लिखने पर अनुवाद भ्रामक तथा समझ से परे हो जाएगा। बेयरफुट डॉक्टर चाइना के किसान होते हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाव तथा साफ-सुधरा रहने की जानकारी देते हैं। ऐसी कोई भी प्रणाली भारत में कार्य नहीं करती। यह एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अनुवाद नहीं हो सकता। अतः अनुवाद में इसका लिप्यंतरण किया गया है।

मिश्र वाक्यों का तद्वत अनुवाद करना कठिन और जटिल होता है। अंग्रेज़ी वाक्य के कर्ता-क्रिया-कर्म को हिंदी में अनुवाद करते समय हिंदी के वाक्य संरचना के अनुसार कर्ता-कर्म-क्रिया क्रम में रखना होता है । इनके क्रम हिंदी में बदल जाते हैं। अनुवाद में कई बार इन वाक्यों को तोड़कर अनुवाद किया गया है जिससे हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो और वाक्य प्रवाहपूर्ण बन सके।

"The Commission's sixteen members -largely representative of the world's ideological, political, economic and geographical spectrum -reached what I consider a surprising measure of agreement on major issues, upon which opinions heretofore had seemed irreconcilable. It was not simply a matter of reaching conclusions; more important, perhaps, was the identification and analysis of the problems and the possible solutions. In the inevitable continuing debates on facets of the developing new world information and communication order we hope that these may be of assistance." (पृष्ठ-xvii)

हिंदी अनुवाद-

आयोग के सोलह सदस्य जो बड़े पैमाने पर दुनिया के वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्पेक्ट्रम के प्रतिनिधि हैं, प्रमुख मुद्दों पर आश्चर्यजनक रूप से समझौते के उपाय पर विचार करने लग जाते हैं जो पहले असंगत लग रहे थे। यह सिर्फ निष्कर्ष तक पहुँचने की बात नहीं थी। शायद इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था समस्याओं और संभावित समाधानों की पहचान और उनका विश्लेषण किया जाना। हम उम्मीद करते

हैं कि विकासशील नई दुनिया में सूचना और संचार क्रम के पहलुओं पर अपरिहार्य रूप से जारी बहस शायद मददगार हो।"

"Despite the large area of consensus reached on most major issues, it is obvious that many questions remain open; in addition, many subjects require further analysis. Many difficulties lie ahead, particularly in organizing and implementing concrete measures to help to construct the new order, which call for continuing review. There are many varying views as to the meaning of the "New Order" and as to what it should encompass, just as there are diverse opinions on ways and means of achieving it." (पृष्ठ-xviii)

हिंदी अनुवाद-

"एक बड़े हिस्से की महत्वपूर्ण विषयों पर आम सहमति होने के बावजूद, बहुत सारे सवालों पर स्पष्टता नहीं बनी, बहुत सारे विषयों में विश्लेषण की आवश्यकता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आगे हैं, विशेष रूप से नई व्यवस्था के निर्माण में मदद हेतु उनको व्यवस्थित करने और ठोस उपायों को लागू करने में, जो सतत समीक्षा की मांग करती है। नये क्रम के अर्थ और इनको किस रूप में शामिल करना चाहिए पर बहुत सारे अलग-अलग विचार है, जैसे इसको प्राप्त करने के तरीके एवं साधन के लिए सिर्फ एक विविध राय के रूप में।

"Probably the major phenomenon of the second half of the twentieth century has been the accession to independence of

almost eighty nations, thanks to which over two billion people have been liberated from colonial domination. Despite this, present-day world conditions -political, economic, scientific, technological and military as well as social and cultural -tend to foster the position and influence of certain countries, and to perpetuate the dependence of a large number of other countries" (पृष्ठ-34)

हिंदी अनुवाद-

"बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की प्रमुख घटना संभवतः लगभग 80 देशों का स्वतंत्र होना है। इससे क़रीब दो अरब लोग उपनिवेशवादी वर्चस्व से आजाद हुए। इसके बावजूद वर्तमान विश्व की हालत राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैन्य के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ देशों के स्थिति और प्रभाव के प्रगति की तरफ है। ऐसे थोड़े से देशों पर बड़ी संख्या में अन्य देशों की निर्भरता बढ़ने के रुझान दिख रहे हैं।"

यहाँ हिंदी अनुवाद में अंग्रेज़ी वाक्यों को विभाजित करके अनुवाद किया गया है ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके और हिंदी की वाक्य संरचना के अनुकूल हो।

ऐसे बहुत से वाक्य अनुवाद में आए जो मिश्रित तथा लम्बे थे, जिनका अनुवाद करने में प्रस्तुत अध्येता को कठिनाई हुई।

अनुवाद करते समय बहुत तरह की समस्याओं का सामना अनुवादक को करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे निरन्तर अपने भाषा तथा शब्द के ज्ञान को समृद्ध करने की आवश्यकता रहती है। अनुवाद की समस्याएं ख़त्म नहीं होती। किसी न किसी स्तर पर अनुवाद की समस्या

बनी रहती है। इस प्रकार अनुवाद की समस्याएं अनुवादक को और भी मांजती हैं। साथ ही, भाषा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ज्ञान से अनुवादक के साथ ही, लक्ष्य भाषा के पाठकों को भी समृद्ध करती हैं।

संदर्भ:

1. Darwish, Ali (2003), "The Translation Process: A View of the Mind", *Turjuman Online.*
2. Dooley, Robert A. (2005), "Source-Language Versus Target-language Discourse Features in Translating the word of god", *Journal of Translation,* 1 (2)
3. अनुवाद: सिद्धांत और प्रविधि-अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकार एवं सीमाएँ(2009), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मानविकी विद्यापीठ, (पृष्ठ-8,9)

उपसंहार

अनुवाद की दुनिया विस्तृत और व्यापक है। ज्ञान एवं सूचना की दृष्टि से भी इसका महत्व अन्यतम है। भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नता एवं भाषाई विषमता एवं विजातीयता को देखते हुए अनुवाद अंतर-सांस्कृतिक आवाजाही का सर्वप्रमुख साधन है। वर्तमान समय में अनुवाद पूरे विश्व में संवाद स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाज, संस्कृति, साहित्य, संवाद, व्यापार, संधि, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुवाद की उपादेयता असंदिग्ध है।

मानव समाज में सामाजिक अंतःक्रिया एवं मानवीय सम्पर्क संचार-प्रक्रिया द्वारा संचालित होते हैं। सामाजिक इकाई के रूप में मनुष्य जब सामाजिक सम्बन्धों का निर्वहन अथवा उसका वैचारिक संपोषण करता है तो उसमें संचार की भूमिका अंतर्निहित होती है। प्रारम्भ में संचार सीमित समुदायों एवं समूहों के मध्य ही स्थापित होता था, जिनका एक निश्चित दायरा था; निर्धारित लोकवृत्त था। हैबरमास ने इसे ही 'पब्लिक स्फ़ियर' नाम से अभिहित किया है। लेकिन, संचार के क्षेत्र में विकास और सूचनाक्रांति के विकास के साथ बहुभाषाभाषी समाज और लोगों के बीच मेलजोल एवं संपर्क का दायरा उत्तरोत्तर विस्तृत होता चला गया है। परिणामतः बहुभाषिक समाज में जनसंचार ने अपनी भूमिका और पैठ को न सिर्फ गहराई में जाकर रोपा है, अपितु तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के सहारे भाषा-अंतरण/लैंग्वेज-ट्रांसफर एवं भाषा-अभिसरण/लैंग्वेज-कनवर्जेंस सम्बन्धी कौशल को पहले से अधिक उन्नत, परिष्कृत, परिवर्धित एवं बहुआयामी बनाया है। आज जनसंचार की सहज उपलब्धता और कार्य-सम्बन्धी विशेषीकृत साधनों/टूल्स ने हरेक व्यक्ति को सूचना-सम्पन्न बना दिया है; उसे देश-दुनिया की ख़बर चंद मिनटों में उपलब्ध है; अन्तर्जाल-युग ने हर व्यक्ति को 'ज्ञानोदय'/इनलाइटमेंट के 'सेट-अप-

बॉक्स' से स्फूर्त माध्यमों से जोड़ दिया है। परस्पर संवाद करती यह पीढ़ी मूल से अपरिचित, अनजान और बिल्कुल भिन्न होते हुए भी आपसी साझेदारी द्वारा जनसंचार के नवयुग में बिना किसी कठिनाई के प्रवेश कर रही है। इस जोड़-जुड़ाव में अनुवाद एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध कर रही है।

निश्चय ही, अनुवाद की सहायता के बिना इतने व्यापक स्तर या परिधि में संचार-प्रक्रिया का सफल होना संभव नहीं था। वर्तमान समय में नवमाध्यम के विभिन्न रूप एवं संरचनाओं; यथा-दृश्य-श्रव्य माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, फ़िल्म, साहित्य, कला इत्यादि में अनुवाद को विशेष महत्व एवं वरीयता प्राप्त है। वैश्वीकरण के वर्तमान सन्दर्भ में अनुवाद की विभिन्न अर्थच्छटाएँ हमारे सामने हैं। आज अनुवाद की वैश्विक ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि इसे एक स्वतंत्र शैक्षिक अनुशासन के रूप में देखा जा रहा है। जनमाध्यमों के निर्बाध प्रवाह एवं सूचनाओं के बेरोकटोक आवागमन की दिशा में अनुवाद एक अनिवार्य कड़ी है जिसे पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। वर्तमान समय में अनुवाद की आवश्यकता तेजी से हो रही है। सांस्कृतिक विचार-विनिमय एवं नवमाध्यमों के प्रचार-प्रसार ने अनुवाद को एक स्वतन्त्र अनुशासन के रूप में मान्यता प्रदान की है।

मेनी "वॉयसेस वन वर्ल्ड" की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर संचार की समस्याओं का सूक्ष्मता से अध्ययन करती है। यह संचार की समस्याओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं के अंतर्गत गहराई से अध्ययन है। यह महत्वपूर्ण शोधकार्य था जिसे 1970 से शुरू किया गया और 1980 में एक स्पष्ट निष्कर्ष के साथ सम्पन्न हुआ। सीन मैकब्राइड ने इसमें संचार सम्बंधी समस्याओं और संचार के सभी पक्षों पर किये गए अध्ययन को ईमानदारी से रखा है। इस रिपोर्ट में वर्णन है कि संचार किस तरह हमारे जीवन को गति प्रदान करने का

महत्वपूर्ण साधन है। बिना संचार के पूरा विश्व अपने जीवन को गति प्रदान नहीं कर सकता और मूकबधिर की तरह जीवन व्यतीत करने को बाध्य है। इस शोध से पता चलता है कि हमें संचार कैसा और क्यों चाहिए। कौन इन साधनों का प्रयोग अपने हित में करके विश्व को क्षति पहुँचा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्र चालाकी से किस प्रकार संचार के माध्यमों पर एकाधिकार हासिल कर अपने को दुनिया को दुनिया का सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाना चाह रहे थे जो विश्व के लिए एक बड़े ख़तरे का संकेत था। इस प्रकार संचार से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हमें इस शोधकृति में मिल जाती है। इस पुस्तक की महत्ता इस बात से लगायी जा सकती है कि इसके निष्कर्ष तीन दशक बाद भी संचार के वर्तमान समस्याओं के हल आज भी बता सकते हैं। इस शोध की रिपोर्ट जो विभिन्न भाषाओं में भी लिखी गई एवं अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद कर के एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध कराई गई।

अनुवाद केवल स्रोत भाषा के अर्थ को लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित कर देने से नहीं हो सकता और अनुवाद की प्रक्रिया भी सरल नहीं होती है। अनुवाद करने से पहले स्रोत भाषा के विषय की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए क्योंकि साहित्यिक, काव्यात्मक, नाटक , तकनीकी आदि विषयों का अनुवाद एक-दूसरे से भिन्न तरह से होता है। इन सभी अनुवादों को करने की प्रविधि भी भिन्न होती है। मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट तकनीकी अनुवाद है। तकनीकी अनुवाद में अर्थ एवं भाव के साथ-साथ उस क्षेत्र के विशिष्ट तथा पारिभाषिक शब्दावलियों की भी जानकारी आवश्यक है।

प्रत्येक भाषा की अपनी अलग स्थिति, प्रकृति, शैली तथा विशिष्ट भाषिक संरचना होती है। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करते समय इन बातों का भी ज्ञान रखना होता है तभी वह सफल अनुवाद कर पाता है। अनुवाद करते समय भाषा के स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। अंग्रेज़ी और हिन्दी भाषा के वाक्य-क्रम में अंतर के स्तर पर भी समस्या

आती है क्योंकि अंग्रेज़ी वाक्य-क्रम में कर्ता-क्रिया-कर्म और हिन्दी में कर्ता-कर्म-क्रिया होता है। अंग्रेजी में क्रिया विशेषण का प्रयोग बाद में किया जाता है जबकि हिन्दी में क्रिया-विशेषण का प्रयोग क्रिया से पहले। इसलिए हिन्दी में अनुवाद करते समय अंग्रेज़ी का वाक्य-क्रम व्याकरण व्यवस्था के अनुरूप बदल जाता है जिससे बहुत बार अर्थ सम्प्रेषणीय बनता है और नहीं भी। बहुत बार स्रोत भाषा का अर्थ लक्ष्य भाषा में अबूझ ही नहीं जटिल भी हो जाता है।

अंग्रेज़ी के लम्बे तथा मिश्रित वाक्यों का अनुवाद हिन्दी के वाक्य संरचना के अनुसार करने में कठिनाई होती है। बहुत बार इन मिश्रित वाक्यों को क्रमानुसार विभक्त अनुवाद करना होता है क्योंकि हिन्दी की संरचना के अनुसार लम्बे तथा मिश्रित वाक्यों को सम्प्रेष्णीय बनाने के लिए तोड़-तोड़ कर रखना पड़ता है। स्रोत-भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय अननुवाद्य की समस्या भी आती है क्योंकि स्रोत भाषा के संस्कृति के शब्दों का पर्याय लक्ष्य भाषा में नहीं होता है। अनुवादक को ऐसे शब्द एवं पदों का लिप्यंतरण कर के पाद टिप्पणी देना अनुवाद के पाठकों के लिए उचित होता है। अनुवाद में बहुत बार उपयुक्त पर्यायों को चुनने की समस्या भी आती है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा पारिभाषिक स्तर पर भी अनुवाद में समकक्ष शब्दों को लेकर भी समस्या बड़ी होती है। अतः अनुवादक वाक्य, भाषाशैली, शब्द के स्तर पर अनुवाद करते समय समस्याओं का सामना करता रहता है। अनुवादक की एक सीमा होती है। इन सीमाओं के आगे अनुवादक को बड़ी सूझ-बूझ के साथ अनुवाद करना होता ताकि लक्ष्य भाषा का अर्थ स्पष्ट हो और लक्ष्य भाषा के पाठक को यह अहसास ही न हो कि वह अनुवाद पढ़ रहा है।

अनुवाद एक ऐसा कार्य है जो एक बार में कोई सीख नहीं सकता। लगातार अनुवाद करते रहने पर ही अनुवाद में कोई पारंगत होता है। इन तमाम समस्याओं के बावजूद अनुवाद की मांग और पूर्ति जारी है। लेकिन

साहित्य को छोड़ अन्य विभिन्न विषयों के साथ संचार में अनुवाद न्यून मात्रा में हो रहे हैं। जिससे बहुत बड़ा तबका संचार सम्बंधी जानकारियों से दूर है। संचार में प्रतिदिन ढ़ेरों जानकारियां आती हैं और उनके अनुवाद की मांग भी है। लेकिन हिन्दी भाषा में इन, मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अनुवादक को मूल लेखक के समान सम्मान एवं मानदेय भी नहीं दिया जाता जो कि इस विधा की सबसे बड़ी जरूरत है। जब अनुवादकों को सम्मान एवं मानदेय दिया जाने लगेगा तो अनुवाद में और तेजी आएगी। अनुवाद भी सटीक एवं उत्कृष्ट होंगे। इस प्रकार अनुवाद वर्तमान समाज की उन सभी जरूरतों से जुड़ा है जो उसे जागरूक और प्रबुद्ध करती हैं। इसे नज़रअंदाज कर कोई भाषा और समाज गतिशील नहीं रह सकते।

संदर्भ ग्रंथ - सूची

आधार ग्रंथ -

- United Nations (1980), "*Many voices one world' MacBride commission Report*".

सहायक ग्रंथ -

- गोपीनाथ, सं. जे. और एस. रंदास्वामी (1993), *अनुवाद की समस्याएं*, नई दिल्ली: लोकभरती प्रकाशन.
- नगेन्द (संपा.) (2003), *अनुवाद विज्ञानः सिद्धांत और अनुप्रयोग*, दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय.
- राजकपूर, भ.ह., और राजमल बोर (संपा.) (2004), *अनुवाद क्या है*, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
- Anderson, R. Bruce W. and Richard W. Brislin (1976)' *Translation Application and Research*, New York: Gardner Press.
- Calabrese, Andrew (2004), *Many voices, one world: Towards a new, more just, and more efficient world information and communication order 'MacBride commission'*, Lanham: Rowman & Littleaeld Publishers.
- Calabrese, Andrew (2005), "The MacBride Report: Its Value to a New Generation" *Quaderns del*, 21: 23-26.
- Catford, J. C. (1965), *A Linguistic Theory of Translation*, London: Oxford Press.
- McGill, Austin (1987), "MacBride: The Myths", *Fortnight*, 250: 8.
- Nida, E. (1975), "A Framework for the Analysis and Evaluation of Theories of Translation", in R.W. Brislin (eds.), *Translation Application and Research*, New York: Gardner Press.
- Roach, Colleen (1997), "The western world and the NWICO", in Peter Golding and Phil Harris (eds.), *Beyond Cultural Imperialism: Globalization, Communication & the New International Order*, London: Sage.

- Schultz, George. 1984. "Letter from U.S. Secretary of State George Schultz to UNESCO Director-General Amadou-Mahtar M'Bow, announcing the decision of the U.S. government to withdraw its membership from UNESCO (28 December 1983)", *Journal of Communication*, 34(4): 82-84.

- Theberge, Leonard J. (1981), "U.N.E.S.C.O.'s "New World Information Order": Colliding with First Amendment Values", *American Bar Association*, 67 (6): 714-718.

- Venuri, Lawrence (eds.) (2012), *The Translation Studies Reader*, London: Routledge.

सहायक शब्दकोश -

- अवस्थी, सुरेश (200), "चेम्बर्स अंग्रेजी- हिंदी कोश", नई दिल्ली: अलाइड, पब्लिशर्स प्रा. लि:
- कुमार, अरविन्द "अंग्रेजी- हिंदी कोश".
- बुल्के, फ़ादर कामिल (2000), "अंग्रेजी- हिंदी कोश", नई दिल्ली: एस चंद एंड कम्पनी लि.
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary (e-Version)

Web Source -

SHABDKOSH

http://www.shabdkosh.com/